खण्ड–483, अंक–8
बुधवार, 08 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(27 फरवरी, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2013)

(खण्ड 483 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-110
पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त हुए प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	110-111
प्रश्नों हेतु समय-सीमा का निर्धारण के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न... ...	111
गन्ना किसानों के भुगतान सम्बन्धी नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-6 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	112-113
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	113
जनपद हाथरस (महामायानगर) के कतिपय नये सम्पर्क मार्गों को बनाये जाने एवं कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113-115
जनपद बस्ती के निर्वाचन क्षेत्र बस्ती सदर के बरदहिया चौराहे से बी0एम0 सिटी मार्ग के गड्ढायुक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115-116
जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम सोटा में निर्मित पानी की टंकी से पानी की सप्लाई शुरू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116
मेरठ शामली मार्ग पर नानू नहर के पुल से कस्बा सरधना तक निर्मित मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	116
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के विकास खण्ड महुली बाजार में सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी में विद्युतीकरण कराये जाने एवं तड़ित चालक लगाकर आकाशीय बिजली गिरने से हो रही जनहानि को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक लोटन में बजहा ताल के बगल से मुडिला बांध होते हुए गौरी गांव तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117-118
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	118

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौण्डा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118-119
जनपद चन्दौली में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-1, चन्दौली द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119
जनपद इलाहाबाद और कौशाम्बी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119
भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा के लिये गोरखपुर में तैनात सशस्त्र सीमा बल से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा अत्यधिक दर पर विद्युत बिल की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120
विधान सभा क्षेत्र गंगोह में फैली विद्युत अव्यवस्था के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120-121
जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम बेल्तुआ नौरंगापुर पुल से गड़रियनपुरवा की 3 कि0मी0 सड़क के ध्वस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	121
जनपद फतेहपुर के निर्वाचन क्षेत्र बिन्दकी के कतिपय गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121
कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के कतिपय इलाकों में विद्युत पोल एवं तार उपलब्ध कराकर विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	122-123
कुम्भ मेले हेतु केन्द्र सरकार से अपेक्षित धन प्राप्त न होने विषयक औचित्य का प्रश्न	123-129
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज, ब्लाक ऐरायां में ब्लाक कार्यालय भवन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मो0 शोएब व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका..... (उपस्थित की गई) ...	130
शून्य प्रहर के अन्तर्गत आज के लिए निर्धारित नियम-56 की सूचनाएं कल प्राथमिकता पर लिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी	130
शून्य प्रहर में आधे घण्टे का समय बढ़ाये जाने का अनुरोध	130-131
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	131-140

विषय	पृष्ठ-संख्या
शून्य प्रहर का बढ़ा हुआ समय समाप्त होने पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की शेष सूचनाएं कल लिये जाने के निर्देश...	140-141
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)... ...	141-210
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	210-213
इलाहाबाद स्थित फाफामऊ बाजार की सड़क के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की टी0ए0सी0 से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	213-214
जनपद पीलीभीत की जिला पंचायत में कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ...	214
जनपद चन्दौली में वित्तीय वर्ष 2012 में अवमुक्त धनराशि से विकास कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन..	215
जनपद शामली के कतिपय क्षेत्रों में फुंके हुए ट्रांसफार्मर को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	215-216
जनपद सीतापुर में चिकित्सकों की तैनाती न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	216
जनपद मेरठ में जल निगम द्वारा पाइप लाइन डालने हेतु खोदी गई सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	216
प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंकों में बैंकिंग लाइसेन्स लेना अनिवार्य किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य	217-218
जनपद कुशीनगर के पडरौना क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों में विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	219-220

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अलीगढ़ के राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी स्थल पर दुकानों के निर्माण में हुई धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ठा0 दलवीर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	220
जनपद शाहजहांपुर के तिलहर में वर्ष 2012-2013 में गन्ना क्रय केन्द्रों पर मनमानी किये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	220
आगरा के विधान सभा फतेहाबाद बाईपास के अन्तर्गत निर्माण कार्य में भूमि अधिग्रहीत किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	220
जनपद शाहजहांपुर में महिला आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को सेवा में वापस लिये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	220
मेरठ विकास प्राधिकरण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कोलोनाइजर विल्डरों से मिलकर बड़े पैमाने में घोटाले किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कुंवर भरतेन्द्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	221
जनपद सुल्तानपुर में निर्माणाधीन तहसील जयसिंहपुर की अवशेष धनराशि को अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	221
जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र कैण्ट के अन्तर्गत स्थित कतिपय कालोनियों के सीवरों की सफाई एवं जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	221
नत्थियां	222-232

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2013

[विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्य-346

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
4. अजय मिश्र 'टेनी', श्री — लखीमपुर खीरी
5. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
6. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
7. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
8. अताउररहमान, श्री — बरेली
9. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
12. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
14. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
21. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
22. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
23. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
24. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
25. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
26. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
27. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
28. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
29. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
30. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
31. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
32. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
33. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
34. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
35. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
36. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
37. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
38. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
39. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
40. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
41. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
42. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
43. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
44. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
45. आशीष यादव, श्री — बदायूं
46. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
47. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर

48. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
49. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
50. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
51. इन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
52. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
53. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
54. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
55. उदयराज, श्री उन्नाव
56. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
57. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
58. उमाशंकर, श्री बलिया
59. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
60. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
61. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
62. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
63. काजिम अली खां
उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
64. काली चरन सुमन, श्री आगरा
65. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
66. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
67. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
68. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
69. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
70. कैलाश, श्री गाजीपुर
71. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
72. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
73. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
74. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
75. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
76. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
77. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
78. गिरीश चन्द्र उर्फ
गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
79. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
80. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
81. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
82. गोमती यादव, श्री लखनऊ
83. गोरख पासवान, श्री बलिया
84. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
85. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
86. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
87. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
88. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
89. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
90. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
91. जगपाल, श्री सहारनपुर
92. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
93. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
94. जफर आलम, श्री अलीगढ़
95. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
96. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
97. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
98. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
99. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
100. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
101. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
102. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
103. जीतेन्द्र कुमार उर्फ
नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
104. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
105. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ
पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
106. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
107. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
108. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
109. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन

110. दलजीत सिंह, श्री बांदा
111. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
112. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
113. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
114. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
115. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
116. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
117. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
118. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
119. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
120. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
121. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
122. धर्मराज, श्री बाराबंकी
123. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
124. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
125. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
126. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
127. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
128. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
129. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
130. नारद राय, श्री बलिया
131. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
132. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
133. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
134. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
135. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
136. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
137. पीतमराम, श्री पीलीभीत
138. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
139. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
140. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
141. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
142. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
143. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
144. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
145. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
146. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
147. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
148. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
149. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
150. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
151. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
152. फेरन लाल, श्री ललितपुर
153. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
154. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
155. बदलू खां, श्री उन्नाव
156. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
157. बाबू खां, श्री हरदोई
158. बाबूलाल, श्री गोण्डा
159. बावन सिंह, श्री गोण्डा
160. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
161. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
162. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
163. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
164. बैजनाथ, श्री मऊ
165. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
166. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
167. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
168. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
169. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
170. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
171. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
172. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद

173. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
174. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
175. मनबोध, श्री देवरिया
176. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
177. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
178. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
179. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
180. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
181. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
182. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
183. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
184. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
185. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
186. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
187. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
188. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
189. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
190. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
191. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
192. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
193. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
194. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
195. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
196. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
197. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
198. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
199. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
200. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
201. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
202. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
203. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
204. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
205. यासर शाह, श्री बहराइच
206. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
207. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
208. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
209. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
210. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
211. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
212. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
213. रणजीत सुमन, श्री एटा
214. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
215. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
216. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
217. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
218. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
219. रवि शर्मा, श्री झांसी
220. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
221. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
222. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
223. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
224. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
225. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
226. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
227. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
228. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
229. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
230. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
231. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर

232. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
233. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
234. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
235. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
236. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
237. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
238. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
239. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
240. राम करन आर्य, श्री बस्ती
241. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
242. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
243. राम गोविन्द, श्री बलिया
244. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
245. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
246. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
247. राम मगन, श्री बाराबंकी
248. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
249. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
250. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
251. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
252. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
253. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
254. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
255. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
256. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
257. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
258. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
259. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
260. लक्ष्मीकान्त उर्फ
पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
261. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
262. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
263. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
264. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
265. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
266. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
267. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
268. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
269. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
270. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
271. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
272. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
273. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
274. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
275. विजय सिंह, श्री रामपुर
276. विजय सिंह पुत्र
प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
277. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
278. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
279. विनोद कुमार उर्फ
पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
280. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
281. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
282. वीरपाल राठी, श्री बागपत
283. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
284. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
285. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
286. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
287. शमशेर बहादुर उर्फ
शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
288. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
289. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
290. शाकिर अली, श्री देवरिया
291. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
292. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ

293. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
294. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
295. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
296. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
297. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
298. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
299. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
300. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
301. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
302. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
303. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
304. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
305. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
306. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
307. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
308. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
309. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
310. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
311. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
312. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
313. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
314. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
315. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
316. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
317. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
318. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
319. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
320. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
321. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
322. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
323. सियाराम सागर, डा0 बरेली
324. सीमा, श्रीमती जौनपुर
325. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
326. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
327. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
328. सुधाकर, श्री मऊ
329. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
330. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
331. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
332. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
333. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
334. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
335. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
336. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
337. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
338. सुल्तान बेग, श्री बरेली
339. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
340. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
341. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
342. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
343. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
344. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
345. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
346. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) एवं कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में स्वाइन फ्लू पर रोकथाम हेतु कार्य योजना

*1-डा0 धर्मपाल सिंह, श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा), श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) एवं श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में स्वाइन फ्लू से लगभग 123 से अधिक मौतें हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते हुये खतरे को रोके जाने हेतु कोई त्वरित कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल माझी)-

जी नहीं। निकटवर्ती राज्यों राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में स्वाइन फ्लू से मृत्यु की सूचना उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मृत्यु की अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश में स्वाइन फ्लू के नियंत्रण/रोकथाम के लिए जारी की गयी कार्य योजना 2013 के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-

1-मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण।

2-स्वाइन इन्फ्लूएन्जा के लिए राज्य में चिकित्सालयों का चिन्हीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।

3-राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों, चिकित्सालयों का चिन्हीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।

4-सर्वेक्षण।

5-चिकित्सा उपचार।

6-जन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यवाही।

7-संसाधन सामग्री की आवश्यकता एवं पूर्ति।

8-जन सम्पर्क एवं मीडिया प्रबन्धन।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह रोज की प्रक्रिया है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, कल यह नहीं था। कल तो मुख्य मंत्री जी खुद ही विद्युत मंत्री थे। इसके मंत्री जी दूसरे सदन को भी देखते हैं।

डा0 धर्मपाल सिंह-

अध्यक्ष जी 2009 में स्वाइन फ्लू की पहली दस्तक अपने देश में प्रकाश में आई थी और करीब एक हजार लोगों की मौत हुई थी। माननीय अध्यक्ष जी आपके संज्ञान में होगा इस साल भी हमारे प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। 265 लोगों में स्वाइन फ्लू के वायरस की पुष्टि हो चुकी है। हरियाणा में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। और 94 लोगों में इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी दिल्ली में भी कई लोगों की मौत हो गई और 94 लोगों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। आगरा में अभी तक दो मरीजों में इसकी पुष्टि हो चुकी है और एक महिला मरीज जो कोरई की निवासी थी उसकी डेथ हो चुकी है। कोसी में एक बच्ची की डेथ हो चुकी है। गाजियाबाद और नोयडा में भी एक एक मरीज में इस स्वाइन फ्लू वायरस की पुष्टि हो चुकी है। अध्यक्ष जी आगरा में दुर्भाग्य यह है कि आगरा में इसका कोई न जिला अस्पताल में न एस0एन0 मेडिकल कालेज में इसकी कंफ्रमरी टेस्ट जो पी0सी0आर0 होता है उसकी कोई सुविधा नहीं है। आगरा के मरीजों का जो श्राव होता है उसे लेकर दिल्ली भेजा जाता है। अध्यक्ष जी इस बीमारी में शुरू के एक या दो दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं अगर मरीज को शुरू के दो दिनों में इलाज नहीं मिलता है तो दवाइयां काम नहीं करती हैं और मरीज को बचाना बहुत मुश्किल होता है। आगरा से वह सैम्पल लेकर दिल्ली भेजा जाता है रोग संचारी केन्द्र वहां से जांच आने में कम से कम आठ या नौ दिन लगते हैं अभी वह महिला जिसकी डेथ हुई जिसमें पाजिटिव पाया गया यह वायरस उसका सैम्पल लेकर दिल्ली भेजा गया वहां से रिपोर्ट नहीं आ पाई इसी बीच में उसकी डेथ हो गई। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या आगरा एस0एन0 मेडिकल कालेज सहित प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों में इस स्वाइन फ्लू वायरस के कंफ्रमरी टेस्ट जो पी0सी0आर0 होता है सभी सुविधाओं सहित क्या लैब खोलने का सरकार काम करेगी ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर उत्तर में ही है कि निकटवर्ती राज्यों में और खुद उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है स्वाइन फ्लू की और किसी मौत की सूचना नहीं है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

आगरा में पुष्टि हुई है एक महिला की मौत हुई है दूसरी महिला एडमिट है कोसी में एक बच्ची की डेथ हुई है नोयडा और गाजियाबाद में भी पाए गए हैं। सरकार अपनी जानकारी अपटू डेट कर ले मैं 100 प्रतिशत जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि आगरा में एक महिला की मृत्यु हो चुकी है दूसरी महिला अभी भी हास्पिटल में है और 12 लोगों के सैम्पल लेकर दिल्ली रोग संचारी केन्द्र भेजे गए हैं। अध्यक्ष जी मैं अपनी बात को दुबारा कह रहा हूं कि इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार इसकी जानकारी कर ले आगरा से मरीजों के सैम्पल लेकर दिल्ली भेजे जाते हैं वहां से 7-8 दिन में रिपोर्ट आती है तब तक मरीजों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। माननीय मुख्य मंत्री जी भी हैं मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आगरा बहुत विशिष्ट शहर है लाखों पर्यटक भी वहां आते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी समय का ध्यान रखना चाहिए और आपने लिखकर भी नहीं दिया था मैं नहीं आ पाऊंगा। यह परिपाटी ठीक नहीं है।

श्री शंखलाल मांझी-

गाड़ी फंस गई थी।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, गाड़ी तो किसी की भी फंस सकती है।

श्री अध्यक्ष-

तो पहले चला करें ना।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

असल में जाम वगैराह लग जाता है इस वजह से। सॉरी।

डा0 धर्म पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आगरा में मरीजों की स्थिति दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, जब सरकार ही जाम में फंसेगी तो उत्तर प्रदेश की जनता का यह रास्ता कैसे साफ करेंगे।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

बस यही फक्र है मान्यवर, लोकतंत्र में यकीन रखने वालों का और तानाशाही में यकीन रखने वालों का। तानाशाहों की जब गाड़ियां चलती हैं तो रास्ते खुद बखुद खाली हो जाते हैं, रास्ते रोक दिये जाते हैं (मेजें थपथपाई गईं) और जब लोकतंत्र चलता है तो हर आम और गरीब आदमी को भी उतना ही अधिकार रास्तों पर होता है। इस सरकार के आने के बाद वह सारी पाबंदियां जो तानाशाहों के चलने पर लगा करती थीं, पानी छिड़का जाता था, हवा से तिनके उड़ाये जाते थे, सड़कों पर खुश्बू बिखेरी जाती थी और लाल बत्ती बंद ही नहीं होती थी वह सारे तानाशाही जितनी भी जरूरतें थीं और पाबन्दियां थीं वह सब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हटा ली गई हैं। अब आपकी भी गाड़ी रुका करेगी क्योंकि आपको जनता के साथ चलना है। (मेजें थपथपाई गई)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

कब तक अपनी असफलता पर चादर डालते रहेंगे।

डॉ0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं फिर कह रहा हूं कि 100 परसेन्ट हमारी सही जानकारी है आगरा में स्वाइन फ्लू से एक महिला की मृत्यु हो चुकी है। सरकार फिर चाहे तो इसकी जानकारी कर लें। एक महिला अभी भी एडमिट है।

श्री अध्यक्ष-

आपने दो बार कह दिया इस बात को, माननीय मंत्री जी का जवाब सुनिये।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मंत्री जी कह रहे हैं कि है ही नहीं कोई सूचना।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि माननीय सदस्य निश्चित जानकारी दे रहे हैं तो उस निश्चित जानकारी का संज्ञान लेते हुए क्या उस पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री शंखलाल मांझी-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक मृत्यु की बात है, पूरे प्रदेश में कोई इस तरह की सूचना नहीं है और माननीय सदस्य कोई निश्चित जानकारी की बात कर रहे हैं तो वह हमको बता दें।

श्री अध्यक्ष-

बता तो रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आप नहीं थे। माननीय विधायक जी ने बता दिया कि फलां-फलां जगह मौत हुई है, आप उसकी जांच करा लीजिये। माननीय सदस्य, आप लिखकर दे दीजिये उसकी जांच करा लेंगे।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, महिला की मौत हुई है और रोग संचारी केन्द्र से उसकी रिपोर्ट पाजिटिव आई है, यह आपके सी0एम0ओ0 आगरा की रिपोर्ट है। एक महिला मेहरा एम0जी0 रोड निवासी एडमिट है। उसकी रिपोर्ट पाजीटिव आई है, फिर भी सरकार कह रही है कि हमारे संज्ञान में नहीं है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, जितनी तजदीक से और जितनी मजबूती से माननीय विधायक जी ने प्रश्न को रखा है, मैं समझता हूं कि अगर वह उस रिपोर्ट की फोटो कापी यहां ले आते और आपके समक्ष देते तो उनकी बात और भारी हो जाती। जरा रुक जाएं, बात कहने दें। चूंकि जिस तरह प्रश्न रखा जा रहा है बर्डन आफ प्रूफ भी उसी पर है जो इल्जाम लगाता है। सरकार की जानकारी है कि ऐसा नहीं है लेकिन क्योंकि सदन के संज्ञान में आ गया है लिहाजा यह जानकारी ली जायेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक सवाल मैं करना चाहता हूं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मेरे ख्याल से स्वाइल फ्लू दब कर रह जायेगा क्योंकि अति लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी ना यह। और जाम का असर इन पर आ गया, पता नहीं कौन सा वाला जामा था वो। मान्यवर, स्पेसिफिक सवाल किया, कार्यवाही का हिस्सा बना। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। अब फोटो कापी जमा करने का, उनके बयान कराने का, भार इन्हीं के ऊपर रहेगा क्या ? जब कार्यवाही का हिस्सा बन गया मान्यवर, तो जानकारी करने का दायित्व आपका है, सरकार आपके हाथ में है, सी0एम0ओ0 आपके साथ में काम कर रहे हैं, सी0एम0ओ0 से रिपोर्ट मंगाने में क्या दिक्कत है और सी0एम0ओ0 की रिपोर्ट मंगाने के बाद में प्रभावी कार्यवाही करने का आश्वासन सरकार की तरफ से आना चाहिए यह मेरा सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

वो कह तो दिया संसदीय कार्य मंत्री ने।

श्री हुकुम सिंह-

आपने तो कह दिया लेकिन बर्डन इनके ऊपर है कि इल्जाम लगा रहे हैं। अध्यक्ष जी, इल्जाम लगाने और तथ्यों को रखने में अंतर है। इल्जाम नहीं लगाया उन्होंने, हकीकत को बयान किया है। हकीकत अगर सामने आई है तो उसका उपचार कराना सरकार का काम है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने कहा कि चूंकि आप कह रहे हैं इसलिए मैं इसको गम्भीरता से दिखवा लूंगा तो इसका मतलब है कि इसकी जांच हो जाएगी।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दिन से इस सदन का सदस्य हूं। हर सरकार की यह बात होती है कि कोई भूख से मौत न हो, अगर होती है तो उसमें कहा जाता है कि प्रशासन की और जिलाधिकारी की जवाबदेही होगी। इसलिए कभी कोई भूख से मौत होती नहीं है। यहां उत्तर आता है कि यह भूख से मौत नहीं है अन्य कारणों से मौत हुई है।

श्री अध्यक्ष- सवाल करें।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

सवाल ही पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय सवाल इतना गम्भीर है कि इसको संवेदनशीलता से लेने की आवश्यकता है और थी। लेकिन मुझे बहुत खेद है कि जो वहां से उत्तर लिखकर आया है मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं यह पिछली सरकार की बात होती थी कि जो लिखकर आता था वह पढ़ दिया जाता था। अब इस रिज्यूम में, मेरे रिज्यूम में ऐसा नहीं होगा। तो मैं यह अपेक्षा करता था, पुष्टि नहीं हुई, जो यह उत्तर आया है उसकी तस्दीक मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी पूरी संवेदनशीलता के साथ कर लेते, तब उत्तर देते तो मुझे बड़ी खुशी होती मेरी जानकारी में मेरठ के अन्दर इस फरवही माह में पांच लोगों की मौत हो चुकी है। उसके आस-पास के जिलों में तीन और मौतें हो चुकी हैं। धर्मपाल सिंह जी ने कहा कि आगरा में एक मौत हो चुकी है। लेकिन इन मौतों का क्या फर्क पड़ता है, अगर फर्क पड़ता है तो सरकार को चाहिए कि उसकी व्यवस्था करे। अगर पुष्टि नहीं हो रही है तो वर्डन ऑफ प्रूफ अगर हम कह रहे हैं तो हमारे ऊपर है, अब मैं तो इसको पुष्टि नहीं कर सकता हूं। न मैं डाक्टर हूं और न मैं मेडिकल साइंस का एक्सपर्ट हूं। तो अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करता हूं आपसे संरक्षण चाहता हूं जब मेरठ जिले के अन्दर पांच मौतें इसी फरवरी माह में हो चुकी हैं आगरा में एक मौत हुई है। मैं और जानकारी दे रहा हूं मेरठ के आसपास जिलों में तीन मौत कुल आठ मौत स्वाइन फ्लू से हो गई है। जो डाक्टर्स हैं इसकी पुष्टि नहीं करेंगे तो इसका असर यह होगा कि वह संवेदनशील नहीं रहेंगे। निष्क्रिय रहेंगे और वह एक अनहोनी को दावत दे रहे हैं इससे और मौतें होंगी, तो सरकार पर तो फक्र पड़ना चाहिए। सरकार संवेदनशील है मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इसकी पुष्टि कैसे होगी, सरकार इसकी पुष्टि कैसे करेगी ? किन शर्तों पर करेगी किसके कहने पर करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

आपने पूछ लिया, आप जो पूछ रहे हैं उसमें प्रश्न यह बन रहा है कि क्या सरकार इन बातों की पुष्टि करके उसका कोई उपाय ढूंढेगी। यही पूछना चाहते हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

मा0 मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रति भी मेरी धारणा यही है तो संवेदनशीलता का परिचय दें और जिन डाक्टरों ने लिखकर दिया है कि उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

वह बहुत कैजुअली ले रहे हैं मौतों को, किसी का घर उजड़ रहा है और आप बहुत कैजुअली ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी ने जवाब दिया है मेरे पास पूरी सूची है अभी यह सूची मांग रहे थे मेरे पास सूची है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, यह बता रहे हैं कि यह-यह मामले हैं, इसकी आप छानबीन करायेंगे ? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी डाक्टर साहब के प्रश्न के उत्तर में कह दिया कि गंभीरता से इसकी जांच करा लेंगे, अब इसमें बचा ही क्या है ?

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद मथुरा में कोसी में चिकित्साधिकारी द्वारा यह सर्टीफाई कर दिया गया है कि कोसी में जो मृत्यु हुई हैं, वह स्वाइन फ्लू से हुई हैं, मंत्री जी, आप उसकी पुष्टि करा लें, यह जो मृत्यु हुई हैं, वह स्वाइन फ्लू से हुई हैं। यह सारे समाचार-पत्रों में छपा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा, केवल इतना कह कर कि हम उसके प्रूफ दें, हम सर्टीफिकेट दें या उसके सर्टीफिकेट यहां लेकर आयें, उससे काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार इसका स्पष्ट जवाब दे कि जो मुख्य चिकित्साधिकारी ने कहा है, उसके अनुसार हम कार्यवाही करायेंगे।

श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कहा कि स्वाइन फ्लू से प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई है। मैं बताना चाहता हूं, हमारे यहां मेरठ में 8 आदमियों की इसके कारण मौत हो चुकी है, कुछ अस्पताल में भर्ती हैं और मौत से जूझ रहे हैं। मैं उनके नाम बता रहा हूं-आरती पुत्री छोटे लाल, उम्र 20 वर्ष, गढ़ रोड, अम्बेडकर नगर, जिला मेरठ, 19 फरवरी, 2013, पार्वती देवी, उम्र-52 वर्ष, शास्त्री नगर, सेक्टर-2, जिला मेरठ, दिनांक 18 फरवरी, 2013, राकेश पाण्डेय, वर्धमान अक्डेमी, उम्र 35 वर्ष, जिला मेरठ, 16 फरवरी, 2013, नीरज, निवासी गोलाबढ़, जिला मेरठ, मुख्तार अंसारी, निवासी सुभाष नगर, जिला मेरठ, सुन्दर सिंह, ग्राम दरियापुर, तहसील-गढ़, जिला हापुड़, रेनू पुत्री सतीश, गांव

पलवाड़ा, तहसील-गढ़, जिला हापुड़ और सुनीता पत्नी जितेन्द्र, मो0 देवीदास, खतौली, जिला मुजफ्फर नगर। इन 8 की सूचना मेरे पास है, अभी 25-30 की सूचना और दे दूंगा। माननीय मंत्री जी जो बता रहे हैं, उनके अधिकारी उन्हें गलत सूचना दे रहे हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। जो प्रश्न मैंने पूछा है, क्या सरकार उस पर कार्यवाही करेगी ? अध्यक्ष जी, आज 3-4 सवाल और पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष-

एक का तो जवाब आने दीजिए।

श्री शंखलाल मांझी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा जो सूचना दी जा रही है। आज ही उसके बारे में नए सिरे से पता करा लिया जायेगा। सरकार संवेदनशील है और यह स्वाइन फ्लू ऐसी बीमारी है, जिसके लक्षण इन्फ्लूएंजा के रूप में होते हैं और इसके वायरस एच1 और एन1 जो होते हैं, यह विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। अपने यहां इस तरह के वायरस वैश्विक स्तर पर आए हैं और यू0पी0 में खासतौर से माननीय सदस्य जिस तरह की बात कह रहे हैं, स्वाइन फ्लू के बारे में, इस तरह की पुष्टि नहीं है लेकिन लक्षण उसकी समानता के रूप में पाए जाते हैं। माननीय सदस्य सम्भवतः इसको स्वाइन फ्लू के रूप में मान रहे होंगे। मान्यवर, हम इसकी आज ही भेज करके पता कर लेते हैं। यह कहा जा रहा है कि सी0एम0ओ0 ने इसकी पुष्टि की है, शासन को इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। दोनों बातों में विरोधाभास है। हम इसकी आज ही जांच करा लेते हैं, अगर बात सही होगी तो हम निश्चित रूप से कार्यवाई करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

जांच हो जायेगी, माननीय अग्रवाल जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आज आपने कहा है, आज ही हम इसकी जांच करा लेते हैं, अगर वह सही है तो उसकी पुष्टि हो जायेगी, फिर उसके हिसाब से जो कार्यवाई होगी, करेंगे।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, सी0एम0ओ0 मथुरा ने तो पुष्टि की है।

श्री अध्यक्ष-

पूरन प्रकाश जी आप दो बार पूछ चुके हैं अब बैठिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिस संवेदनशीलता के साथ सरकार को इसको लेना चाहिए मुझे लगता है कि उसमें कहीं न कहीं कोई कमी है। मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने यह सवाल किया है उन्होंने अपनी निश्चित जानकारी के साथ और नाम के साथ अपनी जानकारी दी है। मान्यवर, यहां पर दो बातें हैं जिस समय आप सी0एम0ओ0 और डाक्टर्स के साथ मिलते हैं तो वह कहते हैं कि स्वाइन फ्लू है तो लेकिन हम लिखकर नहीं दे सकते हैं। मान्यवर, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात के लिए कार्यवाही करेगी कि वहां पर स्वाइन फ्लू पैदा क्यों हुआ ? जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि देश में और वैश्विक

स्तर पर यह बीमारी आयी है। उसकी कोई रोकथाम नहीं है। सरकार क्या यह निर्देश देती है कि अगर एच1, एन1 स्वाइन फ्लू पाया गया तो कार्यवाई करेंगे या सरकार इस बात के निर्देश देती है कि अगर एच1, एन1 स्वाइन फ्लू पाया गया और अगर उसको इलाज सही तरीके से नहीं किया गया तो कार्रवाई करेंगे ? मान्यवर, इन दोनों बातों में सारा अंतर छुपकर आता है। क्योंकि जो बातें कही गयी हैं वह नाम, स्थान के साथ कही गयी हैं यह बड़ी गंभीर बात है। जो सदस्य यहां पर अपनी जानकारी के आधार पर बात कहते हैं तो सदन यह मानता है कि यह बात सही है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने गलत जानकारी दी है क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आगे से उसकी रोकथाम के लिए टीकाकरण या जो भी आवश्यक कदम उठाने हों वह करेंगे ?

श्री शंखलाल मांझी-

माननीय अध्यक्ष जी, स्वाइन फ्लू का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है। केवल टेमीफ्लू एक दवा है वही दिया जाता है। इसके लक्षण पाये जाने और रोग की पुष्टि होने पर इसके रोकथाम की रणनीति के तहत मानव संसाधन का हम सुदृढ़ीकरण करते हैं। राज्य जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन हुआ है। स्वाइन फ्लू इन्फ्लूएंजा के लिए राज्य नोडल अधिकारी और जिला नोडल अधिकारी बनाये गये हैं। और इसके लिए चिकित्सालयों का चिन्हींकरण भी किया गया है जहां पर आई0सी0यू0 की व्यवस्था है। जहां पर इस तरह के लक्षणों के मरीजों के लिए व्यवस्थायें उपलब्ध करायी गयी हैं। जहां तक अभी आपने बताया कि इस पर जो गलत रिपोर्ट आयी है उसमें कोई कार्रवाई की जाएगी तो मैंने पहले ही कहा कि आज ही उसकी जांच करा ली जाएगी और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सी0एम0ओ0 ने पुष्टि किया है और शासन को पूरे प्रदेश के किसी सी0एम0ओ0 द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गयी है। अब अगर यह विरोधाभासी बातें हैं तो आज ही उसकी जांच कराकर पता कर लेते हैं। अगर इस तरह से विरोधाभासी बातें होंगी तो निश्चित तौर से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री श्यामदेव राय चौधरी के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष-

अब जब मंत्री जी ने कह दिया कि मैं इसकी जांच करा लूंगा। तो अब इसके बाद और क्या बचा है। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आगे हैं। अब आप बैठ जायें।

तारांकित प्रश्न

*1-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप एवं श्री उपेन्द्र तिवारी-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में विधायकों की संस्तुति पर विद्युत विहीन गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

*02-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के विद्युत विहीन गांवों में से प्रतिवर्ष 10 गांवों में विधायकों की संस्तुति पर विद्युतीकरण कराने की सरकार की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

जी नहीं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग सभी राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। योजना के द्वितीय चरण में 300 से अधिक आबादी वाले समस्त ग्रामों का मजरों सहित सघन विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण से संतृप्तीकरण किया जा रहा है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था कि क्या मा0 मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के विद्युत विहीन गांवों में से प्रति वर्ष 10 गांवों में विधायकों की संस्तुति पर विद्युतीकरण कराने की सरकार की योजना है ? मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि आपकी योजना क्या है ? मैंनें स्पष्ट पूछा था कि करायेंगे या नहीं करायेंगे ? नहीं करायेंगे तो क्यों ? मा0 मंत्री जी अभी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे गांव होंगे जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि जिस जिले से आप आते होंगे, उस जिले के सभी गांव संतृप्त होंगे, यह माना जा सकता है, लेकिन पूरे प्रदेश का यह हाल है, यह कदाचित कहना उचित नहीं है। तो मान्यवर, मैं एक बात यह पूछना चाहता हूं कि अगर आपको यह करना ही है, तो उस क्षेत्र से जो मा0 विधायक चुन कर आते हैं, उनके ऊपर उसका दबाव होता है, जनता उनसे उसकी मांग करती है, उनको पता होता है, कहां पर उसकी आवश्यकता है। तो मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या विधायकों के कहने के ऊपर प्रत्येक वर्ष 10 गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा ? अगर गांव बचेंगे ही नहीं तो, करने की आवश्यता ही नहीं होगी, बचे हैं तभी तो कह रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि कोई बचा नहीं है, बचा नहीं है तो कहेंगे नहीं। अगर किसी गांव में विद्युतीकरण हो चुका है और हम लिख कर देंगें कि इस गांव का विद्युतीकरण कर दिया जाय तो आप कहेंगे कि यह तो गलत प्रश्न है, इसमें बचा ही नहीं, अगर बचा हुआ है, तो क्या आप मा0 विधायकों की संस्तुति पर इसको करवायेंगे, एक प्रश्न है ? दूसरा प्रश्न है मान्यवर, आपने इसमें लिखा हुआ है कि 300 से कम आबादी वाले समस्त गांवों और मजरों सहित सघन विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है। अगर प्रस्तावित है, तो कब तक है और क्या उसकी योजना है? मान्यवर, यह दो बातें बता दें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, विधायकों के 10 गांव के लिए कोई योजना नहीं है, लेकिन 300 से अधिक आबादी वाले मजरों में, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है, तो इसमें 22 जिले लिये गये हैं। इन 22 जिलों के नाम अगर आप कहें तो मैं बता दूं और राजीव गांधी योजना जानते हो कि प्रदेश की योजना तो है नहीं, केन्द्रीय योजना है।

श्री सतीश महाना-

अगर आपकी कोई योजना हो, तो बता दें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, इसमें मैनपुरी, एटा, कन्नौज, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलन्दशहर, लखीमपुर, बाराबंकी, हरदोई, गोण्डा, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, उन्नाव, शाहजहांपुर और बहराइच यह 22 जिले हैं। तो यह 300 से अधिक आबादी वाले ग्रामों, मजरों में विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित गांव हैं । अब जैसे-जैसे धन की उपलब्धि होती जायेगी, वैसे-वैसे ही आगे बढ़ते जायेंगे और जो 500 से अधिक आबादी के गांव हैं, इनमें राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत हर जिले में 20 गांव से लेकर के 26 गांव तक राम मनोहर लोहिया गांव में विद्युतीकरण कराया जा रहा है। तो इस तरीके से धन की जैसी उपलब्धि होती जायेगी, वैसे ही चयनित कर लिये जायेंगे।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, लोहिया गांवों में जो काम हो रहा है, वह विभागीय बजटों के माध्यम से काम हो रहा है, चाहे वह जल निगम हो, चाहे बिजली विभाग हो, जो भी विभागीय बजट हैं, उसका प्रयोग हो रहा है। हम विधायक लोग भिखारियों की तरह कटोरा लेकर इधर-उधर घूमते फिरते हैं, क्योंकि जनता ने हमें चुना है। क्या हमारा अधिकार यह भी नहीं है कि हमारे सुझाव पर 5-10 गांव दे दिये जायं। क्या करें हम लोग ? पूर्व मुख्य मंत्री मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने सबके लिए बराबर बांटे थे, सड़क नल और बिजली के गांव। तो यह वर्तमान सरकार से सब लोगों को आशा है पूरे प्रदेश को कि यह सभी विधायक चुन कर आये हैं। हर विधायक के क्षेत्र में अपनी जनता है तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है और मा0 मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं। अब तो पूरी सरकार बैठी है इस वक्त। आप घोषणा कराइये। सड़क, बिजली के लिये गांव और नल इन तीन चीजों के लिये विधायक जगह जगह कटोरा ले करके भीख मांगता है। ये अच्छी बात नहीं है। ये घोषणा जरूर कराइये और ये हम लोगों के लिये भारी शर्म की बात है कि हम एक एक नल के लिये पूछते हैं कि हमें नल दे दीजिये। ये कोई बात हुई। भई, ये तो आपकी सरकार है और समान भाव से बंटना चाहिये, हर एक विधायक अपने क्षेत्र से चुन कर आया है। आप जरूर व्यवस्था दें।

(कई मा0 सदस्यों द्वारा एक साथ अनुपूरक प्रश्न करने का प्रयास करने से उत्पन्न शोर के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अरे, इतने सवाल हो जायेंगे तो कैसे उत्तर आयेगा ? मा0 नेतागण आप लोग बैठ जायेंगे, तब न मंत्री जी कुछ कहेंगे।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, खुशी के वातवरण में सदन चल रहा है। सब लोग, सब विधायक बड़े खुश हो रहे हैं। एक ऐसी बात की घोषणा आप करा दें जिससे सबको खुशी हो।

श्री अध्यक्ष-

अब यह घोषणा कराना।

(नेता अपना दल, मा0 अनुप्रिया पटेल द्वारा अनुपूरक प्रश्न करने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

देखिये मंत्री जी कुछ कहने जा रहे हैं। मा0 अनुप्रिया पटेल जी, मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, सुन लो।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, वैसे तो सभी जिले स्वीकृति के लिये दे दिये गये हैं लेकिन अभी 22 जिले ले लिये गये हैं और मैंने कहा कि जैसे जैसे धन की उपलब्धता होती जायेगी तो सभी गांव हर वर्ष लेते जायेंगे।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

(मा0 सदस्य श्री पूरन प्रकाश द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 पूरन जी, मा0 मंत्री जी को बैठ जाने दीजिये, तब पूछिये, तरीका यह है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, पिछले पांच सालों से यह परम्परा टूट गयी है। 5 सालों से ही तो परम्परा टूटी है।

(कतिपय मा0 सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, आप लोग मा0 मंत्री जी को बोल लेने दीजिये न। आप लोग मंत्री जी को सुनो तो।

(कतिपय मा0 सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

मा0 सदस्य, रायबरेली, बैठ जाइये। अनुप्रिया जी, जब तक मंत्री जी को सुनोगी नहीं, तब तक कैसे चलेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, वैसे तो मैंने बहुत सी परम्पराओं को तोड़ा है। मैंने बहुत सी परम्पराओं को तोड़ा है। पिछली सरकार में विभाग के एक एक मंत्री के पास विभाग की 72-72 गाड़ियां थीं। उस परम्परा को भी मैंने तोड़ दिया। बिजली विभाग के एक मंत्री के पास, आप पता लगा लेना 72 गाड़ियां थीं। वित्तीय साधनों की कमी थी इसलिये भी वित्तीय स्थिति जर्जर हुयी है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, और परम्पराओं के बारे में क्या ख्याल है ?

(सदन में जोर की हंसी)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, ये सही है और विधायकों की जिज्ञासा है कि नेता जी की सरकार में 5-5 गांव दिये गये हैं, 5-5 गांव मिले हैं। मान्यवर, तो मुख्य मंत्री जी से बात करेंगे, फिर आप भी चाहते हैं।

(सदन में तीव्र शोर के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अरे, शोर मत करिये। मंत्री जी को बोलने दीजिये न। मा0 हुकुम सिंह, अब आप लोग बैठ जायें, आपके नेता बोल रहे हैं न।

(मा0 सदस्य पूरन प्रकाश द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

पूरन जी, बैठ जाओ न।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न बिजली विभाग का था लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं मंत्री जी के प्रति कि उन्होंने परिवहन विभाग, सारे विभाग उन्होंने ले लिये सिवाय बिजली विभाग के मान्यवर, मैं पूछना यह चाह रहा हूं कि आपने कहा कि 300 से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों का मजरों सहित सघन विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है। मैं 300 से ऊपर वालों की बात कर रहा हूं, जो आपने ऊपर कहा और मान्यवर, 11 महीने इस सरकार को बने हुए हो गए, जैसे ही सरकार बनी थी और हम यहां आए थे, क्योंकि नये-नये विधान सभा क्षेत्र बने हैं अबकी बार, पुराने सबके बदल गए हैं। हमारा भी बदला है। 59 गांव ऐसे हैं, मान्यवर, 300 से अधिक आबादी वाले हैं और 1000 से अधिक आबादी वाले भी हैं, जो अभी तक विद्युतीकरण से वंचित हैं और मैं 11 महीने से बराबर उन 59 गांवों की सूची विद्युत परिषद् से लेकर के शक्ति भवन से लेकर के एक्जिक्यूटिव इंजीनियर तक को दे रहा हूं, आज तक तो कार्यवाही हुई नहीं, आश्वासन वे भी दे रहे हैं, आश्वासन आप भी दे रहे हैं। अगर 11 महीने में अब तक इस कार्यक्रम को नहीं लिया गया है, मान्यवर, तो समस्त सदस्यगण जो बैठे हैं, कैसे विश्वास करें। आपने 22 जिले बता दिए। 22 जिलों की सूची भी दे दी, लेकिन यह 300 से नीचे आबादी वाली जो बात आपने कही है, मैं तो 300 से ऊपर वालों की बात कह रहा हूं। मेरी सूचना को सही मानते हुए कि जनपद शामली में मेरे द्वारा 59 गांव के उन ब्लॉक में, 59 गांव एक ब्लॉक में वंचित हैं मान्यवर, 65 साल की आजादी के बाद में जो गांव अभी तक वंचित हैं, आखिर उनकी खता क्या है ? क्या आप मेरी सूचना को सही मानते हुए इसकी जांच करायेंगे और तुरंत उनके विद्युतीकरण की व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

जवाब आ जाने दीजिए।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, वैसे तो 300 गांवों के जो मैंने बताए कि 22 जिले लिए गए हैं। पहले चरण में 22 जिले ले लिए गए हैं और जैसे-जैसे वित्तीय संसाधन जुटाते जायेंगे, उससे 500 गांव से ऊपर 20 गांव से लेकर 26 गांव हर जिले से डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास ग्राम में लिए जा रहे हैं और जैसे-जैसे वित्तीय संसाधन बढ़ते जाएंगे और गांव बढ़ाते जाएंगे। इस तरीके से पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में और चौथे चरण में ऐसे ही लेते जाएंगे और समग्र गांव इसी तरीके से जैसे ही वित्तीय संसाधन जुटते जाएंगे, वैसे ही हर गांव में विद्युतीकरण होता जाएगा।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जैसा अपने जवाब में कहा है कि समस्त राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण हो गया है। हमने अपने दो साल की विधायक निधि से वर्ष 2011-12 और वर्ष 2012-13 में लगभग 1-1 करोड़, डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपया दिया है। इस साल भी 1 करोड़ रुपया दिया

है लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही से, उन राजस्व ग्रामों का भी विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है। हमने अपनी सूची में दिया है, यह निश्चित जानकारी के हिसाब से, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, जो हमने विधायक क्षेत्रीय विकास निधि से पैसा दिया है, राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण करने के लिए और अन्य मजरों का विद्युतीकरण करने के लिए, क्या ऐसे निर्देश मा0 मंत्री जी देंगे कि उन गांवों का तत्काल विद्युतीकरण कर दिया जाए ? ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, जैसे ही विधायक निधि का पैसा मिलता जाएगा, शीघ्र उस पर कार्यवाही होती जाएगी।

(कई विपक्षी मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग रुकिए मैं खुद ही पूछता हूं। मा0 मंत्री जी, आपका जो नियम है।

श्री शिव पाल सिंह यादव-

मान्यवर, सवा करोड़ तो ठीक है, इन्होंने डेढ़ करोड़ कहां से दे दिया।

श्री अध्यक्ष-

वह पिछला बचा रहा होगा। पूर्वांचल का बचा होगा, मध्यांचल का बचा होगा।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

यह तो ठीक है। मा0 सदस्य ने जो कहा कि उनकी निधि के द्वारा जो विद्युतीकरण होना है वह जल्दी हो जाए। तो वह हो जाएगा ।

(कई मा0 सदस्यों के खड़े होकर बोलने के प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रमोद तिवारी जी, आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री प्रदीप माथुर-

अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी पहले खड़े थे, तो मैंने बैठा दिया था।

(कई मा0 सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

आपके सब नेताओं ने इतना पूछ लिया है अब आप ही बाकी रह गए हैं क्या ? सारे प्रश्न का जवाब आ गया है, अब आगे बढ़ने दीजिए।

श्री रामवीर उपाध्याय-

श्रीमन् मैं सदन में मौजूद हूँ, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने अभी यह कहा कि मैं 72 गाड़ियों में चलता था, मैं बताना चाहता हूँ क्या माननीय मंत्री जी इन गाड़ियों का नम्बर मुझे बता देंगें ? मान्यवर, मैं एक गाड़ी में चलता था। कोई व्यक्ति सौ गाड़ियों में कैसे चल सकता है यह आप खुद बेहतर सोच सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

अब आपका स्पष्टीकरण आ गया। आप बैंठ जायें।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, पहले हम पूर्व मुख्य मंत्री के पास जो गाड़ियां उपलब्ध थीं, उनके नम्बरों की सूची भिजवा देंगे, उसके बाद आपकी भी भिजवा देंगे। मेजों की थपथपाहट।

श्री अध्यक्ष-

माननीय रामवीर उपाध्याय जी आप कृपया बैठ जायें, उन्होंने कहा है कि वह सूची आपको दे देंगें। आपने स्पष्टीकरण दे दिया है कि आप एक ही गाड़ी में चलते थे।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, जो भी राजस्व ग्राम हैं, उन ग्रामों का विस्तारीकरण हो गया है प्रदेश में। उस विस्तारीकरण के इलाकों का आप विद्युतीकरण करायेंगे ?

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक निर्माण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि राजस्व ग्रामों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मान्यवर, विस्तारीकरण दो तरह से होता है। एक संख्या में वृद्धि हो गयी हो और दूसरे में उनके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गयी हो। जब क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो वह मजरे बनते हैं। मजरों के बारे में माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट बता दिया है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, गांव बढ़ गये हैं आबादी के हिसाब से और क्षेत्रफल बढ़ गया है विद्युत विभाग उन बढ़े हुए इलाकों में विद्युतीकरण नहीं करता है, तो जो गांवों का एरिया बढ़ गया है क्या उनका विद्युतीकरण करायेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, किसी भी एक राजस्व गांव के क्षेत्रफल में एक इंच की भी वृद्धि नहीं हुई है। वह समान हैं नक्शे पर, उसका विद्युतीकरण नहीं हुआ है वह एक अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी वह समझ नहीं रहे हैं वह शहर में रहते हैं गांवों में मकान बढ़ जाते हैं उसको वह कह रहे हैं, उसमें मंत्री जी ने कहा है कि धन उपलब्ध हो जायेगा, तो करा देंगें।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

जो जिले सूची में नहीं हैं उनका क्या होगा हमारा जिला तो सूची में ही नहीं है ?

श्री अध्यक्ष-

वह सूची में कह रहे हैं कि जो धन आयेगा आता जायेगा, आप बैठिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने लिखित उत्तर दिया और अनुपूरक के जवाब में जो उत्तर दिया वह दोनों अपने आप में कंट्राडिक्ट्री उत्तर हैं। एक तरफ आपने कहा कि प्रदेश में कोई राजस्व

गांव ऐसा नहीं जिसके ऊपर विद्युतीकरण न हुआ हो दूसरी तरफ से बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनके बारे में आपने कहा कि संतृप्त करायेंगे, दोनो बाते हैं। लिखित उत्तर में कह रहे हैं कि है नहीं और अपने अनुपूरक प्रश्न के जवाब में उत्तर दे रहे हैं कि जो हैं उसको करवायेंगे। बहुत सारे उत्तर में यह लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं कि जो माननीय विधायकगण, आपने कहा कि...

श्री अध्यक्ष-

सीधे कहिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अंत भला तो सब भला। प्रश्नों के अन्तर्गत घुमाफिराकर जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी की सरकार में 5 गांव देते थे और परम्पराएं तोड़ी थी तो क्या जो वह 5 गांव देते थे उस परम्परा को जोड़कर 5 गांव प्रत्येक विधायक की संस्तुति पर करायेंगे एक प्रश्न, और दूसरी बात कानपुर जिले को भी जोड़ेंगे।

(श्री बंशी सिंह पहाड़िया के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

पहाड़िया जी बैठिये, आपको जब तक मैं नहीं कहता हूं आप क्यों खड़े हो गये ? आप बैठ जायें, कुछ लिखा नहीं जायेगा। माथुर साहब यह सब क्या है, आप बैठिये ? माननीय मंत्री जी खड़े हैं जवाब देने के लिए तो आपको सुनकर तब पूछना चाहिए। बैठिये वह आप ही के काम की बात हो रही है, बैठिये।

माननीय मंत्री जी, इनका कहना यह है कि क्या पुरानी परम्परा तोड़कर 5 गांव विधायकों को संस्तुति पर दे सकते हैं ? इसी का जवाब दे दीजिए बात खत्म।

श्री शिव पाल सिंह यादव-

मान्यवर, संसाधनों के ऊपर है जैसे जैसे वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते जायेंगे, हम विचार कर लेंगे।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब कोई प्रश्न नहीं, आप कहां बालू से पानी निकालने जा रहे हैं, बैठिये।

(तारांकित प्रश्न संख्या-4 पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक परम्परा रही है कि जब अध्यक्ष जी किसी का नाम बुला लें, यह परम्परा रही है।

श्री अध्यक्ष-

तो आप तो बैठे थे तब से जब सबको बुलवा रहे थे। अब आप उठ गये यह क्या तरीका है ? हम जब बुलाये थे तब बोलना चाहिए था।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूं परम्परा इधर से टूट जाय उधर से नहीं टूटनी चाहिए । आपने मेरा नाम लिया था इसलिए मैं परम्परा की याद दिला रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष-

आप बार बार कह रहे हैं लेकिन मैंने कह दिया माननीय मुख्य मंत्री जी से आप लोग कक्ष में जाकर बात कर लीजिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वरिष्ठतम मंत्री शिवपाल जी से एक अनुरोध करना चाहता हूं स्वयं स्वीकार किया आपने कि आपने बीड़ा उठाया है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बीड़ा उठाया है कि गलत परम्पराएं जो पड़ गयी हैं उसे आप खत्म करेंगे और जो परम्परा आपकी अच्छी टूट गयी है उसे आप पुनर्जीवित करेंगे। मेरा सिर्फ़ इतना कहना है कि आपकी जो अच्छी परम्परा टूटी उसी का नतीजा तो है कि यह उधर बैठ गये जाकर के अब आप क्या चाहते हैं कि वह जो पुरानी परम्पराएं अच्छी परम्पराएं थीं जिनकी वजह से आप बैठे थे उनको तोड़कर आप वही करना चाह रहे हैं जो वह कर रहे हैं, वहां जाना चाहते हैं। मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपने कहा कि हम बातचीत करके कर लेंगे तो बातचीत तो होती होगी ऐसा मत कहिये सदन में कि बात चीत नहीं होती हैं हम लोग आपसे एक अनुरोध करते हैं कि आप बात कर लें और हम लोगों की तरफ से एक वकील के तौर पर माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध कर लें कि 5 गांव कोई बड़ी चीज नहीं होती। 5 गांव महाभारत के समय से चल रहा है, 5 गांव महत्वपूर्ण गांव होता है। अब मान्यवर, 5 गांव नहीं माने थे तो कुरूक्षेत्र हो गया था । तो कुरूक्षेत्र न होने पाये, इसके लिये मैं आपसे विनम्रतापूर्वक एक आग्रह करता हूं बल्कि दो विकल्प भी आपको देता हूं या तो मान्यवर, 5 गांव प्रत्येक विधायक के हिसाब से कर दें या दूसरा यह कर दें कि 5 गांव के विद्युतीकरण में जितना लगता हो, एक करोड़ 75 लाख कर दें, 2 करोड़ कर दें तो तब तो उसमें हम विधायक लोग करा लें अन्यथा मैं आपसे विनम्रतापूर्वक एक आग्रह करूंगा कि 5 गांव तो कुछ नहीं होते, शिवपाल जी आपके लिये तो इत्ते बराबर है और किसी के लिये तो हो सकता है लेकिन आपके लिये तो इत्ता भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

50 मिनट हो गये इन दो सवालों में ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, 50 मिनट हो गये, लेकिन यह 5 नहीं हो पा रहा है। मैं यही चाहता हूं कि कृपापूर्वक इस पर विचार कर लें कि बजट का जब अन्तिम भाषण देने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी अन्तिम रूप से खड़े हों तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे आग्रह करूंगा कि अपने पूज्य पिता

नेताजी की परम्परा का पालन करते हुये उस दिन आप घोषणा कर दें कि हैण्डपंप भी देंगे और उसी दिन आप यह भी घोषणा कर दें कि आप गांव की भी घोषणा कर देंगे तो आप बिल्कुल माननीय मुख्य मंत्री पुराने हमारे जो नेता थे, उनके बराबर हो जायेंगे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस समय आप यह घोषणा करें उस समय आप दॉये-बॉये मत देखियेगा, तब आप जरूर घोषणा कर देंगे।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में 22 जनपदों के बारे में माननीय मंत्री जी ने सदन को जानकारी दी है, मेरी जानकारी है कि एक साल पहले इसके पैसे मिले थे तो क्या इसके टेण्डर हो गये यदि नहीं हुये तो कब तक टेण्डर करके यह विद्युतीकरण शुरू करा देंगे ?

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, शहरी क्षेत्र में जो सोसाइटी के क्षेत्र हैं जहां आज भी बत्ती नहीं है, बांस और बल्लियों के सहारे बत्ती चल रही है ।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये ।

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि जो पैसे मिले हैं, उसका टेण्डर कराकर जल्दी काम करा देंगे ।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, टेण्डर चल रहा है, शीघ्र कार्यवाही चल रही है।

*3-श्री मनीष असीजा-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी, दवाइयों की उपलब्धता आदि के सम्बन्ध में जानकारी

*04-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 चिकित्सालयों में आवश्यक संख्या में चिकित्सकों एवं दवाइयों के अभाव तथा आवश्यक जांच बाहर से कराने के कारण मरीजों को कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या चिकित्सकों की कमी को दूर करने, सभी दवाइयां अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने तथा जांच आदि की सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंखलाल मांझी-

प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति की जा चुकी है। समस्त पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 में पर्याप्त मात्रा में औषधियां उपलब्ध हैं। अस्पतालों में उपलब्ध उपकरणों से संभव जांच अस्पताल में कराने की व्यवस्था है।

जी हां।

प्रदेश में लोक सेवा आयोग से चयनित 1406 चिकित्सकों के सापेक्ष 1313 नव चयनित चिकित्सकों की नियुक्ति/तैनाती की जा चुकी है। चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद को 2868 पदों पर चयन हेतु अधियाचन प्रेषित किया जा चुका है। दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अस्पतालों में उपलब्ध उपकरणों से संभव जांच अस्पताल में कराने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अनुपूरक करूं, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं। जब से यह सदन चल रहा है और जब से इस सरकार का गठन हुआ है, विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में चाहे वह नल हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे अन्य विषय हों, एक नाम का उदाहरण बार-बार दिया जाता है, माननीय सदस्यों के द्वारा कि आदरणीय नेताजी। तो आदरणीय नेताजी के पदचिन्हों पर सरकार को चलना चाहिये, हालांकि गांधी जी के पदचिन्हों पर तो कोई पार्टी नहीं चल रही है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आदरणीय नेताजी का नाम बार-बार आता है, मुझे भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला है, निश्चित रूप से जो लोग आज उनको याद कर रहे हैं, उनकी अच्छाइयों के लिये कर रहे हैं। तो इस सरकार को आप कृपया निर्देश दें कि उनके पदचिन्हों पर, उनके मार्गदर्शन पर लोग चलें। यह सरकार चले। माननीय मुख्य मंत्री जी सुन नहीं रहे हैं, मैं यह कह रहा था माननीय मुख्य मंत्री जी कि जब से इस सरकार का गठन हुआ है, चाहे नल का विषय हो, बिजली का विषय हो, सड़क का विषय हो, या कोई भी विषय हो उसमें एक नाम माननीय सदस्यों द्वारा लिया जाता है कि आदरणीय नेता जी ऐसा करते थे, ऐसा करना चाहिए इस सरकार को भी तो मैं माननीय अध्यक्ष जी से यह निवेदन कर रहा था कि गांधी जी के पद्चिन्हों पर तो कोई चल नहीं रहा है तो आदरणीय नेता जी के पद्चिह्नों पर, उनके मार्ग दर्शन में यह सरकार चले, ऐसी कोई व्यवस्था अपनाई जाए ताकि समय की बचत हो।

श्री अध्यक्ष-

अब तो सवाल कीजिए।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मैंने आपसे अनुमति ले ली थी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपने अपनी भावना सदन में व्यक्त कर दी, यह अच्छी बात है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है कि समस्त पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 में पर्याप्त मात्रा में औषधियां उपलब्ध हैं, डाक्टरों की भी भर्ती कर ली गई है आदि, आदि। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सर्वविदित है कि जो जिला अस्पताल हैं, वहां सारी सुविधाएं रहने के बाद भी जनता को, गरीब मरीज को वह सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। जो

सुदूर अंचल में पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 हैं, उनके सम्बन्ध में यह समाचार भी आए दिन प्रकाशित होता रहता है कि वहां डॉक्टर के अभाव में जो वार्ड ब्वाय हैं या सफाई कर्मचारी हैं, वह इंजेक्शन लगाते हुए पाये गये, स्टिंग आपरेशन हुआ और ऐसा समाचार-पत्रों में आया तो मैं यह बताना चाहता हूं कि उन लोगों का जो दर्द है, जो ग्रामीण जनता है, गरीब जनता है, असहाय जनता है, उनकी पीड़ा को दृष्टिगत रखते हुए इस रटे-रटाये जवाब से हट करके क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि जो जवाब दिया गया है उसके अनुसार ग्रामीण अंचल की गरीब पीड़ित जनता को डॉक्टर भी उपलब्ध हों, दवाइयां भी उपलब्ध हों, उनका आपरेशन भी हो, उनको जो इंजेक्शन लगने हों उनकी भी उपलब्धता हो, क्या ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री शंखलाल मांझी-

मान्यवर, सरकार के गठन के बाद तीसरे दिन ही प्रदेश के समस्त अधिकारियों को बुला करके यह निर्देश दे दिया गया था। पिछली सरकार में जिस तरह से डाक्टर का बैठना कोई निश्चित नहीं था, डाक्टर अगर बैठता था तो एम0आर0 से घण्टों कमीशन तय किया करता था और जो करोड़ों रुपए की दवाइयों का पेपर पर खरीदकर पेपर पर वितरण किया गया था, उसका असर यह हुआ था कि पूरे प्रदेश में गरीब जब अस्पताल में जाता था तो उसे बाहर की दवाइयां पर्ची पर लिख दी जाती थीं, इन पर पूरी तरह से पाबन्दी लगा दी गई है। उस पर निर्णय लिया गया और पूरे प्रदेश के डॉक्टर्स को यह निर्देशित कर दिया गया कि किसी भी दशा में बाहर की दवाइयां नहीं लिखी जाएंगी, अगर कोई डाक्टर बाहर की दवाइयां लिखते हुए पाया जायेगा, उसकी शिकायत मिलेगी तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जायेगी, निलम्बन तक की कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दे दिया गया है। मान्यवर, उसका असर हुआ है हम मानते हैं कि गाड़ी पूरी तरह से पटरी से उतर गई थी, उसको पटरी पर लाने के लिए यह पहला स्टेप लिया गया और उसका असर भी आया है। दवाइयां अस्पताल पर मुकम्मल उपलब्ध रहें, मुफ्त दवा सम्पूर्ण दवा उपलब्ध रहे, इसलिए जिस तरह से पहले दवाइयों की खरीद डी0जी0 ऑफिस से ही होती थी, उसके पीछे कारण क्या था इसको हम नहीं कहना चाहते हैं लेकिन मान्यवर, उसको विखण्डित करते हुए अब पूरे प्रदेश के सी0एम0ओ0 को अधिकृत किया गया कि जो भी आवश्यक दवाइयां हैं उन्हें वह अपने स्तर से ही परचेज करेंगे। पैसे के लिए कोई कमी नहीं है पूरे प्रदेश में। जितनी भी दवाओं की आवश्यकता है सी0एम0ओ0 अपने स्तर से जो भी दवा चाहे खरीद सकता है इसकी उसे पूरी छूट दी गई है, इसीलिए अस्पताल में दवाइयां मिलनी भी शुरू हुई हैं। पूरे प्रदेश में आज से साल भर पहले जो मरीजों की संख्या थी आज उसमें जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। उसका कारण यही है कि अस्पताल पर दवाईयां मिलनी शुरू हुई हैं, डाक्टर बैठने लगा है आठ बजे से लेकर दो बजे तक प्रत्येक दशा में, और इमरजेंसी व्यवस्थाओं के लिए भी एक डाक्टर को बैठने के लिए निर्देशित किया गया है। अगर कहीं से भी यह शिकायत मिलती है, मैं खुद भी इस चीज की मॉनीटरिंग कर रहा हूं और जहां भी शिकायत मिलती है उस पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित भी कर रहा हूं। अब इसके बाद अभी मा0 सदस्य ने कहा कि यह व्यवस्थायें नहीं है। हम आपसे कहना चाहेंगे पर्टीकुलर किसी अस्पताल की अगर कोई सूचना मिलेगी, कहीं से भी आप यह सूचना देंगे कि फलां अस्पताल पर डाक्टर नहीं बैठ रहा है या फलां अस्पताल पर डाक्टर ने बाहर की दवायें लिखा है तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी और त्वरित कार्यवाही होगी। यह व्यवस्थायें हो रही

हैं। एक दूसरी बात आपने कहा कि यह व्यवस्थायें नहीं हुई। माननीय सदस्य जी, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं और आप जानते हैं कि दवाओं के मामले में हमने बता दिया, हमने यह भी बता दिया कि क्या हम निर्णय लिये हैं और सरकार के निर्णय का असर दिखने लगा है। हमारा स्वास्थ्य विभाग जनता से, गरीब से, कमजोर वर्ग से सीधा सरोकार रखने वाला है और इसी के तहत मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर समाजवादी स्वास्थ्य सेवा 108 शुरू किया गया है उसको केवल मैं नहीं, आप भी महसूस कर रहे हैं कि इसका लाभ जनता को मिल रहा है। अब जहां तक रह गयी कि जांच में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, 2005-2006 से जब अस्पतालों में कोई मशीनें, जो पुरानी थी उनके रख रखाव में, उसकी नई खरीददारी नहीं की गयी तो उसका असर स्वाभाविक है।

सुश्री अनुप्रिया पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो बातें यहां रखी हैं उसके आधार पर निश्चित रूप से हम कन्वींन्स हैं कि सरकार ने कोई न कोई ठोस योजना जरूरी बनायी है। लेकिन हकीकत के धरातल पर जाकर देखा जाए तो मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र रोहनियां के बारे में बताना चाहूंगी कि यहां पर जगतदेवपुर और मिश्रपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जहां पर डाक्टरों को आवासीय सुविधा भी दी गयी है लेकिन उसके बाद भी माननीय मंत्री जी वहां महीनों से डाक्टर नहीं हैं। रात को तो दूर की बात है, दिन में भी डाक्टर नहीं रहते हैं। यहां तक रैबीज का प्राइमरी इंजेक्शन जो वहां पर रहना चाहिए, वह भी वहां पर नहीं रहता है। डाक्टर ही नहीं हैं तो इंजेक्शन की क्या बात की जाए, लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो अगर ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र आपकी जानकारी में, आपकी संज्ञान में लाये जा रहे हैं, जो मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बता रही हूं जगतदेवपुर और मिश्रपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इसके सम्बन्ध में क्या योजना है ? कैसे इस अव्यवस्था को दूर किया जायेगा और यह कब तक दूर हो जायेगा ?

श्री शंख लाल मांझी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जैसा पहले कहा है कि जहां भी इस तरह की सूचना मिलेगी उनके खिलाफ कार्यवाही भी करूंगा और वंहां पर व्यवस्था भी कराऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप लिख करके दे दीजिए, मैं उस पर त्वरित कार्रवाई कराऊंगा।

(प्रतिपक्ष के कई मा0 सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछने का आग्रह करने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण कृपया शांत रहें। डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी।

सुश्री अनुप्रिया पटेल-

मान्यवर, हमें आश्वासन चाहिए कि कब तक हो जायेगा। दोबारा हमें न कहना पड़े।

श्री अध्यक्ष-

उनका जो जवाब आया है, वह सुनिये।

सुश्री अनुप्रिया पटेल-

अध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही में आ गया है, अब यह कब तक हो जायेगा, महीना, दो महीना, पन्द्रह दिन, बीस दिन या कब तक ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जांच कराऊंगा, दण्ड दूंगा तो अब इससे ज्यादा क्या कहें।

सुश्री अनुप्रिया पटेल-

हमें क्षेत्र में जवाब देना पड़ता है, हम लोगों से क्या कहें कि हमने यह समस्या उठायी है तो उसका निदान कब तक हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने निदान बता दिया है।

श्री शंख लाल मांझी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कह दिया कि लिखित में भिजवा दें, मैं त्वरित कार्रवाई करा दूंगा।

सुश्री अनुप्रिया पटेल-

हाउस में मैंने कह दिया, सदन की कार्यवाही में आ गया अब लिखित क्या देना है ?

श्री अध्यक्ष-

जब कार्रवाई नहीं होगी तब बताईयेगा। वह बता रहे हैं मैं कार्रवाई करूंगा। जब कार्रवाई नहीं करेंगे तो नियमावली को पढ़ लेना, आश्वासन बना है तो वह आश्वासन समिति को चला जायेगा। कार्यवाई होगी परेशान मत हो।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

एक-एक करके प्रश्न पूछें। उमेश जी बैठें, मैंने डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल को बुला लिया है यह डाक्टर हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी पहले सदन को व्यवस्थित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण जब एक सदस्य पूछ रहे हों तो आपको बैठना चाहिए। बुधौलिया जी आप तो पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं। आप जानते हैं कि कैसे सवाल पूछा जाता है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं सिफ्र दो छोटे-छोटे प्रश्न माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सारे उपकरण सब जगह हैं। माननीय मंत्री जी स्वयं गोरखपुर जिला चिकित्सालय गए थे। मैं परसों गया था तो पता चला कि इन्होंने दौरा किया। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि लिखकर दे दीजिए। यह स्वयं अपनी आंखों से देखकर आए हैं वहां की रीजनल डायग्नोसिस लैबोरेटरी का आटो एनालाइजर है वह पिछले तीन महीने से खराब है खर्चा कुल मिलाकर 60 हजार का माननीय मंत्री जी वायदा करके आए थे कि ठीक करा दूंगा आज तक ठीक नहीं हुआ वहां के ओ0टी0 में जो हड्डी वाले डाक्टर आपरेशन करते हैं वह देखकर करते हैं नेलिंग और प्लेटिंग के लिए उस मशीन को सी0आर0 मशीन कहते हैं तीन महीने से खराब है माननीय मंत्री जी जानते हैं वायदा करके आए थे करा दूंगा नहीं हुआ वहां का हृदय रोग अस्पताल 9 बेड का है एक भी बेड पर मानीटर नहीं है बिना मानीटर के हृदय रोग के मरीज भर्ती होते हैं माननीय मंत्री जी देखकर आए थे कहकर आए थे कि करा दूंगा कुछ नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष-

सवाल पूछिए आप तो सूचनाएं मांग रहे हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं सवाल यह पूछ रहा हूं कि जो माननीय मंत्री जी अपनी आंख से गोरखपुर जिला चिकित्सालय में देखकर आए हैं उन कमियों को कब तक दूर करा देंगे यह हम लोगों को सदन में बता दें ? एक सवाल और है ।

श्री शंखलाल माझी-

माननीय अध्यक्ष जी अभी हमारे विद्वान सदस्य डाक्टर साहब गोरखपुर जिला चिकित्सालय के बारे में जो सवाल कर रहे थे मैं वहां गया था और हमने देखा भी था आटो एनालाइजर भी वहां का ठीक से काम नहीं कर रहा है सी0आर0 नहीं है और मानीटर की बात है मैंने उसकी सूचना मंगा लिया था और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसके लिए पैसा भी रिलीज हो चुका है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार डाक्टरों की कमी को देखते हुए जो यहां प्रदेश में डाक्टर कार्यरत हैं उनकी रिटायरमेंट की अवधि पांच साल बढ़ाने का काम करेगी ? दूसरे प्रदेशों में यह किया गया है क्योंकि नई भर्ती तो हो नहीं रही है ?

श्री अध्यक्ष-

आपका सवाल हो गया।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, जवाब तो दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें तो तभी तो मंत्री जी खड़े होंगे।

मंत्री जी सदस्य का प्रश्न है कि डाक्टरों के अभाव को देखते हुए यहां जो रिटायरमेंट की उम्र है उसे बढ़ाने पर विचार करेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

इसमें मेरा भी प्रश्न जोड़ लिया जाए। अगर रिटायरमेंट का एज न बढ़ाया जा सके तो जैसे मेडिकल कालेज में रिटायर्ड चिकित्सकों को पुनर्नियुक्ति दी गई है जिला अस्पतालों में भी जो डाक्टर सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको पुनर्नियुक्ति दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष-

यह नीतिगत प्रश्न है।

श्री शंखलाल माझी-

माननीय अध्यक्ष जी यह नीतिगत प्रश्न है और फिलहाल अभी इस पर कोई विचार नहीं है। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि डाक्टर की भारी कमी है।

श्री अध्यक्ष-

बहुत से माननीय सदस्य यहां डाक्टर हैं वह भी समय निकालकर अस्पतालों में मरीज देखा करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मैं रोज मरीजों को देखता हूं चार घण्टे।

श्री अध्यक्ष-

आप गोरखपुर जिला चिकित्सालय में बैठा करें। आप अभी तो अपने क्लीनिक में बैठते हैं। चलिये बैठिये। अगला प्रश्न लीजिये। वह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सारा समय इसी में चला जायेगा। उमेश पाण्डेय जी क्या पूछना है, पूछें।

श्री उमेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठिये ना, आप लोग इस तरह का आचरण करेंगे। आप मर्यादा भी तो कुछ समझिये। देखिये बैठ जायं। देखिये माननीय सदस्य आप इस तरह का आचरण करेंगे तो यह आचरण बहुत ठीक नहीं है। मैं खड़ा हूं तो आप बैठिये। एक एक करके इतने सवाल पूछ लिये। मुझे आश्चर्य है कि इससे और महत्वपूर्ण सवाल आगे लगे हैं उस पर आप लोगों का ध्यान केन्द्रित नहीं है और इसी पर सवाल कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण सवाल है वह उन्होंने बता दिया। चलिये, एक आखिरी सवाल उमेश पाण्डेय जी कर लें।

श्री उमेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं। अभी अभी आपके सामने सदन के समक्ष माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सारे हास्पिटलों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर, पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 पर सारी दवाएं उपलब्ध हैं। जबकि हमारे क्षेत्र मधुबन विधान सभा जनपद मऊ में फतेहपुर मनगांव बड़रावं और सुग्गी चौरी। सुग्गी चौरी का तो यह हाल है कि जो करोड़ों रुपये से...

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न कर रहे हैं या सूचना दे रहे हैं। आप सूचना दे रहे हैं तो लिखकर मंत्री जी को दे दीजिये। वह जांच करा लेंगें। इसमें सवाल कुछ नहीं हैं।

श्री उमेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, सवाल है, बनता है। करोड़ों की लागत से बना हुआ हास्पिटल है, जिसमें ताला लटक रहा हैं, कोई डाक्टर नहीं बैठता है, तो ऐसे में वहां पर दवा उपलब्ध होने की बात कैसे कर सकते हैं ? वहां पर दवा उपलब्ध नहीं हैं गांव का गरीब मजदूर वहां जाता है तो दवा नहीं मिलती है। कुत्ते काटने का वैक्सीन नहीं मिलती है। यह सत्य से परे सूचना देकर सदन को गुमराह करने का काम माननीय मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरा सवाल है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, जब बजट आयेगा तब बोल लीजियेगा। एक आखिरी सवाल दादा आप पूछ लीजिये।

(माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री प्रदीप चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत गांव दूधला में 6-7 बीघा जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम पड़ी है। आन रिकार्ड उस पर स्वास्थ्य केन्द्र बना है, तो हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने उस तरीके से व्यवस्था बनाई है कि वहां पर स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है और स्वास्थ्य विभाग के नाम जमीन पड़ी हैं ।

श्री अध्यक्ष-

यह सवाल से संबंधित नहीं है। पहले यह जान लीजिये कि कैसे सवाल पूछा जाता है फिर सवाल करिये। चलिये बैठिये यह सवाल नहीं बनता। आप बैठ जाय। दादा आप आखिरी सवाल कर लें।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वाराणसी में पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय है, जहां पर डायलिसिस मशीन नहीं है। यह प्रश्न मैंने पिछले सत्र में भी उठाया था तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि आप मुझे लिखकर दे दीजिये, मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो यह आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। दूसरी बात यह है कि शिव प्रसाद गुप्त जो मण्डलीय राजकीय चिकित्सालय है वाराणसी में, वहां हृदय कक्ष बना हुआ है, बोर्ड लगे हैं लेकिन कोई उपकरण यानि मॉनीटर इत्यादि, पैरा-मेडिकल स्टाफ वगैराह नहीं है। तो दोनों सवालों के उत्तर मैं चाहता हूं कि क्या इसकी व्यवस्था आप निकट भविष्य में करा देंगें।

(माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठ जायं। उत्तर तो आ जाने दीजिये। उत्तर सुन लीजिये, तब पूछियेगा।

श्री शंख लाल मांझी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विद्वान सदस्य ने जो पूर्वांचल वाराणसी में जिन अस्पतालों का नाम लिया है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि बनारस का जिला अस्पताल और बनारस के अस्पतालों में केवल बनारस के ही नहीं बल्कि अगल बगल मंडल के मरीजों की भी भारी संख्या आती है। वहां पर माननीय मंत्री जी भी कई दौरा कर चुके हैं। वहां पर जहां पर मशीनों की उपलब्धता की बात है, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में जहां भी इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए एक नीतिगत निर्णय हो चुका है और ऐसे अस्पतालों पर जल्दी इन व्यवस्थाओं को दिया जाएगा और व्यवस्थायें सुचारू रूप से चल सकें इसका प्रयास किया जाएगा।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग एक साथ कैसे प्रश्न पूछेंगे ? आप लोग हल्ला किए जा रहे हैं।

डा0 अरूण कुमार-

मान्यवर, हमारे यहां जिला अस्पताल बरेली में डायलेसिस मशीन खरीदे हुए लगभग 6 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक वहां इतनी भी डायलेसिस नहीं हुई है जितनी प्राइवेट अस्पतालों में 6 दिन में हो जाती है। वहां जब पूछते हैं तो कहते हैं कि डायलेसिस का सौल्यूशन नहीं है और मंत्री जी कह रहे हैं कि दवायें मौजूद हैं मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर वहां सौल्यूशन नहीं है तो डायलेसिस क्यों नहीं हो रही हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी आप वहां सौल्यूशन की व्यवस्था करा दें।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

दादा आप क्या चाहते हैं अभी कुछ बाकी है ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

मा0 मंत्री जी ने कहा कि पूर्वांचल के मरीज आते हैं मुझे बड़ी खुशी हुई लेकिन उत्तर में कहा गया है कि नीतिगत निर्णय लिया जाएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मेरा प्रश्न है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

लिखकर दे दीजिएगा मंत्री जी को।

*05-श्री सुरेश राणा-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाये का ब्याज सहित भुगतान कराये जाने की मांग

*06-श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री दलवीर सिंह, श्री वीरपाल राठी एवं श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाये का ब्याज सहित भुगतान सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विजय बहादुर पाल)-

प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कराने हेतु कटिबद्ध है। गन्ना किसानों के बकाये का ब्याज सहित भुगतान की कार्यवाही प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत की जाती है।

गन्ना किसानों के बकाये का यथाशीघ्र भुगतान कराने का प्रयास किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मेरा प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी प्रश्न संख्या-6 पर बोलें।

अब आप लोग बैठ जाएं। सब लोग एक साथ खड़े होकर बोल रहे हैं एक-एक करके बोलें, तो जवाब आ जाएगा। खन्ना जी आप बतायें ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, सहकारी चीनी मिल निजी चीनी मिल पर कितना-कितना रुपया बकाया है और कब तक भुगतान करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अरे खन्ना जी अब बैठ तो जाइए। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। यह क्या तरीका हुआ जब तक मंत्री जी जवाब देंगे तब तक आप खड़े रहेंगे। मंत्री जी बतायें ? (शोर)

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोल रहे थे।)

श्री विजय बहादुर पाल-

मा0 सदस्य या तो प्रश्नों की बौछार करते रहिए या उत्तर देने का मौका दीजिए। राज्य सरकार की सहकारी चीनी मिलों में वर्ष 2011-12 तक का सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है। वर्ष 2012-13 में 65 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मेरा प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठें। प्रश्नों का समय समाप्त।

श्री हुकुम सिंह-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री दलबीर सिंह, श्री सुरेश राणा तथा कुछ अन्य सदस्य प्रश्न पूछने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

शेरू भैय्या, अगर आपको उत्तर गलत लगता है तो नियमों में प्राविधान है, आप हमारे कार्यालय को लिखकर दे सकते हैं। अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है, आप लोग बैठिए।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराये जाने की मांग

*07-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह फरवरी से अप्रैल, 2013 में प्रदेश में कक्षा-10 एवं कक्षा-12 की सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, आई0सी0एस0ई0 बोर्ड एवं यू0पी0 बोर्ड की परीक्षायें प्रारम्भ होने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त बोर्ड परीक्षाओं के एक माह पूर्व से परीक्षा के समापन तक प्रदेश में रात्रि में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान में प्रदेश की औसत मांग लगभग 10500-12000 मेगावाट के मध्य है, जिसके सापेक्ष विभिन्न स्रोतों से विद्युत की उपलब्धता 8500-9000 मेगावाट है। विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी के दृष्टिगत निर्बाध विद्युत आपूर्ति में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

*08-श्री हुकुम सिंह-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने की कार्य योजना

*09-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुयी जनसंख्या को रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी को एक समय-सीमा के अन्तर्गत नियंत्रित करने तथा प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की तर्ज पर प्रदेश की अपनी जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में प्रख्यापित की गई है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2016 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 के स्तर तक लाना है। जनसंख्या नीति के अन्तर्गत समस्त सम्बन्धित विभागों यथा शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आदि को मिलकर कार्य करना है। वर्ष 2005 से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत भी कुल प्रजनन दर को 2012 तक 2.8 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नवत् गतिविधियां संचालित की जा रही हैं :-

<u>अन्तराल विधियां-</u>

- सेवा केन्द्रों पर खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
- सेवा केन्द्रों पर निरोध का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
- सेवा केन्द्रों पर निःशुल्क आई0यू0डी0 380 ए का निवेशन किया जा रहा है, जो 10 वर्ष तक प्रभावी होती है।

- हाल ही में प्रदेश के 45 चयनित जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के द्वार तक गर्भ निरोधक सामग्री का वितरण ''आशा'' कार्यकत्रियों द्वारा किये जाने की योजना प्रारम्भ की गयी है।

<u>स्थायी विधियां</u>

- जिला महिला/पुरुष चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय व मेडिकल कालेजों में नियमित रूप से तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियत दिवस पर निःशुल्क महिला एवं पुरुष नसबन्दी की सेवायें प्रदान की जाती हैं।

<u>अन्य गतिविधियां-</u>

- प्रत्येक पुरुष नसबन्दी स्वीकारकर्ता को रु0 1100/-की धनराशि तथा प्रत्येक महिला नसबन्दी स्वीकारकर्ता को रु0 600/-की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है।
- परिवार कल्याण कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की सहभागिता हेतु जनपदों को अलग से धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है।
- नसबन्दी कार्यक्रम में पुरुषों की सहभागिता बढ़ाये जाने हेतु जनपदों में एन0एस0वी0 शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
- सुदूर क्षेत्रों में नसबन्दी शिविरों का आयोजन किया जाता है।
- प्रसव उपरान्त महिलाओं को नसबन्दी करवाने अथवा अन्य परिवार नियोजन विधियों के सम्बन्ध में सलाह प्रदान करने हेतु प्रदेश के प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर संविदा पर फैमिली वेलफेयर काउन्सलर की तैनाती की गयी है।
- नसबन्दी (महिला एवं पुरुष) स्वीकारकर्ताओं हेतु नसबन्दी उपरान्त मृत्यु, असफल नसबन्दी व नसबन्दी उपरान्त जटिलताओं हेतु परिवार नियोजन बीमा योजना के अन्तर्गत आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड बीमा कम्पनी के माध्यम से क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

*10-श्री दलवीर सिंह-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में जिलेवार एम्बुलेन्स तथा उसके संचालन हेतु वाहन चालक, डीजल-पेट्रोल आदि की जानकारी

*11-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में कितनी-कितनी चिकित्सा एम्बुलेन्स किन-किन जिलों को उपलब्ध करायी गयी हैं ? क्या सरकार ने इनके निरन्तर सफलतापूर्वक संचालन हेतु वाहन चालक, डीजल-पेट्रोल, मरम्मत आदि की पर्याप्त व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जिलेवार एम्बुलेन्स की सूची संलग्न† है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की पूरनपुर एवं बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिलों में तकनीकी परिणामों विशेषकर कम चीनी परता प्राप्त होने के सन्दर्भ में जांच की जानकारी

*12-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों में गन्ने में चीनी का परता 6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक है एवं निजी क्षेत्रों के चीनी मिलों में गन्ने में चीनी का परता 10.50 प्रतिशत है ? यदि हां, तो निजी चीनी मिलों एवं सहकारी चीनी मिलों में गन्ने में चीनी के परता में इतना भारी अन्तर होने के कारणों की जांच कराई जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पूरनपुर किसान सहकारी चीनी मिल एवं बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल में वर्ष 2011-12 में गन्ने में चीनी का परता कितना रहा है, यदि परता 8 प्रतिशत से कम रहा है तो इसके लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

वर्तमान पेराई सत्र, 2012-13 में दिनांक 15-2-2013 तक सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों का औसत परता 8.12 तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों का औसत परता 8.97 प्रतिशत रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2011-12 में पूरनपुर किसान सहकारी चीनी मिल में गन्ने में 6.90 प्रतिशत चीनी परता और बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल में 7.82 प्रतिशत चीनी परता प्राप्त हुआ है। इन चीनी मिलों में चीनी परता प्रतिशत कम प्राप्त होने के कारणों की जांच हेतु सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन के आदेशानुसार पेराई सत्र के दौरान जिला गन्ना अधिकारी, पीलीभीत, उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0, लखनऊ के तकनीकी अधिकारियों तथा निजी क्षेत्र की एल0एच0 शुगर फैक्ट्री पीलीभीत के प्रयोगशाला प्रभारी को संयुक्त रूप से दिनांक 03 एवं 04 फरवरी, 2012 को क्रमशः पूरनपुर एवं बीसलपुर सहकारी चीनी मिलों के तकनीकी परिणामों, विशेषकर कम चीनी परता प्राप्त किये जाने के संदर्भ में मिल का संयुक्त भ्रमण कर विभिन्न महत्वपूर्ण विश्लेषण कराये जाने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त संयुक्त टीम द्वारा कम चीनी परता प्रतिशत प्राप्त होने के संदर्भ में यह निष्कर्ष दिया गया कि पूरनपुर सहकारी चीनी मिल में 25 से 30 प्रतिशत एवं बीसलपुर सहकारी चीनी मिल में 15 से 20 प्रतिशत गन्ना रोग ग्रस्त होने के कारण गन्ने में जूस की कमी है, जूस की ब्रिक्स कम होने के कारण परिणामी रूप से पोल इन केन कम हुआ। रोग आपतन के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-222-224 पर।)

अतारांकित प्रश्न

जनपद शामली में जिला चिकित्सालय के निर्माण कराये जाने की जानकारी

01-श्री सुरेश राणा-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नव-सृजित जनपदों में आमजन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तर के अस्पताल बनाने की कोई योजना सरकार द्वारा बनायी जा रही है ? यदि हां, तो नव-सृजित जनपद शामली में समस्त सुविधा युक्त जिला अस्पताल कब तक और कहां बनाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जनपद शामली में जिला चिकित्सालय के निर्माण हेतु जिलाधिकारी से 06 एकड़ निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत भूमि उपलब्ध होने पर जिला चिकित्सालय के निर्माण की कार्यवाही विभाग द्वारा प्रारम्भ की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली की माइनर भैंसवाल बधेह-कुतुबगढ़ गोगवान की सफाई करवाये जाने की मांग

02-श्री सुरेश राणा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था हेतु राजवाहों और माइनरों की सफाई की सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र थानाभवन, जनपद शामली की माइनर भैंसवाल बधेह-कुतुबगढ़ गोगवान की सफाई की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। प्रश्नगत कार्य आवश्यकतानुसार कराये जाते हैं।

प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 तथा जिलाधिकारी, शामली को निर्देशित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शामली के मुजफ्फरनगर थानाभवन मार्ग से नागल तक के मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने की मांग

03-श्री सुरेश राणा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रमुख जिला मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद शामली के मुजफ्फरनगर थानाभवन मार्ग से नागल तक 07 कि0मी0 मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। प्रदेश में नवीनीकरण का कार्य चक्रानुसार प्रमुख जिला मार्गों पर 4 वर्ष पर किये जाने की नीति है तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य यातायात घनत्व एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

प्रश्नगत मार्ग अन्य जिला मार्गों की श्रेणी का मार्ग है, जिस पर वर्तमान में यातायात घनत्व, चौड़ीकरण हेतु निर्धारित मानक से कम है। इसके अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शामली की पूर्वी यमुना नहर की कुआखेड़ा से लेकर एलम तक क्षतिग्रस्त पटरी की मरम्मत कराये जाने की जानकारी

04-श्री सुरेश राणा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बहने वाली बड़ी नहरों एवं राजवाहों की पटरियों को पक्का कराने एवं पक्की पटरियों की मरम्मत कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद शामली की पूर्वी यमुना नहर की कुआखेड़ा से लेकर एलम तक क्षतिग्रस्त पटरी की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं, प्रश्नगत कार्य आवश्यकतानुसार कराये जाते हैं।

प्रश्नगत मरम्मत/अनुरक्षण हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अर्रा-बिनगवां कालोनी में सड़क, जल निकासी, सीवर आदि कार्य कराये जाने की मांग

05-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित अर्रा एवं बिनगवां कालोनी में प्राधिकरण द्वारा सड़क, जल निकासी, सीवर एवं अन्य अवस्थापना सुविधाएं उक्त क्षेत्र में कब तक उपलब्ध करायी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अर्रा-बिनगवां कालोनी वर्ष 1992 में आंशिक रूप से विकसित की गई थी। लगभग 20 वर्ष व्यतीत होने के बाद विकसित की गई अवस्थापना सुविधायें वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिन्हें चरणबद्ध रूप से धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जाना है। प्रथम चरण में अति आवश्यक कार्यों जैसे-सीवर लाइन, मेनहोल एवं चैम्बर आदि की सफाई तथा क्षतिग्रस्त मेनहोल एवं चैम्बर की मरम्मत का कार्य, खुले मेनहोलों/चैम्बरों पर कवर लगाये जाने का कार्य तथा जल निकासी के कार्य में आंशिक रूप से कुछ डीप ड्रेन का निर्माण कार्य को अवस्थापना निधि में उपलब्ध धनराशि से निविदा एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर में मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेण्टर में कार्यरत चिकित्सकों का विवरण

06-श्री सतीश महाना-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के रामादेवी स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेन्टर में चिकित्सक के कितने पद

स्वीकृत हैं तथा उसके सापेक्ष कितने चिकित्सक कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में रिक्त पदों पर चिकित्सकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

मान्यवर, कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेन्टर, कानपुर नगर में चिकित्सक के कुल 28 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों के सापेक्ष सभी चिकित्सक कार्यरत हैं।

कोई पद रिक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महानगरों में विद्युत वितरण व्यवस्था निजी क्षेत्रों को देने पर विचार

07-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत वितरण व्यवस्था सरकार ने कौन-कौन से महानगरों में निजी क्षेत्रों को दी है तथा किन महानगरों में निजी क्षेत्र में देने पर विचार कर रही है ? क्या सरकार उसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

आगरा शहर की विद्युत वितरण व्यवस्था निजी क्षेत्र को दी गयी है।

कानपुर (केस्को) की विद्युत वितरण व्यवस्था निजी क्षेत्र को दिया जाना विचाराधीन है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की सीमा के अन्दर आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल रोड पर एम्बुलेन्स, वाहन हटाने हेतु क्रेन आदि की व्यवस्था

08-श्री मनीष असीजा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सीमा के अन्दर आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर ''टोल टैक्स'' की वसूली की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क सुरक्षा के उपाय/साधन यथा एम्बुलेन्स, वाहन हटाने के साधन कभी उपलब्ध नहीं होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अपने स्तर पर इन राजमार्ग प्राधिकरणों से राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा नीति के अनुमन्य मानकों को लागू कराने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं, सामान्यतः टोल रोड पर एम्बुलेन्स, वाहन हटाने हेतु क्रेन तथा रूट पेट्रोल वाहन की व्यवस्था रहती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय की ग्राम सभा हसनपुर व परमानन्दपुर (बिन्दपुरवां) में गड़ई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने की मांग

09-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा-हसनपुर व परमानन्दपुर के बीच और ग्राम पंचायत-गौरी (बिन्दपुरवां) में गड़ई नदी पर पुल न हेने से 15-20 गांवों के लोगों को नदी के इस पार या उस पार जाने के लिए लगभग 15 कि0मी0 घूमकर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार आवागमन को सुगम बनाने हेतु उक्त स्थान पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद चन्दौली ग्राम सभा हसनपुर महामाया मन्दिर के पास नहर पर पुलिया के निर्माण की मांग

10-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली की मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा-हसनपुर महामाया मन्दिर के पास नहर पर पुलिया निर्माण व ग्राम सभा-महदेउल गोपालपुर में नाला पर पुलिया न होने से लगभग दस से पन्द्रह गांवों के लोगों को आवागमन में भारी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलियों का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हसनपुर महामाया मन्दिर जोगवा बुधवार रजवाहा के कि0मी0 13.7 के निकट स्थित है। इस मन्दिर के अपस्ट्रीम में रजवाहा के कि0मी0 13.390 तथा डाउन स्ट्रीम में कि0मी0 14.240 पर पुल निर्मित है, जहां से यहां के ग्रामवासियों का आवागमन होता है। अतः सिंचाई विभाग के मानकों के अन्तर्गत महामाया मन्दिर हेतु राजवाहा के कि0मी0 13.7 पर सिंचाई विभाग में लागू मानकों के अन्तर्गत पुल का निर्माण अनुमन्य नहीं है।

ग्राम सभा महदेउल गोपालपुर के पास चिनहट ड्रेन जो गरई नदी में मिलती है, के कि0मी0 1.1 पर पूर्व निर्मित पुलिया के क्षतिग्रस्त स्लैब की मरम्मत किये जाने हेतु प्रमुख अभियन्ता सिंचाई को निर्देशित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा मुगलसराय में हिन्दवारी से सेंगर के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

11-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली की मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा हिन्दवारी से सेंगर होते हुए जिवनाथपुर तक मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जनपद-चन्दौली के विधान सभा मुगलसराय में हिन्दवारी से सेंगर मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुए है, परन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में विचार किया जाना संभव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

12-डा0 धर्मपाल सिंह-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-67 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मांट व हाथरस ब्रान्च की नहरों में सिंचाई हेतु पानी की क्षमता बढ़ाये जाने की मांग

13-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार मांट व हाथरस ब्रान्च की नहरों में सिंचाई हेतु पानी की क्षमता को बढ़ाने के लिए नहरों को पक्का (लाइनिंग) करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

मांट व हाथरस शाखा की नहरों में सिंचाई हेतु पानी की क्षमता बढ़ाने के लिए नहरों को पक्का करने (लाइनिंग) का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी के फिरोजपुर जैती में वनों के किनारे किसानों को भूमि पर खेती का अधिकार दिये जाने की मांग

14-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के फिरोजपुर जैती में वनों के किनारे 30-40 वर्षों से कृषि कार्य कर रहे किसानों को उस भूमि पर खेती का अधिकार देने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वनों के किनारे अवस्थित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य यथा कृषि कार्य प्रतिबंधित है।

जनपद खीरी के ब्लाक मोहम्मदी में विद्युत के फुंके ट्रांसफार्मरों को बदलने व अधिक क्षमता के ट्रान्सफार्मरों को बदलवाने जानकारी

15-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में विद्युत के फुके ट्रान्सफार्मरों के बदलने तथा बड़ी क्षमता वाले ट्रान्सफार्मर लगाने की क्या कोई कार्य योजना है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ब्लाक-मोहम्मदी व ब्लाक पसगवां में कुल कितने ट्रान्सफार्मर एक वर्ष से फुकें पड़े हैं जो नहीं बदले गये हैं एवं इसके लिए दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में विद्युत के फुंके ट्रांसफार्मरों को नगरीय क्षेत्रों में 24 घंटे के अन्दर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तीन दिन के अन्दर बदले जाने की नीति/कार्य योजना है तथा परिवर्तक अतिभारित होने पर आवश्यकतानुसार बड़ी क्षमता के परिवर्तक बिजनेस प्लान के अन्तर्गत लगाये जाते हैं।

ब्लाक मोहम्मदी व ब्लाक पसगवां क्षेत्र के अन्तर्गत विगत एक वर्ष में कुल 261 नग परिवर्तक क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से 253 नग परिवर्तक बदले जा चुके है वर्तमान में 8 नग क्षतिग्रस्त परिवर्तक बदले जाने अवशेष है जिनमें से 7 नग परिवर्तक तेल चोरी से दिनांक 15-02-2013 को क्षतिग्रस्त हुए है और इनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने में विलम्ब के कारण इन्हें अभी तक नहीं बदला जा सका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की पुष्टि हो गयी है तथा अगले तीन दिन में तेल चोरी से क्षतिग्रस्त हुए परिवर्तकों को बदल दिया जायेगा। एक परिवर्तक दिनांक 23-02-2013 को क्षतिग्रस्त हुआ है। अतः किसी विभागीय कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम पिपरिया कप्तान व बनिका गांव के सभी मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने की जानकारी

16-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में ग्राम-पिपरिया कप्तान व बनिका गांव के (पुरवे) मजरों, आंशिक रूप से विद्युतीकृत ग्रामों तथा अन्य ग्रामों का विद्युतीकरण कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के ग्राम-पिपरिया कप्तान व बनिका गांव के ऐसे सभी मजरों, का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में कराये जाने की योजना में सम्मिलित है, जिसकी जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 300 अथवा उससे अधिक है। जनपद लखीमपुर की डी0पी0आर0 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है तथा निविदा प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार से धन प्राप्त होने पर इन ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में ब्लाक मोहम्मदी के कतिपय ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराये जाने की मांग

17-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-खीरी में ब्लाक-मोहम्मदी के ग्राम-लाखीखेड़ा, पड़सर व सहजनिया मजरा मुकुन्दपुर आदि को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण न होने से क्षेत्रीय ग्रामवासियों को आवागमन में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जिला खीरी में ब्लाक-मोहम्मदी के ग्राम-लाखीखेड़ा, पड़सर में सहजनिया पूर्व से लेपित मार्गों से जुड़े है। मजरा मुकुन्दपुर मार्ग नाबार्ड द्वारा आर0आई0डी0एफ0-18 योजनान्तर्गत अनुमोदित कर दिया गया है, जिसकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी व पसगवां में निजी नलकूप के कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण का प्रकरण

18-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-मोहम्मदी व पसगवां में पिछले एक वर्ष से कितने लोगों ने 200 रुपये जमा कर निजी नलकूप के कनेक्शन हेतु आवेदन किया है ? क्या सभी आवेदन-पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी व पसगवां में पिछले एक वर्ष में 280 लोगों ने 200 रुपये जमा करके निजी नलकूप के विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया है।

जी नहीं।

उपरोक्त में से 132 आवंटन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है। अवशेष 148 आवेदन पत्र लम्बित हैं। वर्ष 2012-13 में सामान्य योजना के अन्तर्गत 90 नलकूपों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

19-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी रोड वायु विहार से सुचेता सम्पक्र मार्ग तथा जगनेर रोड नौ मील मोड़ से लखलौआ, सूतैड़ी एवं गड़सानी तक की सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

फतेहपुर सीकरी रोड वायु विहार से सुचेता सम्पक्र मार्ग का स्वामित्व लोक विभाग का नहीं है। जगनेर रोड नौमील मोड़ से खलौआ, सुतैड़ी एवं गढ़सानी तक मार्ग का आबादी भाग क्षतिग्रस्त है।

उक्त मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

20-श्री उमेश पाण्डेय-

[2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-71 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मऊ के ब्लाक बड़रांव के ग्राम भटमीला का विद्युतीकरण कराये जाने की जानकारी

21-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मऊ के ब्लाक बड़रांव के अन्तर्गत ग्राम-भटमीला का विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद-मऊ के ब्लाक बड़रांव के अन्तर्गत ग्राम-भटमीला का विद्युतीकरण का कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित है। भारत सरकार (ग्रामीण विद्युतीकरण) से धन की उपलब्धता होने पर ग्राम-भटमीला का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के गोला बाजार से रौनापार (आजमगढ़) के बीच घाघरा नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

22-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील गोला अन्तर्गत उपनगर गोला बाजार से रौनापार (आजमगढ़) के बीच घाघरा नदी पर आवागमन को सुगम बनाने हेतु पीपे के पुल की मांग ग्रामीणों द्वारा वर्षों से की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पीपे के पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के जिला अस्पताल तथा महिला अस्पताल में पैरा मेडिकल स्टाफ तथा चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की जानकारी

23-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिला अस्पताल तथा जिला महिला अस्पताल में डाक्टर तथा पैरा-मेडिकल स्टाफ के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जिला (पुरुष) चिकित्सालय शाहजहांपुर में चिकित्साधिकारियों के 23 पद एवं पैरामेडिकल स्टाफ के 14 पद तथा जिला महिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में चिकित्साधिकारियों के 06 पद तथा पैरामेडिकल स्टाफ के 03 पद रिक्त हैं।

लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्साधिकारियों की तैनाती जनपदों में उनकी उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर की जाती है तथा पैरामेडिकल स्टाफ के चयन की प्रक्रिया क्रमित है। चयनोपरान्त रिक्त पदों के सापेक्ष तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहरों में रिंग रोड बनवाये जाने की मांग

24-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के शहरों में आबादी तथा वाहनों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हर बड़े शहर में आवागमन को सहज करने के लिए एक-एक रिंग रोड की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रदेश के हर बड़े शहर में रिंग रोड की स्वीकृति प्रदान किये जाने की कोई योजना नहीं है।

प्रदेश के रौजा थर्मल पावर यूनिट का विस्तारीकरण कराये जाने की मांग

25-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ताप विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण तथा क्षमता विस्तार की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि रौजा थर्मल पावर यूनिट के विस्तारीकरण के प्लान को मंजूरी देने में क्या कठिनाई है ? क्या प्रदेश में विद्युत कमी को देखते हुए विस्तारीकरण को मंजूरी दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

रोजा थर्मल पावर यूनिट का एक बार विस्तारीकरण होने के पश्चात् वहां पर 300-300 मे0वा0 क्षमता की 2 इकाइयां लगायी गयी हैं, जो कि वाणिज्यिक उत्पादन पर है। मे0 रोजा पावर द्वारा पुनः विस्तार हेतु 3x660 मे0वा0 क्षमता की इकाइयां लगाने हेतु इच्छा व्यक्त की गयी थी तथा यह अनुरोध किया गया था उन्हें चेण्दीपाडा कोल ब्लाक से 8.5 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला उपलब्ध कराया जाये, किन्तु चेण्दीपाडा कोल ब्लाक का कोयला ओबरा-सी जवाहरपुर एवं दोपाहा परियोजनाओं के लिये पहले से ही आवंटित है। अतः यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित विस्तारीकरण के लिये चेण्दीपाडा कोल ब्लाक से कोयला उपलब्ध नहीं होगा। अतः नया समझौता ज्ञापन सम्भव नहीं होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में ददरौल ब्लाक के शाहबाजनगर से कपेड़कटका ग्राम के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत व पुलिया का निर्माण कराये जाने की मांग

26-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के ददरौल ब्लाक के शाहबाजनगर से कपेड़कटका ग्राम को जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है तथा इसी मार्ग से ग्राम घुसगवॉ जाने वाले 300 मीटर लम्बे कच्चे रास्ते पर तालाब के पास एक पुलिया बननी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत/निर्माण के साथ-साथ पुलिया का भी निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उक्त की मरम्मत/निर्माण एवं पुलिया का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद हमीरपुर के ब्लाक कुरारा के ग्राम भौली पटिया में यमुना नदी से हो रही कटान रोके जाने का प्रकरण

27-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एवं विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर के कुरारा में ग्राम-मदौना के बड़ी मनकी ग्राम भौली पटिया में यमुना नदी से लगातार हो रही कटान से ग्रामवासियों को खतरा उत्पन्न हो गया है एवं उपजाऊ भूमि बरबाद हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार हो रही कटान को रोकने हेतु पिचिंग निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जनपद-हमीरपुर के कुरारा ब्लाक में यमुना नदी के किनारे स्थित ग्राम भौली, पटिया में यमुना नदी से कटान हो रही है। इस कटान को रोकने हेतु कार्य योजना आवश्यकतानुसार एवं तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर परियोजना स्वीकृत की जायेगी।

योजना स्वीकृत होने पर ही कार्य कराया जाना प्रस्तावित होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को मुफ्त बिजली दिये जाने की मांग

28-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सरकार द्वारा मुफ्त बिजली दिये जाने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में किसी भी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली देने की कोई नीति नहीं है। यद्यपि 01 कि0वा0 भार के विद्युत उपभोक्ता (लाइफ लाइन उपभोक्ता) जिनका मासिक उपभोग 150 यूनिट तक है, के लिए दरें रु0 1.90 प्रति यूनिट है, जो अन्य उपभोक्ताओं के लिये निर्धारित सामान्य दर रु0 3.45 प्रति यूनिट से काफी कम है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं हेतु भी दरें रु0 125/ संयोजन या रु0 1/यूनिट है, जो काफी कम है। यह भी अवगत कराना है कि विद्युत दरों का निर्धारण उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है।

जनपद हमीरपुर की ग्राम सभा मेरापुर भिलावा को यमुना नदी के कटान से बचाये जाने की मांग

29-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में यमुना पुल से सटे हुए ग्राम सभा मेरापुर भिलावा में यमुना नदी से कटान काफी अर्से से हो रही है ? यदि हां, तो उक्त हो रही कटान से गांव को बचाने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जनपद हमीरपुर में यमुना पुल से सटे हुए ग्राम सभा मेरापुर भिलावा में यमुना नदी से कटान हो रही है। इस कटान को रोकने तथा नदी किनारे की बस्ती को बचाने हेतु कार्य योजना आवश्यकतानुसार एवं तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर परियोजना स्वीकृत की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर से महोबा के बीच (राष्ट्रीय राजमार्ग-86) के निर्माण व मरम्मत कराये जाने की जानकारी

30-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर में यमुना पुल से महोबा तक एन0एच0-86 मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हमीरपुर से महोबा के बीच (राष्ट्रीय राजमार्ग-86) के निर्माण का कार्य भारत सरकार की स्वीकृति के पश्चात् रियायतग्राही द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है। निर्माण कार्य के साथ-साथ मरम्मत का भी कार्य आवश्यकतानुसार कराया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर में यमुना व बेतवा नदी की बाढ़ के कटान से बचाव की जानकारी

31-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में यमुना व बेतवा नदी की बाढ़ की कटान से बचाव हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

जनपद हमीरपुर में यमुना व बेतवा नदी की बाढ़ के कटान से सुरक्षा हेतु हमीरपुर नगर में दोनों नदियों पर तटबंध पूर्व से ही निर्मित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की बन्द चीनी मिलों को पुनः चलाये जाने की मांग

32-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछली सरकार ने कतिपय चालू हालत की चीनी मिलों को बन्द करा दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें पुनः चलाने पर विचार करेगी ? क्या सरकार इसी श्रेणी की पुवायॉ चीनी मिल शाहजहांपुर को किसानों के हित में पुनः चालू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां, रामकोला, देवरिया, भटनी, बैतालपुर, शाहगंज तथा लक्ष्मीगंज चीनी मिलें निजी क्षेत्र को विक्रीत की जा चुकी है। बुढ़वल, पिपराईच तथा 03 सहायक कम्पनियों छाता, घाटमपुर एवं रायबरेली को चलाये जाने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ द्वारा संचालित चीनी मिलें यथा-औराई, धुरियापार, सठियांव, मझोला एवं पुवायां को उनकी क्षमता के अनुरूप गन्ना उपलब्ध न होने के कारण संचालित न किये जाने का निर्णय लिया गया। इन चीनी मिलों को वर्तमान में चलाये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

सम्प्रति कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकीय स्टाफ के रिक्त पदों को भरे जाने की जानकारी

33-श्री दलवीर सिंह-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकीय स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जी हां।

चिकित्साधिकारियों के रिक्त 2868 पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को दिनांक 11-01-2013 को भेजा जा चुका है।

पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु शासकीय अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में छेरत से कासिमपुर पावर हाउस तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

34-श्री दलवीर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में छेरत से कासिमपुर पावर हाउस तक मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उक्त मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के किसानों द्वारा निजी नलकूप के बिल का अग्रिम धनराशि जमा करने पर छूट दिये जाने की मांग

35-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों द्वारा निजी नलकूप के बिल की एक वर्ष की अग्रिम बिल धनराशि जमा करने पर विभाग द्वारा छूट दिये जाने का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अग्रिम बिल धनराशि जमा करने पर छूट देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में सोमना मोड़ से खैर तक के मार्ग का पुनः निर्माण व मरम्मत कराये जाने की मांग

36-श्री दलवीर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में सोमना मोड़ से खैर तक मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनः निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उक्त मार्ग का पुनः निर्माण/मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर नौतार से माघी भगवानपुर बन्धे के बीच नये साइफन का निर्माण कराये जाने की मांग

37-श्री विजय कुमार दूबे-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नौतार से माघी भगवानपुर बन्धे के बीच नये साइफन के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा महीनों पूर्व सर्वे के बाद भी कार्य शुरू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार जन सामान्य की आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त साइफन का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्वे उपरान्त नये साइफन का निर्माण तकनीकी रूप से साध्य नहीं पाया गया।

जनपद कुशीनगर में दामोदरी से ग्राम सभा कठिनाइयां तक कच्चे मार्ग पर पिच निर्माण कराये जाने की जानकारी

38-श्री विजय कुमार दूबे-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कठिनाइयां ग्राम सभा से दामोदरी तक 3 कि0मी0 के कच्चे प्रमुख मार्ग जो हजारों ग्रामीणों के आवागमन का प्रमुख मार्ग है तथा दर्जनों गांवों को जोड़ने का प्रमुख मार्ग है, पर नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कच्चे प्रमुख मार्ग पर पिच निर्माण जनहित में करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

दामोदरी से ग्राम सभा कठिनाइयां तक मार्ग की स्वीकृति/निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा विकास खण्ड नेबुआ के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की जानकारी

39-श्री विजय कुमार दूबे-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बनवारी छपरा से गुल्हरिया रेगूलेटर का लगभग 03 कि0मी0 क्षतिग्रस्त खड़न्जा नहर का पटरी मार्ग जो खड्डा विकास खण्ड एवं नेबुआ-नौ0 विकास खण्ड को जोड़ने का प्रमुख मार्ग है, क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रमुख क्षतिग्रस्त खड़न्जा मार्ग पर पिच निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग नाबार्ड द्वारा आर0आई0डी0एफ0-18 योजनान्तर्गत अनुमोदित कर दिया गया है, जिसकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर में डोमन पट्टी से पानमती स्थान होते हुए तिनबरदहा खैरी ग्राम सभा तक के कच्चे मार्ग पर पिच स्तर तक निर्माण कराये जाने की जानकारी

40-श्री विजय कुमार दूबे-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत डोमन पट्टी से पानमती, स्थान होते हुए तिनबरदहा से खैरी ग्राम सभा तक के लगभग 4 कि0मी0 कच्चा मार्ग जो दर्जनों ग्राम के ग्रामीणों के आवागमन का प्रमुख मार्ग है, कच्चा एवं क्षतिग्रस्त है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? क्या सरकार उक्त मार्ग पर पिच स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जनपद कुशीनगर में डोमन पट्टी से पानमती स्थान होते हुए तिनबरदहा से खैरी ग्राम सभा तक मार्ग खड्डा विधान सभा में स्थित है। उक्त मार्ग के निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रस्ताव, पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत आयुक्त, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर के पत्र दिनांक 4-2-2013 के माध्यम से शासन में दिनांक 12-2-2013 को प्राप्त हुआ है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य की स्वीकृति पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में बेहटा हाजीपुर विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने की मांग

41-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने विद्युत उपकेन्द्र हैं तथा उनकी क्षमता क्या है ? क्या सरकार पूर्व में प्रस्तावित बेहटा हाजीपुर विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र में 33/11 के0वी0 के कुल 11 विद्युत उपकेन्द्र हैं तथा उनकी कुल क्षमता 145 एम0वी0ए0 है :-

क्र0सं0	उपकेन्द्र का नाम	क्षमता	कुल क्षमता (एम0वी0ए0)
1	लोनी नं0-1	3x5+10	25
2	लोनी नं0-2	10+5	15
3	ट्रोनिका सिटी	5+5	10
4	रूप नगर	5+5	10
5	सी-10 ट्रोनिका सिटी	5	5
6	डी0एल0एफ0	5+5	10
7	पावी	2x10	20
8	चिरौडी	10+5	15
9	निस्तौली	10+5	15
10	सिकरानी	2x5	10
11	इन्द्रप्रस्थ	1x10	10

जी हां।

उपकेन्द्र हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में महापुरुषों की याद में निर्मित पार्कों, स्मारकों एवं उद्यानों में प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की जानकारी

42-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में महापुरुषों की याद में बने पार्कों, स्मारकों एवं उद्यानों में लगे अधिकांश प्रकाश बिन्दु रात में न जलने से मार्गों पर अंधेरा छाया रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन सभी प्रकाश बिन्दुओं का अनुरक्षण कराते हुए उन्हें ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

लखनऊ में महापुरुषों की याद में निर्मित पार्कों, स्मारकों एवं उद्यानों में लगे प्रकाश बिन्दु रात में निरन्तर प्रकाशित होते हैं, अतः मार्गों पर अंधेरा नहीं रहता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2007 से वर्ष 2012 के मध्य बनाये गये नये अस्पतालों में चिकित्सकों व स्टाफ के तैनाती की जानकारी

43-श्री सतीश महाना-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2007 से 2012 के बीच में कितने नये अस्पताल बनाये गये हैं ? क्या इन वर्षों में निर्मित अस्पतालों में मानक के अनुरूप चिकित्सा सेवायें एवं डाक्टर उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

वर्ष 2007 से वर्ष 2012 के मध्य कुल (100 शैय्या/300 शैय्या युक्त) 13 नये अस्पताल बनाये गये हैं।

चिकित्सकों के रिक्त पदों पर तैनाती हेतु 2868 चिकित्सकों के चयन के लिये लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद को अधियाचन भेजा जा चुका है। चयनित चिकित्सकों की सूची आयोग से प्राप्त होते ही मानक के अनुरूप तैनाती की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा के ग्राम फत्तेपुर एवं सिजवाई तथा खण्डेह को लेपित मार्ग से जोड़े जाने की जानकारी

44-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा में खण्डेह से फत्तेपुर एवं सिजवाई से फत्तेपुर तक रोड व रपटा निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-5/009407, दिनांक 19.06.2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

ग्राम फत्तेपुर, सिजवाही तथा ग्राम खण्डेह पूर्व से एकल लेपित मार्ग से जुड़े हैं।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद हमीरपुर स्थित दीवान शत्रुघन सिंह जिला चिकित्सालय में विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की मांग

45-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर स्थित दीवान शत्रुघन सिंह जिला चिकित्सालय में विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-5/009408, दिनांक 19.06.2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त चिकित्सालय में आई0सी0यू0 तथा सी0टी0 स्कैन मशीन स्थापित किये जाने के साथ आवश्यक स्टाफ की तैनाती कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

चिकित्सा विभाग के अभिलेखानुसार संदर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

जी नहीं। जिला चिकित्सालय, हमीरपुर में वित्तीय वर्ष 2012-13 में एक कलर डाप्लर अल्ट्रासाउन्ड मशीन हेतु स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजकीय चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा इकाइयों तथा अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों को स्थापित करना सम्बन्धित चिकित्सा विशेषज्ञों, तकनीकी स्टाफ तथा प्रदेश सरकार की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नलकूपों हेतु लगे खराब व जले ट्रांसफार्मरों को बदले जाने का कथित प्रकरण

46-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही ट्रांसफार्मर से अनेक किसानों को निजी नलकूपों हेतु विद्युत सप्लाई दी जाती है किन्तु एक या कुछ किसानों का बिल जमा न होने पर खराब ट्रान्सफार्मर नहीं बदले जाते हैं, जिसके कारण बिल जमा करने वाले किसान भी नुकसान उठाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसान हित में ट्रान्सफार्मरों को बदलवाने की नीति बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तक ट्रांसफार्मर से अनेक किसानों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति दी जाती है। ट्रान्सफार्मर जलने/खराब होने पर यदि उस ट्रान्सफार्मर से कुछ किसानों का बिल जमा है तो ट्रान्सफार्मर बदला जाता है। ट्रान्सफार्मर पर सभी उपभोक्ताओं के बकायादार होने की स्थिति में जले ट्रान्सफार्मर को बदला जाना नियम संगत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान नीति में संशोधित किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

जनपद आगरा में फतेहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग की मरम्मत कराये जाने की जानकारी

47-श्री छोटेलाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद जनपद आगरा में लगभग 17 वर्षों पहले निर्मित होरी डांडा सपुनागली फतेहाबाद से फतेहाबाद बाइपास फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग पानी भरा होने के कारण वर्तमान में क्षतिग्रस्त होकर बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करायी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

फतेहाबाद से फतेहाबाद बाईपास मार्ग की दशा संतोषजनक है। फतेहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। होरी डांडा सपुनागली मार्ग, जिसका स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है, पर पानी भरा होने के कारण यातायात हेतु बन्द है।

फतेहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य स्वीकृत है जो दिनांक 31-3-13 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा में यमुना ऊंटगन का जल स्तर नीचा होने की जानकारी

48-श्री छोटेलाल वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद जनपद आगरा यमुना ऊटंगन का जल स्तर नीचा होने से फसलें नष्ट हो जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का निराकरण कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। ऐसी कोई समस्या दृष्टिगत नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्तर-1 के अनुसार।

जनपद आगरा में सामाजिक वानिकी प्रभाग द्वारा लगाये गये पौधे व उनके जीवित होने की जानकारी

49-श्री छोटेलाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में वर्ष 2012-13 में कितने हैक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण के अन्तर्गत कितने पौधे किस-किस किस्म के रोपे गये थे तथा उनपर कितना धन व्यय किया गया है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि रोपित वृक्षों में कितने जीवित हैं ?

श्री अखिलेश यादव-

आगरा जनपद के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा वर्ष 2012-13 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 320 हेक्टेयर क्षेत्र में नीम, कंजी, बबूल, सुबबूल, शीशम, अजफ्रन आदि विभिन्न प्रजातियों के 3,15,375 पौधे रोपण/बीज बुवान पद्धति से रोपित किये गये तथा इन पर रु0 115.42 लाख की धनराशि व्यय की गई।

वर्ष 2012-13 में रोपित 3,15,375 पौधों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2012 तक 3,04,497 पौधे वर्तमान में जीवित हैं।

जनपद आगरा के बिचपुरी रेलवे फाटक से लेकर बिचपुरी परिक्रमा आदि मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

50-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र जनपद आगरा के अन्तर्गत बिचपुरी रेलवे फाटक से लेकर बिचपुरी परिक्रमा मार्ग होते हुये नहर तक सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आबादी भाग में क्षतिग्रस्त है किन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

उक्त मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के ग्राम सभा छमियां में ट्यूबवेल प्रथम व द्वितीय की क्षतिग्रस्त नालियों की मरम्मत कराये जाने की जानकारी

51-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा छेमियां में ट्यूबवेल प्रथम व द्वितीय की नालियां वर्तमान में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नालियों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम छेमियां में कार्यशील नलकूप संख्या-118 एम0जी0 व 265 एम0जी0एस0 की नालियां वर्तमान में आंशिक क्षतिग्रस्त होने के कारण खेतों की समुचित सिंचाई नहीं हो पाती है।

नलकूप संख्या-118 एम0जी0 पर 600 मीटर गूल का जीर्णोद्धार वर्ष 2010-11 में कराया गया है। राजकीय नलकूप संख्या-265 एम0जी0एस0 की जल वितरण प्रणाली आंशिक मरम्मत उपरान्त सिंचाईरत कर दी गयी है। राजकीय नलकूपों की जल वितरण प्रणाली (गूल/पी0वी0सी0 पाइप लाइन) की मरम्मत का कार्य आवश्यकतानुसार नियमित रूप से कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियामताबाद में कुण्डा पम्प कैनाल को सुचारु रूप से संचालित कराये जाने की मांग

52-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वि0 खण्ड नियामताबाद में कुण्डा पम्प कैनाल विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से संचालित न होने से हजारों एकड़ फसलों की पैदावार नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पम्प कैनाल को सुचारू रूप से संचालित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियामताबाद में गंगा नदी के दायें तट पर कुण्डा पम्प नहर 20 क्यूसेक क्षमता पर विगत वर्षों में गंगा नदी से कटान हो रही है जिसके कारण नहर प्रणाली का आंशिक भाग प्रभावित हो जाता है। जिसके फलस्वरूप अस्थाई रूप से नहर के संचालन पर आंशिक असर पड़ता है। फसली वर्ष 1420/2012-13 में दिनांक 10-2-2013 तक खरीफ का 340 हेक्टेयर व रबी का 356 हेक्टेयर सींच का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

आंशिक रूप से नहर के संचालन पर असर पड़ने से उसका त्वरित निदान कर नहर को संचालित रखा जाता है। वर्तमान में नहर संचालित हैं एवं सिंचाई कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

53-श्री उमेश पाण्डेय-

[2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-72 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मऊ के ब्लाक फतेहपुर मण्डांव के परसूपुर बस्ती से अल्लीपुर नहर तक सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

54-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के ब्लाक फतेहपुर मण्डांव के अन्तर्गत परसूपुर अनुसूचित जाति बस्ती से खैरा नासीर तक की एवं नेमडाड़ चट्टी से अल्लीपुर नहर तक की सड़क पर बड़ी गिट्टी वर्ष 2006 से पड़ी है एवं अभी तक उक्त सड़क का निर्माण नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का लेपन स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग परसूपुर अनुसूचित बस्ती से खैरा नासिर तक की सड़क पर स्वामित्व पंचायती राज विभाग का है।

नेमडांड चट्टी से अलीपुर तक मार्ग के निर्माण हेतु शासनादेश सं0-408 (1)-ब0प्र0-2004, दिनांक 26-4-2004 द्वारा रु0 17.31 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिससे इण्टरकोट तक कार्य कराया गया है।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ ग्राम सभा उसरी के मौजा चकतुल्ला में मुन्नीलाल के ट्यूबवेल से बृजेश के ढोह तक की सड़क का लेपन स्तर तक मरम्मत कार्य कराये जाने की मांग

55-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामसभा उसरी के मौजा चकतुल्ला में मुन्नीलाल के ट्यूबवेल से ब्रजेश के ढोह तक की सड़क लगभग 1.5 किमी0 पर लेपन कार्य न होने से आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का लेपन स्तर तक मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

ग्राम सभा उसरी पूर्व से लेपित सतह से जुड़ा है। मौजा चकतुल्ला बृजेश का डोह की आबादी 250 से कम है। वर्तमान में 500 से अधिक आबादी को जोड़ा जाना शासन की प्राथमिकता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर के ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने की जानकारी

56-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में कुल कितने ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य हो चुका है एवं कितने ग्रामों का विद्युतीकरण बाकी है ? क्या सरकार बाकी ग्रामों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में कुल 76 नग राजस्व ग्राम है तथा सभी ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी के ग्राम चनौरा के राजकीय नलकूप को चालू कराये जाने की जानकारी

57-श्री राकेश बाबू-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी के ग्राम चनौरा में डीप सिंचाई हेतु नलकूप विभाग द्वारा लगाया गया बोर नलकूप अधिकारियों की लापरवाही से आज तक चालू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार उपरोक्त डीप बोर नलकूप को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी के ग्राम चनौरा में सिंचाई हेतु लगाया गया राजकीय नलकूप सं0-136 फिरोजाबाद दिनांक 19-2-2013 को चालू कर दिया गया है।

नलकूप चालू कर दिया गया है।

दिनांक 19-2-2013 को नलकूप चालू कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर में महिला चिकित्सालयों के पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

58-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त राजकीय महिला चिकित्सालय का करोड़ों का कीमती सामान उपकरण बेड, चौखट, दरवाजे, खिड़की एवं मलबा चोरी हो गया है ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार महिलाओं के चिकित्सीय

समस्याओं के निराकरण हेतु महिला चिकित्सालय का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं। राजकीय महिला चिकित्सालय, बीसलपुर का भवन अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण होने के फलस्वरूप काफी वर्ष पूर्व ही निष्प्रयोज्य हो चुका था एवं भवन पूर्णरूप से ध्वस्त होने से पूर्व ही सभी उपकरण मशीन इत्यादि हटा ली गयी थी। भवन पूर्ण रूप से खाली था। भवन में कोई भी उपकरण इत्यादि नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय महिला चिकित्सालय का समस्त स्टाफ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बीसलपुर में समायोजित कर लिया गया है। बीसलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एक प्रथम संदर्भन इकाई के रूप में पूर्णतया संचालित किया जा रहा है जिसमें महिलाओं की समस्त चिकित्सीय समस्याओं का निराकरण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा किसानों के गन्ना तौल में घटतौली करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

59-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा किसानों के गन्ना तौल में घटतौली की शिकायतें सरकार के संज्ञान में आई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों का गन्ना तौल सही ढंग से कराने का उपाय सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

चीनी मिलों द्वारा की जाने वाली घटतौली पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं गन्ना तौल सही ढंग से कराने हेतु विभागीय नियमों में गन्ना क्रय केन्द्रों के निरीक्षण की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत गन्ना एवं चीनी आयुक्त द्वारा प्रत्येक वर्ष विभागीय अधिकारियों, सांसदों/विधायकों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को क्रय केन्द्रों के निरीक्षण के अधिकार दिये जाते हैं तथा निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाये रखने हेतु यथा आवश्यक अन्तर्क्षेत्रीय जांच दलों का गठन किया जाता है। पेराई सत्र, 2012-13 में दिनांक 15-2-2013 तक चीनी मिलों के गन्ना क्रय केन्द्रों के 10155 निरीक्षण किये गये तथा कुल 1309 अनियमिततायें पकड़ी गयीं, जिनमें घटतौली की 289 अनियमिततायें तथा 1020 साधारण अनियमिततायें पायी गयी हैं। वर्तमान में पकड़ी गयी कुल अनियमितताओं में से 269 मामलों में मिल तौल लिपिकों का तौल लाइसेन्स एवं 05 समिति लिपिकों को निलम्बित करते हुए तौल कार्य से हटा दिया गया है तथा 969 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 02 मामलों में न्यायालयों में वाद दायर किये गये हैं साथ ही 25 मिल कार्मिकों को जिला मजिस्ट्रेट स्तर से दण्डित किया गया है। इसके अतिरिक्त 42 मामलों में दोषी मिलों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3/7 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 योजित करायी गयी है। गन्ने की सही तौल के लिए हस्तधारित कम्प्यूटर (एच0एच0सी0) का उपयोग किया जा रहा है तथा वर्तमान पेराई सत्र में 25 प्रतिशत मिलों पर इलेक्ट्रानिक तौल कांटे की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने की कार्यवाही

60-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा वर्तमान पेराई सत्र में 15.01.2013 तक कुल कितने टन गन्ने की पेराई की गई है तथा कुल कितने टन चीनी का उत्पादन हुआ है ? चीनी मिलों द्वारा 15.01.2013 तक कितने गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है ? बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान पेराई सत्र, 2012-13 में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा दिनांक 15-1-2013 तक 316.72 लाख टन गन्ना पेराई कर 27.93 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया है।

प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा दिनांक 15-1-2013 की स्थिति के अनुसार रु0 3066.92 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है।

बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान की गहन समीक्षा करते हुए सम्बन्धित चीनी मिलों को नोटिसें निर्गत की गयी हैं। परिक्षेत्रवार समीक्षा बैठक कर प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों, चीनी मिल प्रतिनिधियों को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कड़े निर्देश जारी किये गये हैं। जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों को भी गन्ना मूल्य भुगतान हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

जनपद शाहजहांपुर के भावलखेड़ा एवं ददरौल ब्लाकों की सोसाइटी द्वारा काश्तकारों को दी गयी यूरिया खाद की जानकारी का विवरण

61-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उर्वरकों की विशेष रूप से यूरिया की कमी के कारण काश्तकारों को यूरिया ब्लैक में लेनी पड़ रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शाहजहांपुर जनपद के भावलखेड़ा तथा ददरौल ब्लाकों की सोसाइटी पर 1 जून, 2012 से 27-08-12 तक कितनी-कितनी खाद उपलब्ध कराई गयी है तथा किन-किन काश्तकारों को दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

जनपद शाहजहांपुर के भावलखेड़ा एवं ददरौल ब्लाकों की सोसायटी पर 1 जून, 2012 से 27-8-2012 तक कुल 3415.050 मी0 टन खाद उपलब्ध करायी गयी जिसमें भावलखेड़ा की समितियों द्वारा 1413 कास्तकारों और ददरौल की समितियों द्वारा 2750 कास्तकारों कुल 4163 कास्तकारों को खाद दी गयी। उक्त कास्तकारों के नाम की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नेशनल हाई-वे पर एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

62-श्री दलवीर सिंह-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने सम्बन्धी कोई आदेश निर्गत किया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश से होकर निकलने वाले प्रत्येक हाईवे पर स्थानीय प्रशासन द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां, इमरजेन्सी मेडिकल ट्रान्सपोर्ट सेवा के अन्तर्गत नेशनल हाई-वे पर एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।

इमरजेन्सी मेडिकल ट्रान्सपोर्ट सेवा जनपद देवरिया जहां चुनाव आचार-संहिता प्रभावी है को छोड़कर अन्य सभी जनपदों में प्रारम्भ कर दी गयी है। इस सेवा के अन्तर्गत एक एम्बुलेन्स प्रत्येक विकास खण्ड क्षेत्र हेतु एवं न्यूनतम दो एम्बुलेन्स जनपद मुख्यालय हेतु उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के गांवों व मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

63-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में कुल कितने गांव व मजरों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? क्या इनका विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद अलीगढ़ में कुल 17 गांव व 623 मजरों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

जी हां।

जनपद अलीगढ़ के 300 व उससे अधिक आबादी वाले 17 ग्रामों एवं 381 मजरों के विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय के अन्तर्गत प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है। केन्द्र सरकार से स्वीकृति एवं धन प्राप्ति के उपरान्त इनका विद्युतीकरण का कार्य संभव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में ब्रांच लाइन अलीगढ़ से बरेली लाइन के दोनों ओर सड़क बनवाये जाने की मांग

64-श्री दलवीर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में ब्रांच लाइन अलीगढ़ से बरेली रेलवे लाइन पर फाटक सं0 86 सी/ई 3 पर रेल विभाग द्वारा केवल रेलवे लाइन पर पुल बना दिया गया है एवं फाटक स्थाई रूप से बन्द है ? क्या पुल के दोनों ओर उतार चढ़ाव पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त सड़क का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

पहुंच मार्ग हेतु पूर्व में भूमि की अनुपलब्धता एवं निर्मित रेल सेतु की ऊंचाई बदल जाने के कारण संशोधित आगणन बनाया गया है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

उपरोक्तानुसार।

65-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद सोनभद्र के ओबरा के स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप डाक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, दवायें आदि उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

66-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा के स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप डाक्टरों, महिला डाक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, दवायें, एण्टीरैबीज, एन्टीस्नैक दवायें एवं चिकित्सीय उपकरणों का अभाव होने से नागरिकों को काफी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप डाक्टरों, महिला डाक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में दवाओं एवं चिकित्सीय उपकरणों की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपदवार किराये के भवनों में चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी

67-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवन में चल रहे हैं ? क्या सरकार इसको जनपदवार विवरण उपलब्ध कराते हुये अपने भवन बनवाकर उसमें स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

प्रदेश में कुल 105 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवन में चल रहे हैं तथा प्रदेश में समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकारी भवन में चल रहे हैं।

जी हां।

जनपदवार किराये के भवन में चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सूची संलग्न[†] है।

51 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माणाधीन है जो एक वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ-225-227 पर।)

प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में वेंटीलेटर उपलब्ध कराये जाने की मांग

68-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षा हेतु वेंटीलेटर की व्यवस्था है ? क्या सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में वेंटीलेटर की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

प्रदेश के 34 चिकित्सालयों में वेन्टीलेटर की सुविधा प्राप्त सूचना के अनुसार उपलब्ध है, जिसकी सूची संलग्न†† है।

जी हां।

विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता तथा वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित परिवार के सदस्यों को स्मार्ट कार्ड की सुविधा

69-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की मलिन बस्तियों में निवास करने वाले लोगों के स्वास्थ्य लाभ हेतु सरकार स्वास्थ्य कार्ड बनाये जाने विषयक कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 सूची 2002 में सम्मिलित परिवार के सदस्यों को स्मार्ट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के विभिन्न खण्डों में निर्माण कार्य कराये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

70-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र में सरयू नहर परियोजना के विभिन्न खण्डों में निर्माण कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 09.08.2012, मुख्य अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई भवन, उ0प्र0 लखनऊ को स्पीड पोस्ट सं0 आर0यू0 075783496, दिनांक 11.08.2012 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उक्त प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 09-08-2012 में उल्लिखित विभिन्न निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति का विवरण संलग्न है।*

प्रश्न नहीं उठता।

---

†† (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ-228-229 पर।)

* (देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ-230-232 पर।)

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के ग्राम मासिना खास में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

71-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के ग्राम मासिना खास में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन निर्माण हेतु आपके पत्रांक सं0 52865/2012, दिनांक 05-06-2012 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रस्ताव की जांच कराई गई है। ग्राम मासिना खास का नजदीकी 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र खैरतिया है, जिस पर 5 एम0वी0ए0 का परिवर्तक लगा हुआ है। इस परिवर्तक पर अधिकतम भार 250 एम्पियर के सापेक्ष वर्तमान में मात्र 150 एम्पियर भार है। अतः प्रस्तावित उपकेन्द्र की वर्तमान में तकनीकी आधार पर आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज में स्थित ग्राम भारतभारी में प्राचीन काल में महाराज भरत जी के किला को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग

72-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज में स्थित ग्राम भारतभारी में प्राचीन काल में महाराजा भरत जी का किला/निवास स्थल था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज में स्थित ग्राम भारतभारी में प्राचीनकाल में महाराजा भरत जी का किला/निवास स्थल के अवशेष टीले के रूप में पाये जाते हैं।

उक्त स्थल को विकसित किये जाने हेतु रु0 478.70 लाख की योजना का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, परन्तु भारत सरकार से वांछित स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत केन्द्रों/उपकेन्द्रों पर लाइन मैनों/पेट्रोल मैनों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने की मांग

73-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत केन्द्रों/उपकेन्द्रों पर लाइन मैनों/पेट्रोल मैनों के सृजित पदों की संख्या क्या है ? क्या वर्तमान समय में ऊर्जीकृत ग्रामों तथा बढ़े

हुए विद्युत केन्द्रों/उपकेन्द्रों के भार के सापेक्ष लाइन मैनों/पेट्रोल मैनों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान में पूववर्ती पद लाइनमैन एवं पेट्रोल मैन का पद परिवर्तित होकर क्रमशः टी0जी0-2 (लाइन) एवं कुशल श्रमिक हो गया है जो कि प्रोन्नति के पद है जिनके स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :-

पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
टी0जी0-2 (लाइन)	5997	2864
कुशल श्रमिक	12313	9247

प्रोन्नति द्वारा रिक्त पदों पर कार्मिकों का चयन किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत नियुक्तियां की जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

74-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[2सरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-78 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ में लालबाग के राजा अपार्टमेन्ट के बेसमेन्ट में स्थित पार्किंग में अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के विरुद्ध स्थगन आदेश को निरस्त कराये जाने की जानकारी

75-श्री उपेन्द्र तिवारी-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2011 के अता0प्र0सं0-72 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 32 बी0एन0 रोड, लालबाग, लखनऊ के राजा अपार्टमेन्ट के बेसमेन्ट में स्थित पार्किंग में अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के विरुद्ध मा0 एडिशनल सिविल जज तृतीय (सी0डी0) के यहां योजित वाद संख्या-85/01 के स्थगन आदेश को वैकेट कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-10-2003, 20-1-2004, 24-10-2005 एवं 17-8-2007 के आलोक में प्रश्नगत स्थगन आदेश को वैकेट कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्नगत स्थगन आदेश निरस्त करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07-11-2012 को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है। वाद पर अगली सुनवाई दिनांक 07-03-2013 को नियत है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम खमरिया के सामने शारदा नदी के कटान व दिशा परिवर्तन को रोकने हेतु स्टड निर्माण कराये जाने की मांग

76-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी में बाढ़ व कटान से प्रभावित ग्राम खमरिया के सामने शारदा नदी के कटान व दिशा परिवर्तन को रोकने हेतु स्टड निर्माण की सरकार की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। इसका तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। आवश्यकता होने पर तथा परियोजना साध्य पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम तिकुनियां, सूरजनगर व खैरटिया को मोहना नदी की बाढ़ व कटान से बचाने की योजना

77-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम तिकुनियां, सूरजनगर व खैरटिया को मोहना नदी की बाढ़ व कटान से बचाने हेतु कोई योजना बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। इसका तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है आवश्यकता होने पर तथा परियोजना साध्य पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के मंझरा रेलवे स्टेशन से कोड़ियाला घाट तक सड़क निर्माण कराये जाने की मांग

78-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 138-निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के मँझरा रेलवे स्टेशन से कोड़ियाला घाट तक आवागमन की कठिनाई को दूर करने हेतु सरकार द्वारा सड़क निर्माण कराये जाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बे निघासन में पोस्टमार्टम हाउस को चालू कराये जाने की जानकारी

79-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बे निघासन में 20 वर्ष से पोस्टमार्टम हाउस का भवन है ? यदि हां, तो क्या उसका उपयोग किया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

लखीमपुर खीरी के कस्बे निघासन में पोस्टमार्टम हाउस पुनर्निर्माणाधीन है।

वाह्य विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण होने एवं हस्तगत होने के उपरान्त तत्काल क्रियाशील हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला महिला चिकित्सालयों में 100 शैय्या मैटरनिटी विंग तैयार करने की योजना

80-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रदेश के जिला महिला चिकित्सालयों में सौ बेड की अत्याधुनिक यूनिट तैयार करने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो इसके लिए कब तक प्रशासनिक व वित्तीय अनुमोदन दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। 100 शैय्या मैटरनिटी विंग तैयार करने की योजना है।

कतिपय जनपदों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दे दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड कुरारा के ब्रह्माडेरा के लगे हुए कतिपय मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

81-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-5/009410, दिनांक 19 जून, 2012 जो विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर, जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड कुरारा के ब्रह्माडेरा के लगे हुए मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड कुरारा के अन्तर्गत ग्राम सभा चन्दूपुर के मजरा ब्रह्माडेरा से लगे हुए मजरें गोहाई, विश्वनाथ का डेरा, गंगवा डेरा, अठभइया का डेरा, चुमकी का डेरा, बच्ची का डेरा एवं बसवारी का डेरा हैं। वर्तमान में 300 से अधिक आबादी वाले ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। उक्त मजरों की आबादी 300 से कम होने के कारण मानक के अनुरूप राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में शामिल नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर में सुमेरपुर के ग्राम करेना डेरा मजरे का विद्युतीकरण कराये जाने की जानकारी

82-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-5/009410, दिनांक 19 जून, 2012 जो विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर, जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड-सुमेरपुर के ग्राम

सभा कैंथी व करेना डेरा सहित सभी डेरों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सुमेरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा कैंथी पूर्व से ही विद्युतीकृत है। इस ग्राम को विद्युत आपूर्ति 100 के0वी0ए0 परिवर्तक से की जा रही है तथा ग्राम में 70 नग उपभोक्ता हैं।

करेना डेरा मजरे के विद्युतीकरण के कार्य को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित कर लिया गया है। योजना की स्वीकृति एवं धन प्राप्ति के उपरान्त कार्य किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर के ग्राम सभा पढ़ोरी के मजरा बजरंग डेरा नई दिल्ली आदि का विद्युतीकरण कराये जाने की जानकारी

83-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-5/009410, दिनांक 19 जून, 2012 जो विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर, जनपद हमीरपुर के ग्राम सभा पढ़ोरी के मजरा बजरंग डेरा नई दिल्ली आदि में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद हमीरपुर के ग्राम सभा पढ़ोरी के मजरा बजरंग के विद्युतीकरण के कार्य को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित कर लिया गया है। योजना की स्वीकृति एवं धन प्राप्ति के उपरान्त कार्य को किया जायेगा।

जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत मजरा नई दिल्ली के विद्युतीकरण के कार्य को बिजनेस प्लान 2012-13 में स्वीकृति है। कार्य को माह माार्च, 2013 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर के मौदहा में ग्राम रीबन तथा खण्डेह मार्ग का डामरीकरण कराये जाने की जानकारी

84-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-5/009407, दिनांक 19-6-2012 जो जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड-मौदहा में रीवन से खण्डेह तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम रीवन तथा खण्डेह पूर्व से ही एकल लेपित मार्ग से जुड़े है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद हमीरपुर के मौदहा में परछट से खैरी तथा मार्ग एवं रपटा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

85-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-5/009407, दिनांक 19-6-2012 जो जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड-मौदहा में परछट से खैरी तक मार्ग एवं रपटा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम परछट तथा ग्राम खैरी पूर्व से ही एकल लेपित मार्ग में जुड़े है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के किसानों का ऋण माफ करने की योजना

86-श्री सुरेश राणा-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों का 50 हजार रुपये तक का ऋण माफ करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है और अब तक कितने किसानों का ऋण माफ किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ऋण माफी योजना-2012 का लाभ केवल उन्हीं कृषकों को देय है जिन्होनें अपनी कृषि योग्य भूमि बन्धक रखकर ऋण स्वीकृत कराया है तथा जो दिनांक 31-03-2012 को निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करते हों :--

क-कृषक की कृषि योग्य भूमि बैंक द्वारा बन्धक रखी गयी हो।

ख-कृषक का स्वीकृत ऋण का मूलधन रु0 50 हजार से अधिक न हो।

ग-कृषक द्वारा लिये गये ऋण का 10 प्रतिशत तक की अदायगी कर दी गयी हो।

किसी का नहीं।

कतिपय जनपदों से जिलास्तरीय कमेटी की संस्तुति प्राप्त न होने के कारण लम्बित है।

उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्युत दरों में कटौती करने की मांग

87-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योगों पर विद्युत दरों में भारी बढ़ोत्तरी की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उक्त दरों में कटौती करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

यह वृद्धि पिछले लगभग ढाई वर्ष के बाद की गयी है, क्योंकि इस अन्तराल में ऊर्जा क्रय के मद में लगभग 43 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है।

उद्योगों पर वर्तमान में लागू विद्युत दरें निम्नवत् हैं :--

	लघु एवं मध्यम उद्योग				
	क-शहरी आपूर्ति				
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 225.00 प्रति कि0ग्रा0 प्रतिमाह			
	इनर्जी चार्ज	रु0 5.85 प्रति यूनिट			
	न्यूनतम चार्ज	रु0 500.00 प्रति कि0वा0 प्रतिमाह			
एल0एम0वी0-6	**टाईम ऑफ डे**	**टी0ओ0डी0 दर**			
	22.00 से 06.00 बजे तक	(-) 7.5%			
	06.00 से 17.00 बजे तक	0			
	17.00 से 22.00 बजे तक	(+) 15%			
	ख-ग्रामीण आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को 15 प्रतिशत की डिमाण्ड एवं इनर्जी चार्ज पर टी0ओ0डी0 रहित छूट अनुमन्य होगी।			
	बड़े एवं भारी उद्योग				
	0.4 के0वी0 मीटरिंग पर	11 के0वी0 विद्युत आपूर्ति पर लागू दर के अनुसार			
	11 के0वी0 विद्युत आपूर्ति पर				
	क-शहरी आपूर्ति				
	आधार दर	11 के0वी0 विद्युत आपूर्ति पर	11 के0वी0 ऊपर एवं 66 के0वी0 तक विद्युत आपूर्ति पर	66 के0वी0 से ऊपर एवं 132 के0 वी0 तक विद्युत आपूर्ति पर	132 के0वी0 के ऊपर विद्युत आपूर्ति पर
एच0वी0-2	डिमाण्ड चार्ज (रु0/के0वी0ए0/माह)	250.00	240.00	220.00	220.00
	इनर्जी चार्ज (रु0/के0वी0ए0एच0/माह)	5.90	5.60	5.40	5.20

	टाईम ऑफ डे	टी0ओ0डी0 दर
	22.00 से 06.00 बजे तक	(-) 7.5%
	06.00 से 17.00 बजे तक	0
	17.00 से 22.00 बजे तक	(+) 15%
	ख-ग्रामीण आपूर्ति	यह दर सूची केवल 11 के0वी0 तक के उपभोक्ता जिन्हें ग्रामीण शिड्यूल से आपूर्ति होती है, लागू होगी तथा इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को 15 प्रतिशत की डिमाण्ड एवं इनर्जी चार्ज पर टी0ओ0डी0 रहित छूट अनुमन्य होगी।

जी नहीं।

यह वृद्धि गत् ढाई वर्षों के उपरान्त की गयी है क्योंकि विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा क्रय कर विद्युत उपभोक्ताओं तक पहुंचाने हेतु रु0 5.87/यूनिट का खर्च वर्ष 2012-13 में अनुमोदित है। टैरिफ वृद्धि से पूर्व औसत विक्रय मूल्य रु0 3.84/यूनिट अनुमोदित था तथा दिनांक 01-10-2012 को की गई टैरिफ वृद्धि-के उपरान्त भी औसत विक्रय मूल्य रु0 4.51 यूनिट अनुमोदित किया गया है। उक्त वृद्धि के बाद भी प्रति यूनिट विक्रय पर विभाग को रु0 1.36/ यूनिट का राजस्व घाटा उठाना पड़ेगा। अतः प्रस्तावित वृद्धि को वापस लिया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन सरयू सहकारी चीनी मिल के गन्ना क्रय केन्द्रों पर गन्ना उतरवाई के नाम पर वसूली करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

88-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन में स्थित सरयू सहकारी चीनी मिल के गन्ना क्रय केन्द्रों पर गन्ना उतरवाई के नाम पर वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या यह सरकारी गन्ना क्रय नीति के अनुरूप है ? क्या सरकार इसको समाप्त करेगी तथा दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

दिनांक 19-12-2012 को उप जिलाधिकारी, निघासन, जनपद-खीरी द्वारा सहकारी चीनी मिल बेलरायाँ के गन्ना क्रय केन्द्र-निघासन प्रथम का निरीक्षण किया गया। उप जिलाधिकारी द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या में उतरवाई के नाम पर वसूली की शिकायत का उल्लेख किया गया है।

जी नहीं।

जी हां।

उप जिलाधिकारी, निघासन की उक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त होने पर मिल द्वारा तत्काल सुधारात्मक कदम उठाते हुए सभी क्रय केन्द्रों के परिवहन ठेकेदारों को श्रमिकों द्वारा किए जा रहे उक्त कृत्य, जो निविदा शर्तों एवं अनुबन्ध के विपरीत है, तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रधान प्रबन्धक, चीनी मिल, बेलरायां द्वारा मिल के मुख्य गन्ना अधिकारी को चेतावनी जारी की गई है तथा अन्य दोषियों को चिन्हित कर दण्डित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में वनों के पास स्थित रास्तों को जो राजस्व ग्रामों के उपयोग में है, की मरम्मत व खड़न्जा लगावाये जाने की मांग

89-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वनों के पास स्थित रास्तों को जो राजस्व ग्रामों के उपयोग में है, की मरम्मत व खड़न्जा लगाने से वन विभाग द्वारा रोका जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निदान हेतु कोई योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वनों के पास स्थित गैर वनभूमि के रास्तों पर भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 व अन्य सुसंगत प्राविधान लागू नहीं होते है।

जनपद आगरा के राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाटर वर्क्स चौराहा एवं सिकन्दरा चौराहा के पास की सड़क को मरम्मत कराये जाने की मांग

90-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाटर वर्क्स चौराहा एवं सिकन्दरा चौराहा के पास सड़क जर्जर एवं गड्ढायुक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब सड़कों को ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में चम्बल नदी पर पिनाहट पुल के निर्माण का कथित प्रकरण

91-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में चम्बल नदी पर पिनाहट पुल के निर्माण की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2012 में की जा चुकी है तथा जिसके लिये प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मांग की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत सेतु राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्रान्तर्गत निर्मित किया जाना है, इस कार्य हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित कमेटी द्वारा अनुमति जारी की जायेगी।

92-श्री उमेश पाण्डेय-

[2सरे सोमवार के अतारांकित प्र0सं0-76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मऊ के मधुबन की ग्राम सभा गाजियापुर के सिवान नाले पर पुल निर्माण का कथित प्रकरण

93-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा गजियापुर में सिंचाई विभाग के बन्धे से कवलपुरा सिवान तक नाले पर पुल व सड़क न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में परेशानी होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले पर पुल एवं सड़क बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

कवलपुरा सिवान तथा गजियापुर गांव हाहानाला मुख्य बांध तथा हाहानाला रिंग बांध के मध्य पड़ने वाले फ्लड प्लेन में स्थित है। वर्षा ऋतु में इस भू-भाग के नसेब जमीन में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे तत्समय क्षेत्रीय जनता को आवागमन में असुविधा होती है। इस भू-भाग में कोई नाला नहीं है।

जल भराव का बरसाती पानी बांध पर बने रेगुलेटर से खारिज हो जाता है।

इस भू-भाग में कोई नाला नहीं है। अतएव नाले पर पुल बनाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ के मधुबन में रामगढ़ से खन्टिया तक मार्ग की लेपन स्तर पर निर्माण कार्य किये जाने की मांग

94-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्र में रामगढ़ से खन्टिया तक एवं दोहरीघाट मार्ग से गोधनी गांव तक सड़कें अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क पर लेपन स्तर पर निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

रामगढ़-खन्टिहा मार्ग की कुल लम्बाई 2.00 कि0मी0 है। लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाला 1.00 कि0मी0 भाग लेपित है, जो संतोषजनक है। शेष भाग (1.00 कि0मी0) पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

दोहरीघाट मार्ग से गोधनी गांव तक मार्ग की कुल लम्बाई 3.519 कि0मी0 है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसमें 3.10 कि0मी0 लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाला लेपित भाग आंशिक रूप से कहीं-कहीं क्षतिग्रस्त है। शेष 419 मीटर खड़न्जा स्तर का है, जिस पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में गोमती नगर योजना के विराट खण्ड-2 स्थित भू-खण्ड संख्या सी-1 पर मार्केट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

95-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विराट खण्ड-2 गोमती नगर, लखनऊ में मार्केट का निर्माण कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया था, जो इस समय अज्ञात कारणों से बन्द है, को पुनः प्रारम्भ कराने विषयक मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा उ0प्र0 का पत्रांक 0926/ने0वि0द0/2012, दिनांक 03-12-2013 उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त बन्द पड़े कार्य को पुनः प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्रांक 0926/ने0वि0द0/2012, दिनांक 03-12-2012 उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है।

गोमती नगर योजना के विराट खण्ड-2 में स्थित व्यवसायिक भू-खण्ड संख्या-सी-1 पर स्थानीय निवासियों के प्रबल विरोध के कारण मार्केट का निर्माण/विकास कार्य अवरुद्ध है। भू-खण्ड के नियोजित तलपट मानचित्र में संशोधन करते हुये पुनर्नियोजन किया जा रहा है और तद्नुसार भू-खण्ड पर निर्माण/विकास कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के गोला में जमीन शुक्ल होते हुए बाल भीटी आदि मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

96-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील गोला अन्तर्गत जमीन शुक्ल होते हुये बाल भीटी से समय स्थान पड़ौली होते हुये कौवाडील तक की सड़क पूर्णतया जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण/मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग की कुल लम्बाई 11.00 कि0मी0 है जिसमें प्रारम्भ के 3.50 कि0मी0 का भाग (बालभीटी से जमीन शुक्ल तक) मण्डी परिषद्, गोरखपुर के स्वामित्व में है। शेष भाग, जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला में रामजानकी राज्य मार्ग का अवशेष कार्य पूर्ण कराये जाने की जानकारी

97-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील-गोला अन्तर्गत रामजानकी मार्ग संख्या-72 के कि0मी0 136 से 151 तक सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग रु0 28 करोड़ स्वीकृत है तथा उसके सापेक्ष लगभग रु0 9 करोड़ अवमुक्त कर कुछ निर्माण कार्य भी हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में है कि गत 6 माह से निर्माण कार्य बन्द हो जाने से उक्त प्रमुख राज्य मार्ग-72 पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राज्य मार्ग का अवशेष निर्माण शीघ्र पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत कार्य हेतु रु0 2891.98 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रु0 1152.56 लाख अवमुक्त किया जा चुका है।

कार्य प्रगति पर है एवं यातायात चल रहा है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चन्दौली की मुगलसराय के बबुरी बाजार में 50 बेड का अस्पताल बनवाये जाने की मांग

98-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली की मुगलसराय-विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बबुरी बाजार में अस्पताल न होने के कारण इस क्षेत्र की जनता को लगभग 15 कि0मी0 दूर चन्दौली, 20 किमी0 दूर चकिया तथा 17 किमी0 दूर मुगलसराय जाकर इलाज कराना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बबुरी बाजार में 50 बेड का एक अस्पताल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार 30 हजार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन/सृजन का निर्धारण किया गया है। मानक के अनुरूप ब्लाक चंदौली में 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 4 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है तथा चंदौली मुख्यालय पर एक संयुक्त जिला चिकित्सालय तथा चकिया में 01 संचुक्त जिला स्तरीय चिकित्सालय संचालित है जिनकी दूरी बबुरी से नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मद्वपुर की दूरी 10 कि0मी0 तथा नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिसुनपुरा की दूरी 10 कि0मी0 है तथा संयुक्त जिला चिकित्सालय चंदौली तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदौली की दूरी 12 कि0मी0 है एवं बबुरी से संयुक्त चिकित्सालय चकिया की दूरी 18 कि0मी0 है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय कतिपय ग्राम सभाओं का विद्युतीकरण कराये जाने की जानकारी

99-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा-सिकरी, पचोखर, पुरैनी, गोपालापुर के चांदातारा, रेंमा, गोधना, गंगेहरा, कुरई, जलखोर हरिजन बस्ती, भरछा तलपरा, शाहपुर, डगरापर, बिन्दपुरवा तथा नवागढ़ ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण न होने से यहां की जनता अंधेरे में रह रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभाओं का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा सिकरी, पचोखर, पुरैनी, गोपालपुर, चांदातारा, रेंमा, गोधना, गंगेहरा, कुरई, जलखोर, हरिजन बस्ती, भरछां तलपरा, शाहपुर, डकरापर, बिन्दुपुरवा तथा नवागढ़ ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सभी राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्व मानक के अनुसार किया जा चुका है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 300 से अधिक आबादी वाले मजरों के विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना द्वितीय फेज-2 की डी0पी0आर0 भारत सरकार को प्रेषित है। डी0पी0आर0 स्वीकृत होने अथवा अन्य किसी योजना में धनराशि प्राप्त होने पर विद्युतीकरण कराना सम्भव होगा।

300 से अधिक आबादी वाले ग्रामों एवं मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेज-2 के अन्तर्गत भारत सरकार को डी0पी0आर0 की स्वीकृति एवं धन प्राप्त होने पर सम्भव हो सकेगा। 300 से कम आबादी वाले ग्रामों/मजरों के विद्युतीकरण की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय के अन्तर्गत चन्दाइत नहर से घुरहूपुर तक तथा ग्राम पंचायत चन्दाइत से उसरौड़ी गडई नदी की सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने की मांग

100-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चन्दाइत नहर से घुरहूपुर तक तथा ग्राम पंचायत चन्दाइत से उसरौड़ी गडई नदी सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण उक्त मार्गों से आने-जाने में नागरिकों को भारी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का पुनर्निर्माण लेपन स्तर तक करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

ग्राम पंचायत चन्दाइत से उसरौड़ी गडई नदी तक सड़क लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है। चन्दाइत नहर से घुरहूपुर तक मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

उक्त मार्ग का पुनः निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय ग्राम सभा भिसौरी में अम्बेडकर गेट से जमुनीपुर मार्ग तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

101-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भिसौरी ग्राम सभा में अम्बेडकर गेट से जमुनीपुर मार्ग तक सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को पुनः बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुसार चिकित्सकों, पैरा-मेडिकल स्टाफ आदि की व्यवस्था की मांग

102-श्री जाकिर अली-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप चिकित्सकों, महिला चिकित्सकों, पैरा-मेडिकल स्टाफ, दवाओं, एण्टीरैबीज, एन्टीस्नैक तथा चिकित्सीय उपकरणों का अभाव होने से नागरिकों को काफी कठिनाइयां होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप चिकित्सकों, महिला चिकित्सकों, पैरा-मेडिकल स्टाफ तथा पर्याप्त मात्रा में दवाओं व चिकित्सीय उपकरणों की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के कतिपय ब्लाकों में वृक्षों की कटान पर रोक लगाते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

103-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के तहत आम (देसी, कलमी और तुकमी) नीम, महुआ, साल, पीपल, बरगद, बीजा (साल) के पेड़ को काटने पर 2020 तक रोक लगी हैं ? यदि हां, तो क्या जनपद-लखनऊ के बक्शी का तालाब, मलिहाबाद, गोसाईगंज, माल, काकोरी, चिनहट तथा सरोजनी नगर में उक्त वृक्षों की कटाई की जा रही है ? यदि

हां, तो क्या सरकार उक्त वृक्षों के काटने पर रोक लगाते हुये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। अधिसुचना दिनांक 20-7-2012 के द्वारा इन वृक्षों को तब तक नहीं काटा जायेगा जब तक कि कोई वृक्ष सूख न गया हो या सूख रहा हो या यह व्यक्ति या सम्पत्ति के लिए खतरा पैदा कर रहा हो, या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विकास कार्य के निष्पादन के लिए इसका काटा जाना आवश्यक हो और ऐसे वृक्ष को काटने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत आने वाले वृक्षों के पातन की अनुमति समय-समय पर प्रदान की गयी है।

पातन अनुज्ञा के बिना उक्त वृक्षों के काटने पर सम्बन्धित के विरुद्ध संगत अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2012-13 में माह जनवरी, 2013 तक इन क्षेत्रों में 385 मामलों में 1637 वृक्षों का अवैध पातन पाया गया। 28 अभियुक्तों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी। विभागीय मामलों से रु0 17,69,427.00 प्रतिकर वसूला गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में समस्त प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहकारी भवन में स्थापित होने की जानकारी

104-श्री जाकिर अली-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवन में चल रहे हैं ? क्या सरकार अपने भवन बनाकर उनको उसमें स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद-गजियाबाद में समस्त प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकारी भवन में स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों में वेन्टीलेटर सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

105-श्री जाकिर अली-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के किन-किन सरकारी अस्पतालों में वेंटीलेटर की व्यवस्था है ? क्या सरकार गाजियाबाद के सभी सरकारी अस्पतालों में वेंटीलेटर की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों में वेन्टीलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

जी हां।

विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता तथा वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने की मांग

106-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र में कोई इंजीनियरिंग कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री आलोक कुमार शाक्य)-

जी हां।

जनपद गाजियाबाद में 48 निजी इंजीनियरिंग कालेज स्थापित है। सम्प्रति लोनी विधान सभा क्षेत्र में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज खोलने का कोई प्रकरण विचाराधीन नही है।

107-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-70 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय व पेट्रोल के बिलों के भुगतान कराये जाने का मांग

108-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय तथा विगत दो वर्षों के पेट्रोल के बिलों का भुगतान न करने के कारण कर्मचारियों के भरण पोषण की विषम समस्या है ? यदि हां, तो क्या इनके भुगतान शीघ्र किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जी नहीं।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में भारत सरकार से स्वीकृत राज्य कार्य योजना के सापेक्ष कम बजट प्राप्त होने के कारण संविदा कर्मियों के मानदेय एवं पेट्रोल भुगतान मदों में लम्बित देनदारियां उत्पन्न हुई हैं। लम्बित देयता के भुगतान के लिये बजट प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा लम्बित देयता हेतु बजट आवंटित किये जाने के उपरान्त जनपद-पीलीभीत की लम्बित देयता का भुगतान नियमानुसार तत्काल कर दिया जायेगा।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक दद्रौल की न्याय पंचायत घुसगवां ग्रामों में आने वाले मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

109-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के ब्लाक दद्रौल की न्याय पंचायत घुसगवां के अन्तर्गत आने वाले सभी ग्रामों/राजस्व ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक कराया जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक दद्रौल की न्याय पंचायत घुसगवां के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्राम है-टिकरी, रसूलपुर, सिमरिया, मधवामई, बलेली, खिरिया, कपेडकटका, निवाडी, भूरखेडा, शाहवाजनगर, खुर्दराई, नई बस्ती, सतवां एवं कटैया है।

उपरोक्त ग्रामों/मजरों में शाहवाजनगर का मजरा रोशनगर, घुसगवां का मजरा यादव गौटिया एवं ग्राम खुर्दराई का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मजरा रोशनगर के विद्युतीकरण कार्य को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण में सम्मिलित कर लिया गया है। निविदा निस्तारण का कार्य प्रक्रियाधीन है। ग्राम घुसगवां का मजरा यादव गौटिया एवं ग्राम खुर्दराई का विद्युतीकरण मानक के अनुसार न होने के कारण योजना में प्रस्तावित नहीं है।

जनपद गोरखपुर में विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये कार्य की जानकारी

110-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2011-2012 में लोक निर्माण विभाग को कुल कितना धन विकास कार्य हेतु आवंटित हुआ था, तथा उसके सापेक्ष विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में कौन-कौन सी सड़कों, पुल/पुलिया का निर्माण तथा मरम्मत कार्य कराया गया तथा उसमें कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जिला गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2011-12 में लोक निर्माण विभाग को विकास कार्यों हेतु कुल रु0 11723.48 लाख की धनराशि आवंटित हुई थी तथा उसके सापेक्ष विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में कुल 21 सड़कों के निर्माण हेतु रु0 809.32 लाख तथा कुल 13 सड़कों की मरम्मत कार्य हेतु रु0 238.54 लाख एवं एक सेतु निर्माण हेतु रु0 22.23 लाख अर्थात् कुल रु0 1070.09 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर आदि के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे मशीन आदि उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

111-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विकास खण्ड-सरदार नगर, ब्रहमपुर, पिपराइच के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों

पर एक्स-रे एवं अन्य जांच उपकरण नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे व अन्य जांच उपकरण उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जिला गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 100 एम0ए0 क्षमता की एक्स-रे मशीन स्थापित है। विकास खण्ड सरदार नगर एवं ब्रह्मपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है।

मानक के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्स-रे मशीन की व्यवस्था की जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्स-रे मशीन स्थापित किये जाने का मानक नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर आदि प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवायें उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

112-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विकास ख्ण्ड-सरदार नगर, ब्रहमपुर, पिपराइच के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एलोपैथिक दवाओं का अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों के निजी नलकूपों के विद्युत बिल पर लगे संट कैपिसिटर चार्ज समाप्त कराये जाने की मांग

113-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों के निजी नलकूपों के विद्युत बिल पर प्रतिमाह कितना सनकेपिसटर चार्ज लिया जाता है ? क्या यह सत्य है कि सनकेपिसटर चार्ज के रूप में प्रदेश में किसानों पर अतिरिक्त बोझ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस चार्ज को समाप्त कर प्रदेश के किसानों को राहत प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जिन किसानों के निजी नलकूपों पर कैपिसिटर नहीं लगे हैं उन किसानों के निजी नलकूपों के विद्युत बिलों का प्रतिमाह 15 प्रतिशत पावर फैक्टर सरचार्ज के रूप में लिया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

निजी नलकूपों पर संट केपीसिटर सरचार्ज नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार लिया जाता है। निजी नलकूपों के कनेक्शनों पर केपीसिटर का अधिष्ठापन पावर फैक्टर में सुधार के लिए किया जाता है, पावर फैक्टर में सुधार (इम्प्रूवमेन्ट) से मोटर की दक्षता बढ़ जाती है, जिससे नलकूप से पानी निकलने का डिस्चार्ज बढ़ जाता है और विद्युत की खपत में बचत होती है।

जनपद गाजियाबाद में प्राइवेट अस्पताल नर्सिंग होम से निकलने वाले कचरे के निस्तारण की योजना

114-श्री जाकिर अली-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में प्राइवेट अस्पताल तथा नर्सिंग होम से निकलने वाले कचरों को खुले स्थानों में ही फेंकने से आस-पास के क्षेत्रों में संक्रमण फैलने से बीमारियों का खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राइवेट अस्पतालों तथा नर्सिंग होमों से निकलने वाले कचरों के निस्तारण हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 1998 तथा संशोधन 2000 में निहित प्राविधानों के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण प्राईवेट अस्पतालों तथा नर्सिंग होमों के स्वामी/प्रभारी द्वारा सुनिश्चित कराये जाने का प्राविधान किया गया है जो वर्तमान में भी प्रभावी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस आदि बीमारियों के रोकथाम की योजना

115-श्री जाकिर अली-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माह जुलाई, 2012 से अब तक डायरिया, तीव्र ज्वर, बुखार, जापानी इंसेफ्लाइटिस से कितनी मौतें हुईं ? क्या सरकार के पास उक्त की रोकथाम हेतु कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

प्रश्नगत बीमारियों से प्रदेश में माह जुलाई, 2012 से दिनांक 18-01-2013 तक डायरिया से 104 की मृत्यु हुईं तथा जापानी इन्सेफ्लाईटिस से 23 मृत्यु हुईं, तीव्र ज्वर एवं बुखार मात्र लक्षण है।

जी हां।

जी हां। संक्रामक रोग डायरिया आदि की तथा जापानी इन्सेफ्लाइटिस की रोकथाम हेतु कार्य योजना बनायी गयी है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-

संक्रामक नियंत्रण कार्य योजना 2013

संक्रामक रोग के रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत निम्न कार्यवाही की जाती है :-

1-विभागीय एवं अंतविर्भागीय समन्वय समितियों का गठन।

2-रयूमर रजिस्टर।

3-रेपिड रिस्पान्स टीम का गठन।

4-चिकित्सा व्यवस्था एवं त्वरित कार्यवाही।

5-मलिन बस्तियों एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों का सर्विलेंस।

6-लैब परीक्षण।

7-संक्रामक रोगों के प्रसार की स्थिति में मुख्यालय पर दैनिक प्रारूप पर रिपोर्ट।

8-क्रांस रिफरेंस।

9-नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।

10-प्रदूषित खाद्य सामग्री की बिक्री पर रोक।

11-स्वास्थ्य शिक्षा।

12-परिवहन व्यवस्था।

13-व्यय आवश्यकता तथा माइक्रो प्लान।

14-कन्ट्रोल रूम की स्थापना।

जापानी इन्सेफ्लाइटिस की कार्य योजना 2013 के मुख्य बिन्दु :-

1-एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिंट्रोम (ए0ई0एस0)

- एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिंट्रोम (ए0ई0एस0) रोगी का लक्षणों की तीव्रता के आधार पर वर्गीकरण एवं उपचार।
- शुद्ध पेयजल की उपलब्धता

2-जापानी इन्सेफ्लाइटिस (जे0ई0)

- वाहक पर नियंत्रण।
- मच्छर के लार्वा पर नियंत्रण।
- वयस्क मच्छरों के नियंत्रण हेतु कीटनाशक छिड़काव एवं फॉगिंग।
- सुअर, मच्छर के सम्पर्क के रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय।
- मनुष्य, मच्छर के सम्पर्क को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय।
- टीकाकरण।
- सर्वेक्षण।

3-ए0ई0एस0/जे0ई0

- निदान एवं उपचार।
- सामु0/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आवश्यक उपकरण/औषधियों की उपलब्धता।
- प्रशिक्षण।
- पुनर्वासन।
- रिपोर्टिंग तथा अभिलेखन।

प्रश्न नहीं उठता।

116-श्री जाकिर अली-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद सोनभद्र के बभनी राबर्ट्सगंज में एल0 टी0 लाइन हाई वोल्टेज के जर्जर तारों को बदलवाये जाने की मांग

117-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के बभनी राबर्ट्सगंज में एल0टी0 लाइन के ऊपर हाई वोल्टेज के जर्जर तार टूट कर गिर जाने से हाई वोल्टेज आने से अब तक 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जर्जर तार को बदलवाते हुये उक्त मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद सोनभद्र के बभनी में एल0टी0 लाइन के ऊपर हाई बोल्टेज के जर्जर तार टूटकर गिरने के प्रकरण में अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि पिछले तीन वर्षों में कोई घटना घटित नहीं हुई है। फिर भी वस्तुस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दो अधिशासी अभियन्ताओं की समिति से जांच कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त समिति की जांच आख्या प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के मुर्धवा में विद्युत पोल से तार खींचकर स्थानीय लोगों के घरों तक विद्युत आपूर्ति की जानकारी

118-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के मुर्धवा में विद्युत पोल स्थापित होने के बावजूद उस पर तार न खींचे जाने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा घरों तक विद्युत आपूर्ति हेतु केबिल का प्रयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत पोलों पर तार खिंचवा कर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद सोनभद्र के मुर्धवा में पावर कारपोरेशन के नियमों के अनुसार विद्युत पोल से केबिल खींचकर स्थानीय लोगों के घरों तक सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। मुर्धवा में 15 नग कनेक्शन केबिल के द्वारा निर्गत किये गये हैं जिनकी बिलिंग हो रही है और सभी कनेक्शन लेजराईज हैं। स्थानीय लोगों द्वारा कोई शिकायत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में हो रहे वृक्षों के अवैध कटान को रोकने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

119-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के तहत आम (देशी, कलमी और तुकमी) नीम, महुआ, शाल, पीपल, बरगद (बड़) के पेड़ को काटने पर वर्ष 2010 तक रोक लगे होने के बावजूद आज भी इसे सोनभद्र में धड़ल्ले से काटा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत बिना पातन अनुज्ञा के वृक्षों का पातन होने पर सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 2012-13 में माह जनवरी, 2013 तक निजी भूमि पर प्रतिबन्धित वृक्षों के अवैध कटान के 05 मामले प्रकाश में आये। इन मामलों में विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के विद्युत उपकेन्द्रों के संविदा श्रमिकों की लाइन दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाये जाने की मांग

120-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विद्युत उपकेन्द्रों व विद्युत लाइनों के मेन्टीनेन्स के लिये रखे जाने वाले संविदा श्रमिकों की लाइन दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को रुपया 1.5 (डेढ़ लाख) लाख दी जाने वाली मुआवजा धनराशि को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के विद्युत उपकेन्द्रों व विद्युत लाइनों के मेन्टीनेन्स के लिए रखे जाने वाले संविदा श्रमिकों की लाइन दुर्घटना पर मृत्यु होने पर उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश दिनांक 03-08-2012 द्वारा अनुग्रह धनराशि रुपये 1.00 लाख के स्थान पर रुपये 1.50 लाख की धनराशि की गयी है। इसी प्रकार अनुमन्य धनराशि समय-समय पर पुनरीक्षित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के कोइली मोहान ताल में बरसात के दिनों में भरे पानी को निकालने की जानकारी

121-श्री गोरख पासवान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत हल्दी रामपुर, विकास खण्ड सीयर, जनपद बलिया के कोइली मोहान ताल में बरसात के दिनों में बाढ़ का पानी भर जाने से किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जल निकासी हेतु स्थापित कम क्षमता वाले वर्तमान में खराब पड़े पम्प की क्षमता बढ़ाते हुये नया पम्प लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। तुर्तीपार-श्रीनगर तटबंध के कि0मी0 6.60 पर तटबन्ध के पृष्ठ भाग में एकत्रित वर्षा के जल की निकासी हेतु एक रेगुलेटर (2x6.10 मीटर) निर्मित है। इस रेगलुटर से वर्षा के जल की निकासी घाघरा नदी में हो जाती है। बाढ़ अवधि में जब घाघरा नदी में जल स्तर की वृद्धि इस स्तर तक हो जाती है कि तटबन्ध के प्रोटेक्टेड साइड में नदी के पानी के जाने की आशंका उत्पन्न हो तो उस स्थिति में रेगुलेटर के गेट बन्द करने पड़ते हैं। इस अवधि में स्थानीय क्षेत्र में अतिवृष्टि होने पर तुर्तीपार-श्रीनगर तटबन्ध के उक्त रेगुलेटर के पृष्ठ भाग में जल जमाव से फसल न बर्बाद हो इसके लिए कोइली मोहान में 60 क्येसेक (6x10 क्यूसेक) क्षमता का एक पम्प गृह का निर्माण किया गया है जिसके माध्यम से तटबन्ध के सुरक्षित क्षेत्र में जमा हुए वर्षा के जल को घाघरा नदी में खारिज किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में फुंकने/खराब होने वाले ट्रांसफार्मरों को बदलवाये जाने की जानकारी

122-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर के फुंकने/खराब होने पर उसे बदलने हेतु स्टोर तक लाने-ले जाने का उत्तरदायित्व किसका है तथा स्टोर तक लाने-ले जाने का व्यय किसके द्वारा वहन किये जाने की नीति है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में फुंकने/खराब होने वाले विद्युत ट्रान्सफार्मर बदलने के लिये सरकार कोई समय-सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर जो निजी नलकूप के लिये लगा है, उसके बदलने हेतु स्टोर तक लाने-ले जाने की जिम्मेदारी उपभोक्ता/किसान की है तथा जो ग्रामों में किसी अन्य संयोजन जैसे पंखा, बत्ती, उद्योग इत्यादि हेतु लगाये गये हैं, उसके बदलने हेतु स्टोर तक ले जाने एवं ले आने की जिम्मेदारी विभाग की है।

ग्रामीण क्षेत्रों में फुंकने/खराब होने वाले विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने के लिये 72 घण्टे की समय-सीमा निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों सिंचाई हेतु निजी नलकूप ट्यूबवेल हेतु विद्युत कनेक्शन दिये जाने की योजना

123-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निजी ट्यूबवेल के लिये विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की सरकार की कोई विशेष योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई विशेष योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु सामान्य योजना के अन्तर्गत 7.5 हार्स पावर तक के नलकूप संयोजनों के प्राक्कलन राशि पर सरकार द्वारा 25 के0वी0ए0 परिवर्तक पर 3 संयोजनों के आधार पर रु0 68,000/-की छूट का प्रावधान है। इसमें किसानों द्वारा दिये गये आवेदन-पत्रों पर प्रथम आवत प्रथम पावत नीति के आधार पर क्रमानुसार संयोजन शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत दिये जाते हैं। 7.5 हार्स पावर से अधिक के संयोजन को प्रदान करने में परिवर्तक की लागत का समानुपातिक आधार पर अतिरिक्त राशि उपभोक्ता द्वारा वहन करनी होती है। योजना के अन्तर्गत 2012-13 में 20503 निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन के अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण

124-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युतीकरण से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण किये जाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन के विकास खण्ड-निघासन एवं रमियाबेहड़ में कितने ग्राम विद्युतीकरण से वंचित हैं ? क्या सरकार उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रदेश में विद्युतीकरण से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण किये जाने हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण प्रचलित है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 300 अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले समस्त अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण किया जाना है। इसके अतिरिक्त डा0 राममनोहर लोहिया समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों/मजरों में भी विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना है।

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन के 11 ग्राम तथा विकास खण्ड रमियाबेहड़ के तीन ग्राम अविद्युतीकृत है।

जी हां।

जनपद खीरी के ग्रामों/मजरों के विद्युतीकरण हेतु डी0पी0आर0 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (भारत सरकार की कार्यदायी संस्था) द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। विद्युतीकरण हेतु निविदा निस्तारण प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार द्वारा धन प्राप्त होने के उपरान्त उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत मार्च, 2015 तक कराना संभव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की बस्तियों के बीच में लगे ट्रांसफार्मरों व विद्युत लाइनों को हटाये जाने की मांग

125-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की बस्तियों के बीच में लगे ट्रान्सफार्मरों एवं घरों के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत लाइनों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिये उन्हें हटाये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित ट्रांसफार्मरों एवं लाइनों के नीचे क्षेत्रवासियों द्वारा अनधिकृत रूप से मकान/छप्पर आदि बना लिये जाते हैं। ऐसी स्थिति में लाइनों को हटाया जाना संभव नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी की राप्ती नदी से हो रही कटान को रोके जाने की मांग

126-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन के ग्राम मझरा पूरब एवं दुमेड़ा सहित सैकड़ों लोगों के घर, फसल एवं रेलवे स्टेशन वाला रास्ता राप्ती नदी के कटाव से प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कटान को रोकने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

इसका तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। आवश्यकता होने एवं परियोजना साध्य पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में वनरोज (नीलगाय) के आतंक से प्रभावित कृषकों की समस्या का समाधान

127-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में वनरोज (नील गाय) द्वारा फसलों को नष्ट करने से किसानों को भारी आर्थिक क्षति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें पकड़वाने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वनरोजों (नीलगायों) से कृषि फसलों को क्षति पहुंचाये जाने की यदा-कदा घटनायें प्रकाश में आती रहती हैं।

वनरोजों को पकड़वाना व्यवहारिक नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

वनरोजों से कृषि फसलों को नष्ट करने से बचाने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथा संशोधित धारा-4 (1) के तहत शासनादेश संख्या-736/14-4-94-854/92, दिनांक 09-3-1994 एवं शासनादेश संख्या-2194/14-4-2001-854/92, दिनांक 28-9-2001 तथा शासनादेश संख्या-1464/14-4-2008-854/92, दिनांक 31-7-2008 द्वारा समस्त जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी के स्तर से लेकर मुख्य वन संरक्षक स्तर तक तथा राजस्व विभाग के समस्त तहसीलदारों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। वनरोजों के आतंक से प्रभावित कृषक अपने क्षेत्र के उक्त अधिकारियों से सम्पर्क कर उनकी अधिकारी सीमा के अन्तर्गत समस्या का समाधान कर सकते हैं।

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सुमेरपुर के कतिपय ग्रामों के मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

128-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सुमेरपुर में गुढई से बैजेमऊ तथा बैजेमऊ से गढ़ा होते हुये कुटी डेरा तक मार्ग निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-5/009407 दिनांक 19-6-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम बुढ़ई, बैजेमऊ, गढ़ा तथा ग्राम कुटी का डेरा पूर्व से ही एकल लेपित मार्ग से जुड़े हैं।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर तैनाती की मांग

129-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत आने वाले पी0एच0सी, सी0एच0सी0 में महिला चिकित्सकों एवं महिला फार्मेसिस्टों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर महिला चिकित्सकों एवं महिला फार्मासिस्टों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरी-चौरा में महिला चिकित्साधिकारी का 01 पद सृजित है जिसके सापेक्ष महिला चिकित्सक संविदा पर तैनात है। इसी प्रकार पी0एच0सी0 पर आयुष महिला चिकित्साधिकारी, एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत तैनात हैं। पैरामेडिकल (फार्मासिस्ट) संवर्ग में महिला संवर्ग अलग से नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में वन विभाग द्वारा नये लगाये गये पेड़ एवं उन पर व्यय

130-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत वर्ष 2011-2012 में कितनी धनराशि वन विभाग द्वारा नये पेड़ों के लगाये जाने पर खर्च की गयी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त क्षेत्र में बगैर नये पेड़ लगाये ही सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद गोरखपुर के चौरी-चौरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में गोरखपुर वन प्रभाग द्वारा 15.60 हेक्टेयर ब्लाक/पटरी वृक्षारोपण एवं 90 ब्रिक गार्ड वृक्षारोपण किया गया। उक्त वृक्षारोपण पर वर्ष 2011-12 में कुल रु0 6.39 लाख व्यय किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के शमसाबाद मार्ग की क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत कराये जाने की मांग

131-श्री छोटेलाल वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा-शमसाबाद मार्ग से ग्राम वांगुरी मार्ग के मध्य नहर की पुलिया टूट जाने से यातायात बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद आगरा शमसाबाद मार्ग के मध्य रजवाहा टर्मिनल के कि0मी0 40.600 पर नहर की पुलिया क्षतिग्रस्त है एवं यातायात आंशिक रूप से बाधित है।

जी नहीं, अपितु क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत किये जाने की कार्यवाही प्रगति में है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों व स्टाफ की तैनाती

132-श्री दलवीर सिंह-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी0एच0सी0) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी0एच0सी0) डाक्टर विहीन हैं तथा जिला अस्पताल में कितने डाक्टरों की कमी है ? क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर समुचित स्टाफ की तैनाती करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद अलीगढ़ में 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं, सभी पर चिकित्सक तैनात हैं। कोई भी स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक विहीन नहीं है।

जिला अस्पताल में चिकित्सकों के 29 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष 22 चिकित्सकों की तैनाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के ग्राम मोतियारी के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु बजट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

133-श्री तसलीम-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2012 के 1ले बुधवार के श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न संख्या-188 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय संसाधन एवं बजट उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के कारण।

134-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सहारनपुर में रजवाहा सिजूड की जलापूर्ति हेतु गंगा-यमुना लिंक चैनल पर रेगुलेटर व फीडर चैनल के निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

135-श्री सुरेश राणा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में रजवाहा सिजूड की जलापूर्ति हेतु गंगा-यमुना लिंक चैनल पर रेगुलेटर व फीडर चैनल के निर्माण की परियोजना लागत रु0 136.27 लाख रु0 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति किये जाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या-अ0शा0 पत्रांक-112/अनिम-2/यू-4/राज0 सिजूड, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-2 सिंचाई, एनेक्सी, लखनऊ का पत्र दिनांक 5 मार्च, 2010 विशेष सचिव, सिंचाई-4 उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

परियोजना विभाग द्वारा साध्य नहीं पायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शामली के थानाभवन ग्राम कैड़ी में पाल बस्ती के जर्जर तारों का बदला जाना

136-श्री सुरेश राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जर्जर तारों को बदलने की नीति के अन्तर्गत जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र के कितने जर्जर तारों को बदला गया है ? क्या जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र में ग्राम कैड़ी में पाल बस्ती के जर्जर विद्युत तारों को बदलने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र में 145 कि0मी0 जर्जर तार बदला गया है।

ग्राम कैडी के पाल बस्ती का वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है, जर्जर तार बदलने का कार्य प्रगति पर है एवं इस वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली में मुजफ्फरनगर थानाभवन रोड से नांगल तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

137-श्री सुरेश राणा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद शामली थानाभवन विधान सभा क्षेत्र में मुजफ्फरनगर थानाभवन रोड से नांगल तक क्षतिग्रस्त जिला मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। प्रदेश में नवीनीकरण का कार्य चक्रानुसार प्रमुख जिला मार्गों पर 4 वर्ष एवं अन्य जिला मार्ग पर ग्रामीण भाग में 5 वर्ष में एवं शहरी भाग में 04 वर्ष में किये जाने की नीति है तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य यातायात घनत्व एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर सुमेरपुर के ग्राम पत्योरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन्द रहने का कथित प्रकरण

138-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सुमेरपुर के ग्राम पत्योरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर एवं अन्य स्टाफ के उपस्थित न रहने के कारण स्वास्थ्य केन्द्र बन्द रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच

कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए डाक्टर एवं अन्य स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर की नहरों एवं माइनरों में टेल तक पानी नहीं पहुंचने का कथित प्रकरण

139-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर की नहरों एवं माइनरों तथा रजवाहों में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त नहरों आदि की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्तर-1 के अनुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हमीरपुर के मनकी घाट पर यमुना में पुल निर्माण के अवशेष कार्य को पूर्ण कराये जाने की जानकारी

140-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर के मनकी घाट पर सेतु निगम द्वारा यमुना में पुल निर्माण का कार्य पिछले 6-7 वर्षों से चल रहा है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त पुल निर्माण में वहीं का रेता निकालकर प्रयोग किया जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पुल का निर्माण समयबद्ध सीमा में पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सेतु का अवशेष निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के लोनी में पालीटेक्निक कालेज खोले जाने की मांग

141-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र में सरकार पालीटेक्निक कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आलोक कुमार शाक्य-

जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र में राजकीय पालीटेक्निक खोले जाने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

जनपद गाजियाबाद में एक राजकीय पालीटेक्निक एवं 11 निजी क्षेत्र के पालीटेक्निक पूर्व से ही संचालित हैं।

जनपद गाजियाबाद के लोनी को विद्युत कटौती से मुक्त करने की मांग

142-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुल कितने जिलों को विद्युत कटौती से मुक्त रखा गया है ? क्या सरकार जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र को भी विद्युत कटौती से मुक्त रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के जनपद आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज एवं गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), रायबरेली नगर, अमेठी नगर, रामपुर नगर, सम्भल नगर तथा लोक सभा क्षेत्र लखनऊ को विद्युत कटौती से मुक्त रखा गया है।

जी नहीं।

वर्तमान में विद्युत की मांग से सापेक्ष उपलब्धता में कमी के दृष्टिगत प्रश्नगत क्षेत्र को विद्युत कटौती से मुक्त किया जाना संभव नहीं है।

जनपद लखनऊ स्थित बलरामपुर चिकित्सालय के वार्डों व भवनों का रिनोवेशन/मरम्मत कराये जाने का कथित प्रकरण

143-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित बलरामपुर चिकित्सालय के कई वार्डों तथा कई विभागों के भवनों का रिनोवेशन पिछले कई सालों से न होने के कारण उक्त भवन जर्जर हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का रिनोवेशन/मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यकतानुसार रिनोवेशन/मरम्मत प्रतिवर्ष करायी जा रही है।

जनपद सोनभद्र के विढ़मगंज थाना क्षेत्र हाई वोल्टेज बिजली से झुलसे हुए लोगों को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

144-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विढ़मगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बुटवेडवा के धरती डोलवा में माह मई, 2012 में एच0टी0 लाइन में हाई वोल्टेज बिजली से यहां के लोगों के घरों के इलेक्ट्रानिक उपकरण फुंक जाने के साथ-साथ कुल 12 लोग बुरी तरह से झुलस गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाने के साथ-साथ गंभीर रूप से झुलसे हुये लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय के अभिलेखों में ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं है। फिर भी वस्तुस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दो अधिशासी अभियन्ताओं की एक समिति से जांच कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त समिति की जांच आख्या प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विद्युत उपकेन्द्रों के संविदा कर्मियों की मृत्यु होने पर आश्रितों को मुआवजे का भुगतान किये जाने की मांग

145-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विद्युत उपकेन्द्रों तथा विद्युत लाइनों के मेन्टीनेन्स के लिए रखे जाने वाले संविदा कर्मियों की लाइन दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाने पर मुआवजे की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित ठेकेदार से वसूली करके दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार भी उतनी ही धनराशि का भुगतान मुआवजे के रूप में संविदा कर्मी के आश्रित को करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

वाह्य सेवा प्रदाता द्वारा उपकेन्द्रों/लाइनों के अनुरक्षण आदि के कार्य पर रखे जाने वाले संविदाकार के श्रमिकों की कार्य करते समय घातक विद्युत दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति किये जाने का दायित्व सम्बन्धित वाह्य सेवा प्रदाता एजेन्सी का होता है।

जनपद सोनभद्र में वाराणसी शक्तिनगर से हाथी नाला तक के मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने की मांग

146-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में वाराणसी शक्ति नगर मुख्य मार्ग, मारकुण्डी होते हुए हाथी नाला होकर एन0 एच0-75 ई रांची रीवा मार्ग पर हमेशा जाम

लगा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जाम से निजात दिलाने के लिए उक्त सड़क का चौड़ीकरण अथवा बाईपास रोड बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग (राज्य राजमार्ग संख्या-5ए) हाथीनाला तक के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के कार्य का अनुबन्ध उ0 प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण तथा निजी विकासकर्ता मेसर्स ए0सी0पी0 टालवेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ के मध्य गठित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में काली नदी पर पुल निर्माण कराये जाने की मांग

174-श्री दलवीर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में काली नदी पर ग्राम-कल्याणपुर व ग्राम-बरानदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-04-2012 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ की आवासीय योजना रतन खण्ड (शारदानगर योजना) में बिजली व्यवस्था की देख-रेख का कथित प्रकरण

148-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की आवासीय योजना रतन खण्ड (शारदानगर योजना) में बिजली व्यवस्था की देखरेख का कार्य ठेकेदारी प्रथा से कराये जाने के कारण सुचारू रूप से नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ठेकदारी व्यवस्था को समाप्त करते हुए विकास प्राधिकरण को वापस उक्त कार्य दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

लेसा क्षेत्रान्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण मण्डल तृतीय के अधीनस्थ आने वाले रतन खण्ड (शारदा नगर योजना) के विद्युत व्यवस्था की देख-रेख का कार्य आवश्यकतानुसार नियमित कर्मचारियों की कमी के कारण निगमीय व्यवस्थानुसार संविदा एवं विभागीय कर्मचारियों द्वारा कराया जा रहा है इस क्षेत्र की विद्युत लाइनों एवं परिवर्तकों के परिचालन एवं अनुरक्षण कार्य हेतु 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रजनी खण्ड पर प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक चार गैंग (प्रत्येक गैंग में कुल तीन कर्मी) नियमित कार्यरत रहते हैं। क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं है। रतन खण्ड के कुल चारों पार्ट में पार्ट 'ए', पार्ट 'बी0' एवं पार्ट 'डी0' की विद्युत आपूर्ति रजनी खण्ड विद्युत उपकेन्द्र से निर्गत 11 के0वी0 रतन खण्ड फीडर द्वारा की जा रही है तथा पार्ट 'सी0' के वाह्य

विद्युतीकरण का कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्ण न कराये जाने के कारण 11 के0वी0 रतन खण्ड फीडर से ऊर्जीकृत नहीं किया जा सका है। वर्तमान में इस क्षेत्र की आपूर्ति आशियाना उपकेन्द्र से निर्गत 11 के0वी0 किला फीडर से ऊर्जीकृत कर की जा रही है।

रतन खण्ड (शारदा नगर योजना) की विद्युत आपूर्ति पूर्णतया सुचारु रूप से की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

149-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-70 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया एवं मऊ की सीमा पर स्थित हाहा नाला पर पुल निर्माण कराये जाने की मांग

150-श्री गोरख पासवान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दोय जो जनपद मऊ की सीमा पर स्थित है व मऊ बलिया की सीमा पर हाहा नाला है, जो दोनों जनपदों को जोड़ता है ? क्या सरकार जनहित में उक्त हाहा नाला पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लगभग 2.00 कि0मी0 दूरी पर पहले से ही एक पुल हाहा नाला पर स्थित है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा में स्थित विद्युत फीडरों से विद्युत आपूर्ति का कथित प्रकरण

151-श्री गोरख पासवान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड जनपद बलिया के अन्तर्गत कितने विद्युत फीडर विद्युत सप्लाई हेतु स्थापित हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त फीडरों से सप्लाई समयबद्ध तरीके से नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार समयबद्ध तरीके से विद्युत सप्लाई कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड जनपद बलिया के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र अवाएं नगरा, पशुहारी एवं रजईपुर से कुल 17 नग फीडर विद्युत आपूर्ति हेतु स्थापित है।

विद्युत आपूर्ति निर्धारित शिड्यूल के अनुसार की जाती है। स्थानीय व्यवधान एवं राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा के दृष्टिगत कभी-कभी विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी के इटौवा से पिपरी अजीज मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

152-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के इटौवा से गूजरपुर सुन्दरपुर मार्ग व मैगलगंज हाईवे मार्ग से गुरूदेव खेड़ा व पिपरी अजीज मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के ग्राम गुरुदेवखेड़ा, पिपरी, अजीज, इटौआ व सुन्दरपुर पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़े हैं। मजरा गूजरपुर खड़न्जा मार्ग से जुड़ा है। मजरा गूजरपुर की आबादी 500 से कम होने के कारण सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना शासन की प्राथमिकता में नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी बहराइच मार्ग हाई-वे ईसानगर तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने की मांग

153-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-ईसानगर में लखीमपुर-बहराइच मार्ग हाईवे से बसढ़िया खमरिया ऐरा शुगर मिल होते हुए सरैया से नौरगपुर वाया रायपुर-ईसानगर बाईपास तक पहले से प्रस्तावित मार्ग का चौड़ीकरण व हाटमिक्स प्लान्ट से सड़क का नवनिर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर में लखीमपुर-बहराइच मार्ग से बसढ़िया-खुमरिया-ईसानगर लिकिंग ऐरा शुगर मिल होते हुए सरैया से नौरंगपुर वाया रायपुर-ईसानगर बाईपास तक का मार्ग अन्य जिला मार्ग की श्रेणी का है। वर्तमान यातायात के अनुसार इस मार्ग के चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं है।

लखीमपुर खीरी में शारदा नदी से हो रही कटान को रोकने हेतु तकनीकी परीक्षण

154-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी से हो रहे प्रतिवर्ष भीषण कटान को रोकने हेतु सरकार समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। इसका तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है आवश्यकता होने पर तथा परियोजना साध्य पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा धौरहरा में स्थित ऐतिहासिक स्थल राम बट्टी को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग

155-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा धौरहरा में स्थित ऐतिहासिक स्थल रामबट्टी में श्री तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित रामायण की प्रतियां मौजूद हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थल को पर्यटन स्थल घोषित कर सौन्दर्यीकरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा धौरहरा में स्थित ऐतिहासिक स्थल राम बट्टी में श्री तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित रामायण की प्रतियां मौजूद नहीं हैं।

जनपद लखीमपुर खीरी में बाईपास बनाने का प्रक्रियाधीन निर्माण कार्य

156-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी में मुख्यालय पर बन रहे ओवर ब्रिज व मार्केट में रोडवेज बस अड्डा के कारण मेन मार्केट पर कई-कई घण्टे जाम लगे रहने से दुर्घटनाग्रस्त मरीज तथा गम्भीर रूप से बीमार मरीजों को जाम के कारण कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां बाईपास बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

लखीमपुर रजवाहा बाईपास बनाने का कार्य शासनादेश संख्या-166 (1)/23-11-2012, दिनांक 12-02-2013 द्वारा स्वीकृत है। निर्माण कार्य प्रक्रिया में है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय ग्राम सभा कुण्डा में चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने की मांग

157-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुण्डा कला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने से क्षेत्र की जनता को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में एक चिकित्सालय बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

ग्राम सभा कुण्डा कला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नियमताबाद के अन्तर्गत आता है। ग्राम पंचायत के निवासियों को 03 किमी0 दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहजोर एवं 08-10 कि0मी0 की दूरी पर लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय, रामनगर, वाराणसी से स्वास्थ्य सुविधायें मिल रही हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि स्वास्थ्य सुविधायें मिल रही हैं।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के कतिपय ग्रामों में विद्युत आपूर्ति

158-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला के अन्तर्गत बड़हलगंज, अहिरौली, गोला, मंझगांवा, डेरवा, चैनपुर, धुरियापार, चीनी मिल पकड़ी फीडर पर विद्युत आपूर्ति समुचित एवं पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व की भांति उपरोक्त फीडर्स पर दो शिफ्टों में दिन में 10 बजे से 4 बजे तक तथा रात्रि में 10 बजे से प्रातः तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

गोरखपुर जनपद की तहसील गोला के अन्तर्गत बड़हलगंज, अहिरौली, गोला, मंझगांवा, डेरवा, चैनपुर, धुरियापार, चीनी मिल पकड़ी फीडर पर ग्रामीण रोस्टर के अनुसार 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है। उक्त के सापेक्ष गत दिनांक लगभग 08 घण्टे 40 मिनट की विद्युत आपूर्ति की गयी है।

वर्तमान में उक्त फीडर पर प्रतिदिन दिन में 12.00 बजे से सायंकाल 4.00 बजे तक तथा रात्रि में 10.00 बजे से सुबह 4.00 बजे तक विद्युत की आपूर्ति आदेशित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के ग्राम डेहरीभार में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने की मांग

159-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला के अन्तर्गत ग्राम डेहरीभार में गोरखपुर परिक्षेत्र एवं आजमगढ़-बस्ती परिक्षेत्र के मध्य विद्युत सम्बन्धी समस्या के निदान हेतु 220 के0वी0ए0 का विद्युत उप केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव स्टीमेट सहित विभाग के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त 220 के0वी0ए0 का विद्युत उप केन्द्र स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

इस समय गोरखपुर जनपद में 2 नग 220 के0वी0 उपकेन्द्र यथा मोती राम अड्डा तथा बरहुआं स्थापित है। 220 के0वी0 उपकेन्द्र बरहुआं द्वारा गोला तहसील गोरखपुर जनपद को 132 के0वी0 उपकेन्द्र कौड़ीराम के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जाती है तथा वर्तमान में 132 के0वी0 उपकेन्द्र कौड़ीराम अतिभारित नहीं है। इस क्षेत्र में वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत किसी 220 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउण्ड मशीन स्थापित करने का प्रस्ताव

160-श्री उमाशंकर-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अल्ट्रासाउण्ड व एक्सरे मशीनें उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड एवं एक्सरे मशीनें उपलब्ध कराने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

प्रदेश में वर्तमान समय में 773 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं जिनमें 377 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे मशीन स्थापित है। शेष 396 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे मशीन उपलब्ध नहीं है एवं अल्ट्रासाउण्ड 751 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध नहीं है। पूर्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्थापना के मानक के अनुसार अल्ट्रासाउण्ड मशीन लगाये जाने की व्यवस्था नहीं थी। जी हां। वर्ष 2013-14 की पी0आई0पी0 में 100 एक्स-रे मशीन एवं 100 कलर अल्ट्रासाउण्ड मशीन स्थापित/उपलब्ध कराने का प्रस्ताव राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रस्तुत किया जा चुका है। इन चिकित्सालयों में चरणबद्ध रूप से वित्तीय एवं मानव संसाधन की उपलब्धता के आधार पर उक्त उपकरण स्थापित किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव की जानकारी

161-श्री उमाशंकर-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने तहसील मुख्यालय व नगर पालिका परिषद हैं जहां पर महिला चिकित्सालय की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी तहसीलों/नगर पालिका परिषद मुख्यालयों पर महिला चिकित्सालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने/स्थापित किये जाने के मानक है। वर्तमान में प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का मानक है, जहां तक एक महिला चिकित्सक का पद सृजित है। वर्तमान में कोई तहसील मुख्यालय ऐसा नहीं है। जहां महिला चिकित्सक की व्यवस्था/पद सृजित न हो।

जी नहीं। वर्ष 2012-13 में 12 नग 50 शैय्यायुक्त मैटरनिटी विंग एवं 78 नग 30 शैय्यायुक्त महिला चिकित्सालय स्थापित किये जा रहे हैं, जिसमें से कुछ तहसील मुख्यालय/ नगरपालिका परिषद् में भी अवस्थित है एवं वर्ष 2013-14 की पी0आई0पी0 में 30 नग 50 शैय्या एवं 50 नगर 30 शैय्यायुक्त (मैटरनिटी विंग) का प्रस्ताव किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थित प्रयोगशाला के रिक्त सहायकों के पदों पर तैनाती का मामला

162-श्री उमाशंकर-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रिक्त प्रयोगशाला सहायकों के पदों पर सरकार नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-184 (एस0एस0)/2012 धर्मेन्द्र कुमार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक

25-9-2012 के समादर में प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलित है जो मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के निर्णय दिनांक 25-9-2012 के विरुद्ध दाखिल विशेष अपील संख्या-812/2012 उत्तर प्रदेश व अन्य बनाम धर्मेन्द्र कुमार व अन्य में पारित निर्णय के अधीन होंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के ग्रामीण विद्युत वितरण खण्डों के खराब/जले ट्रान्सफार्मरों का बदला जाना

163-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ के ग्रामीण विद्युत वितरण खण्ड के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में वर्तमान में कुल कितने ट्रान्सफारमर खराब हैं ? क्या सरकार इन ट्रान्सफारमरों को शीघ्र बदलवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ट्रान्सफारमर खराब होने के कारण किसानों का विद्युत बिल माफ किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद अलीगढ़ के ग्रामीण विद्युत वितरण खण्डों के अन्तर्गत वर्तमान में मात्र 13 नग खराब परिवर्तक बदलने हेतु शेष हैं।

जी हां।

उपरोक्त सभी खराब ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया में है, 3 दिन में बदल दिये जायेंगे।

परिवर्तक के क्षतिग्रस्त होने के उपरान्त एक माह के बाद में न बदलने तथा उक्त उपभोक्ता पर कोई बिल बकाया न होने की दशा में विद्युत बिल माफ करने की व्यवस्था है।

उपभोक्ता द्वारा आवेदन के उपरान्त 15 दिन में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ की सरकारी सेवा में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस किये जाने का कथित प्रकरण

164-श्री दलवीर सिंह-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ में ऐसे कितने चिकित्सक हैं, जो सरकारी सेवा में रहते हुये प्रतिबन्ध के बाबजूद भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ? क्या सरकार उक्त चिकित्सकों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद अलीगढ़ में विभाग में तैनात चिकित्सकों में से किसी भी चिकित्सक द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस किये जाने की सूचना नहीं है और किसी चिकित्सक के विरुद्ध प्राइवेट प्रैक्टिस करने की शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन में चीनी मिल लगवाये जाने की मांग

165-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निघासन विधान सभा क्षेत्र, जनपद लखीमपुर खीरी में गन्ने की अत्याधिक फसल होती है तथा उक्त क्षेत्र में स्थापित एक मात्र चीनी मिल द्वारा गन्ने की पेराई सुगमता से नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नयी चीनी मिल लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

निघासन विधान सभा क्षेत्र, जनपद लखीमपुर खीरी के कुल 130 राजस्व ग्राम एवं सम्बद्ध मजरों में कुल 36,474 है0 गन्ना फसल का आच्छादन है जिसमें कुल 225.82 लाख कु0 गन्ना उत्पादित होने का अनुमान है। गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के सुरक्षण आदेशानुसार निघासन विधान सभा क्षेत्र के गन्ने की पेराई सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल बेलरायॉ के अतिरिक्त निजी क्षेत्र की पलिया, गुलरिया, ऐरा तथा खम्भारखेड़ा द्वारा भी की जाती है तथा क्षेत्र का समस्त गन्ना पेरने के उपरान्त गन्ना आयुक्त की अनुमति प्राप्त कर चीनी मिलें पेराई कार्य का समापन करती हैं।

वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना किये जाने की मांग

166-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अलीगढ़ में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है ? यदि नहीं तो क्या सरकार ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्राधिकरण के पास वर्तमान में भूमि उपलब्ध न होने के कारण ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

167-श्री दलवीर सिंह-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के गरीब बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

168-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में वर्तमान में संचालित (निजी क्षेत्र में) मल्टी यूटीलिटी हास्पिटलों में गरीब एवं गम्भीर रूप से बीमार रोगियों को रियायती दरों अथवा मुफ्त में इलाज की सुविधा प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

1-बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को सभी जिला चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा उपलब्ध है।

2-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति एवं उनके परिवार के पांच सदस्यों के लिए फ्लोटर के आधार पर रु0 30,000/- तक की सूचीबद्ध सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों में भर्ती होकर इलाज कराने की सुविधा समस्त जनपदों में उपलब्ध है।

3-बी0पी0एल0 कार्ड धारकों एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित संस्थानों में राज्य आरोग्य निधि (मुख्य मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष) के अन्तर्गत गम्भीर रोगों के चिकित्सा उपचार की पूर्ण सुविधा उपलब्ध है।

जिला गोरखपुर के चौरी-चौरा के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सालयों में चिकित्सक व स्टाफ की तैनाती की जानकारी

169-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत आने वाली पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 में मानक के अनुरूप डाक्टर एवं पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पी0एच0सी0, तथा सी0एच0सी0 में मानक के अनुरूप चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरी-चौरा में पैथालॉजिस्ट एवं दन्त चिकित्सक को छोड़कर शेष पद भरे हुए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदार नगर एवं ब्रह्मपुर तथा नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डुमरीखास में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के पद भरे हुए हैं। नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलवाबाबू, नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिशुनपुरा एवं नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरही में ए0एन0एम0 को छोड़कर चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के पद भरे हुए हैं। नव सृजित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरही में पदों का सृजन हो गया है। उक्त पदों पर चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कथित प्रकरण

170-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी है तथा उक्त विद्युतीकरण योजना को कब तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में कुल रु0 30268.19 लाख की डी0पी0आर0 स्वीकृत की गयी है। इस विद्युतीकरण योजना को पूरा करने का लक्ष्य कार्यदायी संस्था के साथ अनुबन्ध होने की तिथि से 2 (दो) वर्ष के भीतर है। निविदा निस्तारण प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार से धन प्राप्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण का कार्य कराना संभव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के गोला में उरूवा बाजार में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक व स्टाफ के तैनाती की मांग

171-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला के उरूवा बाजार में निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में निर्धारित मानक के अनुसार चिकित्सक, स्टाफ एवं दवा की उपलब्धता सरकार सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

उरूवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्मित हो जाने पर चिकित्सकों एवं स्टाफ की आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार तैनाती तथा दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में गोला के रसूलपुर माफी में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मांग

172-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की गोला तहसील के अन्तर्गत रसूलपुर द्वाबा क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण वहां के नागरिकों को इलाज के लिये काफी दूर नदी पार कर आना-जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रसूलपुर ग्राम सभा में स्वास्थ्य केन्द्र खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

रसूलपुर माफी की कुल आबादी 2137 है। रसूलपुर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उरूवा की दूरी मात्र 05 कि0मी0 है जहां से चिकित्सा सुविधायें मिल रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उरूवा (अराव जगदीशपुर) निर्माणाधीन है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की गोला के बेसहनी नाले पर पुल निर्माण कराये जाने की जानकारी

173-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाोरखपुर जनपद की गोला तहसील के अन्तर्गत बेसहनी नाले पर स्वीकृत पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

बेसहनी नाले पर स्वीकृत सेतु की डिजाइन मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर से करायी जा रही है। प्रश्नगत सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

174-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

[प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद अम्बेडकरनगर के खतनीपुर गांव में पुलिया निर्माण कराये जाने की जानकारी

175-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आलापुर, जनपद अम्बेडकरनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों खतनीपुर गांव एवं नुरद्दीनपुर गांव में पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र माह अगस्त, 2012 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्न में उल्लिखित स्थल का निरीक्षण/सर्वेक्षण का कार्य कराया जा चुका है, जहांगीरगंज राजवाहा (खतनीपुर गांव के पास) के कि0मी0 36.500 पर शारदा सहायक क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना (वर्तमान में चालू) का पुनरीक्षण किया जा रहा है, में पुलिया का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना की स्वीकृति/धनावंटन के उपरान्त पुलिया का निर्माण करा दिया जाएगा।

नुरद्दीनपुर गांव के पूर्व में कोई विभागीय नाला नहीं है। अतः पुलिया का निर्माण साध्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के आलापुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों में डबल पुलिया निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

176-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों में डबल पुलिया निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-8-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नकर्ता का उल्लिखित पत्र नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ को भेजा गया है।

उपरोक्तानुसार।

177-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-71 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में निर्मित कोलाघाट पुल के नीचे ठोकरों का निर्माण कराये जाने की मांग

178-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में निर्मित कोलाघाट पुल के नीचे दोनों तरफ कटान रोकने हेतु ठोकरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त ठोकरों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में निर्मित कोलाघाट पुल के पीयर एवं एवेटमेंट के नीचे दोनों तरफ कटान नहीं हो रहा है। पुल के पीयर व एवेटमेंट सुरक्षित हैं। अतः पुल के नीचे ठोकरों के निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन में शारदा नदी की कटान से ग्राम बल्लीपुर को बचाने का कथित प्रकरण

179-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन में शारदा नदी की कटान से ग्राम बल्लीपुर से महादेवा तक तथा खमरिया-वैलहा तक का अस्तित्व खतरे में है ? यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र को बाढ़ व कटान से बचाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन में शारदा नदी की कटान से ग्राम बल्लीपुर के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है।

ग्राम महादेवा शारदा नदी के किनारे पर ग्राम खमरिया से वैलहा के मध्य स्थित था जो कई वर्ष पूर्व सुरक्षित स्थान पर बसाया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद में जैन ओवरसीज चीनी मिल का कथित प्रकरण

180-श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के गांव सावली में स्थापित जैन ओवरसीज चीनी मिल जो कृषि भूमि पर स्थापित है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि का भू-उपयोग बदलवाकर औद्योगिक कराया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

तहसील सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर के ग्राम सांवली में जैन ओवरसीज चीनी मिल के नाम से कोई मिल स्थापित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के नगर से अट्टा तक अधिग्रहीत भूमि पर मुआवजे की दरें एक समान देने की मांग

181-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के गाजियाबाद नगर से अट्टा तक एन0एच0-91 वाया खुर्जा पर अधिग्रहीत भूमि पर मुआवजे की दरें क्या भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न हैं ? क्या सरकार मुआवजे की दरें समान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

एन0एच0-91 पर अट्टा नाम से कोई स्थान ज्ञात नहीं हुआ है। अलग-अलग स्थानों पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित सक्रिल रेट में भिन्नता होने से देय प्रतिकर में भिन्नता हो जाती है।

जी नहीं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की योजनाओं में प्रतिकर का निर्धारण कलेक्टर द्वारा स्थान विशेष हेतु निर्धारित सक्रिल रेट के आधार पर किया जाता है।

जनपद कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनी का किराया श्रम विभाग की कालोनियों के बराबर करने की मांग

182-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गोविन्दनगर लेबर कालोनी (रिफ्यूजी कालोनी) का पूर्व में निर्धारित किराया रु0 13 से बढ़ाकर रु0 433 कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कालोनी का किराया श्रम विभाग की अन्य लेबर कालोनियों के बराबर करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनी सभी वर्गों के लिये बनायी गयी थी जबकि श्रम विभाग द्वारा निर्मित कालोनियां श्रमिकों के लिये बनायी गयी थीं। इसलिये प्राधिकरण की कालोनियों का किराया लेबर कालोनी के बराबर नहीं किया जा सकता है।

श्रम विभाग द्वारा बनायी गयी लेबर कालोनियों का आवंटन श्रम विभाग के नियमों के अन्तर्गत किया जाता है जबकि प्राधिकरण की कालोनियों का आवंटन प्राधिकरण के नियमों एवं शर्तों के अन्तर्गत किया गया है।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय के ग्राम सभा गोधना में मा0 कांशीराम आवास के जल निकासी हेतु नाला निर्माण कराये जाने की मांग

183-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा गोधना में मा0 कांशीराम आवास के जल निकासी की एक बड़ी गम्भीर समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार जल निकासी हेतु नाला बनाकर महेवा नाले में मिलाकर समस्या का निदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा गोधना में मा0 कांशीराम आवास के जल निकासी की समस्या है।

कच्चे ड्रेन के माध्यम से महेवां नाले में जल निकासी की व्यवस्था है। उक्त आवासीय योजना लो लाइंग क्षेत्र में निर्मित होने के कारण पानी का निकास धीरे-धीरे ही हो पाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय के कठौरी एवं बरहुली को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने की मांग

184-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कठौरी एवं बरहुली को जोड़ने के लिए सम्पर्क मार्ग मुराहू बिन्द के खेत से राजेन्द्र पासवान के घर तक कच्चा अर्द्धनिर्मित मार्ग है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण कराते हुए पूर्ण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम कठौरी एवं बरहुली एकल लेपित मार्ग से जुड़े हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में स्थापित स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों एवं महापुरुषों की प्रतिमाओं के अनुरक्षण, संरक्षण आदि की नीति

185-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों एवं महापुरुषों की प्रतिमाओं के अनुरक्षण, संरक्षण तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अलिखेश यादव-

जी हां।

उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा राज्य संरक्षण में लिये गये ऐतिहासिक स्मारकों एवं स्थलों का अनुरक्षण एवं परिरक्षण, ''उ0 प्र0 प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956'' के अन्तर्गत किया जा रहा है।

लखनऊ एवं गौतमबुद्ध नगर में विगत वर्षों में निर्मित स्मारकों, महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनुरक्षण स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, लखनऊ द्वारा किया जा रहा है। इन स्मारकों, स्थलों एवं महापुरुषों की प्रतिमाओं की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी द्वारा की जा रही है। प्रदेश के अन्य स्थलों पर स्थापित महापुरुषों की मूर्तियों की सुरक्षा स्थानीय पुलिस बल द्वारा सुनिश्चित की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों एवं पशुपालकों के विद्युत करेन्ट से मरने वाले पशुओं के सापेक्ष मिलने वाली धनराशि को बढ़ाये जाने की मांग

186-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों एवं पशुपालकों के विद्युत करेन्ट से मरने वाले पशुओं गाय, भैंस, ऊंट, बैल आदि के मुआवजे की धनराशि वास्तविक कीमत के सापेक्ष अत्यधिक कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार पशुपालकों को विभाग की लापरवाही से पशुओं के मरने पर मिलने वाली क्षतिपूर्ति की उक्त धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत करेन्ट से पशुओं की घातक विद्युत दुर्घटना होने पर राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अधिकतम रुपये 3000/-की अनुग्रह धनराशि का प्राविधान वर्ष 1992 में किया गया था। उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश दिनांक 19-6-2008 द्वारा अनुग्रह धनराशि बढ़ाकर रुपये 5000/- कर दी गयी है।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय पुरैनी से धोबिया का पुरवा आदि क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

187-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पुरैनी से धोबिया का पुरवा तथा गोरारी ग्राम सभा में राम सिंह के मकान से सुरेन्द्र चौहान के मकान तक, नानू के चक से आजाद के चक तक व अशोक सिंह के चक से काली जी के मन्दिर तक मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। आंशिक रूप से।

उक्त मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त हुए प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, प्रश्नों से सम्बन्धित मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या द्वारा प्रश्न पूछने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपसे ही सम्बन्धित पूछ रहे हैं, अब आप बैठिए।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आप तारांकित प्रश्न देखें, नत्थी (ख) में आज 12 तारांकित प्रश्न लगे हैं और 12 में से 5 प्रश्न पुनरावृत्ति के कारण निरस्त हुए हैं। मान्यवर, आप देखें, प्रश्न नं0-1 यह 11-01-2013 को दिया गया, प्रश्न नं0-3 15-01-2013 को दिया गया, यह सारे प्रश्न ऐसे हैं जो जनवरी के महीने में दिए गए, 14 फरवरी को सत्र शुरू हुआ, अगर दो माननीय सदस्यों के प्रश्न एक विषय पर थे तो दोनों के नाम एक स्थान पर क्लब किए जा सकते थे। अगर एक ही विषय पर थे तो दोनों के नाम आना चाहिए थे और अगर नहीं थे तो पुनरावृत्ति के कारण से निरस्त नहीं होने चाहिए थे। मान्यवर, मैंने कई प्रश्न देखें हैं और आपके संज्ञान में मैं लाना भी चाहता हूं, बिल्कुल अलग विषय है, कोई सम्बन्ध नहीं, उसके बावजूद भी प्रश्नों को निरस्त किया गया है। मेरा मान्यवर, आग्रह है, यदि प्रश्न एक विषय पर हैं तो नाम जुड़ जाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

यह सही है।

श्री हुकुम सिंह-

दूसरा यह है, अगर यह संज्ञान में आता है कि एक विषय पर दो प्रश्न हैं तो कम से कम जब उनको निरस्त किया जाए तो उस माननीय सदस्य को जिसके कारण पुनरावृत्ति है, उसको भेज दिया जाए, कम से कम उसको संतोष तो हो जाए। मान्यवर, यह जो प्रश्न नं0-3 है, मैंने देखा है, बिल्कुल अलग विषय है। मैं आग्रह करूंगा, आप इसका संज्ञान ले लें, सम्भवतः आपको देखने का समय नहीं मिलता है और यह किसी न किसी कारण से निरस्त किए जा रहे हैं। मान्यवर, यह हमारे अधिकारों का हनन है। हम इस विषय को रखना चाहते थे। मैं इसको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं और मान्यवर, जब आप यहां से उठेंगे, अपने चेम्बर में जायेंगे, आपके सामने प्रस्तुत भी कर देंगे, मैं आपका और इस सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। विषय बिल्कुल अलग-अलग हैं, उसके बावजूद भी निरस्त किए गए। मान्यवर, मैंने अपना भी प्रश्न देखा, मनीष असीजा और सुरेश राणा का भी प्रश्न देखा, सबके प्रश्न देखा, चलिए मैं अपना छोड़ देता हूं, लेकिन इन दोनों सदस्यों के प्रश्नों के विषय अलग-अलग हैं। मान्यवर, मेरा विनम्रता के साथ आपसे आग्रह है कि 12 में से 5 निरस्त केवल इस कारण से हुए हैं, अगर एक-एक प्रश्न को मैं आपके सामने रखना चाहूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, मैं इसे दिखवा लूंगा। मैं इसको देखता हूं कि निरस्त का कारण क्या है क्योंकि इसमें कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, एक प्रश्न का उत्तर आ जाता है, उसके बाद भी सवाल आ जाते हैं। मैं इसको दिखवा लूंगा और हम आप लोगों को बुला भी लूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ? अब आप लोग व्यवस्था में ही चलाइये। एक घण्टे का जीरो आवर है, उसके बाद बन्द कर देंगे, फिर आप लोग जानें।

(श्री सतीश महाना खड़े होकर बोलने लगे)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपने किसको अनुमति दी है ?

श्री अध्यक्ष-

आप दोनों लोग एक ही हैं, जो बोलना चाहें, बोलें। पहले इन्हीं को बोल लेने दीजिए।

[12.22 बजे] प्रश्नों हेतु समय-सीमा का निर्धारण के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, प्रश्न प्रहर जो होता है, यह हम सबका अधिकार होता है और हम अपने प्रश्नकाल के किसी भी प्रश्न को किसी दूसरे के प्रश्न से कम महत्व नहीं दे सकते हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। मान्यवर, नत्थी-क में एक प्रश्न लिया गया।

श्री सतीश महाना-

और नत्थी (ख) में आज केवल दो प्रश्न लिये गये हैं। मान्यवर, एक घण्टा बीस मिनट में आज केवल तीन प्रश्न लिये गये हैं। हम अपनी जिज्ञासा को बात के रूप में कहेंगे ही कहेंगे लेकिन आप हमारे संरक्षक के रूप में वहां पर बैठे हैं आपको समय-सीमा का निर्धारण करना है, यह आपको देखना है।

श्री अध्यक्ष-

आप मानते ही नहीं हैं। हम तो कहते हैं कि बहुत सवाल हैं।

श्री सतीश महाना-

हम तो सवाल करेंगे ही करेंगे लेकिन आप हमें रोकेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लिये जा सकें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने तो कल भी सब प्रश्नों को ले लिया था। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हुआ इसको निरस्त किया जाता है।

गन्ना किसानों के भुगतान सम्बन्धी नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-6 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आज कार्यसूची में प्रश्न संख्या-4 पर मैं खड़ा हुआ। मैंने आपसे अनुमति मांगी आपने अनुमति नहीं दी। खैर यह पीठ का अधिकार है हम इसको चुनौती नहीं देना चाहते हैं। हमारा सवाल नं0-6 था। एक-एक सवाल पर 20 मिनट, आधा घण्टा और 20 मिनट हो गये। मान्यवर, यह सवाल गन्ने के मूल्य से संबंधित था इसका समुचित उत्तर नहीं आ पाया। मान्यवर, इसमें 4 प्रश्नकर्ता हैं। इसके अलावा भी बहुत से लोगों की रुचि इस सवाल में थी। चूंकि आज समय के न रहने के कारण इस सवाल का उत्तर नहीं आ पाया इसलिए हम आपसे यह जरूर चाहते हैं कि इसको स्थगित कर दें, यह कल के लिए लगा दें।

श्री अध्यक्ष-

यह उत्तरित हो गया, अब स्थगित कैसे कर दें। यह नियमों में नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस पर नियमों में चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष-

जब गन्ना पर बात आएगी तो आप उस पर चर्चा कर लीजिएगा। नियम-301 की सूचना लेने दीजिए। मैं बार-बार मा0 सदस्यों से कह रहा था कि आगे के प्रश्न लेने दीजिए। आज आप लोग अपनी आजादी का ज्यादा लाभ उठा ले गये। एक-एक सवाल पर दस-दस सवाल हो गये। अनुपूरक बनता भी नहीं है उस पर आप अनुपूरक बनाते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। माननीय सदस्यों को चाहिए जिनको प्रश्न पूछना है तो यहां पर सुबह लांबी में प्रश्नों की कापी आ जाती है। जिनको सवाल पूछना है उसको ले लें पढ़ लें इसके बाद कायदे का अनुपूरक बनाकर पूछें जिससे समय भी कम लगे और उनका समुचित उत्तर भी आ जाये। यहां जितना प्रश्न नहीं पूछा जाता उससे ज्यादा भाषण दिया जाता है तो समय चला जाता है तो उसमें मेरा क्या दोष है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस पर नियम-49 में चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष-

गन्ना पर चर्चा लगी है तो क्यों परेशान हैं। उस पर आप बोलियेगा। अब आप बैठिये।

श्री वीरपाल राठी-

मान्यवर, प्रदेश में 35 लाख लोग इस धन्धे को करते हैं और यहां पर घण्टों-घण्टों बुखार के लिए और बीमारी के लिए तो यह सदन चलेगा लेकिन गन्ना पेमेंट पर सदन नहीं चलेगा। उस समय-समय समाप्त हो जाएगा। मान्यवर, अगर आप इस पर चर्चा नहीं कराते तो हम सदन छोड़कर जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप सदन से बाहर मत जाइये इस पर चर्चा लगी है। आप बैठें न बैठें यह आपका अधिकार है।

(श्री वीरपाल राठी राष्ट्रीय लोक दल के मा0 सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, इस पर नियम-49 में चर्चा करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

अब मुझे पहले नियम-301 लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27-02-2013 को नियम-301 के अंतर्गत कुल 39 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 18 सूचनायें स्वीकार की गईं- पहली सूचना श्री गेंदालाल चौधरी की जनपद हाथरस (महामायानगर) के कतिपय नये सम्पक्र मार्गों को बनाये जाने एवं कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। (उपस्थित), दूसरी सूचना श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की जनपद बस्ती के निर्वाचन क्षेत्र बस्ती सदर के बरदहिया चौराहे से बी0एम0 सिटी मार्ग के गड्ढायुक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। (उपस्थित), तीसरी सूचना श्री सुरेश राणा की जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोटा में निर्मित पानी की टंकी से पानी की सप्लाई शुरू किये जाने के संबंध में है। (उपस्थित), चौथी सूचना श्री संगीत सिंह सोम की मेरठ शामली मार्ग पर नानू नहर के पुल से कस्बा सरधना तक निर्मित मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। (उपस्थित)।

पांचवी सूचना श्री राजबली जैसल की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के विकास खण्ड महुली बाजार में सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

छठी सूचना श्रीमती रूबी प्रसाद की जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी में विद्युतीकरण कराये जाने एवं तड़ित चालक लगाकर आकाशीय बिजली गिरने से हो रही जनहानि को रोके जाने के सम्बन्ध में है,

सातवीं सूचना श्री विजय कुमार पासवान की जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक लोटन में बजहा ताल के बगल से मुडिला बांध होते हुये गौरी गांव तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

आठवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है,

नौवीं सूचना श्री त्रिलोकी राम की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौण्डा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में है,

दसवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-1, चन्दौली द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,

ग्यारहवीं सूचना श्री केशव प्रसाद मौर्य की जनपद इलाहाबाद और कौशाम्बी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में है,

बारहवीं सूचना डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल की भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा के लिये गोरखपुर में तैनात सशस्त्र सीमा बल से पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम द्वारा अत्यधिक दर पर विद्युत बिल की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में है,

तेरहवीं सूचना श्री सुधाकर सिंह की है।

(मा0 सदस्य श्री सुधाकर सिंह का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

चौदहवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की विधान सभा क्षेत्र गंगोह में फैली विद्युत अव्यवस्था के सम्बन्ध में है,

पंद्रहवीं सूचना श्री रामहेत भारती की है,

(मा0 सदस्य श्री राम हेत भारती का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

सोलहवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसा नगर के अन्तर्गत ग्राम बेल्तुआ नौरंगापुर पुल से गड़रियन पुरवा की 03 कि0मी0 सड़क के ध्वस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

सत्रहवीं सूचना श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा की जनपद फतेहपुर के निर्वाचन क्षेत्र बिन्दकी के कतिपय गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

अट्ठारहवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के कतिपय इलाकों में विद्युत पोल एवं तार उपलब्ध कराकर विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है।

चूंकि 18 सूचनायें ली गई हैं आज जो भी मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हैं, उनके स्थान पर किसी अन्य की सूचना नहीं ली जायेगी, दूसरे दिन दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं:-

1. साध्वी निरंजन ज्योति,
2. श्रीमती कृष्णा पासवान,
3. श्रीमती विमला सिंह सोलंकी,
4. श्री अजय मिश्र 'टेनी',
5. श्री मुकुट बिहारी वर्मा,
6. श्री प्रदीप माथुर,
7. श्री दिलनवाज खां,
8. श्री रामलाल अकेला,
9. ठा0 दलवीर सिंह,
10. श्री छोटेलाल वर्मा,
11. श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,
12. श्री मुकेश श्रीवास्तव,
13. श्री मदन चौहान,

14. श्री धर्मपाल सिंह,
15. श्री राधेश्याम जायसवाल,
16. श्री भीम प्रसाद सोनकर,
17. डा0 पूर्णमासी देहाती,
18. श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू,
19. श्री गोरख पासवान,
20. श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज तथा
21. श्री मदन गोपाल वर्मा।

(स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद हाथरस (महामायानगर) के कतिपय नये सम्पक्र मार्गों को बनाये जाने एवं कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गेंदालाल चौधरी-

[महोदय,

मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद हाथरस (महामायानगर) के निम्नलिखित सम्पक्र मार्गों का जनहित में बनाया जाना अतिआवश्यक है, जिससे जनपद हाथरस (महामायानगर) के हजारों निवासी लाभान्वित हो सकेंगे :-

1-सासनी विजयगढ़ मार्ग से नगला विजैया तक 800 मी0 सड़क,

2-ग्राम कटैलियन से ग्राम टोडरपुर तक 800 मी0 सड़क,

3-आगरा-अलीगढ़ रोड पर ग्राम पापरी में 1 कि0मी0 सड़क तथा

4-मधुगढ़ी चौराहे से अलीगढ़ आगरा रोड का मरम्मत कार्य।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सम्पक्र मार्गों को बनाये जाने की मांग करता हूं ताकि हजारों लोग को प्रतिदिन आवाजाही में हो रही परेशानियों से निजात मिल सके।]

जनपद बस्ती के निर्वाचन क्षेत्र बस्ती सदर के बरदहिया चौराहे से बी0एम0 सिटी मार्ग के गड्ढायुक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से आपका ध्यान जनपद बस्ती के अपने निर्वाचन क्षेत्र सं0-310 बस्ती सदर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां पर बरदहिया चौराहे से 6 से 16 किमी0 तक बी0एम0 सिटी मार्ग अत्यन्त गड्डायुक्त हो गया है जो शहर से जुड़ा हुआ है तथा यह रास्ता बस्ती शुगर मिल से होता हुआ जाता है जिससे हजारों वाहन प्रतिदिन इस मार्ग से गुजरते हैं। आये दिन प्रायः दुर्घटनायें होती रहती हैं। सड़क न बनने के कारण यहां जनता काफी आक्रोशित एवं भयभीत है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मैं सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम सोटा में निर्मित पानी की टंकी से पानी की सप्लाई शुरू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश राणा-

[महोदय,

जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम सोटा में लगभग 5 वर्ष पूर्व जल निगम विभाग द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था। टंकी बनकर तैयार है। गांव की आबादी लगभग 4 हजार है। लेकिन आज तक टंकी से गांव में सप्लाई के लिए डलने वाला पाइप डाला नहीं गया है। जिसके कारण गांव के व्यक्तियों को शुद्ध पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। मान्यवर, कृष्णा नदी के प्रदूषण के कारण आस-पास के गांव का जल पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। सोटा गांव भी उनमें से एक गांव है। गांव में अनेक लोग प्रदूषित जल के कारण कैंसर, पीलिया तथा अन्य गम्भीर रोगों का शिकार हो गये हैं। इसलिए निर्मित टंकी का सप्लाई पाइप लगने से गांव के हजारों लोगों को बीमारी से बचाया जा सकता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए हजारों लोगों को बीमारी से बचाने हेतु टंकी के पाइप को गांव में सप्लाई हेतु तत्काल डलवाये जाने तथा टंकी निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।]

मेरठ शामली मार्ग पर नानू नहर के पुल से कस्बा सरधना तक निर्मित मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संगीत सिंह सोम-

[महोदय,

मेरठ शामली मार्ग पर नानू नहर के पुल से कस्बा सरधना तक जाने वाली सड़क जिसकी लम्बाई लगभग 4 कि0मी0 है अत्यन्त खस्ताहाल है। जहां मेरठ से नानू नहर के पुल तक लगभग 14 कि0मी0 की दूरी तय करने में 25 से 30 मिनट लगते हैं वहीं नानू नहर से सरधना तक 4 कि0मी0 की दूरी तय करने में 45 से 50 मिनट लगते हैं जिससे अत्यधिक ईंधन व समय की बर्बादी होती है। इसके अलावा शाम ढलते ही आये दिन लूटमार की घटनाएं भी उक्त मार्ग पर होती रहती हैं। चूंकि इसी रास्ते पर पड़ने वाले मढियाई गांव में प्रत्येक सप्ताह एक विशाल पशु पैंठ लगती है जिसमें दूर-दूर से बड़ी संख्या में किसान व व्यापारी पशुओं की खरीद-फरोख्त हेतु आते हैं सरधना में सूत बुनाई का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। जिससे व्यापारियों को कच्चा माल लाने व तैयार माल ले जाने में भी घोर परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व की इस सूचना पर सदन में चर्चा कराये जाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा की जाय तथा सम्बन्धित कार्यवाही कराने की भी मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के विकास खण्ड महुली बाजार में सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजबली जैसल-

[महोदय,

अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कोरांव जनपद इलाहाबाद अन्तर्गत विकास खण्ड कोरांव में महुली बाजार है जो ग्राम सभा महुली के नाम से जाना जाता है। जहां पर अल्पसंख्यक एवं पिछड़े समाज के लोग अत्यधिक निवास करते हैं। उक्त बाजार में सड़क एवं नाली का निर्माण न होने के कारण थोड़ा सा भी वर्षा होने पर पूरे बाजार में गन्दगी का अम्बार लग जाता है। लोगों का आवागमन बाधित हो जाता है जहां पर दुकानदारों को काफी क्षति होती है। जिससे क्षेत्रीय जनता को भी काफी असुविधा होती है।

अतः जनहित में महुली बाजार में सी0सी0 रोड एवं रोड के किनारे के0सी0 ड्रेन का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी में विद्युतीकरण कराये जाने एवं तड़ित चालक लगाकर आकाशीय बिजली गिरने से हो रही जनहानि को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती रूबी प्रसाद-

[महोदय,

अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र दुद्धी, जनपद सोनभद्र के कई मजरों में विद्युतीकरण का कार्य न होने से प्रतिवर्ष आकाशीय बिजली गिरने से मौतें हो रही हैं। आकाशीय बिजली गिरने से इस क्षेत्र में सैकड़ों निरीह ग्रामीणों के साथ ही साथ दर्जनों पशुओं की मौतें प्रतिवर्ष होती हैं। इन गांवों में अभी तक विद्युतीकरण का कार्य नहीं कराया गया है। इस क्षेत्र में विद्युतीकरण का कार्य यदि नहीं संभव है तो स्थान-स्थान पर तड़ित चालक लगाकर वज्रपात को रोका जा सकता है तथा प्रतिवर्ष हो रही सैकड़ों असामयिक मृत्यु को रोका जा सकता है। इस हेतु शासन जिला पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कराकर कार्य करा सकता है। शासन को जनपद सोनभद्र में वज्रपात से हो रही इस तरह की असामयिक मौतों को रोकने हेतु एक विस्तृत कार्य योजना बनाने, जिला स्तर पर आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने एवं निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक लोटन में बजहा ताल के बगल से मुडिला बांध होते हुए गौरी गांव तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार पासवान-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक लोटन के ग्राम बरदगवा से धन्निहवां, ठड़वरिया पुल से होते हुए नदी तक हगनी नाला की गहराई

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अत्यन्त कम होने के कारण बरसात में जलभराव अत्यधिक हो जाता है जिससे कृषकों की सैकड़ों बीघे जमीन जलमग्न हो जाती है। इस जल भराव की गम्भीर समस्या के निराकरण हेतु उक्त नाले की गहराई कराये जाने एवं क्षेत्रीय जनता के आवागमन की समस्या के निराकरण हेतु उसकी पटरी का चौड़ीकरण का कार्य एवं बजहा ताल के बगल से मुडिला बांध होते हुए गौरी गांव तक (विकास खण्ड बर्डपुर) सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। उक्त जनहित के कार्य न होने से क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से जनपद सिद्धार्थनगर के उक्त कार्यों को कराये जाने हेतु कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[महोदय,

आपको अवगत कराना है कि हमारे जनपद मथुरा में मेरे बल्देव विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण अंचल में पेयजल की टी0टी0एस0पी0 योजना जल निगम विभाग के लापरवाही के कारण 90 प्रतिशत असफल है। जनपद के बल्देव ब्लाक, राया ब्लाक एवं फरह ब्लाकों के ग्रामों में स्थापित पेयजल की टी0टी0एस0पी0 योजना के माध्यम से स्थापित टंकियों में क्षेत्रीय जनता को पेयजल का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जिसका मुख्य कारण निम्नलिखित है :-

1-टी0टी0एस0पी0 योजना की इन टंकियों का खारे पानी में बोरिंग होना।

2-टी0टी0एस0पी0 योजना की जो पाइप लाइन डाली गयी है उसका मानक निचले स्तर का होने के कारण फट जाना।

3-टी0टी0एस0पी0 योजना की जहां बोरिंग हो गयी है वहां पर चलाने के लिए विद्युत कनेक्शन न होना।

4-टी0टी0एस0पी0 योजना की जहां जनरेटर लगाये गये हैं वहां डीजल की व्यवस्था न होना आदि मुख्य कारण हैं।

अतः इस जनहित व लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से ग्रामीण क्षेत्र के उपरोक्त ब्लाकों के ग्रामों में पेयजल की सुनिश्चितता कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौण्डा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिलोकी राम-

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र इगलास, जनपद अलीगढ़ के कस्बा गौण्डा में मात्र एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है आबादी काफी अधिक है कस्बा गौण्डा के आस-पास 20 से 25 कि0मी0 तक कोई भी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं। जनता को अपने उपचार के लिए 20 से 25 कि0मी0 दूरी का सफर करना पड़ता है। क्षेत्र के सड़कों की हालत भी काफी खराब है जब कभी जनता को संक्रामक जैसे रोगों के उपचार के लिए काफी दूरी का सफर करना पड़ता है। जिला अस्पताल की दूरी अधिक होने के कारण मरीजों की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है जिससे जनता में काफी आक्रोश है। अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौण्डा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा दे दिया जाये तो जनता को अपना उपचार कराने में काफी राहत मिलेगी और जनता का आक्रोश भी समाप्त हो जायेगा।

अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन से त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद चन्दौली में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-1, चन्दौली द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद चन्दौली में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-1, चन्दौली जो लगभग 5 वर्षों से भी अधिक समय इसी जनपद में कार्यरत है जिसकी शिकायत के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 5-2-13 को मुख्य मंत्री कार्यालय पंचम तल में दिया गया था। जिसमें विगत वर्षों में जो भी सरकारी योजनायें जिले पर आयी थीं। उसमें भारी पैमाने पर अनियमितितायें बरती गयी हैं।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अतिशीघ्र उक्त योजनाओं की अनियमितताओं में शामिल अधिकारी के खिलाफ जांच कराकर दण्डात्मक कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद और कौशाम्बी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

[महोदय,

जनपद कौशाम्बी और इलाहाबाद में गरीबी के कारण इलाहाबाद के अभाव में आये दिन लोगों को मौत को गले लगाने के लिये मजबूर होना पड़ता है। जनपद में पिछले दो वर्ष से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बन्द पड़ी है गरीबों का कार्ड बनाने का काम पिछले कई माह से बनाये जाने के कारण सरकारी खजाने से प्रीमियम तो दिया जा रहा है परन्तु गरीबों को इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है। स्मार्ट कार्ड से इलाज शुरू कराने में देरी से बीमा कम्पनी का फायदा और स्मार्ट कार्ड धारक का नुकसान है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के स्मार्ट कार्ड धारकों का इलाज अविलम्ब शुरू कराने के लिये सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा के लिये गोरखपुर में तैनात सशस्त्र सीमा बल से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा अत्यधिक दर पर विद्युत बिल की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[महोदय,

देश की सुरक्षा के लिए भारत-नेपाल सीमा पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत सशस्त्र सीमा बल की तैनाती की गयी है। सशस्त्र सीमा बल का क्षेत्रीय मुख्यालय गोरखपुर महानगर में स्थित बन्द पड़े हुए फर्टिलाइजर कारखाने में बनाया गया है जहां सशस्त्र सीमा बल के प्रशासनिक कार्य होते हैं तथा बल में तैनात पैरा मिलेट्री सुरक्षा कर्मियों का निवास है।

इसके अतिरिक्त इसी बन्द पड़े फर्टिलाइजर कारखाने के आस-पास के हिस्से में तकरीबन 300 से अधिक सेवानिवृत्त फर्टिलाइजर कर्मियों के निवास हैं।

इन सेवानिवृत्त फर्टिलाइजर कर्मियों के निवास स्थलों को सशस्त्र सीमा बल के द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाती है तथा सशस्त्र सीमा बल को पांच सितम्बर, 2009 से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के द्वारा विद्युत आपूर्ति करायी जाती है। सशस्त्र सीमा बल के वहां स्थापित होने के पूर्व में कार्यरत फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि0 को टैरिफ प्लान एल0एम0वी0-4ए के अन्तर्गत विद्युत की आपूर्ति की जाती थी। फर्टिलाइजर कार्पोरेशन एक उद्योग था लेकिन सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय सिफ्र एक प्रशासनिक एवं आवासीय कालोनी है जहां किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि का संचालन नहीं होता। इसलिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को सशस्त्र सीमा बल को विद्युत आपूर्ति करते समय टैरिफ प्लान एल0एम0वी0-4ए को आवासी उपभोग के टैरिफ प्लान एल0एम0वी0-1 में बदल देना चाहिए था। ऐसा न किये जाने के कारण न सिफ्र सशस्त्र सीमा बल को अत्यधिक मंहगे दर पर बिजली मिल रही है बल्कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वहां रह रहे 300 नागरिक परिवारों का भी आर्थिक शोषण कर रहा है। व्यापक जनहित में सशस्त्र सीमा बल को दिये गये कनेक्शन एल0एम0वी0-4ए को एल0एम0वी0-1 में बदला जाना आवश्यक है तथा 5-9-2009 से अब तक वसूले गये विद्युत बिलों की वापसी भी न्यायोचित है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र गंगोह में फैली विद्युत अव्यवस्था के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी-

[मान्यवर,

अवगत कराना चाहता हूं कि विधान सभा गंगोह के ग्राम-शेरमऊ व ग्राम-रामसहायवाला में बिजली की व्यवस्था अत्यन्त खराब है। यहां ओवरलोडिंग की वजह से अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर व खम्भे लगवाये जाने नितान्त आवश्यक हैं तथा एक अन्य ग्राम बाड़ी माजरा के मजरा मक्खन माजरा में 33 के0वी0 की लाइन किसानों के घर के ऊपर से जा रही है जिससे किसानों में जान-माल की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई है। जनहित में उक्त कार्यों को कराये जाने हेतु विद्युत विभाग को कई बार लिखा गया परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यन्त रोष है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम बेल्तुआ नौरंगापुर पुल से गड़रियनपुरवा की 3 कि0मी0 सड़क के ध्वस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[महोदय,

संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम बेल्तुआ नौरंगापुर पुल से गड़रियन पुरवा होते हुए बृजेन्द्र यादव के मकान के पास से ग्राम मूड़ी तक 3.0 कि0मी0 डामर की सड़क पूर्णतया ध्वस्त हो गयी है। जिससे सैकड़ों गन्ना किसानों को शुगर मिल में अपना गन्ना पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पूरी सड़क गड्ढायुक्त हो गयी है, जिससे आये दि क्षेत्रीय जनता एवं किसानों के साथ सड़क दुर्घटनायें हो रही हैं। जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार जिला स्तर के अधिकारियों एवं शासन से सड़क निर्माण हेतु अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक उक्त सड़क की मरम्मत नहीं हो सकी है। सड़क के निर्माण न होने से सभी क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता एवं किसानों में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की भी मांग करता हूं।]

जनपद फतेहपुर के निर्वाचन क्षेत्र बिन्दकी के कतिपय गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा-

[मान्यवर,

मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर के निर्वाचन क्षेत्र बिन्दकी के ग्राम पसियन पुरवा मजरे सिकरोढ़ी, ग्राम लोधनपुरवा मजरे कोरसम विकास खण्ड मलवां तथा ग्राम कबीरपुर, ग्राम नयापुरवा मजरे हाजीपुर गंग विकास खण्ड तेलियानी एवं ग्राम कमरापुर मजरे जड़रांव विकास खण्ड खजुहा में विद्युतीकरण न होने के कारण वहां के निवासियों का जीवन अन्धकारमय हो गया है। उपरोक्त गांवों में जनहित की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए विद्युतीकरण कराना अति आवश्यक है।

अतः मेरा माननीय महोदय से अनुरोध है कि जनमानस की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त गांवों में विद्युतीकरण कराने हेतु सदन से मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के कतिपय इलाकों में विद्युत पोल एवं तार उपलब्ध कराकर विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

[महोदय,

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी में न्यू आजादनगर, देहली, सुजानपुर, सतबरी रोड, कोयला नगर, मंगला बिहार प्रथम, मंगला बिहार द्वितीय, गदियाना, न्यौरा गांव, भवानीनगर, आनन्द नगर, जवाहरपुरम, सेंगर चौराहा और समता सोसाइटी, राजपूत नगर, राधापुरम, शिवपुरम क्षेत्रों में विद्युतीकरण व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। यहां पर बांस-बल्लियों के सहारे लोग विद्युत का उपयोग कर रहे हैं जिससे कई बार दुर्घटनायें भी हो चुकी हैं। परन्तु विद्युत विभाग एवं जिला प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जनहित में अविलम्ब पोल एवं तार उपलब्ध कराकर विद्युत सप्लाई किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त क्षेत्रों में विद्युत पोल एवं तार उपलब्ध कराकर विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

[12.33 बजे] औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27 फरवरी, 2013 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 10 सूचनायें प्राप्त हुयीं:-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की ब्रिटिश काल में बनाये गये जेल मैनुअल में संशोधन कर मा0 सांसद व विधायक को जेल में विशेष सुविधा एवं सुरक्षा युक्त दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री अखिलेश प्रताप सिंह की मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को ''कुम्भ मेले हेतु केन्द्र सरकार से अपेक्षित धन प्राप्त न होने विषयक'' दिये गये वक्तव्य पर खेद व्यक्त करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी धनराशि हेतु उसे धन्यवाद ज्ञापित करने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी से रामनगर जाने हेतु प्रतिवर्ष बनने वाले पीपे के पुल को सुदृढ़ बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री मदन चौहान की मा0 विधायकों के लिए रेलवे यात्रा कूपन की धनराशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव की विधान सभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिखित उत्तर एक दिन पूर्व मा0 सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने एवं तारांकित/अतारांकित प्रश्नों को स्थगित/निरस्त न कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री धर्मपाल सिंह की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित बरेली-बदायूं मार्ग के सम्बन्ध में दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को दिये गये वक्तव्य को भ्रामक बताये जाने के सम्बन्ध में है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सातवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कर्मचारियों व अन्य राज्य कर्मचारियों के वेतन में विसंगति होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद-फैजाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध की गयी शिकायत की जांच आख्या अभी तक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में है।

नौवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की विधान सभा सत्र के समय मा0 सदस्यों/मंत्रीगणों के सुरक्षाकर्मियों एवं वाहन चालकों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री राजेश अग्रवाल की बरेली के मानावीर मन्दिर से बेनीपुर होते हुए सिठौंरा तक एवं मढ़ीनाथ पुलिया से सिटी श्मशान के बासे तक सड़क के सम्बन्ध में दिनांक 26 फरवरी, 2013 को मा0 लोक निर्माण मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को असंतोषजनक बताये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष -

मा0 तिवारी जी की सूचना मा0 सांसद व विधायक को जेल में विशेष सुविधा देने के लिये है। आप बतायें ये नियम-300 में कहां बनता है। आप तो इसके एक्सपर्ट हैं हम जानते हैं। कहां बनता है, बताइये। काहे को आप इसमें बोलेंगे समय ले लेंगे। आज नियम-56 में बहुत लगा है। मा0 अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये जो कुंभ मेले में धन विषयक है। इसमें आपको नियमावली में अधिकार है कि अगर गलतबयानी है तो नियम-63 में देंगे, नियम-167, 168 में देंगे। यह नियम-300 में नहीं बनता। मा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, आपका पीपे का पुल नियम-300 में नहीं आता इसलिये इसको नियम-56 में दीजिये, नियम-51 में दीजिये या और किसी में दीजिये। मदन चौहान जी, कूपन बढ़ाये जाने के बारे में बातें चल रही हैं। श्री मुकेश श्रीवास्तव जी का है विधान सभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिखित उत्तर एक दिन पूर्व मा0 सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, एक दिन पूर्व नहीं दिया जाता है। उत्तर जिस समय सुबह आप आते हैं तो उसके पहले आपके घर पर पहुंचा दिया जाता है। श्री धर्मपाल सिंह जी का है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित बरेली-बदायूं मार्ग का है, यह कहां नियम-300 में बनता है।

कुम्भ मेले हेतु केन्द्र सरकार से अपेक्षित धन प्राप्त न होने विषयक औचित्य का प्रश्न

(मा0 अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा लगातार खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष -

मा0 अखिलेश जी, इसे आप नियम-63 में दो न। ये इस नियम में नहीं बनता है। अब कोई नहीं सुना जायेगा। अब नियम-56, आज नियम-56 बहुत लगा है। दो-दो मिनट सबको बोल लेने दीजिये।

(मा0 श्री प्रमोद तिवारी द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

अरे, पण्डित जी, ये विधायकों वाला इसमें कहां आता है। आप हमारे चैम्बर में हमको समझा दीजिये। अगर बनता है तो जो आप कहेंगे, मैं करूंगा।

*श्री प्रमोद तिवारी -

मान्यवर, आप नियमावली का नियम-300 के देखें। नियमावली के नियम-300 के अन्तर्गत देखें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप भी बहुत पढ़े हैं 300 और हम भी पढ़े हैं। आप नियम-300 को घुमाकर जैसा चाहते हैं, वैसा पेश कर देते हैं। रोज मैं आपकी बात मानता हूं, आज आप हमारी बात मान जाइये।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपको कह दिया कि आपके लिये नियमावली में उपलब्ध है। आप क्यों नहीं देते उसमें, आप मेरे पास भेजिये। नहीं, क्षमा मांगने के लिये नियम-300 नहीं है। अखिलेश जी, मैंने आपको नियम बता दिया। आप सबसे विद्वान सदस्य हैं और आप सारे नियम जानते हैं। मैंने भी नियम बता दिया, उन नियमों में दीजिये उस पर विचार किया जायेगा। मद सं0-2 नहीं है मद सं0-3, आज नियम-56 में बहुत लगा है।

(मा0 अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा लगातार खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे, मान्यवर, इसके नियम हैं। सदन में ये इस तरह से नियम-300 में नहीं उठता। जब आप नियम-63 में देंगे तो आपको बोलने का अवसर मिलेगा। पूरा अवसर मिलेगा, उसमें दीजिये। नियम-167, 168 में दीजिये कि ये गलतबयानी है। मा0 अखिलेश जी, आपसे मेरा कहना है कि आप मुझसे चैम्बर में मिल लीजिये। अगर आप हमें संतुष्ट कर देंगे कि बनता है तो कल हम आपको सुनवा देंगे। नहीं तो आप हमारी बात मान जाइये, बैठिये।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, पैसे जो मिले हैं ऑन रिकॉर्ड हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। चूक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब पैसे मिले हैं तो सरकार को उसको स्वीकार करने में आपत्ति क्या है। हमारे पास डॉक्यूमेण्टरी एविडेंस हैं। हम आपको दे सकते हैं कि केन्द्र सरकार से पैसा आया है। कुंभ मेले को लगभग 1200 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने दिये हैं। ये पांचों लेटर्स हैं। इसको कैसे नकारा जा सकता है सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को। इसे स्वीकारने में सरकार को कहीं झिझक नहीं होनी चाहिये। ये लोग भी काम करते हैं, हम स्वीकारते हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया। ये तो आगे बढ़के स्वीकार करना चाहिये। हम लोग खुद स्वीकारते हैं तो इन्हें भी स्वीकारना चाहिये, सरकार को स्वीकारना चाहिये। मेरे कहने का तात्पर्य सिफ्र यह है कि जो एक गलत सूचना, भ्रामक सूचना चली गयी है, उसका शुद्धिकरण कर दिया जाये। इतना सा मेरा कहना है। अब आप अपनी पीठ से कह दें।

श्री अध्यक्ष-

अब आपने अपनी बात कह ली।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मा0 सदस्य ने जिस प्रश्न को सदन में रखा है। सम्भवतः उसकी वजह यह है कि एक दिन सदन में यह बात आयी थी और आपने उसका संज्ञान लिया। मैंने उस वक्त भी कहा था कि भारत सरकार से कुम्भ मेले के लिये कोई धनराशि शुरू में नहीं मिली और यह सत्य है। इसके बाद मुख्य

मंत्री जी ने अपने स्तर से कोशिश की। प्रधान मंत्री जी का पत्र मुख्य मंत्री जी को आया कि मैंने विचार किया। वित्त ने मना कर दिया था लेकिन मैंने उनके प्रपोजल का टर्न डाउन कर दिया है और धनराशि दी जा रही है। मगर देर इतनी हो चुकी थी कि उस धनराशि के सहारे पर कुंभ मेले का रिस्क नहीं लिया जा सकता था, लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई काम न रुके, कोई जरूरत न रुके, उसमें धन की कमी नहीं होने दी और मैं बार-बार यह कहता रहा कि कुंभ में पैसे की वजह से कोई कमी नहीं होने दी जायेगी और यह सत्य है, यह पूरी दुनिया जानती है। जहां तक पैसा मिलने की बात है, पैसा दिया गया, लेकिन उस वक्त दिया गया, जब उसकी सही जरूरत का वक्त नहीं था, वह निकल गया था। अब वह पैसा कहां है, कहां पहुंचा है, कितना उपयोग हुआ है, इसकी जानकारी लेकर ही आपको बताया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

ये वक्तव्य है मा0 मंत्री जी का, हम बहुत सम्मान करते हैं। हम इसमें कुछ सही बात बताना चाहते हैं, जो बोला था कुंभ के लिए जो पैसा भारत सरकार से मिलना था, वह भारत सरकार ने मना कर दिया था। अगर भारत सरकार के सहारे बैठे होते तो कुंभ में जिस बेइज्जती का सामना होता और जिस मसाइल का सामना होता और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के किसी भी वायदे पर या किसी ऐसी बात पर जिस पर हमें यकीन न हो, उसको सामने रखकर अपनी कोई स्कीम तैयार करें, यह मा0 मंत्री जी का वक्तव्य था। जो पैसे मिले हैं दिनांक 23-11-2011 को पहला लॉट मिला है, जिस प्रोजेक्ट के लिए मिला है, वह मैं आपको अभी दे दूंगा। 5 चिट्ठियां मिली हैं, दूसरा पैसा जारी हुआ है दिनांक 21-02-2012 को, तीसरा पैसा जारी हुआ है दि0 19-09-2012 को, चौथा पैसा जारी हुआ है दिनांक 12-11-2012 को, पांचवा पैसा जारी हुआ है 24-01-2013 कुल 11 सौ 41 करोड़ 62 लाख रुपये प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार ने इन पत्रों के माध्यम से जारी किए हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आपकी बात आ गई है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 अध्यक्ष जी, स्वतः तारीखों का आप ध्यान दें, दिनांक 24.01.2013 को जो पैसा मिला है, क्या वह सही मिला है, इसी तारीख में मिलना चाहिए था। देखिए अगर आप इन चीजों पर बहस करेंगे तो फिर क्योंकि मेरे पास वह तथ्य नहीं हैं, जो आप लेकर आए हैं, मुझे तथ्य लाने दीजिए, उस पर फिर बात करेंगे। मैंने जो कहा कि भारत सरकार ने मना किया था। प्रधानमंत्री जी के पत्र में उसका जिक्र है कि मैंने वित्त के उस फैसले का टर्न डाउन किया और मैं पैसा भेज रहा हूं, अब अगर जनवरी के महीने में आप पैसा भेजेंगे कुंभ का, तो आप तो रेलवे स्टेशन की तरह हम पर डाल देंगे और मुंह काला हमारा कराएंगे आप। कोई हादसा, कोई हादसा इलाहाबाद में नहीं हुआ, जहां स्नान होता है, वहां नहीं हुआ, मेला परिसर में नहीं हुआ।

(कई विपक्षी मा0 सदस्यों के बीच में टोकने पर)

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा लगी है। जब इस पर चर्चा डेढ़ घंटे लगी है, उसी दिन इस पर बोलिएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं, मेला परिसर में कोई हादसा नहीं हुआ, किसी प्रकार का। कोई भगदड़, भगदड़ से कोई मौत, कोई हादसे से मेरी मुराद वह है, वह नहीं जो एक टेण्ट में आग लग गई उससे मेरी मुराद नहीं है। वह तो दो-तीन हादसे ऐसे हुए हैं। टेण्ट में सिलेण्डर फट गया, नदानी उन्होंने यह की कि वह सलेण्डर उठाकर दूसरे के टेण्ट में फेंक दिया, उससे दूसरा टेण्ट जल गया, वह नदानी थी सिफ्र, लेकिन इतने बड़े मजमें में और इस पर आपको मुतमयिन भी होना चाहिए और खुश भी कि जहां इस तरह के हादसे होते हैं, वहां गलत सूचना पर भगदड़ मच जाती है, लेकिन क्योंकि धर्म से मुतालिक था, आस्था से मुतालिक था, इतना बड़ा हादसा होने के बाद कि टेण्ट्स में आग लग रही है, एक टेण्ट से भी कोई एक श्रद्धालु भागे नहीं वहां से, सब वहीं रहे और व्यवस्था करने में आसानी हुई। अगर इन जलते हुए टेण्ट्स को देखकर लोग टेण्ट से निकलकर भागना शुरू कर देते तो शायद बड़ी परेशानी सामने आती, तो कोई हादसा भगदड़ का, भगदड़ से दब कर मर जाने का न तो परिसर में हुआ, न इलाहाबाद शहर में हुआ। मान्यवर, जो कुछ हुआ, वह रेलवे स्टेशन के परिसर में हुआ, प्लेटफार्म पर उसकी सीढ़ियों पर हुआ, क्यों हुआ, कौंन जिम्मेदार है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं। आप काहे में दाढ़ी में तिनका-बोल रहे हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, कुम्भ मेले की व्यवस्था की हम तारीफ करते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, 23 नवम्बर, 2011 को जब आपकी सरकार नहीं थी, तब 177 करोड़ रुपये दिये गये शुरु करने के लिए। 21, फरवरी, 2012 को जब आपकी सरकार नहीं थी तब 22 करोड़ 45 लाख रुपये दिये गये। मान्यवर, 19 सितम्बर, 2012 को 130 करोड़ रुपये दिये गये और मान्यवर, 12 नवम्बर, 2012 को 800 करोड़ रुपये दिये गये। 24 जनवरी, 2013 को दस करोड़ रुपये दिये गये हैं। मान्यवर, जनवरी में सिफ्र दस करोड़ रुपये दिये गये हैं। बाकी 1130 करोड़ रुपये भारत सरकार ने पहले दे दिए थे। अब चूंकि तथ्य एक आया है, दल पर कोई एक आरोप लगा है तो दल को अपनी बात कहनी चाहिए। मान्यवर, तथ्यों के आधार पर हमने बताया 1130 करोड़ रुपये पहले दे दिए गये थे। मान्यवर, आजादी के बाद किसी केन्द्रीय सरकार ने कुम्भ मेले के लिए इतना पैसा नहीं दिया है। वहां हमारी सरकार ने दिया है। इसके लिए हम अपनी सरकार को बधाई देते हैं। मेजों की थपथपाहट। मान्यवर, रेलवे स्टेशन पर जो हुआ उसकी ज्यूडिशयल जांच चल रही है। उस पर मंत्री जी न बोलें तो ज्यादा अच्छा है। ज्यूडिशयल जांच में वह तथ्य देख लेंगें। टर्म्स आफ रेफरेन्स में यह जरूर बढ़ा दिया जाय कि स्टेशन की जो संख्या है वह सीमित है, निर्धारित है वह न घटाई जा सकती है और न बढ़ाई जा सकती है।

श्री अध्यक्ष-

जब कुम्भ मेले पर डेढ़ घण्टे की चर्चा लगी है। तब आप उस पर बोल लीजिएगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

श्रीमन् इस पर कोई समझौता नहीं है। स्टेशन पर कितने लोग जायेंगें। यह तो देखने की बात है, इसको हम तो नियंत्रित कर सकते थे। इसके अलावा वहां आग में विस्फोट हुआ। मान्यवर, मेले की निश्चित रूप से, कई वर्षो के मुकाबले, व्यवस्था बेहतर हुई है। यह मैं स्वीकार करता हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य द्वारा सीट पर बैठे-बैठे कुछ कहने पर) व्यवधान

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं इनको दंगे नहीं कराने दूंगा। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि व्यक्तियों को मरने से रोक सकें। खून-खराबा नहीं होने देंगें। मान्यवर, यह हम अपने दल की ओर से स्पष्ट कर दें कि 1130 करोड़ रुपये आपको सही समय पर केन्द्र सरकार की ओर से दिए गये। मेले में आपने अच्छा प्रबन्ध किया है, उसके लिए आपको बधाई।

(श्री प्रदीप माथुर व अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मेले पर कितनी चर्चा चलेगी आप सुनना नहीं चाहते हैं। माननीय संसदीय कार्य मत्री जी ने कह दिया कि आप सारे तथ्य लाकर फिर स्पष्ट करेंगे।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, 2001 में भी कुम्भ हुआ था।

श्री प्रमोद तिवारी-

तो उसमें क्या हुआ ?

श्री हुकुम सिंह-

कोई हादसा नहीं होने दिया।

श्री प्रमोद तिवारी-

हरिद्वार में किसकी सरकार थी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कोई हादसा नहीं होने दिया भा0ज0पा0 सरकार ने। मेजों की थपथपाहट

श्री अध्यक्ष-

जब कुम्भ पर चर्चा होगी, तब बोल लीजिएगा।

श्री हुकुम सिंह-

श्रीमन् यह पूंछा गया कि सरकार ने कितना दिया है उत्तर प्रदेश को। उसमें ऐसा तो नहीं है कि अपनी जेब से निकालकर दिया हो। हमने जो दिया है व्यवस्था के अनुसार नियमों के अनुसार दिया है और समय के अन्दर दिया है। जब सारा आयोजन हो गया तो तब आप डींग क्यों हांक रहें हैं। इटली से लेकर दिल्ली तक घोटालों से घिरी आपकी सरकार है उसकी आप तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने क्या अपने घर से पैसा दिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष जी, पार्टी ने एक आरोप लगाया वह मैं कहना चाहता हूं। हम बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं। हमने एक बहुत निश्चित बात कही है और बहुत सुनिश्चित बात कही है जो माननीय मंत्री जी ने कही थी, सही कर दी, उन्होंने स्वीकार किया और आकड़ों के साथ हम फोटोस्टेट लेकर के आये हैं। अब बीच में, बात चल रही है कायदे की बीच में आ गये हादसे पर। मान्यवर, सुनिये हादसे तो हुए हैं।

(श्री हुकुम सिंह जी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म कीजिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जो इन्होंने घोटाले का नाम लिया है, कारगिल शहीदों के साथ घोटाला करने वाले, नहीं मान्यवर।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

कुछ नहीं लिखा जायेगा। आप लोग एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगायेंगे तो कैसे सदन चलेगा। अब आप आगे की कार्यवाही लेने दीजिए।

(डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्य सदन के वेल में आकर स0पा0, ब0स0पा0, कांग्रेस आई, चोर चोर मौसेरे भाई का नारा लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

डा0 साहब चलिये हो गया। गिर पड़ोगे इतना तेज बोल रहे हो। अब चलिये।

(सदन के वेल में आये हुए माननीय सदस्य अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे)

माननीय वाजपेयी जी, अब इन लोगों को वापस बुलाइये।

आप चलिये। आप सब से अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपनी सीटों पर चले और वहीं से बोले, इधर मत बढ़ें यह अच्छी बात नहीं है, चलिये।

माननीय तिवारी जी, आप लोग थोड़ा अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य सदन के वेल में आकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे)

चलिये, अब आप लोग चलिये अपनी अपनी सीटों पर, माननीय हुकुम सिंह जी आप बुला लीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दोनो दलों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से, दोनों से आग्रह करूंगा कि अपनी अपनी सीटों पर आयें, मैं जवाब देना चाहूंगा, मैं तथ्यों पर आधारित जवाब देना चाहूंगा। मान्यवर, मैं तथ्यों पर आधारित जवाब देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप जाइये, आप भी जाइये और आप भी जाइये। चलिये अब आप भी चलिये। माननीय हुकुम सिंह जी आप इन लोगों को बुला लीजिए। आप जाइये। मेरा आग्रह है माननीय नेता भाजपा आप इन लोगों को बुला लीजिए, आप बुला लीजिए।

(सदन के वेल में आये हुए भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा आमने सामने आरोप प्रत्यारोप करने पर)

अब वहीं लड़ोगे क्या। आप लोग अपनी अपनी सीटों पर चलें। मेरा सभी सदस्यों से नम्र निवेदन हैं कि आपकी बाते हो गयी अब आप अपनी अपनी सीटों पर जायें।

(भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा वेल में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने के कारण उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, समझ में यह नहीं आ रहा है कि यह आपस में मुकाबला किस बात का है और यह आपस के मुकाबले के लिये वेल में क्यों बैठे हैं। न अध्यक्ष महोदय ने कुछ कहा, न मुझसे कोई शिकायत, अब यह आपस का झगड़ा तो बाहर निपटाइये, इससे सदन से क्या लेना देना । अब कौन चैम्पियन है यह तो जनता तय करेगी । 2014 का चुनाव तय कर देगा ।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा अब तो जाइये, आप लोग सदन स्थगित कराकर क्या पाओगे ? आप लोग बैठ जाओगे तो बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह आपस की पंचायत कहां होगी ।

श्री अध्यक्ष-

अरे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इन लोगों को समझाइये ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह दोनों समझ के ही तो कर रहे हैं, यह समझ कर ही कर रहे हैं, इसमें क्या समझायेंगे आप ।

(व्यवधान जारी रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को 10 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 12 बजकर 56 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी। 01 बजकर 06 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 01 बजकर 20 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है। 01 बजकर 20 मिनट पर सहायक मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 05 मिनट और बढ़ा दिया है। 01 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज, ब्लाक ऐरायां में ब्लाक कार्यालय भवन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री शोएब व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अध्यक्ष-

श्री मोहम्मद आसिफ अपनी याचिका उपस्थित करें।

श्री मो0 आसिफ-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज, ब्लाक ऐरायां में ब्लाक कार्यालय भवन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मो0शोएब व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

मान्यवर, मैं इस याचिका के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-याचिका पर बोला नहीं जाता है। आपकी याचिका चली जाएगी और उस पर याचिका समिति में विचार होगा।

शून्य प्रहर के अन्तर्गत आज के लिए निर्धारित नियम-56 की सूचनाएं कल प्राथमिकता पर लिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4, मद संख्या-5, मद संख्या-6 में कुछ नहीं है। मद संख्या-7 में कार्य-स्थगन है। सदस्यों को जानकारी दे दें कि यह हुआ है उस समय मौर्य जी व सारे लोग थे तो यह तय हुआ था कि एक घण्टे का जीरो आवर रहेगा चूंकि 1.20 तक यह चलता है और 1.25 हो गया है तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो आज आपने नियम-56 दिया है कल उसे प्राथमिकता पर ले लिया जायेगा आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। इसी नोटिस पर कल चर्चा हो जाएगी।

शून्य प्रहर में आधे घण्टे का समय बढ़ाये जाने का अनुरोध

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

आप सुन लीजिएगा उसके बाद मना कर दीजिएगा हम मान जाएंगे। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिसका आज ही महत्व है अगर आज इसको हम नहीं उठाते हैं तो एक समस्या होगी इसलिए आप उसको सुन लीजिएगा नकार दीजिएगा हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

आप मेरे चेम्बर में चलिए मैं आपकी बात समझ रहा हूं जो गोरखपुर में फीस बढ़ाई गई है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी पांच मिनट दस मिनट तो आगे पीछे होता रहता है। मैं सिफ्र पांच मिनट में अपनी बात कह लूं। एक महत्वपूर्ण विषय है आप अनुमति दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

फिर सब लोग बोलेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, आधे घण्टे के अन्दर सब निपट जाएगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप ही ने नियम बनाया था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आप वहां पर इसीलिए बैठे हैं कि किसी चीज की आवश्यकता पड़ने पर आप नियमों को शिथिल कर सकते हैं। बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

क्या यह सदन सहमत है कि जीरो आवर आधा घण्टे के लिए और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। फिर हम क्रम से लेंगे।

माननीय मौर्या जी आपकी सूचना है जनपद इटावा के जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक वाली आप दो मिनट में अपनी बात रख लें फिर हम इस पर अपनी व्यवस्था दे दें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी जैसा कि नित्य प्रति हम यहां पर कानून के विषय में चिन्ता करते हैं अभी इसी 23 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी गृह जनपद इटावा में वहां अदनान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई। मात्र इसलिए कि वह एक लड़की से विवाह करने के लिए आवेदन पत्र देने गया था कलेक्ट्रेट में विवाह अधिकारी के पास और प्रार्थना देकर आ रहा था तो कुछ सिरफिरे लोगों ने दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ठीक कलेक्ट्रेट के सामने और एस0एस0पी0 बंगला के पीछे जहां पर सारे के सारे अधिकारी रहते हैं जो इस बात का साफ संकेत दे रहा है कि आज अधिकारियों में भय बिल्कुल नहीं रह गया है। अभी महविश और मो0 फकीर के हादसे को लोग भुला नहीं पाए थे कि यह दूसरा हादसा अदनान जी का हो गया सिंचाई मंत्री जी घटना के दिन शायद इटावा थे उन्होंने इस बात के लिए आश्वासन भी दिया था कि जो भी हत्यारे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही होगी तो मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि जो भी हत्यारे हैं और जो दिनदहाड़े कानून की इस प्रकार से धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ तत्काल प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जिससे कि इस प्रकार के हादसे करने वाले लोगों पर कहीं न कहीं कानून का भय दिखाई पड़े।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, जैसा कि आपने खुद भी कहा कि सिंचाई मंत्री जी ने आश्वासन दिया था मैंने इस खबर को समाचार पत्रों में भी पढ़ा। अब जिस तरह का मामला है वह आपकी जानकारी में है लेकिन फिर भी कानून की सख्ती होना चाहिए और कड़ाई होना चाहिए सो होगी। सो होगी ।जो कमी महसूस की जा रही है उस कमी को दूर किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

बहुत धन्यवाद। मैंने माननीय मौर्या जी को सुना और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

* डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी,

श्री अध्यक्ष-

यह गोरखपुर के चितरंजन मिश्र वाला सवाल आप उठायेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

यह तो आप जान रहे हैं और इसीलिये मैंने कहा कि यह आपका विषय है और इसीलिये आपकी अनुमति मिली।

श्री अध्यक्ष-

जल्दी कहियेगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। आज यह सदन के लिये चिन्ता और चिन्तन का विषय होना चाहिए। वह जो समाज को दिशा देते हैं, वह जो पूरे समाज की पीढ़ी दर पीढ़ी का निर्माण करते हैं। जो संस्कारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करते हैं। जिन्हें हमारी संस्कृति भगवान का दर्जा देती है। आज प्रदेश के ऐसे सारे विश्वविद्यालयों के शिक्षक और प्रदेश के सारे महाविद्यालयों के शिक्षक आज लखनऊ की सड़कों पर खड़े हैं और आन्दोलनरत् हैं और ऐसा नहीं कि अपनी तनख्वाह बढ़ाये जाने की मांग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी मांग कर रहे हैं जिससे लगे कि वो अपने दायित्वों से हटना चाहते हैं। वह बहुत सीधी सपाट बात कह रहे हैं। 1 जनवरी, 2006 को छठवां वेतन आयोग लग गया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने इसे स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके 2010 में एक यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन का रेगुलेशन बना दिया। पूरे देश के सारे राज्यों ने उस रेगुलेशन को स्वीकार करते हुए उसके आधार पर एक्ट का निर्माण कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन में जितने भी प्राविधान उस रेगुलेशन के तहत किये गये थे देश के सारे प्रदेशों के सारे विश्व विद्यालयों में, सारे महाविद्यालयों में वह प्राविधान लागू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सैद्धान्तिक आधार पर छठे वेतन आयोग को लागू भी कर दिया। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन का जो रेगुलेशन 2010 आया था उसके संदर्भ में चिट्ठी भी जाहिर कर दी लेकिन चिट्ठी मंशा जाहिर करती थी। जमीन पर कार्यान्वित करने के लिये उसको एक्ट बनाना था। 2006 का मसला, आज सातवें वेतन आयोग की बात हो रही है। नई संस्तुतियों को लेने की बात हो रही है, आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने वह एक्ट संशोधन नहीं किया जिसके माध्यम से यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन जिन चीजों को विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिये लाना चाहती है, ला सके। इतनी ही बात नहीं, छठवें वेतन आयोग में माननीय शिक्षकों के वेतन बढ़ाये गये। सरकार अगर मना कर देती तो बात दूसरी थी। सरकार ने स्वीकार कर लिया और 31 दिसम्बर 2008 से वह बढ़ा हुआ वेतन दिया भी जा रहा है। लेकिन 1-1-2006 से लेकर 31 दिसम्बर 2008 के बीच का यह जो एरियर का भुगतान है, अध्यक्ष जी, 2013 आ गया। आज तक इस भुगतान को नहीं किया गया। अब समस्या यह है कि टीचर्स जाएं कहां ? यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के पास जाते हैं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने कहा कि हमने डायरेक्शन दिया है कि जो हमारे रेगुलेशन लागू करेगा जो यह एरियर का भुगतान करेगा हम उसको 80 प्रतिशत एरियर दे देंगे। भारत सरकार 80 प्रतिशत एरियर के रिइम्बर्समेंट के लिये तैयार बैठी है। अब समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले वह भुगतान करे शिक्षकों को उसके बाद भारत सरकार उस धन को उत्तर प्रदेश सरकार को दे। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर सैद्धान्तिक आधार पर इस बात को स्वीकार करती है कि शिक्षकों को यह वेतनमान मिलना चाहिए और स्वंय 2008 से इस बढ़े हुए वेतनमान को दे रही है। 1-1-2006 से 2008 के बीच के एरियर के भुगतान को करने के लिये प्रतिबद्ध है इसके बावजूद नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, यह विषय है और आप इस विषय को जानते भी हैं। इसलिये आपका संरक्षण चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को यह पैसा देना है इसलिये सरकार अपनी मंशा जाहिर करे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस प्रकार के कई मामले हैं यूनिवर्सिटीज का भी है, महाविद्यालयों का भी है, माध्यमिक विद्यालयों का भी है, बेसिक विद्यालयों का भी है, थोड़ा थोड़ा बदल बदल कर। वित्तीय बोझ चाहे 20 प्रतिशत का हो, पड़ेगा तो। सैद्धान्तिक तौर पर हमने इससे कभी इन्कार नहीं किया और यहां तक कि हमारी पार्टी के घोषणा-पत्र में भी यह सब बातें शामिल हैं। उनका एक प्रतिनिधिमंडल शायद हमारे यहां बैठा है, उनसे सदन की कार्यवाही की वजह से बात नहीं हो सकी। पूरी तरह से तो मैं तथ्य नहीं रख सकूंगा इस वक्त, लेकिन इस सिलसिले में जो भी कार्यवाही हो सकती है, जानकारी लेकर कोशिश करेंगे कि समस्या का समाधान हो, और कोई दो राय नहीं है बड़ा अजीब सा लगता है और यह अपमानजनक भी है कि एक ही क्वालिफिकेशन के टीचर्स, यह तो समस्या है ही, जो डिसपेरिटी ऑफ सैलरी है, कि एक ही क्वालिफिकेशन के लेक्चरर हैं, टीचर्स हैं और जो रेगुलर हैं उनकी तनख्वाह कुछ है, जो नॉन रेगुलर हैं उनकी तनख्वाह कुछ है, जिन लोगों को काम करते-करते, 12-15 बरस हो गए हैं और यह भी सच है कि प्रिन्सिपल साहिबान और मैनेजमेंट उनसे काम भी ज्यादा लेता है और उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं। यह कुछ चीजें ऐसी हैं जो वाकई हल होनी चाहिए। लेकिन डाक्टर साहब अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि चाहे वह बेसिक हो, माध्यमिक हो, हायर एजूकेशन हो, इन सबमें कुल मिलाकर इतना बड़ा वित्तीय भार आने वाला है कि उसको संसाधनों के साथ ही, मैं इसको बहस में, चर्चा में, या अन्यथा नहीं कह रहा हूं लेकिन सच यही है, दिल चाहता है कि इसका समाधान हो। वह बच्चे जो बड़ी-बड़ी डिग्रियां लेकर निकलते हैं मैं तो खुद अपने यहां जब इन्टरव्यू होते हैं देखता हूं और यूनीवर्सिटी में देखता हूं कि एम0टेक पास किए बहुत अच्छी परसेन्टेज वाले बच्चे नौकरी के लिए आते हैं तो मैं सोचता हूं कि मेरा बच्चा भी यही कर रहा है तो क्या वह भी इसी तरह से छोटी सी नौकरी के लिए फिरेगा। मां-बाप क्या सोचते हैं कि यह डाक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा लेकिन बहुत अच्छी मेरिट के बच्चे बहुत कम तनख्वाहों पर कालेजेज में काम करते हैं। बड़ी समस्या है लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था करने की जरूरत है। हम समझते हैं कि हम सबकी कोशिश रहेगी तो हम कहीं न कहीं कामयाब होंगे।

*श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। गम्भीर विषय है सुन लें, मुझे जानकारी मिली है अलीगढ़ में ए0पी0 दधउआ चीनी मिल पर किसानों पर गोली चल गई बताते हैं, यह जानकारी टी0वी0 के माध्यम से और वहां से सूचना भी आई है उसके आधार पर कहना चाहता हूं मेरा आपसे निवेदन है कि सदन उठने के पहले मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी वहां से जानकारी हासिल करें कि वहां क्या घटना हुई है। घटना अति गम्भीर है। मैं चाहता हूं कि सदन उठने से पहले वहां से जानकारी मंगा लें और दो शब्द इस पर कह दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

ठीक है अभी जानकारी करा लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 मंत्री जी को सुना डा0 साहब को सुना सब बातें आ गई हैं मैं इसे अग्राह्य करता हूं। तिवारी जी आप तो कल बोलेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप जो कहते हैं वह मैं मान जाता हूं मेरा कल पहले ले लीजिएगा। (शोर)

*डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, कल आगरा में एक बहुत बड़ी घटना हुई। कल दो बजे के करीब आगरा और ग्वालियर हाइवे पर सहस्र ग्रामीण बैंक देहरा में पांच बदमाश घुसे और उन्होंने उस बैंक को लूटने का प्रयास किया। वहां जो ग्रामीण आए हुए थे उनको बन्धक बना लिया गया। वहां के सहायक मैनेजेर सन्तोष कुमार पाठक ने जब इसका विरोध किया तो उनकी मौके पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहां कैशियर अशोक कुमार ने भी उनसे भिड़ने की कोशिश की तो उनकी भी हत्या कर दी गई। मान्यवर, सरकारी खजाने को लूटने का प्रयास किया गया और उन्हें बचाने वाले सहायक मैनेजर और कैशियर की हत्या कर दी गई।यह बहुत बड़ी घटना है। वहां से पचास मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है। मान्यवर, मैंने कल भी यह बात कहीं थी इस पर चिन्ता व्यक्त की थी कि आगरा में अपराध बहुत बढ़ रहे हैं उन पर लगाम नहीं लग रही है।...

डा0 धर्मपाल सिंह-

पिछले 50 दिनों में 22 हत्याएं हो चुकी हैं, 20 लूट की घटनाएं हो चुकी हैं, 10 बलात्कार हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, यह बहुत गंभीर घटना है, सरकार से अनुरोध है कि वह लोग गिरफ्तार किए जायें। आगरा में चाहे किसान हो, व्यापारी हो, चाहे छात्र हों, चाहे महिलाएं हों, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, गंभीर है और सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। लेकिन कोई असुरक्षित नहीं है, यह सूचना गलत है, सब सुरक्षित हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इस पर सम्पूर्ण जानकारी आ जायेगी, मैं इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लेता हूं। इसमें आपकी जांच रिपोर्ट आ जायेगी, सारे तथ्य सामने आ जायेंगे। खन्ना जी, एक मिनट में अपनी बात कह लें।

(श्री योगेन्द्र उपाध्याय, श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा कुछ अन्य सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष-

योगेन्द्र जी, उसी घटना पर अभी माननीय सदस्य बोल चुके हैं। खन्ना जी बोल रहे हैं, आप बैठिए। जब वक्तव्य आ जायेगा तो उस पर जो कहना होगा, कहिएगा। मैंने आपको बता दिया है, मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है, जब वक्तव्य आ जायेगा तो पूछ लीजिएगा।

(श्री योगेन्द्र उपाध्याय के बोलने का प्रयास करने पर)

आप बैठिए, यह नहीं सुना जाएगा। सुरेश कुमार खन्ना जी, आप बोलें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-56 की सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया, मैं आभारी हूं। मान्यवर, बीपीएल कार्ड का वर्तमान में सर्वे चल रहा है, जो लोग 5 हजार रुपये से कम की मासिक आय वाले हैं, ऐसे लोगों को 21 परसेण्ट और कार्ड बढ़ाने का निर्देश भारत सरकार की तरफ से आया और उसी का अनुपालन जनपदों में हो रहा था। शाहजहांपुर वह जनपद है, जहां पर कमियों के कारण, गलतियों के कारण जिलाधिकारी ने दोबारा सर्वे का आदेश दिया था। लेकिन अभी तक वह चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। इसलिए मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसमें दबाव, प्रभाव काम कर रहा है, अपना-पराया काम कर रहा है और निष्पक्षता के साथ जो लोग 5 हजार प्रति माह से कम आमदनी वाले हैं, उन लोगों को बीपीएल कार्ड मुहैय्या नहीं कराया जा रहा है। मान्यवर, यह केवल शाहजहांपुर की समस्या नहीं है, यह सारे प्रदेश की समस्या है। सारे प्रदेश में लगभग 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। मान्यवर, जब 2002 की एक सूची बनी थी, उसके बाद नवम्बर, 2007 में एक आदेश हुआ था कि एक सर्वे कराया जाए। लेकिन राजनैतिक कारणों से अक्टूबर, 2008 में उस सर्वे को वापस ले लिया गया। कोई कानूनी बाधा नहीं थी, कोई कानूनी प्रक्रिया भी इन्वाल्व नहीं थी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यही मांग करता हूं कि जो 2002 की सूची है, अगर दोबारा सर्वे नहीं हुआ, जिसमें 40 परसेण्ट कार्ड अपात्रों के बने हुए हैं और आज जो वृद्धावस्था पेंशन है, वह उसी पर दी जाती है, इन्दिरा आवास उसी पर दिया जाता है और सरकारी अस्पतालों में बीपीएल कार्ड के माध्यम से ही चिकित्सा सुविधा मिलती है। यह पूरे प्रदेश की समस्या है, पूरे प्रदेश में अगर यह सर्वे दोबारा नहीं हुआ, बहुत बड़ा अन्याय उन लोगों के साथ हो रहा है जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं लेकिन उनके पास कार्ड नहीं हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं मैं उनसे भी मांग करता हूं कि इसमें एक बार सर्वे जरूर करवा लें और 04 अक्टूबर, 2008 का शासनादेश देख लें जो बिना वजह इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि इस सर्वे की आवश्यकता

नहीं है। नवम्बर, 2007 में इस सरकार ने किया था और उसको बाद में वापस ले लिया गया। यह प्रदेश के 5 करोड़ लोगों के भाग्य का प्रश्न है। शाहजहांपुर पर मैं विशेष रूप से बल देता हूं। जो प्रक्रिया अपनायी जा रही है वह पारदर्शी हो और एक बार सर्वे करा लें। आपने मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, दो-तीन दिन पहले ऐसा ही प्रश्न था और बहुत लम्बा जवाब मा0 मंत्री जी की तरफ से दिया गया था। सदस्यों की तरफ से भी इस पर कई ऐतराजात् हुए थे। और उन्होंने जो जवाब दिया उसी का तज्करा आपने फिर किया है। एक तो भारत सरकार की अनुमति से ही और जब उनके यहां से डेट्स आती हैं तब ही यहां इस तरह का सर्वे या रीसर्वे होता है। मैं भी आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से आग्रह कर लूंगा कि इस पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मैंने इस सूचना पर माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी को तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 में नहीं आता है। मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जनपद मथुरा में दिल्ली से आगरा तक एन0एच0 2 फोर लेन रोड है। जो कि लगभग 12-13 साल पहले बनाया गया है। उस पर मथुरा-आगरा के मध्य महुअल पर टोल टैक्स का स्टापेज है। मान्यवर, वहां पर 13 साल से वहां के स्थानीय लोगों से एक रुपया भी नहीं लिया जाता था। क्योंकि जनपद मथुरा के उस टोल बूथ के इस तरफ 60-70 गांव हैं और 60-70 गांव उस तरफ हैं। रोजाना पढ़ाई के लिए, कचहरी के लिए, डाक्टरी करने के लिए वाहन उधर से इधर आते हैं और इधर से उधर जाते हैं। मान्यवर, अब हर बार उनको रोककर उनसे जबरन वसूली की जाती है। यह भी कहना चाहता हूं कि जब यह फोर लेन सड़क बनी थी तो जमीन वहां के किसानों की गयी, हमारे मथुरावासियों की ली गयी और उन्होंने वहां के लोगों को रोजगार न देकर बाहरी असामाजिक तत्व भर्ती कर लिये हैं जो शराब पीकर बद्तमीजी करते हैं और जाती हुयी बहन-बेटियों के साथ मिसबिहेव करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह बताइये कि इसमें आपने झगड़े की बात लिखी है। तो यह किस तारीख को झगड़ा हुआ है ?

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, कल ही हुआ है। मान्यवर, उस नेशनल हाईवे पर सात लाइन इधर से आने की और सात लाइन उधर से जाने की है। उसमें सिफ्र दो-दो लाइनों को चालू रखते हैं और पांच-पांच लाइनों को बंद कर देते हैं। एक-दो किमी0 की लाइन लग जाती है। मान्यवर, पिछले 12-13 सालों से वहां पर टोल टैक्स लेने की बात नहीं आयी अभी ऐसी बात चल रही है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि वहां पर जो इस तरह की अनियमितायें चल रही हैं उनको खत्म किया जाये जो स्थानीय लोग हैं जो पास होल्डर हैं जिनके पास आईडेन्टिफिकेशन है उनको आने-जाने दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी इस पर कुछ कहेंगे यह टोल टैक्स माफ कराने की बात कह रह हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं, माफ कराने की बात नहीं है। आपका कहना यह है कि जो बैरियर के दांये-बांये गांव हैं, जो भी आबादी है उनके वाहनों से पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। जब ऐसी सड़कें डिजाइन की जाती हैं तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अड़ोस-पड़ोस के ऐसे रास्ते निकाले जायें क्योंकि जाहिर है कि उन लोगों को बार-बार आना-जाना है तो बार-बार टोल टेक्स देंगे तो कुछ ही दिन में गाड़ी की कीमत तो वह ले लेंगे। यह है तो समस्या मगर यह हमारे अधिकार से बाहर की है। आपके आगे जो लोग बैठे हैं और आपके नेता जी जिनके साथ बैठते हैं। अगर इनकी कृपा हो जाये तो आप क्या पूरे प्रदेश पर कृपा हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

आपने ठीक कहा, यह केंद्र सरकार का मामला है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

चूंकि नेशनल हाई-वे पर या जितने भी फोर लेन बनते हैं प्राइवेट पार्टीस बनाती हैं तो पैसा तो भारत सरकार की जेब में जाता है। और इस तरह के ठेके अच्छे लोगों को मिलते हैं यह भी आप जानते हैं।

श्री अध्यक्ष-

देखिये मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत जल्दी में इसीलिए स्थगित किया था कि चयन करूंगा। यह केन्द्रीय सरकार का मामला है, यहां इसे नहीं उठाना चाहिए। इसे पार्लियामेण्ट में अपने मेम्बर से कह दें वह पार्लियामेण्ट में इसको उठायें। यह यहां का मामला ही नहीं है, फिर भी आप कितना बोल गये। चलिये अब बैठिये, यह नियम-56 में नहीं आता है, इसे अग्राह्य किया जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट का समय लूंगा, मेरे पास सूचना आ गई है, मान्यवर जिलाधिकारी अलीगढ़ ने यह जानकारी दी है कि कुछ किसान मिल के अन्दर दाखिल होना चाहते थे और जो मिल का अपना गार्ड है, जिसके पास 12 बोर की बन्दूक थी, उससे इश्कफल जिसे कहते हैं धक्का-मुक्की हुई और इसलिए कि वह दाखिल न हो सकें। उसी इश्कफल में धक्का-मुक्की में ट्राईगर उसका दब गया है जिससे एक फायर हो गया है। पुलिस की कोई फायरिंग नहीं हुई है, पुलिस मौके पर पहुंच गई है और उस गार्ड के एक फायर से एक छर्रा लग गया है। एस0डी0एम0 उस किसान को लेकर अस्पताल चले गये हैं। अभी तक पुलिस से कोई मतलब नहीं है, पुलिस कण्ट्रोल करने के लिए मौके पर पहुंच गई है।

श्री दलवीर सिंह-

आप उस किसान का समुचित इलाज करवा दें और उस मामले की जांच करा लें, मेरा आपसे निवेदन है, वहां से जो सूचनायें आ रही हैं, किस तरह से मैनेज किया है, क्या सूचना है आपके पास।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मेरे पास तो जिलाधिकारी की बिल्कुल अभी पांच मिनट की सूचना हैं।

श्री दलवीर सिंह-

ठीक है, आप इसकी जांच करा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं देख लूंगा, अगर कुछ भी होगा तो जाहिर है किसी भी किसान के साथ कोई ज्यादती हो, तो उसे सरकार नहीं बरदाश्त करेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मा0 अयूब साहब, आप जल्दी से अपनी बात रख दें, क्योंकि आधा घण्टा खत्म हो रहा है।

डा0 मो0 अयूब-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों को किस आधार पर भवनों का आवंटन होता है। पीस पार्टी उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत के आधार पर पांचवीं सबसे बड़ी पार्टी है जिसके चार विधायक हैं।

(सत्ता पक्ष से आवाज आई कि अब चार विधायक नहीं हैं)

जानकारी नहीं है तो पता कर लो। मान्यवर, पीस पार्टी ने भवन आवंटन के लिए कार्यालय के लिए आवेदन दिया था, जिसे निरस्त कर दिया गया है, उसके बाद भी बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं को भवन आवंटित किये गये हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहूंगा कि अगर पीस पार्टी को भवन आवंटित करने का अथवा कार्यालय के लिए भवन आवंटित करने का नियम है तो उसके आधार पर उसे आवंटित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बैठ जायं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, भवन के बारे में कोई राय है?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं तो सुन्नी मुसलमान हूं, जो मैंने सुना वह यह सुना कि आपने चार सदस्य बताये और इधर से आवाज आई कि चार सदस्य नहीं हैं। तो अब क्योंकि रिकगनाइज्ड पार्टी नहीं है लिहाजा सदस्यों की तादात तस्दीक से नहीं बतायी जा सकती, फिर भी मान्यवर इसे देख लेंगे, अगर नियमों में आता है, तो व्यवस्था की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 सदस्य को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, इसे अग्राह्य किया जाता है।

*श्री विजय बहादुर यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि छात्रों के हित का मामला था, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, पं0 दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोरखपुर में प्रबन्ध समिति की आकस्मिक बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि जिन महाविद्यालयों का अनुमोदन अब तक नहीं हुआ है, उन पर 300 रुपया अर्थदण्ड के रूप में परीक्षा शुल्क लगेगा। ऐसे मैं आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अनुमोदन की प्रक्रिया प्रबन्धन की टीम का होता है, प्राचार्य का होता है, बच्चों पर यह बोझ नहीं जाना चाहिए। चूंकि पूर्वान्चल पिछड़ा हुआ है, गोरखपुर के जो महाविद्यालय हैं अति पिछड़े जगहों पर स्थापित हैं। ऐसे में हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि जो 300 रूपया अर्थदण्ड के रूप में बच्चों के ऊपर लगा हुआ है, चूंकि अनुमोदन करवाना बच्चों का काम नहीं है । अनुमोदन का काम तो वहां की जो टीम है, उसका होता है, जिनके द्वारा विद्यालय खोला गया है वह अध्यापकों का अनुमोदन करवायें और प्राचार्य अनुमोदन करवायें तो अनुमोदन से जुड़ा हुआ बच्चों का मामला नहीं है इसलिये हम चाहते हैं कि लगभग 20 हजार बच्चे, 44 महाविद्यालय ऐसे हैं जिनका अनुमोदन नहीं हो पाया था तो इसमें गोरखपुर के पं0 दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय ने 22 तारीख को, 22.02.2013 को यह निर्णय लिया कि 3 दिन का अवसर दिया जा रहा है। तीन दिन का अवसर 26, 27 और 28 का और उस पर 300 रुपये विलम्ब के साथ, 1408 प्लस 300 सब के सब आके जमा करें तब आपको परीक्षा देने दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष -

मा0 सदस्य यह विश्वविद्यालय का आन्तरिक मामला है। विश्वविद्यालय में उसकी कार्य समिति एग्जीक्यूटिव बाडी होती है, परीक्षा समिति होती है। फीस का निर्धारण का अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग ढंग से, वे आटोनामस बाडी हैं, वही करती हैं। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह एक कुलपति के मनमानेपन का विषय है और यह 300 रुपये जबरन बच्चों से वसूलना, यह किसी नियमावली के तहत नहीं है इसलिये आप इसकी जांच करवा लीजिये। खाली एक जानकारी हो जाये कि जो ये जबरन और मनमाने तरीके से पैसा वसूल रहे हैं, यह गलत है।

श्री अध्यक्ष-

आपने कहा और मैंने यह बता दिया कि यह चूंकि यूनिवर्सिटी का मामला है। इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, ऑटोनॉमस बाडी है। वह गवर्नर द्वारा गवर्न होती है, उनकी परीक्षा समिति होती है, कार्य समिति होती है और ये सब अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से लेते हैं। सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती इसलिये इस प्रश्न को आपने रखा ये नियम-56 में नहीं आता इसे अग्राह्य करता हूं।

* श्री जमीर उल्ला खां-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत अहम है और ऐसा है।

श्री अध्यक्ष-

अरे क्या है, आप नियम-56 में बोलोगे, सरकारी दल से हो। संसदीय कार्य मंत्री जी, आप इनको समझाइये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जमीर उल्ला खां-

मा0 अध्यक्ष जी, देख लीजिये, खाली बस बात समझ लीजिये। हमारे यहां पूरे प्रदेश के अन्दर जो नैचुरल मौत हो जाती है।

श्री अध्यक्ष-

ये कौन विषय है, क्या ये लिख के दिया है।

श्री जमीर उल्ला खां-

नहीं, लिख के नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष-

तो कैसे उठा रहे हैं।

श्री जमीर उल्ला खां-

मान्यवर, लिख के नहीं दिया लेकिन बात तो सुन लीजिये, समाधान तो आपसे ही होना है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, कभी कभी मा0 सदस्यों के लिये बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। स्थानीय राजनीति में उसका मतलब होता है। इनकी परेशानी है, मुझसे बात भी हुयी है लेकिन बेहतर था कि सदन में न होता। मैं जिलाधिकारी अलीगढ़ से बात कर लूंगा। ऐसी मौतें जिनमें परिवार वाले पोस्टमार्टम नहीं चाहते और कोई कम्पलेण्ट भी न हो, कोई कम्पलेण्ट न हो। किसी ने हत्या न की हो, कोई ऐसी शिकायत न हो। कोई पेड़ से गिर मर जाये, कोई कार एक्सीडेण्ट में मर जाये। परिवार वाले नहीं चाहते और लिखकर देना चाहते हैं तो उसमें पंचायतनामा हो जाता है तो अगर कोई ऐसा है, आप कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

तो आप अपने चैम्बर में बुला के कह देते। यहां उठाने की क्या जरूरत थी इनको।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अरे, वो थोड़ा सा संदेश वहां तक पहुंच जायेगा आपके माध्यम से। बस यही मंशा होगी तो मैं इसमें बात कर लूंगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी एक आध मामले में अगर बहुत वाजिब हो तो हम इसे दृष्टान्त बना लें। वरना तो लोग गाड़ी से उड़ा देंगे और पोस्टमार्टम होगा नहीं, कहेंगे साहब पंचायतनामा कर दीजिये। वह भी नहीं होना चाहिये।

शून्य प्रहर का बढ़ा हुआ समय समाप्त होने पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की शेष सूचनाएं कल लिये जाने के निर्देश

श्री अध्यक्ष-

अब विजय बहादुर यादव जी का हो गया। अब आधे घण्टे से ज्यादा हो गया है। मा0 माथुर साहब, अब जितने लोगों का है। कल इसको ले लेंगे प्राथमिकता पर, जो अवशेष रह गये हैं। अब चर्चा करायेंगे।

(कतिपय मा0 सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

(श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या जी द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

मा0 मौर्य जी, अब आधा घण्टा हो गया है। अब चर्चा शुरू करायी जाये। अरे, कल लेंगे, कह दिया कि कल होगा अब। अब मौर्य जी से क्या कह रहे हो। अब मौर्य जी से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो, बैठो, अरे, छोड़िये, अब सबको बुलवाना पड़ेगा। कल सबका ले लेंगे।

आपका भी कल लेंगे, आधा घण्टा टाइम था। जो आप आज दिये हैं, कल मत दीजियेगा। कल मैं इसको दिखवा लूंगा, बैठिये। अब चर्चा प्रारम्भ होगी।

(श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

हां, दादा, आपका भी कल हो जायेगा नियम-56 बैठ जाइये।

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा †

श्री अमरपाल शर्मा-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने मा0 मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण 2013-2014 के अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया। आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, जिस तरीके से हमने ये 2013-2014 का बजट पढ़ा और सुना। और सुना और हमने उसमें देखा कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को खासकर के पश्चिम के जितने भी जिले हैं, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बागपत, मेरठ इनको इग्नोर किया गया है। चूंकि बजट पर हमारे नेता सब कुछ पहले भी बता चुके हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा चर्चा न करके अपने क्षेत्र की तरफ जाना चाहूंगा।

मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा पश्चिमी प्रदेश सबसे ज्यादा राजस्व देता है पूरे प्रदेश को, और गाजियाबाद जिला उसमें से एक जिला है, जो साल का करीब 6-7 हजार करोड़ रूपया राजस्व देता है, लेकिन गाजियाबाद जिले को बिल्कुल इग्नोर रखा गया है। यहां तक की, पश्चिमी प्रदेश के अंदर जितने भी युवा हैं, हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री युवा हैं, इन्होंने उनको भी इग्नोर रखा है। न कहीं उनके लिए स्टेडियम की व्यवस्था की है, न कहीं खेलने की व्यवस्था की है, और इसी के साथ-साथ गाजियाबाद के अंदर जिस तरह से ट्रैफिक का दबाव है, उस ट्रैफिक का संतुलन करने के लिए कोई विशेष योजना इस बजट के अंदर गाजियाबाद को नहीं दिया है, क्योंकि गाजियाबाद एन0सी0आर0 के अन्तर्गत आता है, दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है और वहां पर ट्रैफिक का, इतना दबाव रहता है कि आप भी कई बार वहां गए हैं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी गए हैं, इन्होंने भी देखा है, लेकिन इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए जो बजट पेश किया गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों के साथ यह अन्याय है। यह सरकार ने जो बजट पेश किया है, न गाजियाबाद की जितनी भी वहां की समस्याएं हैं, चाहें नालों की सफाई हो, चाहे वहां की कालोनियां, सैकड़ों कालोनियां वहां पर हैं चाहे उनके विकास की बात हो और सबसे बड़ी जो प्रदेश में नाम से जानी जाती है हिण्डन नदी, उस हिण्डन नदी की सफाई की जब बात होती है, हिण्डन नदी को भी बिल्कुल इग्नोर रखा गया है, न उसमें प्रदूषण से मुक्त कराने का कहीं जिक्र किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिण्डन नदी को भू माफियाओं के द्वारा बेच दिया गया है। आज जब रात को उसके पुल पर आप खड़े हो जाएंगे तो दोनों तरफ की लाइटें आपस में एक साथ मिलकर दिखती हैं, जिससे

† दिनांक 26 फरवरी, 2013 की कार्यवाही से।

लगता है कि यह कोई नदी थी ही नहीं, यहां पर कोई गांव, खेत का कोई बम्बा बह रहा है, उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही करने का या उस नदी को इन भू-माफियाओं से मुक्त कराने का कोई जिक्र इस बजट के अंदर नहीं किया गया है। इसी तरीके से साहिबाबाद के अंदर साइड-4 में जो इन्डस्ट्रीज लगी हुई हैं, उनके द्वारा वहां की कालोनियों में इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि पानी वहां पर ट्रैक्टरों के द्वारा 5 रुपये लीटर बिकता है, क्योंकि वहां का जो भू-जल है, वह बिल्कुल दूषित हो चुका है। उन फैक्ट्रियों का सबका पानी जितना जहरीला है वह नालों में आता है और वह नाले जो कि साफ नहीं हैं, उनका आगे कहीं निकास नहीं है, जिनके कारण वह वही फैलते हैं, और वह पानी वहीं जाता है और वही हैण्डपम्प के द्वारा वहां के नागरिकों को पीना पड़ता है। उनका भी कहीं जिक्र नहीं है, यही नहीं गाजियाबाद के अंदर जो हॉट सिटी कहा जाता है, सभी मा0 सदस्य चाहते हैं कि हम गाजियाबाद में जाकर बसें, सभी मा0 सदस्य चाहते हैं कि हमारा प्लांट गाजियाबाद में हो, हमारा फ्लैट गाजियाबाद में हो, लेकिन विकास के नाम पर, सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला हमारा जिला और उसको बिल्कुल इग्नोर रखा गया है, कहीं कोई नई रोड की व्यवस्था वहां नहीं की गयी है, कोई अस्पताल की व्यवस्था वहां नहीं की गई है, किसी भी सरकारी डिग्री कालेज की वहां व्यवस्था नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब वह प्रदेश को इतना राजस्व दे सकता है, तो उस राजस्व का कम-से-कम 20 परसेन्ट तो आप लगवाएं उसमें। 20 परसेन्ट तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो कहीं 2 परसेन्ट भी लगता नजर नहीं आ रहा हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली से सटा होने के कारण एन0एच-24, एन0एच0-54, जो आए दिन जाम से जूझता रहता है, आप भी चाहें इधर बैठे लोग हों, या उधर बैठे लोग हो, जब भी दिल्ली जाते होंगे तो दो-दो घंटे वहां जाम से जूझते हैं। उस जाम से मुक्ति के लिए कोई भी बजट में प्राविधान नहीं किया गया है। यहां तक कि जो मैंने अभी बजट पढ़ा, उसमें क्रिकेट के स्टेडियम की बात की गई है, लेकिन जो हमारा नेशनल गेम है कबड्डी है, कुश्ती है, उनका कहीं जिक्र तक नहीं है, इससे यह लगता है कि अपना सरकारी बजट प्रस्तुत किया गया है मुख्य मंत्री जी के द्वारा।

मान्यवर, इसलिए पश्चिम का खासकर ध्यान नहीं रखा गया है इस बजट में। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन न करके मैं इसका विरोध करता हूं

*श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी एवं गरिमामय सदन, आपने वित्तीय वर्ष 2013-2014 के बजट भाषण के पक्ष में जो चर्चा हो रही है उसमें आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। मान्यवर, बजट भाषण किसी सरकार का दस्तावेज होता है वह दस्तावेज जिसमें उसकी नीयत और नीति दोनों नजर आती है और यकीनन यह बजट कोई जो सरकार ने पेश किया है वह समाजवादी विचारधारा की अक्कासी करता हुआ नजर आता है। मैं इसलिए इसके पक्ष में नहीं कह रही हूं कि यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बड़ा होना बड़ी बात नहीं है बड़ी बात है उस समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना जो सचमुच समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। बजट इससे पहले भी आये 5 सालों तक आये लेकिन लोगों ने देखा कि उस बजट में कहीं भी आम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इंसान नहीं था आम इंसान की जरूरतें नहीं थीं वह बजट जिन्दा इंसानों के शहर का नहीं बल्कि शहरे-खमोशा का बजट था। वह बजट पत्थरों के शहरों का बजट था। एक ऐसा बजट था जो पत्थरों के बेजान मोसूमों के लिए जगह रखता था लेकिन जिन्दा इंसानों के लिए नहीं। उस पत्थरों के बेजान शहर के बजट में एक आदमी की हसरें उसकी उम्मीदें उसकी जरुरतें उन बेजुबान पत्थरों से सर टकरा टकरा करके खत्म हो गयी थीं और उसके सामने ना उम्मीदी का घना कोहरा था। उस वक्त जब यह बजट आया है तो उससे हटकर क्योंकि वह वक्त था जब उसकी आवाज कोई नहीं सुनता था, उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। उस किसान की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। उस मजलूम की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी आवाजें शहरें खामोशा म्रें टकराकर के लौट आती थीं। मान्यवर आलम यह था कि कि बेनूर का चेहरा सुलत था, आंखों में गजब की सुर्खी थी, तकरीब के परचम किया था सच्चे में पड़ी चारों तरफ थी तासीरें। तकरीबकारों की जमात थी तामीर का काम रुक गया था। जब तामीर का काम रुक गया है सिर्फ घोटाले हो रहे हों, कहीं एन0एच0आर0एम0 हो कहीं पर मनरेगा हो, कहीं पर लेकफैड घोटाला हो रहा हो आलम यह था कि सूबे का निजाम दरहम बरहम हो चुका था शिरजा बिखर चुका था खजाना खाली था। तकरीबकारों की जमात थी। मेजों की थपथपाहट। शिराजे बिखरे हुए थे और इस बिखरे हुए शिराज के तिनकों को चुनना आसान नहीं था।

''तिनके उधर उधर से लगे पड़े हैं मुझको तब जाकर हो सका है तामिर आशियाना।''

तो यह बजट मान्यवर जब जाकर के पेश हो सका है जब इधर उधर से हमने तमाम कोशिशें करके इस बजट को लाने की कोशिश की। उसमें से सिजादे खोज-खोज कर इस बजट को बनाने का काम किया गया है। मेंजों की थपथपाहट। मान्यवर वित्तीय घाटा जी0डी0पी0 का तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, उसके अनुमन्य सीमा के अन्दर है। यह बजट वह बजट है जिसमें किसानों के बारे में सोचा गया है। पिछले वर्ष में 18000 करोड़ रुपये का गन्ना किसानों को भुगतान के लिए धन रखा गया था। हमारी सरकार ने इस बजट में उसे बढ़ाकर 21000 करोड़ रुपये करने का काम किया है। सिफ्र इतना ही नहीं किसानों की ऋण माफी के लिए भी पैसे की व्यवस्था इस बजट में की गयी है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के इस बजट में 750 करोड़ रुपये किसानों के लिए रखा गया है। पिछले वर्ष यह रकम 900 करोड़ रुपये थी इस तरह से मिलाकर कुल 1650 करोड़ रुपये हुए जिससे प्रदेश के आठ लाख किसान लाभान्वित होंगें। मान्यवर, सिफ्र इतना ही नहीं किसानों को सस्ती बिजली दी जा सके, मुफ्त बिजली दी जा सके सिंचाई के लिए उसके लिए दो सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था अपने बजट में की है। किसानों के लिए दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत 375 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर इतना ही नहीं हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले घोषणा की थी कि हम चार प्रतिशत की व्याज दर पर किसानों को ऋण देंगें। मैं फक्र के साथ कहना चाहती हूँ कि समाजवादी सोच के हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस चार प्रतिशत की ब्याज दर को घटाकर तीन प्रतिशत दर पर तीन लाख रुपये तक का ऋण देने की बात कही है। जो अल्पकालिक फसली ऋण टैक्स के माध्यम से जो प्रारम्भिक सहकारियां समितियां हैं उनके माध्यम से देने की व्यवस्था की गयी है। अक्सर बात आती है, हम लोगों ने भी पिछले वर्ष खाद की कमीं को देखा था, महसूस किया था उस कमीं को, किसानों के दर्द को महसूस किया था और इसका नतीजा है किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके इसलिए

दो लाख मीट्रिक टन यूरिया और 7.38 लाख मीट्रिक टन फास्फेटिक उर्वरक को इकट्ठा करने के लिए, उसके भंडारण के लिए अग्रिम 100 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। यह व्यवस्था क्या बताती है यह व्यवस्था वह कर सकता है जिसने किसानों के दर्द को समझा हो । यही नहीं जो इंदिरा आवास मिलते थे वह उन्हें ही मिलते थे जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में था। अक्सर बात आई है इधर से भी और उधर से भी कि बी0पी0एल0 सूची किस तरह से बनती है जो गरीब है उसका नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं है जो अमीर है उसका नाम बीपीएल सूची में था ऐसा हुआ है मान्यवर, इसलिए यह घोषणा की है इस सरकार ने कि ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक आय 36 हजार से कम है और जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं है उनके लिए भी 2 कमरों के आवास के लिए एक लाख रुपये अनुदान के रूप में दिये जायें साथ ही सोलर लाइट के लिए भी 15 हजार रुपये की व्यवस्था की गयी। लोहिया ग्राम, लोहिया समग्र विकास ग्रामों के लिए लगभग 2100 ग्रामों को वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए लिया गया जिनको सम्पर्क मार्गों से जोड़ दिया जायेगा। इतना ही नहीं मान्यवर, त्वरित योजना के अन्तर्गत 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी ताकि सड़कों का या और भी चीजों का निर्माण कार्य हो सके।

जहां तक छात्राओं की बात है चाहे वह किसी समुदाय की रही हों, सरकारी या अनुदानित जो भी महाविद्यालय हैं उनमें स्नातक स्तर तक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने के लिए इस बजट में प्राविधान किया गया है। किसानों की जहां तक बात है चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो या किसान पेंशन हो उसके लिए भी अलग से 1683 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था प्राविधानित की गयी है इस बजट में । यह मामूली बात नहीं थी चाहे वह रानी लक्ष्मी बाई पेंशन येाजना रही हो साढ़े बारह सौ करोड़ उसके लिए रखे गये और अल्पसंख्यक समुदाय की जो बेटियां थी उस समुदाय की वह बेटियां उनके लिए एक योजना यह सरकार लाई 'हमारी बेटी उसका कल' और उसके लिए 350 करोड़ रुपये रखे गये, कब्रिस्तानों के लिए 300 करोड़ रखे गये लेकिन ऐसा नही है मान्यवर, कि सिफ्र कब्रिस्तानों के लिए रखे गये बल्कि जो हमारे काबिल स्टूडेन्ट थे, जो हमारे मेधावी छात्र थे उनके लिए अल्पसंख्यक बहुल्य छात्रों में एजूकेशन हब बनाने के लिए 34 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया ताकि वह पैरामेडिकल हो या आई0टी0आई0 हो या इंजीनियरिंग के लिए भी वह कोचिंग कर सकते हैं उसकी व्यवस्था की गयी, यह व्यवस्था कौन कर सकता था यह व्यवस्था की गयी मान्यवर, और केवल इतना नहीं सभी जानते हैं कि कोई भी प्रदेश बिना सड़को के बिना बिजली के आगे नहीं बढ़ सकता है यह आधारभूत ढ़ांचा है जिस पर किसी प्रदेश की इमारत बनती है या बिगड़ती है और इसीलिए पी0डब्लू0डी0 का अब तक का सबसे बड़ा बजट है सम्भवतः 7848 करोड़ रुपये। यह बजट इसलिए रखा गया ताकि सड़कों का नवनिर्माण हो सके, पुरानी सड़कों की मरम्मत हो सके, पुलों का निर्माण हो सके क्योंकि हालत यह थी कि आपने एक वर्ष पहले भी देखा होगा कि पता नहीं चलता था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क के अन्दर गड्ढे हैं। आज जब चलते हैं हम, आप लखनऊ से आजमगढ़ चले जायें वह सड़क जिस पर चलना मुश्किल था, यह वह सड़क है जिस पर 3-3 मंत्रियों का आवास पड़ता था उस सड़क पर चलना मुश्किल था लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उस सड़क पर आप आराम से जो सफर 3 घन्टे में तय करते थे वह सफर 2 घन्टे में आराम से तय कर सकते हैं। ऐसा बजट हमारी सरकार ने रखा।

जहां तक सवाल उर्जा का है, माननीय उर्जा मंत्री जी बैठे हुए हैं और कोई दिन इस सदन में ऐसा नहीं जाता जब उर्जा के ऊपर बात न होती हो और इसीलिए अब तक का सबसे बड़ा बजट आया 11,732 करोड़ रुपये का, जो पिछले बजट से 24.5 प्रतिशत ज्यादा है । किसी बजट का ज्यादा होना बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है उसका इम्प्लीमेन्टेशन । आज आप लोगों ने कहा कि बिजली की दिक्कत है, बिजली की किल्लत है, लेकिन मैं इस सम्मानित सदन से कहूंगी कि यह किल्लत, यह शार्टेज क्या एक-आध दिनों में हुयी। इन पांच सालों में क्या कोई नई विद्युत परियोजना लगी ? अगर हरदुआगंज की बात होती है, रोजा की बात होती है, अनपरा सी की बात होती है तो यह परियोजनायें किसकी थीं ? ईमानदारी से कहियेगा कि क्या यह परियोजनायें आपकी थीं, या समाजवादी पार्टी की सरकार की यह परियोजनायें थीं, चाहे अनपरा सी रहा हो, चाहे हरदुआगंज रहा हो। हां, अगर आपकी सरकार में कुछ हुआ तो यह जरूर हुआ और यह मैं नहीं कह रही हूं, आप सांख्यिकी आकड़ें उठाकर देख लीजिये कि वित्तीय वर्ष 2007-08 से लेकर लगातार वर्ष 2011-12 तक आपकी सभी इकाईयों का चाहे वह अनपरा हो, चाहे वह ओबरा हो, हरदुआगंज हो, पनकी हो या पारीछा हो, इन सबका उत्पादन लगातार गिरता चला गया । क्यों गिरता चला गया, इस पर जरा गौर कीजियेगा। 22 हजार लाख यूनिट था और उससे घटते-घटते हम आपको सिर्फ यह दिखाना चाहते हैं कि ताकि आप अपनी आंखों से स्पष्ट देखें कि मेरे कहने का कोई स्पष्ट आधार है, इसको आप स्वंय देख सकते हैं कि लगातार विद्युत का उत्पादन घटता चला गया। वर्ष दर वर्ष घटता चला गया, मॉग बढ़ती चली गई, आपने इसके लिये क्या किया, क्या उत्पादन बढ़ाने के लिये कुछ किया । नहीं, अगर कोई प्रयास किया होता तो निश्चित रूप से रोजा जैसी कोई परियोजना शुरू हो सकती थी, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश अंधेरे में जूझता रहा और आप पत्थरों की उस इमारत को रोशनी में नहलाते रहे हैं जो जिन्दा इंसानों की नहीं मुर्दा लोगों के मकाबिल थी । सोचना पड़ेगा हमें, इसलिये सोचना पड़ेगा, मैं एक बात सुझाव के रूप में कहूंगी कि हमारे जो थर्मल प्लान्ट हैं, जो कोयले से ऊर्जा बन रही है, वह अक्षय भंडार नहीं हैं। वह भंडार खत्म होगें इसलिये हमें नान कन्वेन्शनल इनर्जी, रिनीवेबिल इनर्जी, रिक्नेशिबिल इनर्जी की तरफ आना होगा और अकेला हिन्दुस्तान नहीं, विश्व के देशों में अगर आप देखें ता 82 देश ऐसे हैं, जो विन्ड इनर्जी को लेकर व्यवसायिक स्तर पर शुरूआत कर चुके हैं। डेनमार्क को अगर आप देख लें तो पहले उसकी टोटल ऊर्जा का एक चौथाई लगभग विन्ड इनर्जी से आ रहा है, पहले 2.5 प्रतिशत था यह पूरे विश्व की विन्ड इनर्जी का आज वह प्रतिशत बढ़कर 25 पहुंच रहा है और खुद हिन्दुस्तान में चाहे वह तामिलनाडु हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो, विंड इनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, सोलर इनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है । हमें भी इसके इस्तेमाल को बढ़ाना होगा, बायोमांस पर करना होगा और एक चीज जो सबसे सरल है, सुलभ है और चूंकि मैं पूर्वांचल की हूं इसलिये कह रही हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूर्वांचल को बहुत दिया है, 291 करोड़ दिये हैं, उसके लिये हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन पूर्वांचल में धान बहुत होता है, धान की भूसी का अगर हम विद्युत उत्पादन में उपयोग करें तो हम समस्या को दूर कर सकते हैं, इसी तरह से एक दूसरा सेंटर बन सकता है, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं का, यह भी धान उत्पादक क्षेत्र हैं। चन्दौली, गाजीपुर, बलिया, बनारस है, जहां से आप देख सकते हैं, पटना में भूसी से उत्पादन करके डेढ़ किमी0 के क्षेत्र में, कम से कम 600-700 घरों को बिना ग्रिड के बिजली दी गयी है, इसे बढ़ाया जा सकता है। एक चीज जरूर कहूंगी कि उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था

की रीढ़ होते हैं। उद्योगों के लिये प्रयास किया गया है, सराहनीय प्रयास है, मैं उस क्षेत्र की हूं इसलिये अपनी बात जरूर कहूंगी । हमारे क्षेत्र में बड़ौरा की एक मिल है, वह मिल सालों से बीमार चल रही है, उसके परिसर में कम से कम तीसों एकड़ जमीन है और उसके अंदर खाद्य प्रंसस्करण इकाई लगाई जा सकती है, इससे कई लाभ होगें, अमरूद की जेली बनाने का कारखाना लग सकता है, इससे अमरूद के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, केले के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। केले के चिप्स केवल साउथ में ही नहीं, बल्कि इसकी विदेशों में भी खपत है। आलू का उत्पादन पूर्वांचल में अच्छा होता है, वह खप सकता है, इनको लगाया जाए क्योंकि इसमें महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। महिलाओं को उनकी गरीबी से निजात दिलाने के लिए 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को दो साड़ी देने का वायदा इस सरकार ने किया है और 6 सौ करोड़ रुपए की अपने बजट में व्यवस्था भी की है। यह व्यवस्था कौन कर सकता है, कौन कर सकता है यह व्यवस्था, यह सोचना होगा। अगर रिक्शा चालकों को बैटरी चालित रिक्शा देने के लिए किसी ने सोचा तो यह सोचा है कि वह इंसान जो अपना खून-पसीना बहा करके फटी हुई कमीज में अपने आपको खींचता हुआ लोगों को खींच रहा है, उस इंसान के बारे में सोचना समाजवादी सोच का ही परिचायक है वरना तो लोग वो थे जिनको तब भी चैन नहीं पड़ता था जब गरीबों के जिस्म के ऊपर अगर लिबास भी बाकी रहता था। लोगों ने देखा है कि पत्थरों के मुजस्समें पर इतना खर्च हुआ लेकिन प्रदेश का गरीब किसान फटी हुई कमीज के लिए तरसता रहा है और लोग अट्टहास लगाते रहे हैं कि फकीरे शहर के जिस्म पर लिबास बाकी है,

फकीरे शहर के तन पर लिबास बाकी है,
अमीरे शहर के अरमॉ अभी कहां निकले हैं।

अमीरे शहर के अरमान तब तक नहीं निकले जब तक फकीरे शहर के जिस्म के ऊपर चीथड़े कपड़े भी नजर आते रहे। आज आप कह सकते हैं कि पूरी समस्याएं खत्म नहीं हुईं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्या, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, मैं दो बातें कहकर अपनी बात को खत्म कर दूंगी। मैं महिला हूं इसलिए कह रही हूं मैंने स्वयं बनारस के जैतेपुरा में देखा कि वहां पर जो विक्षिप्त महिलाएं हैं मान्यवर, वह महिलाएं विक्षिप्त नहीं थीं, वहां रोते हुए अपनों की बेरुखी ने उन्हें तोड़ दिया, वह विक्षिप्त हो गई हैं और उनके साथ जो सामान्य हैं उन्हें भी उनके साथ रहना पड़ रहा है। इसलिए मेरी तरफ से प्रस्ताव है कि इसे भी इसमें जोड़ लिया जाए कि कम से कम जो विक्षिप्त मानसिक रूप से महिलाएं हैं उनके रहने के लिए अलग से व्यवस्था कर दी जाए। यह व्यवस्था इसलिए जरूरी है ताकि उनका इलाज हो सके। मान्यवर, यह पहले की खामियां हैं, हमारी सरकार ने तो उन्हें दूर करने की कोशिश की है लेकिन कोई भी सरकार रातोंरात चमत्कार नहीं कर सकती है। हमसे यह उम्मीद की जाती है कि यह सरकार रातोंरात चमत्कार कर देगी, हम सिर्फ इतना कहकर अपनी बात को खत्म कर देते हैं कि चलिये मान लिया हमने कि हम इसको गुलशन नहीं बना सके, मान लिया हमने कि हम हर राह को फूलों से नहीं सजा सके, मान लिया हमने कि सबके आंसू नहीं पोछ सके, लेकिन इतना तो आप भी मानेंगे कि-

माना कि हम चमन को नहीं गुलजार कर सके,
कुछ खार कम तो कर सके गुजरे जिधर से हम।

अगर हम थोड़े-थोड़े खार कम करते रहेंगे तो यकीन मानिये कि आने वाले पांच सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जायेगी, तकदीर बदल जायेगी, हिन्दुस्तान बदल जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बजट भाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं, आपने हमें बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद्।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, फातिमा जी इतनी अच्छी वक्ता हैं, पिछले पांच साल से बोल रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप भी उसी टक्कर के हैं।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

लेकिन यह समाजवादी पार्टी महिलाओं के आरक्षण की विरोधी तो है ही, बोलने वाली महिलाओं की भी विरोधी है। ऐसी मंत्री बनाया जिसको हम लोगों ने अभी तक सदन में बोलते हुए नहीं सुना। मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर हम लोगों को अपना विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। पिछले वर्ष जब हम लोग बजट पर बोल रहे थे तो हम लोगों ने कहा था कि नई सरकार है, नये मुख्य मंत्री हैं और इस नाते अभी हम लोग इस सरकार के बजट पर कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। साल भर का मौका देंगे और देखेंगे कि यह सरकार काम क्या करती है। मान्यवर, साल भर का समय लगभग बीत रहा है, बजट पर आने से पहले मैंने स्वाभाविक रूप से जो विकास की प्रतीक संस्था है उत्तर प्रदेश की पी0एच0डी0 चैम्बर, मैंने उसकी वेबसाइट को खोल कर देखा। उत्तर प्रदेश के बारे में इस प्रदेश के उद्योगपति कहते क्या हैं, क्या माहौल वह महसूस करते हैं इस उत्तर प्रदेश के बारे में। बड़ा आश्चर्य सा लगा, गवर्नेन्स के बारे में वह प्रदेश को नौवां स्थान देते हैं, कानून-व्यवस्था के बारे में नौवां स्थान देते हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में बीस प्रदेशों में वह सोलहवां स्थान देते हैं, इकोनॉमिक विकास के जो इंडेक्स हैं उनमें बीस प्रदेशों में वह सोलहवां स्थान देते हैं, जो कन्ज्यूमर मार्केट है, जिसके बारे में उद्योगपति लगातार चर्चा करते हैं, उसमें चौदहवां स्थान देते हैं। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 19वां स्थान देते हैं और जो निवेश का माहौल बनता है उसके बारे में 17वां स्थान देते हैं। कुल मिलाकर विकास की कल्पना जो बनाते हैं कि देश के विभिन्न प्रदेश कम्पोजिट इण्डेक्स ऑफ डेवलेपमेण्ट में कहां खड़े होते हैं, इस प्रदेश के उद्योगपति यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का स्थान 15 बड़े राज्यों में फिलहाल 14वां है। जिस प्रदेश के उद्योगपति प्रदेश के बारे में ऐसा आर्थिक आंकलन करके बैठे हैं, उस प्रदेश का बजट प्रस्तुत हो 17.64 लाख करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट की बात हो और सरकार यह कहे कि इसमें से 12 लाख 51 हजार करोड़ रुपये निजी क्षेत्र से निवेश किये जायेंगे। समझ में नहीं आता कि उद्योगपति अगर इस प्रदेश के बारे में एक ऐसा ही आंकलन करके बैठे हैं तो यह 12.51 लाख करोड़ रुपये निवेश में आयेंगे कहां से ? पांच साल का, एक साल अध्यक्ष महोदय, बीत चुका है। एक साल के अन्दर कितना निवेश हुआ ? जो आंकड़े हम लोगों को दिये गये हैं, कुल मिलाकर 5700 करोड़ रुपये का निवेश इस प्रदेश में हुआ है। 5700 करोड़ रुपये से 12 लाख 51 हजार करोड़ रुपये की यात्रा आने वाले चार सालों में किस प्रकार से पूरी होने वाली है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह हम लोगों के समझ से परे है। जो भारत सरकार ने देश के विभिन्न प्रान्तों का इकोनॉमिक सर्वे आज का प्रस्तुत किया है, देश के विभिन्न प्रांतों की आर्थिक स्थिति की उसमें चर्चा आयी है। आज की ही बात है। उस चर्चा को पलट करके देखिये। प्रदेश की आय की जो सूची बनती है, आय की सूची में उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे नीचे आता है। अध्यक्ष महोदय, औसत आय प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश की आज के दिन तकरीबन 29,500 रुपये है जबकि देश की औसत आय प्रति व्यक्ति इस समय 61 हजार रुपये है और उत्तर प्रदेश तकरीबन 29500 रुपये की सीमा पर खड़ा है अर्थात जितनी एक औसत देश के नागरिक की आय होती है उत्तर प्रदेश में रहने वाले नागरिक की औसत आय उसके ठीक आधी है। पिछले साल का जो बजट आया था और इस साल का जो बजट आया है, आर्थिक समीक्षा के आंकड़े छपे हैं। पिछले साल इस प्रदेश के ऊपर 2.28 लाख करोड़ रुपये का ऋण था। आज जो बजट के साथ हम लोगों को आंकड़े दिये गये हैं, यह ऋण 11 हजार करोड़ रुपये बढ़ गया अर्थात 500 रुपये प्रति नागरिक पर ऋण बढ़ गया। लेकिन जब देश की आय की सीमा पर चलने का प्रयास करते हैं तो एक औसत आय 60 हजार रुपये, हम लगभग 30 हजार। ऐसे-ऐसे प्रान्त हैं, गुजरात की चर्चा मैं करूं वहां 63 हजार रुपये प्रति व्यक्ति आय आज गुजरात की है जबकि हमारी साढ़े उन्नीस हजार रुपये प्रति व्यक्ति आय है। इतना बड़ा अन्तर प्रति व्यक्ति आय में है। सवाल है कि अन्तर पूरा कैसे होगा ? अध्यक्ष महोदय, यह अन्तर सड़कों के बनने से नहीं पूरा होगा, यह अन्तर इस बात से पूरा होगा कि यहां उद्योग-धन्धे कितने लगते हैं ? यहां कितने लोग उद्योग-धंधों में काम कर पाते हैं ? कितने लोगों को हम उद्योग-धन्धों में रोजगार दे पाते हैं। जो सरकार की एनुअल रिपार्ट्स आयी हैं, नियोजन विभाग से रिपोर्ट्स निकाल करके उसे हम लोगों ने पढ़ा है। आज स्थिति यह है कि प्रति लाख जनसंख्या पर हमारे जितने लोग उद्योगों में काम करते हैं। आज की स्थिति इस सरकार के साल भर के कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूं देश के औसत के मुकाबले हम लोग बहुत पीछे हैं। देश में औसतन एक लाख में तकरीबन सवा सात सौ लोग उद्योगों में काम करते हैं और हमारे प्रदेश का औसत तकरीबन तीन सौ लोगों का है। अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु जैसा प्रान्त जहां आठ घण्टे बिजली नहीं मिलती इस बात की चर्चा हो जाती है सदन में, मैं सुनता रहता हूं कि बिजली को लेकर उद्योग-धंधे नहीं आ रहे हैं। उद्योग-धंधे नहीं आ रहे हैं तो सिर्फ बिजली कारण नहीं है क्योंकि सिर्फ बिजली के कारण उद्योग-धंधे नहीं आते, अगर ऐसा होता तो सबसे कम उद्योग तमिलनाडु में लगे होते। तमिलनाडु में आठ-आठ घंटे, नौ-नौ घंटे उद्योगों को बिजली नहीं दी जाती है। देश में सबसे ज्यादा उद्योग जहां लगे, जहां देश में सबसे अधिक एक लाख की जनसंख्या पर उद्योगकर्मी काम कर रहे हैं वह संख्या अध्यक्ष महोदय, बाइस सौ-तेईस सौ लोगों की है। इतना बड़ा अन्तर एक ऐसे प्रान्त का है जो देश का सबसे बड़ा प्रान्त है, जिसने देश की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, जहां आज प्रदेश के तकरीबन 17 प्रतिशत लोग रहते हैं। हम विकास के पायदान पर इतने नीचे चले आये हैं और स्वाभाविक रूप से बिजली की चर्चा हो रही थी स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश का विद्युत उपयोग देश के ढेर सारे प्रदेशों के मुकाबले हम बहुत नीचे हैं। हमारा जो विद्युत का उपयोग है मुश्किल से 330 कि0वा0 आवर के आस पास होगा। माननीय पूर्व ऊर्जा मंत्री जी हैं उनके पास आंकड़े होंगे आंकड़े सदन में रखे जाएंगे ऐसे ऐसे प्रदेश हैं जिनके प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग 1500-1600 कि0वा0आवर हैं हम आज भी वहीं पड़े हुए हैं हम बात इतनी सारी करते हैं सच्चाई यह है कि बजट की किताब को उठाकर पढ़ लीजिए अध्यक्ष महोदय इस साल नई विद्युत परियोजनाओं

के लिए इस सरकार ने कुल मिलाकर एक हजार 70 करोड़ की व्यवस्था की है। एक मेगावाट विद्युत पैदा करने के लिए पांच करोड़ रुपए लगते हैं एक हजार 70 करोड़ की आपने बजट में व्यवस्था की है नए विद्युत के उद्योगों के लिए इसका मतलब यह है कि सरकार पूरे प्रदेश के लिए कुल 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन बढ़ाने का वायदा कर रही है। अन्यथा कहीं और से यह पैसा नहीं आने वाला है। उद्योग धन्धों की बात अगर हम छोड़ भी दें माननीय मंत्री जी गांव और सरकार की चर्चा कर रहे थे माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे अगर उन आंकड़ों को हम छोड़ भी दें आज स्थिति क्या है कि हम जब विकास के लक्ष्य की चर्चा करते हैं तो हर व्यक्ति की निगाह मिलियम डेवलपमेंट गोल्ड पर जाती है। सहस्त्राब्दि विकास लक्षण पर जाती है। जो हम लक्ष्य तय करते हैं विकास के उन पर जाती है। उन लक्ष्यों से हम कितने पीछे हैं यह सरकार कभी बताने का काम नहीं करती है। पिछली सरकार ने भी पांच साल काम किया है मैं उस सरकार के बारे में आज चर्चा करूं इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता यह सरकार अगर पूरी ईमानदारी से काम कर रही होती तो बहुमत की सरकार थी दुबारा वहां होती। मैं इस बात से डरता हूं कि एक बहुमत की सरकार प्रदेश को विकास में पीछे छोड़ चुकी है दूसरी बहुमत की सरकार जो लक्षण दिख रहे हैं शायद उससे बेहतर नहीं होने वाले हैं। आज भी जितने भी स्वाथ्य सूचकांक अध्यक्ष महोदय हैं सबसे अधिक चर्चा होती है इनफैंट मोर्टेलिटी की पूरे देश में सबसे अधिक इनफैंट मोर्टेलिटी थोड़ी सी बिहार की कहने के लिए एक प्वाइंट अधिक होगी अन्यथा सबसे अधिक इन्फैंट मोर्टेलिटी देश में अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। यह ऐसे मोर्टेलिटी है जिसको ठीक करने के लिए बहुत अधिक खर्चा नहीं चाहिए बहुत पैसे नहीं चाहिए जो व्यवस्थाएं हमारे पास हैं उन व्यवस्थाओं को सुधारने की जरूरत थी। माननीय मंत्री जी अक्सर यहां आते हैं और कभी जब वह बहस में चर्चा करते हैं बहुत कड़ी बातें कहते हैं लेकिन साल भर हो गया कोई परिवर्तन जैसा दिखा हो जननी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में कोई परिवर्तन हो गया हो संस्थागत वित्त डिलीवरी में कोई परिवर्तन हो गया हो जो महिलाएं एण्टी नेटल केयर के लिए जाती हैं उनके प्रतिशत में कोई परिवर्तन हो गया हो उनको जो आयरन और फोलिक एसिड के टेबलेट दिए जाते हैं उनमें कोई परिवर्तन हो गया हो उनको जो टिटनेस के टीके लगाए जाते हैं उसमें कोई परिवर्तन हो गया हो डिलीवरी के दौरान जो उनकी देख-रेख होनी चाहिए डिलीवरी के बाद जो उनकी देख-रेख होनी चाहिए उसमें कोई परिवर्तन हो गया हो जो कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं उनके न्यूट्रीशन और उनके पोषण की व्यवस्था में जो आई0सी0डी0एस0 में भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें कोई परिवर्तन हो गया हो । सच्चाई यह है कि इस साल स्थितियों में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया। वास्तविक सच्चाई यह है कि कल आंकड़े प्रकाशित हुए हैं एनुअल हेल्थ सर्वे के इस साल के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं और कुपोषण की दर मैं अभी अपने सदस्यों से जिक्र कर रहा था ऐसे ऐसे जनपद हैं फिरोजाबाद का मैंने नाम लिया जहां 100 में से 85 बच्चे कुपोषित होकर पैदा होते हैं औसत देखा जाता है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो तीन में से एक बच्चा कुपोषित होकर पैदा होता है। इसका फल यह है कि उत्तर प्रदेश में जो तीन साल से नीचे के बच्चे हैं उनमें आधे से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। यह सारी व्यवस्थाएं सुधारने के लिए हमें अतिरिक्त पैसा नहीं चाहिए भारत सरकार आई0सी0डी0एस0 के लिए बहुत पैसा देती है। सिस्टम को ठीक करने की बात है। लगातार हम यह कहते आ रहे हैं कि आई0सी0डी0एस0 जिसे हम बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना का नाम देते हैं वास्तव में यह बाल विकास और पशु आहार योजना हो गई है साल भर बीतने के बाद भी किसी ने प्रयास भी किया हो क्योंकि

आई0सी0डी0एस0 को ही हमने सुधार दिया होता तो गर्भस्थ जो महिलाएं होती हैं उनके कुपोषण की दर में बच्चों के कुपोषण की दर में और जो गर्भस्थ महिलाएं होती हैं उनमें खून की कमी दर में क्योंकि प्रदेश में सबसे अधिक गर्भस्थ महिलाएं उत्तर प्रदेश में होती हैं। अध्यक्ष महोदय 52 प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जो खून की कमी के दौरान अपने बच्चों को जन्म देती हैं। ऐसी-ऐसी महिलाएं हैं जिनके होमोग्लोबिन दो ग्राम और चार ग्राम तक होते हैं यह सारी व्यवस्था इसी सिस्टम को ठीक करके बिना किसी अतिरिक्त पैसे के हम लोग ठीक कर सकते थे।

माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोगों के बीच बैठे हैं। असद की रिपोर्ट आई है अभी नई नई रिपोर्ट आई है, दिसम्बर 2012 तक का सर्वे हुआ है। जब शिक्षा का बजट आयेगा तो हम उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। एक प्रतीक के रूप में मैं बता दूं कि एक सर्वे यह है कि कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चों का शैक्षणिक स्तर कैसा है ? मैं इसलिये कहता हूं क्योंकि मंत्री जी अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं कि मेरे बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे आप सबको भी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। अच्छी चीज भी है, मैं उसका विरोध भी नहीं करता हूं। हम लोग उसके समर्थक हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ? यह दिसम्बर 2012 की रिपोर्ट है इसलिये सरकार यह नहीं कह सकती कि हमारे कार्य काल की रिपोर्ट नहीं है। कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ 47 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा दो की किताब पढ़ पाते हैं, पढ़ते हैं कक्षा 5 में। 15 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 1 की किताब पढ़ पाते हैं जबकि पढ़ते हैं कक्षा 5 में। 13 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ शब्द पढ़ पाते हैं और पढ़ते हैं कक्षा 5 में। 20 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो अक्षरों को पढ़ पाते हैं और 10 प्रतिशत बच्चे कक्षा 5 में पढ़ने वाले ऐसे हैं जो किसी शब्द और अक्षर को नहीं पढ़ पाते हैं। आप कितना देते हैं पैसा शिक्षा पर इसका कोई महत्व नहीं। आप कितने विद्यालय खोलते हैं इसका कोई महत्व नहीं। कितने शिक्षक एप्वाइन्ट करते हैं इसका भी महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि शिक्षा की गुणवत्ता में आप कितना परिवर्तन करते हैं। अगर शिक्षा की गुणवतत्ता अध्यक्ष महोदय यही है तो आज स्वाभाविक रूप से जितने भी बजट पारित कर लीजिये। मैं इसीलिये इस बात की चर्चा करता हूं कि हम यह कह सकते हैं, यह दावा कर सकते हैं कि हमारी साक्षरता 69 प्रतिशत हो गई। हालांकि देश की साक्षरता के औसत में यह बहुत पीछे है। आज ग्रामीण क्षेत्र में जो महिला साक्षरता है उत्तर प्रदेश की और ग्रामीण क्षेत्र में जो केरल की महिलाओं की साक्षरता है, दोनों के बीच में 32 प्रतिशत का अंतर है। 59 परसेन्ट और 91 परसेन्ट लेकिन यदि इस कागजी साक्षरता को रियलिटी में जानने की कोशिश की जाय कि हम जिनके साक्षर होने का दावा करते हैं वह वास्तव में कितनी पढ़ी लिखी हैं तो सच्चाई इन आंकड़ों से आती है जो असद की रिपोर्ट अभी दिसम्बर 2012 की हम लोगों के सामने आई है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत साफ है। आखिर यह सारी चीजें जो बजट में हम व्यवस्था कर रहे हैं। हम अस्पतालों की चर्चा ढेर सारी करते हैं। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, सुबह चर्चा कर रहे थे। आज डाक्टरों की स्थिति क्या है ? मैं सुबह इस प्रश्न को पूछना चाहता था कि आज 11 हजार पदों में कुल 5 हजार पद पर चिकित्सक काम कर रहे हैं बाकी सारे पद खाली पड़े हैं । (व्यवधान) सोलह हजार में जोड़ लीजिये और फल क्या है ? फल यह है कि औसत यह है कि 1 लाख की जनसंख्या पर देश में 1.1 अस्पताल हैं और हमारा औसत .4 अस्पताल का है। यही स्थिति बिस्तरों की संख्या की है। हम जब तक इस सारी व्यवस्था में मूल चूल आमूल परिवर्तन करके देखने की व्यवस्था नहीं

करेंगे, चिकित्सकों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगें और ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास नहीं करेंगे जिसमें चिकित्सक गांवों में नहीं जाते। यह कहने से काम नहीं चलने वाला कि चिकित्सक गांव में नहीं जाते। हम इसलिये सत्ता में नहीं आये हैं। हम सत्ता में इसलिये बैठे हैं कि हम देखें कि हम किन परिस्थितियों में जी रहे हैं उन परिस्थितियों में हम क्या नीतियां बना सकते हैं जिसके माध्यम से हम इन सारी व्यवस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन करने में सफल हो जायं। अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के स्वंय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये है। किसानों की चर्चा होती है। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि गन्ना किसान 42 प्रतिशत गन्ना पैदा करता है। 35-40 प्रतिशत गेहूं पैदा होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आप जानते हैं कि जमीन आप बढ़ा नहीं सकते। जब आप जानते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था आप और बेहतर नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय मैं आंकड़े दूं आपको पिछले 5 सालों के जब यह बी0एस0पी0 की सरकार थी। एक इंच जमीन अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई पूरे पांच साल में। सिंचाई में हमने चाहे जितना भी व्यय किया एक इंच जमीन की सिंचाई की अतिरिक्त व्यवस्था हम नहीं कर पाये। तो प्रश्न यह है कि जब तक हम उत्पादकता बढ़ायेंगें नहीं आखिर हम किसानों को लाभकारी करेंगें कैसे ? हमाने मन में यह प्रश्न नहीं आता। बजट शांत हो जाता है जब कृषि अनुसन्धान का विषय आता है। मैं इसी बात को बार बार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश को आपने 9 भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया। एग्रो क्लाइमेट जोन से, हर क्षेत्र की अलग-अलग स्थिति है। हर क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अलग-अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आखिर हमारे मन में यह चिन्ता क्यों नहीं है कि उत्तर प्रदेश का किसान सिर्फ 28 कुन्तल प्रति हेक्टेयर गेहूं क्यों पैदा करता है जबकि पंजाब का किसान 45 कुन्तल प्रति हेक्टेयर पैदा कर लेता है। हमारे मन में यह चिन्ता क्यों नहीं आती है कि हमारा किसान 20 कुन्तल धान प्रति हेक्टेयर क्यों पैदा करता है। पंजाब का किसान 40 कुन्तल धान प्रति हेक्टेयर पैदा करता है। हमारे मन में यह चिन्ता क्यों नहीं आती है कि हम बार-बार गन्ने की चर्चा करते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता आखिर यह बहस क्यों नहीं होती कि उत्तर प्रदेश का किसान सिफ्र 572 कुन्तल गन्ना प्रति हैक्टेयर पैदा क्यों करता है जबकि तमिलनाडु का किसान 1100 कुन्तल प्रति हैक्टेयर पैदा करता है। महाराष्ट्र का किसान आज गन्ने के आधार पर सबसे धनी होते चले जा रहे हैं। वहां का किसान 884 कुन्तल प्रति हैक्टेयर पैदा कर रहा है। यह कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारे किसान सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं लेकिन उत्पादकता उनकी बढ़ नहीं पा रही है। अच्छे बीज हम नहीं दे पाते है सिंचाई की बेहतर व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। समय से उनको मौसम के बारे में बता नहीं पाते हैं जो अनाज वह पैदा करते हैं उसके बेहतर विपणन की व्यवस्था हम नहीं कर पाते हैं। इसकी नीतियां सरकार नहीं बनाएगी तो बनाएगा कौन। मा0 अध्यक्ष महोदय पूरा बजट अलट-पलट कर देख लीजिए एक शब्द भी इस बात के लिए आप नहीं पाएंगे कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, यह सरकार क्या करने वाली है।अध्यक्ष महोदय, हम इतनी चर्चा किसानों की करते हैं सच्चाई यह है कि तीन चौथाई किसान ऐसे होते हैं जिनको आपकी नीतियों से कोई फायदा नहीं होता है। आप सिंचाई फ्री करा लें। फसल बीमा योजना चला लें और ढेर सारी योजनायें चला लें लेकिन तीन चौथाई किसान है जो छोटी-छोटी जमीनों के मालिक हैं जिसकी चिन्ता पूरी भारत सरकार कर रही है योजना आयोग की रिपोर्ट को देखिए आज योजना आयोग इस बात को स्वीकार करने लगा है कि गांव में अगर खुशहाली लानी है, गांव की गरीबी को अगर दूर करना है तो जब तक हम तीन चौथाई किसानों की चिन्ता नहीं

करेंगे गांव की गरीबी दूर नहीं होने वाली है वह इस बात की चिन्ता करें कि छोटी-छोटी जोतों वाले किसानों की खेती को कैसे लाभकारी बनाया जाए। उनकी गरीबी को कैसे दूर किया जाए। मैं प्रदेश सरकार के बजट को देख रहा था हम इस बात पर चिन्ता करते हैं कि कितना गरीब किसान है। तेन्दुलकर कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि 35 प्रतिशत के करीब लोग, जो गांव में रहते हैं गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं शहरों में यह संख्या 20 प्रतिशत है।हम यह चिन्ता नहीं करते हैं कि इतनी सारी नीतियों के बावजूद यह गरीबी गांव से दूर क्यों नहीं हो रही है। हम किसानों के लिए योजनायें बनाते हैं, लेकिन यह जमीन तक नहीं पहुंचती हैं। कल परसों वैट की चर्चा हो रही थी मैंने इस बात को कहा था। कि आप 15 परसेन्ट वैट को हटाकर कृषि को सस्ता करेंगे,आप कहते हैं सिंचाई में लगने वाली बिजली को मुफ्त दे देंगे बिजली तो देते नहीं तो आखिर छूट किस बात की देते हैं बिजली न होने के नाते वह डीजल पम्प चलाता है तो उस डीजल पर आप 15 परसेन्ट का वैट लगाकर मंहगा कर देते हैं, जिससे उस किसान की एक-एक उपज मंहगी हो जाती है। जब तक किसानों को अध्यक्ष महोदय आर्थिक रूप से समृद्धशाली नहीं कर पाएंगे इस देश का विकास कैसे संभव होगा। दूसरी बात मान्यवर जो किसानों की मूलभूत समस्यायें हैं सरकार उस पर अपना दिमाग नहीं लगाती है। केन्द्र सरकार इनके बल पर चलती है हम लोगों ने लगातार दो साल से देखा है कि केन्द्र की सरकार जब-जब गिरने को होती है बैसाखी इनकी लगती है। बैसाखी के बदले जो इनको केन्द्र सरकार से मांगना चाहिए, बैसाखी के बदले जो इनको केन्द्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए वह दबाव बनाते हमने आज तक इनकी सरकार को नहीं देखा है। समझ में नहीं आता है उत्तर प्रदेश में आप शासन करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आप दबाव नहीं बनाते हैं तो आप किस नाते केन्द्र सरकार की मदद करते हैं। यह प्रश्न इस प्रदेश के एक-एक नागरिक के सामने है। अध्यक्ष महोदय बिजली की इतनी बड़ी समस्या है सरकार ने अगर एक बार गौर किया होता कि इतना बड़ा अन्याय केन्द्र सरकार बिजली के मामले में हम लोगों से कर रही है जो केन्द्र की बिजली होती है वह हमें मुखर्जी गाडगिल फार्मूले से दी जाती है। मुखर्जी गाडगिल फार्मूला यह कहता है आप इस बात से सहमत होंगे मा0 रामवीर जी, यह दो चीजों पर तय होगा कि केन्द्रीय बिजली उद्योग का कितना हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिलेगा। एक, हमारा पर कैपिटा प्लान एक्सपेंडीचर कितना है और दो-हमारी बिजली की खपत कितनी है ? अब जब हमारा पर कैपिटा प्लान एक्सपेंडीचर इस देश में सबसे कम है, हमारा पर कैपिटा प्लान एक्सपेंडीचर 10 हजार रुपये के आसपास है। देश का औसत 16 हजार रुपये का है। ऐसे-ऐसे प्रान्त हैं जिनके 23, 24 और 25 हजार रुपये पर कैपिटा प्लान एक्सपेंडीचर के हैं। मैं उन स्टेट के नाम और उनके पर कैपिटा प्लान एक्सपेंडीचर के बारे में बता सकता हूं और जब हमारा पर कैपिटा प्लान एक्सपेंडीचर सबसे कम है, मैंने सदन में अभी बताया कि हमारा विद्युत उपयोग सबसे कम है और केन्द्र सरकार ऐसे ही राज्य को सबसे कम बिजली देगी तो इस बिजली के न पाने के नाते हमारी विकास की समस्याओं का समाधान कैसे होगा ? मैं चाहता हूं कि जब सरकार बजट पर जवाब देती है, कौन से वह कारण हैं और कौन सा वह केन्द्र सरकार का दबाव है जिसके नाते मुखर्जी गाडगिल फार्मूले के माध्यम से यह जो अन्याय लगातार केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश के साथ लगातार कर रही है, इस अन्याय के खिलाफ न तो अध्यक्ष महोदय, न तो पिछली सरकार खड़ी हुई और न ही वर्तमान सरकार खड़ा होते हम लोग देख रहे हैं। हम लोग जो बजट बढ़ाते हैं, उसमें जो केन्द्रीय सहायता मिलती है, यह सदन जानकर आश्चर्य करेगा, मुझे नहीं मालूम कि सदन को बताया क्यों नहीं

जाता? पूरे देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता उत्तर प्रदेश को मिलती है, सबसे कम सिर्फ 1256 रुपये प्रति व्यक्ति और देश के अधिकांश प्रान्तों में, गुजरात में 1531 रुपये, बिहार में 1593 रुपये, उड़ीसा में 1597 रुपये और हरियाणा जैसा प्रदेश जो उत्तर प्रदेश से बहुत विकसित है, उसको 2400 रुपये प्रति व्यक्ति सहायता मिलती है। मैं छोटे-छोटे राज्यों की अगर बात करूं, जिस जम्मू-कश्मीर को लेकर हम लोग सबसे अधिक चिन्ता करते हैं, माननीय मंत्री जी, प्रति व्यक्ति 16 हजार रुपये की सहायता केन्द्र सरकार उसे देती है। प्रश्न यह है कि इतने सालों से यदि लगातार केन्द्र सरकार हम लोगों को सहायता कम देती आ रही है, हमारे अधिकार पर डाका डालते चली आ रही है, यह आंकड़े आपके पास हैं, हम लोग तो नियोजन विभाग में जाकर निकलवाते हैं, आपके तो सामने आते होंगे। इन आंकड़े से सरकारें मुंह चुराती क्यों हैं, इन आंकड़े पर अपनी नीतियों को भेजती क्यों नहीं हैं ? आप सदन में प्रस्ताव लाते, केन्द्र सरकार के अन्याय के बारे में चर्चा करते, पूरे सदन को बताते, दलीय सीमाओं से हट करके यदि यह सदन आपके साथ खड़ा नहीं होता तो आप कहते कि हम उत्तर प्रदेश के विकास के साथ राजनीति कर रहे हैं। आप सत्य जानते हैं, आपके सामने आंकड़े आते हैं, आप तथ्यों को पूरे प्रदेश को बताने की जगह पर उन्हें छिपा लेते हैं। क्या कारण है कि आप ऐसा करते हैं ? यह सदन और यह प्रदेश जानना चाहता है कि अगर लगातार केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश के साथ यह अन्याय कर रही है तो आप उस अन्याय को मुद्दा बनाने से डरते क्यों हैं ? जिस दिन आप मुद्दा बनायेंगे, अध्यक्ष महोदय, विकास के नए रास्ते खुलेंगे। हम लोगों का अधिकार है, हम लोगों ने इस देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इन साठ सालों में हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय होता रहा है। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जवाब दें कि वह आंकड़े हमारे सामने आने चाहिए, एक श्वेत-पत्र जारी होना चाहिए, इस बात पर कि इन 60-65 सालों में इस प्रदेश के साथ अन्याय क्या हुआ है, आप श्वेत-पत्र लेकर आइये, हम लडेंगे, आपके नेतृत्व में, यह लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, हमारे विकास के नए रास्ते खोले जाने चाहिए। इसी के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव''-

अध्यक्ष महोदय, जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है, इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बजट जो प्रस्तुत किया गया है, यह पूरी तरह से अपने आप में परिपूर्ण है। परिपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रख करके यह बजट तैयार किया गया है। यह बजट समाजवादी पार्टी का बजट है। समाजवादी पार्टी महात्मा गांधी और डा0 लोहिया के सिद्धान्तों को मानने वाली पार्टी है, इसीलिए जो डा0 लोहिया और महात्मा गांधी की नीति रही है, उसी के तहत् यह बजट तैयार किया गया है। सारे वर्ग के लोगों को, जितने भी कमजोर हैं, गरीब हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है।

(इस समय 2 बजकर 50 मिनट पर श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर तमाम लोग इस बजट के विरोध की बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पार्टियां नीतियों और कार्यक्रमों से चलती हैं। जब किसी पार्टी के पास किसी तरह की नीति और कार्यक्रम नहीं होगा तो उसका बजट भी बढ़िया नहीं हो सकता है। साथियों यह बजट महात्मा गांधी जो पूरे देश को साढ़े सात सौ गांवों में बांटकर लघु उद्योग और कुटीर उद्योग का विकास करना चाहते थे

उसी के आधार पर इस बजट को तैयार किया गया है। इसीलिए नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, लेपटाप और टेबलेट देने की बात की गयी है। और किसानों के हित की बात अगर किसी ने सोची है तो वह समाजवादी पार्टी है। इसीलिए किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए निशुल्क सिंचाई और कर्ज माफी की बात की गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आजादी के दीवाने श्री चन्द्रशेखर आजाद जैसे लोगों को भी कुछ दलों के लोगों ने आतंकवादी कहने का काम किया था। जिन महात्मा गांधी जी को पूरी दुनिया ने महात्मा की उपाधि दिया, आजादी मिलने के बाद उनकी भी हत्या करने का काम किया गया है। मैं बड़े अदब के साथ बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर कुछ ऐसी ताकते हैं जो उस समय भी आजादी के आन्दोलन का विरोध करती थीं और आजाद भारत में भी गरीबों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को उसको नहीं देना चाहती हैं। इस विचाराधारा के लोग भी आज प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मौजूद हैं जो गरीबों और किसानों के हक को मारने का काम किया करते हैं। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत से दलों के पास कार्यक्रम और नीति नहीं है। अगर कार्यक्रम और नीति होती तो शायद वह सत्ता के बाहर न हुए होते। माननीय नेता जी को, उनकी पार्टी को जनता का जो इतना बड़ा विश्वास मिला है तो उसका कारण समाजवादियों की सोच है जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है इसी के आधार पर जनता ने इतना बड़ा विश्वास दिया है। उस विश्वास को हम कभी डिगने नहीं देंगे। अभी कल लिंगानुपात बिगड़ने की बात हो रही थी। तो कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो इस देश के और प्रदेश के लिंगानुपात को बिगाड़ने में भी सहयोग करते हैं। और महाकुम्भ में इकट्ठे होकर धर्मसंसद बनाकर वहां से प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं। जब इस देश के कमजोरों के हक और अधिकार की बात आती है तो उसको छीनने की बात करते हैं। और जब वोट की बात आती है तो वह हिन्दु बनाने की बात करते हैं मुसलमान बनाने की बात करते हैं। ऐसी ताकतें भी आज इस देश और प्रदेश में जीवित हैं। इस प्रदेश के लोगों को इससे सावधान रहने की जरूरत है। मान्यवर, मैं प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र से पहली बार चुनकर आया हूं। प्रतापगढ़ जनपद में सदर विधान सभा क्षेत्र में तमाम नदियां हैं। उनमें अभी तक विकास नहीं हुआ है। हमारा सदर विधान सभा क्षेत्र पूरा शहर में आता है और तीन टाउन एरिया हैं उसमें शहरों से अभी जमींदारी व्यवस्था खत्म नहीं की गयी है। मैं यहां पर सदन में उपस्थित साथियों के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में तो जमींदारी खत्म हो गयी है, बिना किसी खून खराबे के खत्म हुयी लेकिन शहरों में अभी भी जमींदारी मौजूद है। आये दिन हमारे यहां के राजा और महाराजा गरीबों और कमजोरों की जमीनों का बैनामा कर दिया करते हैं और जो भूमाफियां हैं वह सक्रिय होकर उनके घरों पर कब्जा करने का काम करते हैं। एक और निवेदन करना हैं कि हमारा प्रतापगढ़ सदर विधान सभा क्षेत्र आंवला उत्पादक क्षेत्र है। हमारे यहां आंवले का किसी तरह का कोई उद्योग नहीं लगा है। हमारे किसानों को आंवला व्यापारियों को अपने उस आंवला उत्पाद को ओने-पौने दाम पर बेचना पड़ता है। इसीलिए मान्यवर, हम सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यहां पर हमारे यहां के नेता श्री प्रमोद तिवारी जी भी हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष भी हैं और भी बड़े-बड़े नेता है, जो प्रतापगढ़ का अभी पिछड़ापन है, हम चाहते हैं कि उस पर विशेष नजर रखी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय न लेते हुए अपने क्षेत्र की बात समाप्त करता हूं, जय हिन्द ।

श्री उमाशंकर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, जो कुछ भी मा0 मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण 2013-2014 का हमने अध्ययन किया, इसके पिछले बजट भाषण 2012-2013 का भी हमने अध्ययन किया था मान्यवर, तो पिछले बजट में लगभग 18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी और इस बार के बजट में 10.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। जो आज हम सब की एक बड़ी समस्या है, वह इस बजट प्राविधान में न होना, अपने आप में बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। पिछली बार भी बजट चर्चा में हमने कहा था कि हमारे ग्राम्य विकास विभाग से 41 हजार हैण्ड-पम्प लगाने की बात हुई थी। हमने उस बार भी कहा था कि प्रति विधान सभा में लगभग 100 हैण्ड-पम्प आयेंगे और एक विधान सभा में कम से कम विधान सभा में गांव होंगे तो 180 गांव होंगे। उस बार भी हमने यह चिन्ता व्यक्त की थी मान्यवर, लेकिन बड़े अफसोस के साथ इस बात पर पुनः जोर दे रहा हूं कि इस बार के बजट में एक भी हैण्ड पम्प का प्राविजन नहीं है। इस बार के बजट से पूरा हैण्ड-पम्प शब्द ही निकाल दिया गया है। हो सकता है इसके पीछे जो भी सरकार की मन्शा रही हो, हमारे मा0 मंत्री जी लोग उससे अवगत करायेंगे। दूसरा मान्यवर, हम बजट का अध्ययन किये, कुछ नई चीनी मिलों को लगाने की बात हुई है। मान्यवर, इस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि हम नई चीनी मिल लगाने की बात कर रहे हैं और मान्यवर, हम उस जनपद बलिया से आते हैं जिसने भारत वर्ष में सबसे पहले लड़ कर आजादी ले ली थी, लेकिन हम विकास का इन्तजार करते रहे, जो हमारे हिस्से में विकास मिलना चाहिए, जो हमारा हक है, उससे हम बलिया के लोग आज भी कोसों दूर हैं। मान्यवर, हमारे बलिया जनपद में मात्र एक उद्योग चल रहा है जो रसड़ा में चीनी मिल है। हम नई चीनी मिल स्थापित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मान्यवर केवल उस चीनी मिल को दिखा लिया जाय कि वह कितने घण्टे चलती है, दिनों की तो बात छोड़ दें। वह चीनी मिल इतनी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गई है, लेकिन ऐसी चीनी मिलों के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए इस बजट व्यवस्था का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो हम कहां से उद्योगों का बढ़ावा करेंगें। दूसरा मान्यवर, अभी हमारे जिले के सम्मानित मा0 मंत्री जी चूंकि चले गये, पिछले बजट भाषण में उद्योग पर जब चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था, बल्कि उन्होंनें ही खुद उद्योग का बजट भाषण रखा था, जिसमें बन्द पड़ी कताई मिलों को उन्होंनें चालू कराने की बात कही थी। उसमें उन्होंनें अपनी जगह से आश्वासन दिया था कि प्रदेश में कोई भी कताई मिल जो बन्द पड़ी है, पहले वह चालू होगी तो उसमें रसड़ा-बलिया की माधवपुर में जो कताई मिल बन्द पड़ी है, उसको चालू कराया जायेगा। मान्यवर, लगभग 11 महीने बीत गये और हो सकता है कि हमारे मा0 मंत्री जी सोंचे कि भाई हमारे जनपद का है, खड़ा हुआ है, और यह फिर पूछेगा, मा0 मंत्री जी चूंकि चले गये, लेकिन आपके माध्यम से मैं इस ओर भी ध्यान लेकर जाना चाहूंगा कि इस बार कोई भी बन्द कताई मिल को चालू कराये जाने का प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, दूसरा सबसे बड़ा जो विषय है उस ओर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा, इस बार सरकार की जो नई व्यवस्था आई है जी0आई0एस0 एवं ज0पी0एस0 उपकरण से व्हीकल ट्रेकिंग का या जगह-जगह चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने का । मान्यवर, इसमें प्रथम फेज में जो जनपद लिये गये हैं, लखनऊ है, इलाहाबाद है, कानपुर है, गाजियाबाद है। मान्यवर, मैं इन जिलों का विरोध

नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतनी जरूर मेरी आपके माध्यम से शिकायत है कि कम से कम प्रदेश में जो सेंसिटिव जिले हैं, जहां पर अक्सर दंगे हो जाते हैं, जहां पर अक्सर आतंकवादियों द्वारा बम विस्फोट होता है, उन जिलों का यानी इसमें न होना ठीक नहीं है। वाराणसी का जिक्र है न कहीं गोरखपुर का जिक्र है। मान्यवर, इस पर भी मैं अफसोस जाहिर कर रहा हूं कि इसमें बजट में इसमें सुधार लाना चाहिए। प्रथम फेज में जो चार जनपद लिये गये हैं उसमें बनारस और गोरखपुर का भी स्थान होना चाहिये। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा। मान्यवर, हमारे बलिया जनपद में कोई उच्चस्तरीय चिकित्सा की सुविधा नहीं है। अगर एक बहुत कोई हल्का भी एक्सीडेण्ट हो जाता है। हेड इंजरी हो जाती है तो वहां के लोगों को या तो बनारस जाना पड़ेगा 200 कि0मी0 की दूरी तय करके या तो गोरखपुर जाना पड़ेगा 200 कि0मी0 की दूरी तय करके। आप सोच सकते हैं कि हेड इंजरी वाले व्यक्ति की बनारस जाते समय रास्ते में ही मृत्यु हो जायेगी। जबकि पहले हमारे मा0 मुख्यमंत्री जी ने हमारे जनपद बलिया में घोषणा भी की थी कि हम बलिया जनपद को ट्रॉमा सेण्टर देंगे। मान्यवर, हम एक्सीडेण्ट में जितना मुआवजा देते हैं, इससे भी कम पैसे में ट्रॉमा सेण्टर बन सकता है लेकिन इस बजट प्रॉविजन में कहीं भी ट्रॉमा सेण्टर खोलने की बात नहीं कही गयी है जबकि हमारे एक साथी कल चर्चा में कहे थे कि चूंकि हमारे जनपद की एक छात्रा जो मेडिकल से रूचि रखती थी और जिसके लिये पूरा देश ही नहीं, विश्व आंदोलित था। हम तो सरकार से चाहेंगे कि अगर ये ट्रॉमा सेण्टर उसी लड़की के नाम पर बन जाये तो ये हमारे बलिया जनपद के लिये बहुत बड़ा उपहार होगा और इस बजट में हम तब कुछ मानेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने कुछ किया है। मान्यवर, दूसरी इसमें एक और चर्चा हुयी है नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की। मान्यवर, पिछली बार भी बजट चर्चा में ये बात आयी थी कि कम से कम ऐसे तहसील मुख्यालय या नगर पालिका परिषद् जो आबादी के हिसाब से बड़े हैं और जहां पर महिला चिकित्सालय नहीं हैं, वहां पर महिला चिकित्सालय की स्थापना की बात थी लेकिन इसमें कहीं भी कोई महिला चिकित्सालय खोलने की बात नहीं आयी है। मान्यवर, उसमें हमारे जनपद बलिया का एक रसड़ा तहसील भी है, जहां आबादी बहुत अधिक है लेकिन वहां भी महिला चिकित्सालय की व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, आप सबका समय देखें हैं, थोड़ा मेरा भी देख लें, आपका संरक्षण चाहेंगे। दूसरा चूंकि मैंने बजट का अध्ययन किया है और बेसिक शिक्षा मंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। पिछले बजट में मैंने चर्चा की थी, मैंने उसकी कार्यवाही भी निकाली थी। मैंने कहा था कि जब हमारे अन्य गुरूजनों की पेंशन ट्रेजरी से दी जाती है तो बेसिक शिक्षण संस्थाओं के लोगों को पेंशन ट्रेजरी से क्यों नहीं दी जा रही है लेकिन इस बजट में आपने इसका प्रॉविजन किया है इसलिये मैं मा0 मंत्री जी को बधाई देता हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जो सरकार की सबसे प्रमुख योजना है डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्रामीण विकास। इसमें मान्यवर मेरा एक निवेदन है कि जिसके चयन के लिये हमारे मा0 मंत्री जी लोग लगाये गये थे। ठीक है, मा0 प्रभारी मंत्री जी ने अपनी स्वेच्छा अनुसार उसका चयन किया लेकिन उस चयन में यदि कोई विकास खण्ड के गांव ही छूट गये हैं या पूरे विकास खण्ड का एक भी गांव लिया ही नहीं गया हो तो मान्यवर, आप बतायें कि उस विकास खण्ड के गांव के लोगों का क्या दोष है, उनको किस आधार पर छोड़ दिया गया। क्या उनको जो नई व्यवस्था आयेगी तो उसमें क्या उन विकास खण्डों को वरीयता दी जायेगी। मान्यवर, दूसरा पंचायती राज से था कि पंचायती राज में चूंकि गैर बी0आर0जी0एफ0 जनपदों में बहुद्देश्यीय पंचायत

भवन खोलने की बात कही गयी है बजट में। मान्यवर, वह गैर बी0आर0जी0एफ0 जनपद कौन हैं। बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर है और इन जगहों पर 162 पंचायतें खोली जानी हैं लेकिन इसमें कहीं भी पूर्वांचल का एक भी जनपद नहीं है जो हमारे पूर्वांचल के दो, तीन बी0आर0जी0एफ0 जनपद हैं, उसके अलावा और भी पूर्वांचल के गैर बी0आर0जी0एफ0 जनपद हैं तो क्या वह इस मानक को तय नहीं करते हैं लेकिन इसमें एक का भी जिक्र नहीं किया गया है। इसके लिये मैं यह जरूर चाहूंगा कि हमारे जनपद के वरिष्ठ मंत्री जी हैं तो आपका भी संरक्षण चाहूंगा कि इसमें जरूर देख लें कि अगर बलिया जनपद का भी स्थान आये तो उसमें बड़ी खुशी होगी।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे बलिया जनपद में है। यह मात्र बलिया जनपद के लिये है और यह बिजली विभाग से सम्बन्धित है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप सनटेन्स पूरा कर लें फिर समाप्त।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, चूंकि हमारे यहां बलिया में जनपद में किसान अगर दो के0वी0ए0 का कनेक्शन लेते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप कामर्शियल रेट देंगे और मान्यवर, 5 के0वी0ए0 का लेने पर कहते हैं कि आपको कृषि रेट पर मिलेगा। मान्यवर, वहीं गाजीपुर जनपद में, वहीं मऊ जनपद में 2 के0वी0ए0 के कनेक्शन पर उनको कृषि का कनेक्शन दिया जाता है। मान्यवर, जो हमारे यहां किसान अगर दो के0वी0ए0 का विद्युत कनेक्शन लेते हैं, तो उनको लगाया जाता है कि आप कामर्शियल रेट देंगे और 5 के0वी0ए0 का लेने पर कहते हैं कि आपको कृषि रेट पर मिलेगा, जबकि मान्यवर, वहीं गाजीपुर जनपद में, वहीं बलिया जनपद में, मऊ जनपद में 2 के0वी0ए0 के कनेक्शन पर उनको कृषि कनेक्शन दिया जाता है। मान्यवर, इस तरह का विरोधाभास नहीं होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करिए।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मान्यवर, जो लोहिया ग्रामीण आवास योजना रखी गयी है, मैं इसकी तारीफ करता हूं, लेकिन मान्यवर, इसमें जो बजट रखा गया है, उस बजट के हिसाब से मान्यवर, 520 करोड़ का बजट है और 520 करोड़ में लगभग 45217/- आवास के लिए अनुदान आएगा, उसमें सोलर लाइट के लिए 15 हजार ले लीजिए और 1 लाख आवास के लिए ले लीजिए। इस तरह मान्यवर, लगभग एक विधान सभा में 100 लोगों को आप अनुदानित कर पायेंगे। मान्यवर, यही हैण्डपम्प वाली बात आ गई। मिनिमम् 150 से लेकर 180 गांव होते हैं, एक विधान सभा में और अगर हम 100 लोहिया ग्रामीण आवास के लिए अनुदान देंगे तो एक-एक गांव कर पायेंगे, तो इसको बढ़ाया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों में साथ मैं आपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं आपके माध्यम से सरकार से एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जब बजट आहूत किया गया था तो हाउस में एक बात आयी थी कि यह नई सरकार है, लेकिन अधिष्ठाता जी, आज चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, चाहे उसके धन निर्धारण की बात हो, चाहे आयु सीमा की बात हो, इस सरकार ने नौजवानों के साथ धोखा किया है और उनमें से मात्र 10 फीसदी लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात साकार हुई है। कब्रिस्तानों की बाउड्री की बात जो सरकार ने की आज हम विधायक लोग जब क्षेत्र के दौरे पर जाते हैं, तो हमे मालूम होता है, देखने को मिलता है कि कब्रिस्तानों की मात्र 10 प्रतिशत में, पूरे जनपद में या विधान सभा में कब्रिस्तानों की चारदीवारी बनाने का काम हो रहा है।

(कहीं हुई ही नहीं है, विपक्ष की तरफ से शब्द सुनाई दिए)

नहीं कहीं-कहीं हुई है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो यह लालीपाप सरकार ने दिखाकर इस प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया। आज बैटरी चालित रिक्शों को एक ट्रायल देकर, मार्च आने वाला है और रिक्शा चालकों को कोई उस तरह की सुविधा नहीं दी गई। मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं है, आदरणीय हमारे पी0डब्ल्यू0डी0 के मिनिष्टर बैठे हैं अभी जिला योजना का बजट आदरणीय अधिष्ठाता जी, जमीन पर नहीं उतरा है, जबकि इस सरकार की लोकप्रिय योजना, इस सरकार की जो बजट में बार-बार कहा जा रहा है कि हम सारी चीजों को हकीकत और जमीन पर लाना चाहते हैं। आदरणीय अधिष्ठाता जी, आज एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने से यदि प्रदेश का भला हो सकता है, तो बसपा के लोगों का और सपा के लोगों का फूल-मालाओं से स्वागत होना चाहिए और यदि इन बातों से सदन का समय जाया होता है और कोई हल नहीं निकलता है, तो इस तरह की बातें बंद होनी चाहिए, सच्चाई यह है कि पिछली सरकार ने, जहां भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया, पत्थरों की मूर्तियां लगाने पर ध्यान दिया, वर्तमान सरकार से मेरा आग्रह है कि उस तरह की पुनरावृत्ति न हो। 20-20 वर्ष हो गए, कुछ रूटों पर बसें चला करती थीं, उसमें इनकी भी सरकार रही, इनकी भी सरकार रही और इनकी भी सरकार रही (विभिन्न राजनीतिक दलों को इंगित करते हुए कहा) आज उन रूटों पर बसें नहीं चल रही हैं, ये कारण नहीं कि सड़क खराब है, न जाने क्यों उनके परमिट रद्द कर दिए गए। इधर जुगाड़ बनाकर लोगों ने गांव से शहर जाने की व्यवस्था की थी, आज जुगाड़ों को नष्ट करके हाईकोर्ट का हवाला देकर के, उन जुगाड़ों की वीडियो फिल्म बनाकर अधिकारी हाईकोर्ट में जमा कर रहे हैं। मेरा आग्रह है सरकार से कि सरकार हाईकोर्ट में इस बात की पहल करे कि उन जुगाड़ों को नष्ट न किया जाए। सरकार द्वारा ऐसे वाहन जो गांवों से शहर तक ले जाने की बात बीच में अटक गई है, उनका इंतजाम होना चाहिए। आदरणीय सिंचाई मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि नहर-नालों की खुदाई का काम हुआ, लेकिन मा0 मंत्री जी कागजों पर ज्यादा हुआ और हकीकत में कम हुआ। मा0 अधिष्ठाता जी, मैं अपने क्षेत्र की बात कह रहा हूं। वहां पर नहरों के सफाई का काम कुछ हुआ है, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ है कि किसानों को लाभ पहुँचे। किसान विरोधी और प्रदेश की जनता के हित में यह बजट नहीं है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कहना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूँ कि प्राइमरी स्कूलों में बाउण्ड्री नहीं है। कई जगह बाउण्ड्री हो गयी है, लेकिन भराव को निकालने की व्यवस्था नहीं है इतना पानी भर जाता है कि बच्चे स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकते है। आपने मेट्रोरेल के लिए प्राविजन किया है। राजधानीवासियों के लिए मेट्रो चलाने की बात कही है। आपने उनको लालीपाप पकड़ाने का काम किया है। सिंचाई मंत्री जी जो यहां पर बैठे हुए हैं, मान्यवर, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से आप प्रदेश का सारा काम चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश की बजट से भी आप कुछ प्राविधान करें, और विद्युत व्यवस्था को सुधारने का काम करें। तभी इस प्रदेश का भला होगा। मान्यवर इस सरकार ने इस बजट में हकीकतों को जमीन पर उतारने की बात कही है। मान्यवर, गन्ना किसानों के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। आज घटतौली हो रही हैं पर्चियां नहीं मिल रही हैं। गन्ने के दाम का भुगतान नहीं हो रहा है। आपने कहा है कि जो चीनी मिले गन्ना किसानों के दाम का भुगतान नहीं करेंगी आप उसमें आर0सी0 जारी करेंगें और एफ0आई0आर0 दर्ज की जायेगी। मान्यवर मिल मालिकों से ज्यादा गन्ना किसान सरकार के वोटर हैं आप उनकी ओर ध्यान दें। मान्यवर, अभी खाद्यमंत्री जी सदन में बी0पी0एल0 के मानक बताने से कतरा रहे थे, अगर आप मानक सही तरह से तंय कर दें तो जो शिकायतें हैं उसमे हम लोगों के क्षेत्रों मे गिरावट आयेगी। मान्यवर, कन्या डिग्री कालेज नहीं खोले जा रहे हैं, पिछले वर्ष के बजट में भी नहीं थे, और इस बार भी नहीं हैं। मान्यवर पूरे वर्ष में प्रदेश में कोई भी कन्या डिग्री कालेज स्थापित नहीं हुआ है। शिलान्यास होना तो दूर उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। मान्यवर, हमारा विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और यह हरियाणा के बाडर्र से लगा हुआ है। मान्यवर, हरियाणा में शिक्षा की स्थिति और गुणवत्ता अच्छी है जबकि हमारे यहां वह बात नहीं है। आप शिक्षा की स्थिति और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान दें। मान्यवर हमारे यहां बेवर तहसील के सामने एक बड़ा भूखण्ड रिक्त पड़ा हुआ है और उस पर विवाद है। लक्षमण प्रसाद बनाम ग्राम सभा, वह पक्ष भी रजामन्द है लक्ष्मण प्रसाद ने मुझसे कहा है कि वह प्रस्ताव करने को तैयार हैं कि यहां पर कन्या डिग्री कालेज खोल दिया जाय, इससे क्षेत्र की लड़कियों का भला होगा। मान्यवर, बिजली मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि टयूबवेल का बिजली कनेक्शन लेने के लिए लोग परेशान हैं। अगर खम्भे के साथ में एक या दो कनेक्शन होने हैं तो दस हजार का खर्चा आयेगा। मैं दस साल से अपनी बारी का इन्तजार कर रहा हूँ यह सरकार टयूबवेल पर बिजली कनेक्शन दिलाने का काम करे यह किसानों के हित में होगा। मान्यवर, प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने की बात कहना चाहता हूं हजारो हजारो ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं इस सरकार में नहीं, इस सरकार ने तो लगाने का काम किया है जब मुलायम सिंह जी 93 में मुख्य मंत्री थे लेकिन वह सन् 2000 में 10-12 साल से वह ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं उनके कर्मचारी वेतन ले रहे हैं। उन ट्यूबवेलों को ठीक कराया जाय या उन कर्मचारियों को कहीं समायोजित कराया जाय मेरा यह सरकार से आग्रह है।

श्री राम लाल अकेला-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 2013-14 का जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में बोलने का आपने मौका दिया है मैं आभार प्रकट करता हूं मान्यवर, मैं सोच रहा था नेता प्रतिपक्ष अगर सामने होते तो बात करने में थोड़ा अच्छा होता क्योंकि वह जब बजट की आलोचना करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने अपनी आंकड़ों की बाजीगरी से तमाम सवाल

खड़े किये हमारे नेता के ऊपर, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को सजाने में सवारने में हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में आप बात कर रहे थे -

चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गयी होंगी,
यह इल्जाम है मुझपे बेवफाई का।
मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने ही पैरो से,
वह क्या दावा करे इस चमन की रहनुमाई का।।

आप नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में नहीं जानते, हिन्दोस्तान में अगर नेता शब्द किसी को कहा गया है तो एक नेता जी सुभाष चन्द्र बोस थे और दूसरे सख्श का नाम है धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव। जिनको नेता जी के नाम से दुनिया पुकारती है, देश पुकारता है उस महान व्यक्तित्व का नाम है मुलायम सिंह यादव। मान्यवर, जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के अन्दर प्रस्तुत किया है उस बजट से किसान नौजवान और मजलूमों के चेहरे पर मुस्कान पैदा करने वाला यह बजट हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत करने का काम किया है। जो बजट के बारे में आलोचना कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने, हमारी मुखिया ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह इस आधार पर कि डा0 राम मनोहर लोहिया की जो सोंच थी 'दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो' इस सिद्धान्त को बजट पुस्तिका में हमारे मुख्य मंत्री जी ने अमली जामा पहनाने का काम किया है। आप जो बजट बनाते थे वह बजट अपने नेता की आमदनी बढ़ाने के लिए, अपने मंत्रियों की आमदनी बढ़ाने के लिए बनाते थे और प्रदेश की जनता को पता नहीं चलता था कि आपने जो बजट बनाया है वह कहां खर्च हो रहा है धरती पर तो खर्च नहीं हुआ, जेबों में चला गया या आसमान में खर्च हुआ लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो बजट बनाने का काम किया है उससे कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, किसान पेंशन योजना और लड़कियां को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता यह तमाम योजनाएं चलाने के लिए मुख्य मंत्री जी ने यह बजट प्रस्तुत करने का काम किया है। नेता प्रतिपक्ष जी, जो कभी दलित के घर पैदा नहीं हुए, दलितों का दर्द उन्हें पता नहीं, केवल दलितों का वोट लेना सीखा है इसके अलावा कोई काम नहीं किया।

डा0 राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिस मुल्क में इंसान-इंसान को ढोता हो वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता और उसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारे मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अब इंसान-इंसान को ढोने का काम नहीं करेगा और इसीलिए स्वचालित रिक्शा देने का एतिहासिक काम हमारे मुख्य मंत्री जी ने किया है। शिक्षा कक्षा एक से लेकर दस तक और छात्राओं को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा का इंतजाम हमारी सरकार ने करने का काम किया है। अभी सिंचाई के बारे में पहाड़िया जी दिन पर चिट्ठी लिये खड़े रहते हैं लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं पहली बार सरकार बनने क बाद पूरे प्रदेश में अगर युद्वस्तर पर किसी विभाग में काम हुआ है तो सिंचाई विभाग के अंदर काम हुआ है और हेड से टेल तक जिस तरीके से युद्वस्तर पर पानी पहुंचाने का काम किया है, इसी कारण किसानों की जो आज धान की पैदावार है, उसमें बढ़ोत्तरी हुयी है। इस सरकार ने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, कर्ज माफ करके दिखा दिया। किसानों को कहा था कि मुफ्त पानी देने का काम करेंगे तो चाहे सरकारी नलकूप का पानी हो, चाहे नहरों का पानी हो, हमारी सरकार ने उसको भी माफ करने का काम कर दिया है। दवा के बारे में बात कर रहे

थे लोग, याद करिये, पूर्ववर्ती सरकार के साथी बैठे हैं, एक टिकिया भी किसी अस्पताल में मिलने का काम नहीं होता था। लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने जबसे सत्ता संभाली है, आप 108 नं0 डायल करिये, तुरन्त एम्बुलेंस जरूरतमंद के पास पहुंच जायेगी और अस्पताल में कोई भी गरीब आदमी जाता है, उसे तुरन्त दवा देने का काम किया जाता है और अभी कोई कह रहा था कि आपने जो तीमारदारों के लिये भवन स्थल बनाने की बात किया है, वह बेकार की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि यह आपके लिये बेकार की बात होगी, आप बड़े आदमी हो लेकिन जो अस्पताल में गरीब आदमी जाता है, चार आदमी उसके साथ में जाते हैं, वह कहां सोयेंगे, कहां रहेंगे, इसका दर्द आपको नहीं हो सकता, इसका दर्द मुलायम सिंह यादव महसूस कर सकते हैं, इसका दर्द शिवपाल सिंह यादव महसूस कर सकते हैं और इसका दर्द अखिलेश यादव महसूस कर सकते हैं और इसीलिये इस तरह का काम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। समग्र ग्राम विकास योजना, जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना, इसके अलावा कब्रिस्तान की जो बेशकीमती जमीनें थीं, उनको लोग कब्जा कर रहे थे । जब हमारे मुख्य मंत्री जी ने पहली बार सदन के अंदर कहा और जब हमारे घोषणा-पत्र में आया तो लोग सोच रहे थे कि यह कैसे होगा । लेकिन बजट में प्रावधान करके हमारे मुखिया ने यह साबित कर दिया कि हमारी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। जो हम कहेंगे, वह हम करके दिखायेंगे। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, महिलाओं को साड़ी, बुजुर्गो को कम्बल, विकलांग व्यक्तियों का पेंशन यह सारी योजनायें लागू करके हमारी सरकार ने दिखाने का काम किया है और आप दलितों की बड़ी बात करते हो, जरा थोड़ा सुन लीजियेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, मैं दलित परिवार से पैदा हूं और नेता प्रतिपक्ष दलित नहीं हैं और दलितों की बात करने का स्वांग रचते हैं। आपने सरकारी कर्मचारियों के आरक्षण पर बड़ी वाहवाही लूटने का काम किया है। सच्चाई तो यह है और मैं जिम्मेदारी के साथ सदन में कहना चाहता हूं कि इनकी सरकार में जब हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने का आदेश जारी किया और जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा था कि सर्वे करके एक रिपोर्ट कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया जाये, लेकिन इनको दलितों से क्या लेना देना था, यह तो पत्थर से माल वसूल रहे थे और उधर सुप्रीम कोर्ट में गरीबों का गला दबाया जा रहा था और अगर दलितों का आरक्षण प्रमोशन में समाप्त हुआ है तो उसके लिये बहुजन समाज पार्टी जिम्मेदार है, हमारी सरकार ने तो केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन किया है। आप दलितों की बात करते हो, आपको इतिहास पढ़ना चाहिये। मुलायम सिंह यादव जब पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो अम्बेडकर ग्राम विकास योजना चालू करने का काम उत्तर प्रदेश में किसने किया, मुलायम सिंह यादव ने किया। अम्बेदकर महासभा का उत्तर प्रदेश में सृजन किसने किया, उस नेता का नाम है मुलायम सिंह यादव। विधान सभा के सामने जो लखनऊ का सबसे मुख्य मार्ग है, अगर उसका नाम अम्बेदकर के नाम से करने का काम किसी ने किया है तो उस नेता का नाम है, मुलायम सिंह यादव। 18 प्रतिशत रिजर्वेशन था अनुसूचित जाति का और मुलायम सिंह यादव ने सत्ता संभालने के बाद इसको बढ़ाकर 21 प्रतिशत करने का काम किया है, आप लोग तो केवल दलितों की बात करते हो। आपने केवल दलितों का वोट लेने का काम किया है और सत्ता में आने के बाद आपने केवल दलितों को अपमानित करने का काम किया है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सर्वहारा की बात अगर कोई करता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, हमारे नेता

माननीय मुलायम सिंह यादव करते हैं और हमारी सरकार ने, हमारे नेता का, हमारे मुखिया का पक्का इरादा है, उनका कहना है कि गलत बात मत करिये-

''अब हवायें ही करेंगी, रोशनी का फैसला,

वह दिया ही रह जायेगा, जिस दिये में जान होगी''।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री रामलाल अकेला-

जो बजट हमारे मुख्य मंत्री जी ने रखने का काम किया है, उनका पक्का इरादा है और उन्होंने इस बजट के माध्यम से कहा है कि-

कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता,

एक पत्थर तो तबीयत से उछालकर देखो यारों।

यह हृदय है माननीय अखिलेश यादव जी का। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बात मैं रायबरेली की कहना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे नेता प्रतिपक्ष रायबरेली के हैं, मैं उम्मीद करता था कि सरकार में आपने बन्द करा दिया हो सकता है कि विपक्ष के नाते आप रायबरेली की स्पिनिंग मिल की बात उठाते, आपने नहीं उठाया उस दिन मैंने कहा भी था लेकिन आज मैं मा0 अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से मांग करता हूं कि दसियों हजार रायबरेली का मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि रायबरेली की स्पिनिंग मिल को चालू करने का काम किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जो बजट हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका पुरजोर समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*श्री सुरेश राणा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में संशोधन के लिए मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। अभी माननीय अकेला जी, बहुत ऊंचे वैल्यूम में बोल रहे थे और सच्चाई यह है कि वह जिनको सम्बोधित करके बोल रहे थे वह भी बहुत ऊंचे वैल्यूम में बोलते हैं। यह गुम्बद गवाह है यहां एक से एक मुख्य मंत्रियों ने काम किया है और सरकार आती रहती है जाती रहती है। लोग उन्हें याद करते हैं जो कुछ काम करते हैं, काम करने की चर्चा होती है और कामों की चर्चा होती है। मान्यवर, इसी गुम्बद के अन्दर माननीय राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, हम सब जानते हैं और एक माननीय सदस्य ने कहा भी था कि मुजफ्फरनगर से लेकर सोनभद्र तक जो पैसा जेब में है उसे लेकर जब ट्रक का मालिक चलता था वह यात्रा पूरी कर लेता था तभी ध्यान आता था कि जितना पैसा जेब में लेकर चला है उतना ही जेब में बाकी है, कोई लूट-खसोट किसी चौराहे पर नहीं थी। माननीय कल्याण सिंह जी भी इसी सदन में मुख्य मंत्री रहे हैं, उनकी कानून-व्यवस्था को कौन नहीं जानता। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्य मंत्री बने तो हमें लगा था कि अब कुछ न कुछ होगा और उन्होंने कहा भी था कि मैंने एक सपना देखा था उस सपने की लोगों ने मखौल उड़ाई थी, मुझे उनका पहला भाषण याद है उन्होंने कहा था कि सपने की लोगों ने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

मखौल उड़ाई लेकिन हम कामयाब हुए, हमारा सपना सच हुआ। मैंने उस समय भी कहा था कि सपना देखना अच्छी बात है, सपने भी कई प्रकार के होते हैं एक वह सपना होता है जो आदमी किसी मंजिल के लिए देखता है, प्रदेश के विकास के लिए देखता है और एक वह सपना होता है जो आदमी अपनी कामयाबी के लिए देखता है।

मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है,
पंख से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है।

माननीय मुलायम सिंह यादव जी की भी यहां पर चर्चा होती है और मैं भी उनका दिल से सम्मान करता हूं। मैं 1992 में छात्रसंघ का अध्यक्ष था हरिद्वार के अन्दर, मैं तब से सुन रहा हूं कि वह रिक्शे की योजना के बारे में चर्चा किया करते थे, किसानों के बारे में बहुत सारी चर्चा उन्होंने की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केवल आप मुलायम सिंह यादव सरकार की चर्चा करके उनकी उपलब्धियों की चर्चा करके अपने कामों की तारीफ नहीं कर सकते।

गैर परों से उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक,
अम्बर तक तो वही उड़ेगा, जिसके अपने पर होंगे।

माननीय अखिलेश यादव जी की बहुत सी उम्मीदें थीं और उन्होंने कहा था कि जिस देश का किसान आगे बढ़ता है वह देश आगे बढ़ता है, मैं कहना चाहता हूं कि जिस देश का किसान आगे बढ़ता है वह देश आगे बढ़ता है, यह सपना कैसे पूरा होगा। अभी सूचना आई कि गोली चली एक मिल के बाहर किसानों पर और संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत सुलझा हुआ जवाब दिया कि एक गार्ड था किसान अन्दर घुसने का प्रयास कर रहे थे, धक्का-मुक्की हुई, ट्रेगर दब गया और एक छोटा सा छर्रा किसान को लगा। मैं पूछना चाहता हूं कि धरती पुत्रों की सरकार में, किसानों की सरकार में किसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है और गोली क्यों चली क्योंकि किसानों का बकाया है, जहां 14 दिन में भुगतान हुआ करता था वहां डेढ़-डेढ़ महीने में भुगतान हो रहा है। आज मैंने क्वैश्चन लगाया था लेकिन क्वैश्चन को ही निरस्त कर दिया गया। आज किसानों की हालत क्या है ? माननीय राजनाथ सिंह मुख्य मंत्री थे 72 घण्टे के अन्दर ट्रान्सफार्मर बदला जाता था। सभी सदस्य यहां मौजूद हैं, हम लोग गांवों में जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या आज ट्रान्सफार्मर की हो गयी है। 72 घण्टे छोड़ दो, एक-एक महीने के बाद भी आज ट्रान्सफार्मर नहीं बदला जा रहा है। अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज स्थिति यह है कि भूमि विकास बैंक में जब नो-ड्यूज लेने जाते थे तो 50 रुपये किसान क्रेडिट कार्ड के लिए देना पड़ता था। आज किसानों की सरकार आयी है प्रदेश के अन्दर वह 50 रुपया बढ़ाकर 250 रुपया कर दिया गया है। यह किसानों की सरकार है, धरती-पुत्रों की सरकार है और किसान नेता होने का दावा भी इस दल के लोग किया करते हैं। कर्जा माफी की बात कही, मैंने सवाल लगाया, आज ही जवाब मिला, पचास हजार का कर्जा माफ कर देंगे, किसानों के मन में एक उत्साह था, गरीब किसान फूला नहीं समा रहा था कि मेरा पचास हजार रुपये का कर्जा माफ होगा। जब कर्जा माफी की बात आयी तो तमाम प्रकार की शर्तें लगा दी गयीं और कहा कि भूमि विकास बैंक का ही कर्जा माफ होगा, कहा केवल उन लोगों का माफ होगा जिन्होंने 10 प्रतिशत जमा कर दिये हैं और भूमि विकास बैंकों का कर्जा माफ होगा। अगर आपको यही बात करनी थी तो आपने जब अपना चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया था उस समय आपको यह बात करनी चाहिए थी। आपने

किसानों के साथ धोखा किया। पिछले बजट में आपने कहा था कि कृषि आयोग की स्थापना होगी, कहां गया कृषि आयोग ? क्या कोई कृषि आयोग की स्थापना हुई है ? आपने कहा था कि आलू भण्डारण की व्यवस्था होगी, पता नहीं कितने आपने साइंटिफिक इश्यू रख दिये थे, अबकी बार इस बजट में वह सब इश्यू गायब हैं। यह सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है डा0 राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना। माननीय मंत्री जी सामने बैठे हैं, बहुत जिम्मेदार मंत्री हैं इन्होंने कहा कि 2000 की आबादी तक 20 लाख, फिर 30 लाख, फिर 40 लाख। मैं पूछना चाहता हूं कि 700 मीटर सी0सी0 मार्ग, मा0 सदस्यगण भी हमारे साथ विधान सभा के सदस्य हैं, आप भी क्षेत्रों में जाते हैं आप वहां 600 मीटर, 700 मीटर सी0सी0 रोड बनायेंगे, 1000 मीटर सी0सी0 बनवायेंगे। आप बहुत सारे मुद्दों पर आलोचना करते हो लेकिन मैं कहना चाहता हूं, बहुत खुले मन से कहना चाहता हूं, हम भी क्षेत्रों में जाते हैं जब अम्बेड़कर ग्राम विकास योजना के नाम पर विकास हुआ था और कोई एक गांव लिया है तो उस एक गांव में पांच-पांच, सात-सात करोड़ रुपये सी0सी0 रोड़ के नाम पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने खर्च किये हैं। (ब0स0पा0 के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) जो विकास करता है उसकी दुनिया चर्चा करती है। आपने कहा कि 20 लाख रुपया देंगे, 30 लाख रुपया देंगे, 40 लाख रुपया देंगे वह भी 2001 की जनगणना के आधार पर। मैं पूछना चाहता हूं कि सात सौ, आठ सौ, नौ सौ, हजार मीटर जब सी0सी0 बनेगी तो गांवों में अविश्वास पैदा होगा, गांवों में भी ग्रुपबाजी पैदा होगी और गांवों की कानून-व्यवस्था कहीं न कहीं इस बात से प्रभावित होगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उद्योगों पर बहुत बड़ी बहस हुई। हमारे बहुत ही विद्वान सदस्य डॉ0 राधा मोहनदास अग्रवाल जी जो आंकड़ों के जादूगर भी हैं, उन्होंने बहुत शानदार विषय रखा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं। (श्री अधिष्ठाता द्वारा लालबत्ती जलाने पर) मान्यवर, अभी 4 मिनट हुए हैं। मैंने देखा है बहुत महत्वपूर्ण सड़कें दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग, दिल्ली से लेकर मुजफ्फरनगर होते हुए देहरादून मार्ग, आज उन सड़कों की हालत देखिये। मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री आजम खां साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, एक फ्लाई ओवर मिला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, वह भी रामपुर के अन्दर। हमें सोचना चाहिए आप इतने प्रभावी मंत्री हो, आप केवल रामपुर का फ्लाई ओवर ले करके संतुष्ट हो गये। आपको सोचना चाहिए कि मुरादनगर के अंदर फ्लाई ओवर होना चाहिए, मोदी नगर के अन्दर फ्लाई ओवर होना चाहिए, मेरठ के अन्दर फ्लाई ओवर होना चाहिए। यह पूरा का पूरा सड़क है इस पर ट्रैफिक का इतना बोझ रहता है, दिल्ली से लोग देहरादून तक जाते हैं, किसी फ्लाई ओवर की चर्चा आपके बजट में नहीं हुई। दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग उसकी हालत आप देख लो, शामली जिला, बागपत जिला जो इतने बड़े ऊंचे स्तर के किसान रहते हैं, इतना बड़ा राजस्व देते हैं। मैंने कहा था कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर यह सरकार जीरो है। सड़कों में गड्ढे हैं, बहुत बुरा हाल है। मा0 ओम प्रकाश सिंह जी का मैं नाम लेकर कहना चाहता हूं, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। हमारे शामली जिले की जिला योजना की बैठक में उन्हें आना था, वह चले दिल्ली से इस रोड पर, बाद में हरियाणा में घुस गये और ढाई घंटे बाद आये। मैंने पूछा कि विलम्ब के क्या कारण हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके क्षेत्र की सड़कें इतनी गजब की हैं कि मुझे आने में 3 घण्टे हो गये यह वहां की सड़कों का हाल है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार सस्ते न्याय की बात करती है। मैं मांग करता

हूं सरकार से कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर सस्ता न्याय उपलब्ध हो इसलिए वहां हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो जाएगी तो बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मान्यवर, मैं पशुधन की बात करता हूं क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं वहां बहुत सारे पशु हैं पशुओं के ऊपर बहुत सारा ध्यान किसानों का रहता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं और तारीफ में भी कहना चाहता हूं कि आजम खां साहब ने एक कमेला मेरठ का हटवाया लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आज गांव-गांव में कमेला चल रहा है। आज जगह-जगह, गली-गली में दुधारू पशु काटे जा रहे हैं। उनके बारे में सरकार ने कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की। गरीब आदमी के प्रति यह सरकार कितनी संवेदनशील है माननीय राजस्व मंत्री जी बैठे हैं बहुत विद्वान हैं मैं हृदय से इनका सम्मान करता हूं। अभी तीन दिन पहले मैंने सवाल उठाया कम्बल घोटाले का कम्बल की बात मैंने कही जब जीरो डिग्री टेम्परेचर था जब ठण्ड से लोग मर रहे थे इस सरकार ने 60 रुपए का, 65 रुपए का कम्बल जो फटा पड़ा था जीरो डिग्री टेम्परेचर पर क्या वह कम्बल गरीबों की ठंड दूर कर देगा। यह इस सरकार की सोच है यह इस सरकार की संवेदनशीलता है यह सरकार गरीबों के प्रति कितनी संवेदनशून्य है यह सरकार किसानों के प्रति कितनी संवेदनशून्य है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री सुरेश राणा-

यह सरकार छात्रों के प्रति कितनी संवेदनशून्य है मैं आपके माध्यम से अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि हमें बहुत सारी उम्मीदें इस सरकार से हैं यह सरकार नया आयाम आने वाले वर्ष में स्थापित करेगी । आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अधिष्ठाता जी अभी राणा साहब अपनी बात कह रहे थे और मैं आपके चेहरे पर आते-जाते रंग देख रहा था आपके मन में उनकी बातों का जितना भी बुरा लगा हो वह विद्वान सदस्य हैं आप क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र मुख्य मंत्री जिनका सबसे कम कार्यकाल था उनकी यशप्रसस्ति उन्होंने छह, सात, नौ बार की बाकी किसी का नाम नहीं लिया आपको बुरा बहुत लग रहा था। लेकिन आप उन्हें क्षमा करेंगे यही मेरी विनती है।

*श्री लोकेश दीक्षित-

अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले मैं अपने विधान सभा की बात उठाना चाहूंगा अभी 21 तारीख को कार्तिकेय नाम का एक लड़का सन आफ बिजेन्द्र गांव सबका उसका अपहरण हो गया बड़ा मासूम लड़का था, बच्चा था आठ वर्ष का लड़का सरे आम दिनदहाड़े उसका अपहरण कर लिया गया । दूसरी घटना हमारे कस्बे बड़ौत की है एक व्यापारी का लड़का जिसका नाम ऋषभ जैन है पत्थर का व्यापार है 12वीं का छात्र था दिन दहाड़े उसको उठा लिया गया पब्लिक के बीच से उठा लिया गया अपहरणकर्ता उसको जंगल की ओर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ले गए। जब ज्यादा भीड़ का दबाव बना तो उस लड़के का छूरी से गला काट दिया और उसको गन्ने के खेत में डालकर भाग गए। श्रीमन् मैं चाहूंगा कि जो कानून-व्यवस्था आज चरमराई हुई है पता नहीं कहां से माफिया गुण्डे छोड़ दिए गए या आ गए या उनका मनोबल बढ़ गया आज मंत्री जी बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं मेरी जो दो पीड़ाएं हैं ऋषभ जैन और कार्तिकेय जो जयपाल सिंह का पोता है बहुत जिम्मेदार परिवार है। माननीय अध्यक्ष जी बागपत जिला यमुना के किनारे पर बसा हुआ है वहां हालात यह हो गए कि यमुना का जल स्तर जब ज्यादा बढ़ जाता है तो बागपत की तरफ आ करके आठ दस गांव ऐसे हैं और बागपत कस्बा ऐसा है जिसमें मेथला है, खांपर है, जौनमाड़ा है, लोहारी है, ढिगराना है यह बिल्कुल कटान पर हैं और पानी का इस कदर से बहाव बढ़ता जा रहा है कि अबकी बारिश में जिस प्रकार से सर्दियों में बारिश आई इन्द्रदेव प्रसन्न हुए अगर यह बरसातों में प्रसन्न हो गए तो हो सकता है कि वह गांव डूबने की कगार पर चले जाएं तो मैं यह निवेदन करता हूं कि उसे जरूर दिखवा लें यह बहुत जिम्मेदारी का मामला है आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमेशा यह कहा जाता है किसानों की सरकार किसान-किसान-किसान चारों तरफ देखो तो किसान पर किसान का हितैषी कौन किसान के बारे में सोच कौन रहा है हमारा मलकपुर एक मिल है जिस पर 2011 का बकाया 2012 का बकाया सर्दियों का अभी तक उसने नहीं दिया कम से कम 300 करोड़ रुपया बकाया है और बागपत जिले की सबसे बड़ी बात यह है कि वह 90 प्रतिशत गन्ना पैदा करता है, उसका एक ही स्रोत है ज्यादातर गन्ना। माननीय मंत्री जी चले गये। मिल तक पहुंचने के लिये सड़कों का इतना बुरा हाल है कि जो भैंसाबुग्गी जिसको हम कहते हैं जिस पर छोटे किसान, किसानों की बात हम करते हैं। छोटे किसान उस पर अपना गन्ना लादकर मिल तक तो ले जाता है। पर जब मिल से अपना गन्ना वापस लेकर आता है तो उस भैंसे के पैर लहूलुहान हो जाते हैं। मैंने पिछली बार भी इस सदन में कहा था, उससे पहले भी इस सदन में कहा था, कम से कम 20-20 किमी0 की सड़क तो हमको दे दी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जांच कर लें एक किलोमीटर भी, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करना चाहता। अपनी विधान सभा, अपने जिले की बात जरूर करना चाहता हूं कि एक किलोमीटर तो क्या एक इंच भी सड़क गड्ढामुक्त नहीं हो पाई है। यह हमारी पीड़ा है। कभी कोई मजबूती के साथ अपनी बात कहो तो माननीय सदस्यों को मिर्ची लग जाती है, माननीय सदस्यों को परेशानी हो जाती है। हम इन बातों से घबराने वाले, डरने वाले नहीं हैं। बहिन कुमारी मायावती जी, इस प्रदेश की ऐसी मुख्य मंत्री हुईं कि जो कह दिया सो कर दिया लेकिन आप जो कहते हैं वह करते नहीं हैं। यह सबसे बड़ा दुःख का कारण है, पीड़ा का कारण है। किसानों की हितैषी बहिन मायावती जी थीं तो किसी मिल मालिक की हिम्मत नहीं हुई कि एक दिन भी पेमेंट लेट कर दे। किसान खुश थे, खास करके गन्ना किसान खुश थे। आप सर्वे करा लें, पूछ लें गन्ना किसानों से कि आपका हितैषी कौन था। अगर किसी ने किसान का दर्द पहचाना, अगर किसी ने सबसे ज्यादा गन्ने का रेट बढ़ाया तो उसका नाम था बहिन कुमारी मायावती। यह लिखित में है। यह ज्यादा बोलने से, शोर मचाने से कुछ होने वाला नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। बहुत मजबूत बात। किसानों की बात हम करते हैं और किसानों का दुर्घटना बीमा योजना जो 1 लाख से 5 लाख कर दिया गया वह मिलता किसको है ? नहीं मिल पाता। सुन लें मैं पात्र पर ही आ रहा हूं। वह पात्र ही तो गड़बड़ है, किसान गड़बड़ में है पर उसका दर्द उसकी असलियत नहीं पहचान पाते आप। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसान को मिलता है बीमा योजना पर यदि किसान का पुत्र और उसकी पुत्रवधू,

उसका पौत्र है, उसको क्यों नहीं मिलता वह भी तो किसान है। सुबह से लेकर शाम तक वह भी तो खेत में काम करते हैं। परन्तु पीड़ा इस बात की है कि उनका नाम खाता खतौनी में नहीं है। हिन्दू रीति रिवाज, भारत की रीति रिवाज ऐसी है कि अगर उसके पूर्व उसके बाप या दादा या नाना जब तक जिन्दा हैं तो हम जमीन पोते या बेटे के नाम नहीं कराते। इसीलिये 90 प्रतिशत किसान की पीड़ा है। यह किसान का परिवार उससे पीड़ित है। अधिष्ठाता महोदय, एक बहुत बड़ा मामला है किसानों से जुड़ा हुआ। मेरा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र से प्रधानमंत्री आये, कैबिनेट मंत्री आज भी हमारे जिले से ही हैं। इतना छोटा हमारा जिला है कि वहां कोई भी अस्पताल नहीं है, कोई भी स्टेडियम नहीं है। यह बड़ा पीड़ा का कारण है कि विकास के मामले में एन0सी0आर0 में हमारा जिला आते हुए भी शून्य पर है। अभी बाइस जिलों की बात हुई। पश्चिम के जिले हों। यह कहां का इन्साफ है अधिष्ठाता महोदय। यह परिपाटी कब तक चलती रहेगी ? कब तक यह दादागिरी चलती रहेगी ? कब तक यह किसान विरोधी काम होता रहेगा ? कहो तो इन लोगों को मिर्ची लगने लग जाती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं दबने वाला नहीं हूं यह बी0आर0 अम्बेडकर के सिपाही हैं, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। मुंह तोड़ जवाब माननीय बहिन कुमारी मायावती ने राज्य सभा में दे दिया, लोक सभा में दिया। हम भी हमेशा देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, एक जवाब के लिये नहीं एक सूचना के लिये मैं यह बात कहना चाहता था कि माननीय सदस्यगण की मदद चाहिए उसमें। जो यह किसान दुर्घटना बीमा योजना है यह पिछली बार 1 लाख रुपये थी अब 5 लाख रुपये कर दिया है। मैंने उच्च सदन में यह बात कही थी। आज विपक्ष के दो माननीय सदस्यों के पत्र मेरे पास आये, और मैं आप सब लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि अगर कहीं किसी भी अधिकारी की कमी या गड़बड़ी की वजह से अगर पात्र व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है तो आप निश्चित रूप से इसकी सूचना दे दें तो मैं इसको दिखवाऊंगा तो दोनों काम होंगे। एक तो जो पात्र व्यक्ति है उसको इसका लाभ भी मिलेगा। जिस किसी ने जान बूझकर लापरवाही की है जिसकी वजह से उसे नहीं मिला है तो उसको दंडित भी करेंगे। एक जानकारी और देना चाहता हूं चूंकि बीमा योजना पिछली सरकार ने, टिप्पणी के लिए नहीं कह रहा हूं, बीमा योजना किसी कारण से नहीं चल पाई। एक दो साल चल पाई, तो एक अप्रैल से पांच लाख की धनराशि हमने की है तो यह जिलाधिकारी के माध्यम से राशि दे रहे हैं और बीमा कम्पनी से करार चल रहा है और जब करार हो जाएगा तो बीमा कम्पनी से बीमा के दावे के रूप में लेंगे। लेकिन अभी शत-प्रतिशत इस किसान बीमा योजना से आच्छादित लोग हैं अगर एक डिस्मिल का भी किसान है और किसी प्रकार की दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है तो अगर आप उसकी सूचना दे देंगे तो प्रत्येक पीड़ित को उसका लाभ अनिवार्य रूप से मिलेगा। चाहे तो आप मुझे उसको लिखित रूप में दे दें।

*श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एक दुर्घटना सड़क पर हो रही है एक दुर्घटना आग लगने से हो रही है क्या वह भी इसमें सम्मिलित है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

सिर्फ सड़क दुर्घटना ही नहीं, रेल दुर्घटना, बिजली का शाक लग जाना, तालाब में डूब जाना, किसी हिंसक जानवर के हमले में, यहां तक कि हत्या भी हो जाए, हत्या भी एक बड़ी दुर्घटना है, किसी की फायरिंग में हत्या हो गई तो इस प्रकार से तमाम प्रकार की मृत्यु उसमें कवर्ड है। उसमें दो बातें आवश्यक हैं एक तो खतौनी में उसका नाम दर्ज होना चाहिए अगर खतौनी में उसका नाम दर्ज नहीं भी है जैसे आज,बरास्तन उसका नाम दर्ज होना चाहिए उसके पिता की मृत्यु एक दिन पहले, पांच दिन पहले या पन्द्रह दिन पहले हो गई है तो वह भी उसमें कवर्ड होगा, समय उतना चाहिए और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके साक्ष्य होने चाहिए कि उसकी मृत्यु दुर्घटना में हुई है।

श्री अधिष्ठाता-

अगर किसी कृषक की पत्नी हो ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं अवगत कराता हूं। अगर कृषक मरेगा तो उसकी पत्नी को ही उसका दावा मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता-

अगर पत्नी डिसीज्ड हो ?

श्री अम्बिका चौधरी-

नहीं, जो व्यक्ति खुद खातेदार है उसके अलावा किसी दूसरे को यह सुविधा अनुमन्य नहीं है। दूसरी योजना है आम आदमी बीमा योजना, इसमें श्रीमन् हम उसका लाभ नहीं ले सके हैं,मैं यह स्वीकार करना चाहता हूं। आम आदमी बीमा योजना में जितने लोग भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और भूमिहीन कृषक जिनका कोई रिकार्ड नहीं है भूमिहीन लोगों का तो किसी खतौनी पर नाम होता नहीं है, उसके लिए एक फार्म भरना पड़ता है एक लिस्ट बन जाती है वह उस योजना से कवर हो जाते हैं कोई प्रीमियम की राशि, अन्य योजनाओं की भांति, एक रुपया भी प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। आम आदमी बीमा योजना में एक लाभ यह भी है कि उसके दो बच्चों को आजीवन 100 रुपया प्रतिमाह प्रत्येक बच्चे के हिसाब से, एक तरह की स्कालरशिप मिलती है रेगुलर, जब तक वह पढ़ाई करें या जब तक वह बालिग हों, यह दोनों शर्तें हैं अगर ऐसी स्थिति हो तो आप भी अपने क्षेत्रों में देख लें सहयोग करें।

(इस समय 3 बजकर 48 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आज से पांच महीने पहले ब्लाक गढ़वार में छोटेलाल राम का रोडवेज की बस से एक्सीडेंट हो गया वह एक्सपायर कर गया वह किसान था। उसके नाम से जमीन भी थी हजारों की संख्या में वहां लोगों ने चक्का जाम किया, जिला प्रशासन वहां पहुंचा संयोग से मैं भी जनपद में मौजूद था मैं भी मौके पर पहुंचा और जिला प्रशासन की उपस्थिति में मैंने चक्का जाम की स्थिति को तुड़वाया और इस वायदे के साथ कि पारिवारिक लाभ योजना 24 से 72 घंटे तक पहुंच जाएगी और किसान दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कम से कम 5 बार समाज कल्याण अधिकारी से कहा गया, दो बार जिलाधिकारी

के संज्ञान में मैंने इस घटनाक्रम को दे दिया और इन सारी परिस्थितियों के बावजूद उस छोटे लाल राम जो त्रिकालपुर का रहने वाला है, ब्लाक-गडवार है, आज तक परिवारिक लाभ योजना का 20 हजार रुपये भी नहीं मिला है और किसान दुर्घटना बीमा योजना का 5 लाख रुपया मिलना तो दूर की चीज है।

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा की बात नहीं है, आप लिखकर दे दीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अवगत करा दूं। माननीय उपेन्द्र जी हमारे विधायक इसलिए इनको विशेष रूप से अवगत कराता हूं और सदन को भी। श्रीमन्, 24 घण्टों में यह राशि नहीं मिल सकती और 72 घण्टों में भी यह राशि नहीं मिल सकती। इसमें क्लेम का फार्म भरना होता है, जिसके लिए समय है 60 दिन का और उसके बाद प्रासेस होता है और कम से कम 4-5 महीने तो लगते ही लगते हैं। आपने मुझे अवगत करा दिया है, मैं इसे देखूंगा और प्रयास करूंगा, जितनी जल्दी मिल जाये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूं, इसमें 2 दिन में, 24 घण्टों में, 72 घण्टों में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, काफी उसका प्रासेस होने में, सारे कागजात लगा करके कम्प्लीटली उसका क्लेम फार्म दाखिल करना पड़ता है और क्लेम फार्म दाखिल हो करके और प्रोसेस होकर जब जाता है, उसमें समय लगता है। इसमें भी थोड़ा समय लग सकता है। माननीय उपेन्द्र जी, आपने सवाल उठाया, एक बार आप देख लीजिएगा कि उसका क्लेम फार्म सारे कागजात के पास समुचित ढंग से पूरा हो करके तहसील में लग गया है, नहीं जमा होगा तो उसकी मदद कर दीजिएगा और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर उसका क्लेम फार्म पूरी तरह से भर गया है तो उसको उसके क्लेम का पैसा मिलेगा और दूसरी जिस योजना के बारे में आपने कहा, समाज कल्याण की योजना है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अपनी जगह पर है, लेकिन इस योजना में गारण्टी है इस बात की कि काश्तकार है, उसका खतौनी में नाम दर्ज है, दुर्घटना में मृत्यु हुई है तो उसका अनिवार्य रूप से यह राशि मिलेगी और जो पीड़ित परिवार हैं, हम सब लोग उनके फार्म भरवाने में मदद करें।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, 72 घण्टे में नहीं मिल सकता है लेकिन 5 महीने में तो मिल जाना चाहिए और जैसा मंत्री जी ने कहा कि 24 घण्टे, 72 घण्टे में नहीं मिलता है। उसी बलिया जनपद में आपके ही विधान सभा क्षेत्र में माननीय सांसद जी की उपस्थिति में नरही में जो एक्सीडेण्ट हुआ था, वहां हाथों हाथ पारिवारिक लाभ योजना का चेक दिया गया था। तीन-तीन लोगों को दिया गया है, उसमें आप भी मौजूद थे। इस मामले में सारी फारमेलिटी पूरी हो चुकी है, 5 महीने हो गया है, लेकिन कोई पैसा नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष-

यह बहस का विषय नहीं है, अब आप बैठिए।

(श्री जाहिद बेग और श्रीमती कृष्णा पासवान एक साथ बोलने लगे)

श्री जाहिद बेग-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बजट भाषण पर बोलने का समय दिया गया है।

श्रीमती कृष्णा पासवान-

माननीय अध्यक्ष जी, बीमा योजना के बारे में माननीय मंत्री जी कह रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलिये। जब बुलवाते हैं तो बोलते नहीं हैं।

(श्रीमती कृष्णा पासवान के बोलने का प्रयास करने पर, उनका माइक ऑफ था।)

यह कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप लिखकर दे दें। क्या यह प्रश्न पूछने का समय है?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, चूंकि मा0 अम्बिका चौधरी जी ने एक हस्तक्षेप किया और एक जानकारी दी उस जानकारी के गर्भ से बहुत से प्रश्न पैदा हो गये। मा0 सदस्य की भावनाओं से हम सहमत हैं वह आपको पत्र भी लिखकर दे देंगी। वह सिर्फ इतना जानना चाहती थीं कि जिनका पोस्टमार्टम नहीं होता है उनको कैसे मिलता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

अगर पोस्टमार्टम नहीं होता है तो नहीं मिलेगा।

श्री जाहिद बेग-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मा0 मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय नेता विरोधी दल कल एक घण्टा पांच मिनट बजट भाषण पर बोल रहे थे। मैं सोच रहा था कि वह बहुत सी खामियां निकालेंगे। लेकिन पूरे भाषण में उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। उन्होंने एक बात का बार-बार जिक्र किया कि 11 महीने हो गये, 10 महीने हो गये, बजट कम खर्च हुआ। अगर आपकी तरह मा0 मुख्य मंत्री जी को बजट खर्च करना होता तो बजट कब का खर्च हो जाता। लेकिन सड़कों पर दिखायी नहीं देता। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा बजट है और वह बजट जनता के बीच जाना चाहिए और जनता के काम में लगना चाहिए। तिजोरियों में नहीं भरना चाहिए। बजट जाने में कुछ देरी जरूर हुयी इस बात को मा0 मुख्य मंत्री जी बोल चुके हैं। चूंकि आपने पांच साल तक भ्रष्ट अधिकारियों को बैठा रखा था उन अधिकारियों को अगर हटाया नहीं जाता तो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा आपकी तिजोरियों में चला जाता। जो आपने पांच साल लिया है। आपने किसानों की बात कही। सिंचाई की व्यवस्था किसने की ? किसान बीमा जो एक लाख था उसको बढ़ाकर पांच लाख किसने किया ? बिजली की व्यवस्था के सवाल पर मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो बिजली की व्यवस्था दी थी आज उसमें सुधार हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले पांच साल में किसी विधान सभा में एक भी काम नहीं हुआ। सारे मा0 सदस्य चाहते हैं कि मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा है कि इस बार सारी विधान सभाओं में काम हो जाये। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सारे जिलों में एक साथ सारे काम नहीं हो सकते। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। मैं माननीय सदस्यों की पीड़ा समझता हूं। पिछले पांच साल तक किसी भी सड़क पर काम नहीं हुआ। पांच साल तक रोडो पर गड्ढा करने का काम किया गया। आज निवेश की बात हो रही थी। निवेश पर हमारे डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी कह रहे थे। हमनें आंकड़ा तो नहीं देखा है। 5700 सौ करोड़ रुपये निवेश किया

गया। पांच साल के अन्दर कितना निवेश किया गया, मैं यह पूछना चाहता हूं, किसी उद्योगपति ने निवेश नहीं किया। निवेश बढ़ रहा है, यह इस बात का प्रमाण है कि उद्योगपतियों का मा0 मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी पर भरोसा है। निवेश छः महीने में नहीं हो जायेगा, निवेश के लिए आपको पांच साल इन्तजार करना पड़ेगा। आपकी जब सरकार आई थी, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर नागरिकों के ऊपर 15 सौ रुपये का ऋण था, जब आप की सरकार गई वह ऋण 17 हजार करोड़ रुपये हो गया। यह किसकी देन है, यह आपकी सरकार की देन है, इसलिए मा0 अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं कि छः महीने, सात महीने के अन्दर पूरे प्रदेश की व्यवस्था नहीं बदली जा सकती है। पिछला बजट आपने देखा था, आज यह बजट पेश हो रहा है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जब अगला बजट पेश होगा, अबकी बार भी आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं था और जब अगला बजट मा0 मुख्य मंत्री जी पेश करेंगे तो आपको प्रदेश की तस्वीर बदली नजर आयेगी । आज फोर लेन की जो व्यवस्था, यह सोंच हमारे मुख्यमंत्री जी की है, प्रत्येक जिलों को फोरलेन से जोड़ने का काम किया जा रहा है, यह मा0 मुख्यमंत्री जी की सोंच है और ''नया सवेरा'', ''असरा'', ''आदर्श नगर'', आपने पिछले पांच साल तक नगर विकास के लिए पैसा देना बन्द कर दिया था, हमारे नगर विकास मंत्री जी ने उसको लागू करने का काम किया है। आज अल्पसंख्यकों के लिए, ''मेरी बेटी उसका कल'', कब्रिस्तान के नाम पर बाउण्ड्री यह पहली बार किया गया है प्रदेश में, पूरे देश में किसी सरकार ने भी लागू नहीं किया, यह हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने लागू किया है। कल जब नेता विरोध दल बोल रहे थे, तो भाजपा के नेता ने उनका समर्थन किया था, मुझे इस बात का दुःख होता है कि आपने भी उनकी बात का समर्थन किया, इसलिए इस बात का दुःख होता है, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि आपने पांच साल तक जो यह सरकार चलाई है, इसके पहले छः महीने की अल्टा-पल्टी सरकार आपने चलाई, इसलिए कहीं न कहीं रास्ता आप साफ रखना चाहते हैं, लेकिन यह भी कहना चाहता हूं, इसके पहले आपकी संख्या कितनी थी और जब आपने इनसे समझौता किया तो आप कहां पर आ गये, इसलिए आपको इस बात पर सोंचना पड़ेगा। आज हमारे साथी बार-बार, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हमारे ही बगल के हैं मा0 राजनाथ सिंह जी, नाम ले लिया और हमारे लखनऊ, भदोही जिले के बगल में मिर्जापुर से हमारे पिता स्व0 श्री यूसुफ बेग मेम्बर आफ पार्लियामेण्ट थे, उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके थे और मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं, आपने नाम लिया, लेकिन कानून-व्यवस्था के नाम पर आपके ही मुख्य मंत्री को कोर्ट से सजा मिली। कानून-व्यवस्था की बात कौन से मुंह से करते हैं आप। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पूरा देश गवाह है, पूरा प्रदेश गवाह है कानून-व्यवस्था के नाम पर सरकार को बर्खास्त किया गया, आज आप हमारी सरकार है, आप कानून-व्यवस्था की बात करते हैं, जेल के अन्दर हत्या किसने कराई। आज पूरे बजट भाषण में सारे मुद्दों पर आपने बोला, लेकिन आपने कभी स्वास्थ्य के मुद्दे पर नहीं बोला, इनका पूरा बजट भाषण निकाल लीजिए जो इन्होंनें बोला है और देख लीजिए स्वास्थ्य के मुद्दे पर नेता विरोधी दल ने एक बात तक नहीं कही है, क्योंकि उनको डर है कि एनएचआरएम घोटाला उनका दामन नहीं छोड़ रहा है। व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो पैसा लखनऊ में एक जगह खर्च होता था, अब वह पैसा दवाई के नाम पर जिलों में सीएमओ को हैण्ड ओवर कर दिया गया है। हमारी नीयत साफ है, एक संचार क्रान्ति आई है, 108 नम्बर आप डायल कीजिए, कहीं भी रहिये, जंगल में रहिये, गांव में रहिये कहीं भी रहिये, 10 मिनट के अन्दर एम्बुलेन्स आपके पास पहुंच जायेगी, यह व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार ने दी है और जो चुनाव

लड़ने से पहले पार्टियों का घोषणा पत्र होता है। आपका घोषणा पत्र कुछ था नहीं। हमारा घोषणा पत्र जो था, जो बार-बार हमारे सदस्य कहते हैं कि घोषणा पत्र को लागू कीजिये। आपने भी तो घोषणा पत्र दिया था। हमारे बगल के भाई को कहना चाहता हूं कि अगर आपने अपना घोषणा पत्र लागू किया होता तो फिर आज ये आपकी दशा न होती। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। अब घोषणा पत्र पर सवाल का जवाब जब चाहें तब ही है। मा0 अध्यक्ष जी, चूंकि आप जब बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपका समय हो गया।

श्री जाहिद बेग-

सवाल इस बात का है कि वे लोग पहले अपने गिरेबान में देख लें। जनता को किये हुये वादों को जो लोग यहां पूरा नहीं करेंगे, उनकी संख्या घट जायेगी। आप चुनाव घोषणा की बात करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि जो 92 के पहले आपने घोषणा पत्र में लागू किया था, उसको आपने समाप्त कर दिया। सरकार आने के बाद नाम लेना बन्द कर दिया इसलिये आपकी ये दशा हो गयी और फिर चुनाव आयेगा फिर आप जनता के बीच में आना शुरू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री जाहिद बेग-

चूंकि जनता चालाक हो गयी है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं मा0 अध्यक्ष जी। मा0 पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारी भदोही विधान सभा में उद्योग का क्षेत्र रहा है। कालीन उद्योग का क्षेत्र रहा है। वहां एक भी काम नहीं किया गया। सड़कों में गड्ढे हो गये थे, वाहनों का आना जाना बन्द हो गया था लेकिन अब भदोही से गोपीगंज मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य स्वीकृत हो गया। अब भदोही से दुर्गगंज मार्ग भी स्वीकृत होने जा रहा है। ये इसी बात का प्रमाण है कि हम उद्योग के क्षेत्र में, व्यापारियों के क्षेत्र में कितना प्रयत्नशील हैं। जहां तक आकस्मिक एक्सीडेण्ट की बात है, आपदा से मरने की बात हैं। 392 नम्बर हमारा विधान सभा क्षेत्र है, 25 लाख रुपये से अधिक कृषि बीमा के अलावा हमने अपने विधान सभा में दिलाने का काम किया है। हम इस बात को झूठ नहीं बोल रहा हूं। हमारी विधान सभा के 392 नम्बर से आप निकलवा करके देख सकते हैं। इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि लैपटाप के मुद्दे पर, रिक्शा के मुद्दे पर मैं कहना चाहता हूं। हमारे एक सदस्य बोल रहे थे। अध्यक्ष जी, बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि लैपटाप में इसलिये देर हुयी क्योंकि मैं चाहता हूं, हमारी सरकार यह चाहती है कि जिसको लैपटाप मिले, सही मिले अच्छी कम्पनी का मिले और दिल्ली वाला लैपटाप देना होता तो अब तक हम लोग बांट चुके होते। हमारी मंशा साफ है और सही है, आप देख सकते हैं कि जो भी चीज मिले, सही मिले। सही पैसा जनता के बीच जाये और इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मा0 अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके माध्यम से बोलने का मौका मिला, जय हिन्द। जय समाजवाद।

*श्रीमती सीमा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे मा0 मुख्य मंत्री के बजट पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिये मा0 अध्यक्ष जी, हम हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, सरकार का बजट लम्बा है, चौड़ा है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं और जैसा कि हमारे विधान सभा की व्यवस्था है कि पक्ष और विपक्ष दोनों बोलते हैं, कोई सुझाव देने के लिये, कोई शिकायत करने के लिये और उसी सुझाव और शिकायत में आदमी अपनी बात भी आसानी से कर लेता है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं भी दो-तीन सुझाव देना चाहूंगी। जैसे अभी सरकार ने पिछड़े और निर्धन व्यक्तियों की शादी और बीमारी के लिये कितना पैसा दिया है, 150 करोड़ रूपया दिया है जोकि 2012-13 से 60 करोड़ अधिक है लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, क्या न्याय होगा जिसकी शादी में अभी तक 10 हजार रुपया मिलता चला आ रहा है, शादी के नाम पर। क्या इस 10 हजार को बढ़ाकर 20 हजार नहीं कर देना चाहिये। महंगाई इतनी ज्यादा हो गयी है, खर्चे इतने ज्यादा हो गये हैं। अगर हम गरीबों की शादी के नाम पर 10 हजार रुपये देते हैं मा0 अध्यक्ष जी। 20 हजार मिलता है मा0 अध्यक्ष जी उसको बढ़ा करके इस बजट में अगर आपने 60 करोड़ रुपये की वृद्धि करी है तो मुझे लगता है इसका जितना भी मिलता है उसका दोगुना हो जाना चाहिये था। ये मेरा अपना सुझाव है। मा0 अध्यक्ष जी, आपने राम मनोहर लोहिया के तहत अभी मा0 मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव जी का जवाब आ रहा था कि वह हर साल एक जनपद में 22-23 गांवों के विद्युतीकरण के लिये और सड़क मार्गों के लिये चयन करते हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या पूरे प्रदेश का विकास होगा, तब सही है कि एक जिले का विकास होगा, तब सही है। एक जनपद में 9-10 विधान सभाएं होती हैं, किसी विधान सभा से 15 गांव चयनित कर लिए जाएं और किसी विधान सभा से एक भी गांव चयनित न किये जाए मा0 अध्यक्ष जी, तो मुझे नहीं लगता कि यह राम मनोहर लोहिया के नाम को साकार करना होगा। मा0 अध्यक्ष जी, राम मनोहर लोहिया जी सबके थे, उनका कोई अपना-पराया नहीं था, वह सबमें अपना विश्वास रखते थे, ऐसे महान व्यक्ति के नाम पर अगर हमारे आपस में विभेद किया जाए मा0 अध्यक्ष जी, तो मुझे नहीं लगता कि यह कहीं से न्यायसंगत होगा इसलिए हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि हर जनपद से चाहे 20 ही गांवों का चयन क्यों न हो, लेकिन सारे विधायकों के प्रस्ताव उसमें शामिल हो, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। मा0 अध्यक्ष जी, अभी मैं देख रही थी, एक बहुत अच्छी बात आई है कि अल्पसंख्यक लोगों को दफनाने के लिए उनके मस्जिदों को सही करने के लिए, बाउन्ड्रीवाल करने की व्यवस्था की गयी है। मा0 अध्यक्ष जी, बहुत अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष-

कब्रिस्तान की बाउन्ड्रीवाल है, मस्जिद का नहीं।

श्रीमती सीमा-

सॉरी, कब्रिस्तान के बाउन्ड्रीवाल की व्यवस्था की गई है, मा0 अध्यक्ष जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी हमारे यहां एक मुस्लिम की मृत्यु हो गई थी और स्थल विवाद को लेकर के 24 घंटे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक लाश वहीं पर पड़ी रही। कब्रिस्तान का इतना विवाद था कि लाश दफन कहां की जाए, इसकी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। अच्छा निर्णय है आपका आपने अच्छा काम किया, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, हम सभी लोग गांव से जीतकर आते हैं, हमारे गांव में मंदिर है, हमारे गांव में चौरा है, हमारे गांव में अगल-बगल के ऐसे-ऐसे स्थल हैं, वहां पर भी हमको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी, मैं किसी जाति या किसी भी धर्म के नाम पर नहीं कह रही हूं। मेरी अपनी सोच है, अगर हम कब्रिस्तान में बाउन्ड्री दे सकते हैं, तो किसी मंदिर को भी बाउन्ड्री देने में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी अपनी सोच है।

श्री अध्यक्ष-

थोड़ा-थोड़ा बोलो, जिससे सब लोग बोल सके, जल्दी खत्म करो।

श्रीमती सीमा-

जी मान्यवर, शिक्षा की बात अगर मा0 अध्यक्ष जी की जाए, आप सभी लोग पढ़े-लिखें हैं, हम भी पढ़े-लिखें हैं, हमने इंटर में पढ़ा था और यह बात हम बार-बार कहते हैं, अरस्तु जो दार्शनिक था मा0 अध्यक्ष जी, उसकी यह सोच थी। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर कोई मुझे 2000 शिक्षित मां दे दें तो मैं उसे एक सुन्दर राष्ट्र प्रदान कर सकता हूं मा0 अध्यक्ष जी, जहां मेरी विधान सभा है, यह मेरा दुर्भाग्य है या सौभाग्य मैं समझ नहीं पाती, मेरे विधान सभा से प्रतापगढ़ 60 किलोमीटर, इलाहाबाद 60 किलोमीटर, जौनपुर 65 किलोमीटर, आज मेरी विधान सभा में एक भी राजकीय महिला विद्यालय नहीं है, मैं सरकार से उम्मीद करना चाहूंगी कि जब आपने कई जगहों पर विद्यालय देने का काम किया है, तो एक महिला के क्षेत्र में महिला विद्यालय की स्थापना अगर न हो पाएगी, तो मैं समझती हूं कि आप महिलाओं के विरोधी हैं, आप महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं करना चाहते हैं। शिक्षा की बात करें अगर मा0 अध्यक्ष जी, आप सभी गांवों से चुनकर आते हैं, इंटर कालेजों में चले जाइये, डिग्री कालेजों में चले जाइये, पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं, प्रबन्धक के पास, प्रिसिंपल के पास नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है, चयन आयोग नियुक्ति कर नहीं रहा है, आखिर अध्यक्ष जी, विद्यालय बंद होने के कगार पर हैं, इसके बारे में भी हमारी कोई सोच होनी चाहिए। यदि बिजली की बात हम करें, जब बिजली की बात होती है तो पक्ष-विपक्ष दोनों का बड़ा हंगामेदार भाषण होता है। हम अध्यक्ष जी, जिस जनपद से चुनकर आते हैं, जनपद जौनपुर आपका पड़ोसी जनपद है। जनपद जौनपुर सिराज हिन्द की धरती है। जनपद जौनपुर का अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हमारे यहां मा0 अध्यक्ष जी, जब हम देखते हैं कि आजमगढ़ में 18 घंटे लाइट जलती है, बनारस में 15 घंटे लाइट जलती है, इलाहाबाद में 19 घंटे लाइट जलती है, जब हमारे शहर में 8-9 घंटे हमको लाइट मिलती है, तो बड़ी पीड़ा होती है कि आखिर हम सी-श्रेणी में क्यों हैं? मैंने कई बार इस बात को कहा है, हमारे जनपद में 9 विधान सभा सीटे हैं, 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी सरकार का कब्जा है, जिला पंचायत इनकी है, इनके सारे लोग हैं, दो में से एक इनके सांसद हैं। आखिर जनपद जौनपुर को सी-श्रेणी से हटकर ए-श्रेणी में आने का अधिकार कब प्राप्त होगा, मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी, एक दिन में गयी थी, जिला जेल में अपने किसी एक आदमी को देखने के लिए, मैंने वहां पर देखा बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। मैंने जेलर से पूछा कि यह बताइये कि यहां पर कैदी कितने हैं, उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा- मैडम यहां

पर अगर एक हजार कैदी रखने की व्यवस्था है, तो यहां पर डेढ़ हजार कैदी हैं, जेल में कैदियों के रहने के लिए जगह भी नहीं है। हमारे जनपद में जेल प्रस्तावित है, जेल कहीं बनने की योजना है, लेकिन किन कारणों से नहीं बन पा रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जेल में कम-से-कम ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो कैदी वहां पर जाएं सुकून की सांस ले सके। आखिरी बात कहना चाहूंगी मा0 अध्यक्ष जी, सरकार ने कई करोड़ रुपये दिए हैं, पुल के नाम पर, सड़क के नाम पर, सरकार ने बहुत सारा पैसा दिया है, रोडो के नाम पर, जब मा0 मुलायम सिंह की सरकार थी, शायद 2002 में मैं उसमें विधायक नहीं थीं। सी0एन0 सिंह हमारे यहां सांसद थे।

मान्यवर, बिलवर घाट पर सई नदी पर पुल का शिलान्यास हुए 14 साल हो गये हैं, पुल नहीं बन पा रहा है। शायद पैसे के अभाव में नहीं बन पा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि आप चाहे नया पुल नई रोड न बनवायें परन्तु जो परियोजनाएं अधर में पड़ी हुई हैं, काम खराब हुआ है उन कामों को आप प्राथमिकता पर लेकर, पूरा कराने का काम करें। उससे जनता का बहुत भला होगा। मान्यवर, हमारे यहां चमोर नाला है उसको पार करने के लिए 50 किलोमीटर दूर चल कर जाना पड़ता है। उस बन्धे पर एक पुल बन जायेगा। तो जनता को बहुत बड़ी सुविधा होगीं। हमारे यहां कनवोरा में 133 के0वी0 का पावर हाउस लगा हुआ है लेकिन बड़ी विडम्बना है कि उससे केवल तीन गांव ही जुड़े हुए हैं यह शायद लाइन की व्यवस्था न होने कारण है इसको आप दिखवाने का काम करें। तो लोगों का भला होगा। धन्यवाद।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह योगेश भइया)-

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-2014 के बजट पर हो रही सामान्य चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, बजट किसी भी सरकार के दृष्टिकोण का आइना हुआ करता है। आज जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह दो लाख इक्कीस हजार दो सौ एक करोड़ उन्तीस लाख रुपये का है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। मान्यवर, इसमें वित्तीय वर्ष 2012-13 की अपेक्षा कर राजस्व में 19 प्रतिशत की वृद्धि का दिग्दर्शन होता है। इसमें दो सौ उन्नीस नई योजनाओं हेतु 7787.80 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसमें अवस्थापना सुविधाओं हेतु 26641 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। त्वरित आर्थिक विकास के लिए इसमें एक हजार करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं हेतु 17174 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसी तरह से शिक्षा का विस्तार एवं गुणवत्ता हेतु 32886 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु 10645 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के लिए 20292.92 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, 2013-14 में किसानों की ऋण माफी हेतु 750 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया है। मुफ्त सिंचाई हेतु 200 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया है। किसान-दुर्घटना बीमा योजना हेतु 375 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया है। अधिवक्ताओं हेतु 40 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया है। मान्यवर, 2013-14 में प्राप्तियां 215919.82 करोड़ रुपये अनुमानित हैं और व्यय 221201.19 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। इसमे राजस्व बचत 9856.01 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। राजकोषीय घाटा

23913.29 करोड़ अनुमानित है। जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.94 प्रतिशत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में बैठे थे और नेता विरोधी दल ने बजट पर चर्चा का प्रारम्भ किया था उसमें उन्होंने अपनी उन बीती हुई काली रातों को याद किया जो इस प्रदेश के इतिहास में एक काला अध्याय था। उन्होंने सरकार को यह बताने का काम किया कि हमने यह काम किया था आप यह कर रहे हैं आपने यह प्राविधान किया है। लेकिन मान्यवर, यह सब बातें जिस कसौटी पर मापी जाती हैं वह होती है जनता की भावना। मान्यवर, वर्ष 2012 में प्रदेश में सामान्य चुनाव हुए और जनता ने अपने जन प्रतिनिधियों को चुना और हमारी पार्टी की सरकार बनवाई।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करे।

श्री योगेश प्रताप सिंह (योगेश भइया)-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश देश और पूरे विश्व में चाहे वह यूरोपियन कन्ट्रीज हों या अफरीकन कन्ट्रीज को ले लें, हर जगह उम्र का प्रतिशत बढ़ता ही चला जा रहा है। वहां के निवासियों का जो प्रतिशत है वह बुढ़ापे की तरफ बढ़ता जा रहा है और हमारा भारत एक नौजवान भारत होकर उभर रहा है। जिस तरह से आज 62 प्रतिशत आबादी पूरे भारत में नौजवानों की है आज हम यह कहने में जरा भी संकोच नहीं हैं कि आज भारत की आबादी युवा हो चुकी है। मेरा सौभाग्य है तथा इस प्रदेश का सौभाग्य है कि आज उत्तर प्रदेश को एक नौजवान नेतृत्व मिला है। नौजवान हमारी आबादी, अभी कुछ हमारे साथी कल कह रहे थे कि टैबलेट से काम नहीं चलेगा, कम्प्यूटर से, लैपटाप से काम नहीं चलेगा उन्हें अपनी याददाश्त सुधारना चाहिए। उन्हें कहीं न कहीं बैठ करके इन अपने विचारों पर स्वयं मंथन करना चाहिए। आज जब पूरा विश्व ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, पूरा विश्व वैश्वीकरण की तरफ बढ़ रहा है, संचार माध्यमों की वजह से विश्व का दायरा छोटा होता चला जा रहा है ऐसे समय में यह कह करके बैठ जाना कि कम्प्यूटर बेमानी है, लैपटाप बेमानी है, टेबलेट बेमानी है यह कहीं न कहीं हमारी पूरी आबादी को पीछे ढकेलने का काम करेगा। मैं उन अपने वरिष्ठ साथियों से कहना चाहूंगा कि आपको भी अपने विचारों में कहीं न कहीं बैठ करके सोचना चाहिए। अगर बढ़ती हुई इस प्रगति की तरफ आप अपने को जोड़ना नहीं चाहेंगे तो हम पीछे रह जायेंगे, पूरा विश्व हमसे आगे चला जायेगा। आज मैं माननीय मुख्य मंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहेंगे चाहे कन्या विद्या धन की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात हो, चाहे लैपटाप, टेबलेट की बात हो, चाहे आपके किसान दुर्घटना बीमा योजना की बात हो यह सारी चीजें एक स्वप्नदृष्टा का स्वप्न था। जो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव का है जिन्होंने अपने स्वप्न को जमीन पर उतारने का काम किया था और भी दल हैं सबके घोषणा-पत्र आते हैं लेकिन हमारे दल ने जो घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया था आज हमने उसको राजनैतिक रूप से बाइबिल, गीता और कुरान मान करके उसके अनुरूप अनुपालन करने का काम किया है और आने वाले समय में उसका शत-प्रतिशत पालन होगा। यह मेरा अपना मानना है। साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मान्यवर, जहां से आप आते हैं, नैपाल की उस तराई से जहां से निकल करके विधान सभा की इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं वह पूरा हमारा सम्पूर्ण क्षेत्र उपेक्षित पड़ा हुआ था, आज मुख्य मंत्री जी की कृपादृष्टि हुई है और पूरे प्रदेश

में 9 थ्री पी के तहत सड़कें बनने जा रही हैं। बलरामपुर से लेकर के गोण्डा और जरवल की जो सड़क हुई है उस सड़क के लिए मैं विशेषता माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं थ्री पी से सड़क का निर्माण होता है तो हमारा पूरा पूर्वान्चल, पूरी नैपाल की तराई का वह इलाका उन्नति की तरफ आगे बढ़ेगा, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 2013-14 में 2100 गावों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है उसके लिए हम माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। मान्यवर, आपका निर्देश है, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में बोलते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं

*श्रीमती रूबी प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया हम जनपद सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के बाद सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला है यह जनपद मध्य प्रदेश, झारखण्ड, बिहार एवं छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है इस जनपद में कई औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं। यहां पर हमारे यहां आवागमन जनपद सोनभद्र से वाराणसी और जिला तक जाने के लिए सोन नदी पर सिर्फ एक पुल बना है जिससे घन्टों जाम में यात्री फंसे रहते हैं, मरीजों को ट्रीटमेन्ट के लिए जिला अस्पताल ले जाना हो या वाराणसी ले जाना हो तो वह घन्टों जाम में फसे रहते हैं। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि उन्होंने अपने बजट पत्रिका में जो 259 पुलों की बात कही है यदि वह 260 पुल बनवा लेते और हमारे जनपद सोनभद्र में सोन नदी को एक पुल दे देते तो इसके लिए हमारे क्षेत्र की जनता और हम लोग आपकी सरकार को धन्यवाद देती। साथ ही साथ आपकी बजट पुस्तिका के पेज नं0 22 पर नक्सल प्रभावित जिले मिर्जापुर, सोनभद्र और चन्दौली में अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। लेकिन मान्यवर, उसमें यह नही बताया गया कि कितने धन की व्यवस्था की गई है और क्या कार्यक्रम इन नक्सल प्रभावित जिलों के लिये चलाया जायेगा। सोनभद्र जनपद की दुद्धी विधान सभा क्षेत्र जहां से हम प्रतिनिधित्व करते हैं, पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है, यहां के किसानों के लिये सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, यह सरकार अपने को किसानों का हितैषी मानती है और मुख्य मंत्री जी भी हमेशा किसानों का जिक्र करते हैं, हम भी अपेक्षा रखते हैं कि यहां के किसान जो सिंचाई के लिये सिर्फ भगवान के सहारे रहते हैं, हम चाहेंगे कि इन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा चेकडैम बंधी का निर्माण किया जाये ताकि किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान लाई जा सके। चूंकि यह ऐसा पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जहां पर नहर नहीं निकाली जा सकती, इसलिये यहां पर सिर्फ चेकडैम और बंधी ही बन सकते हैं, इसलिये हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि उस दुर्गम क्षेत्र में जहां सिंचाई के लिये किसान भगवान पर निर्भर रहते हैं, उनके लिये चेक डैम और बंधी का निर्माण किया जाये। हमारे जनपद सोनभद्र में 2011 की जनगणना के अनुसार 1 करोड़ 86 लाख 2 हजार 612 और आबादी का घनत्व 270 प्रति वर्ग किमी0 लोगों की जनसंख्या है, हमारे यहां सिंगरौली थर्मल संयंत्र है और कोयले की खानों का 85 से भी ज्यादा प्रतिशत सोनभद्र में मौजूद है। इसके बावजूद भी जिले में बुनियादी सुविधाओं की हालत निराशाजनक है, कुल 3 लाख 27 हजार घरों में से मात्र 29 प्रतिशत घरों में बिजली उपलब्ध है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पेयजल की स्थिति भी बेहतर नहीं है, जिले में कुल घरों के केवल 22 प्रतिशत घरों के अंदर पेयजल का स्रोत उपलब्ध है, 44 प्रतिशत घरों को जहां स्वच्छ पानी मिलना चाहिये, वह उपलब्ध नही है, इसके अलावा 30 प्रतिशत घरों में पानी का स्रोत उनके घरों से दो-दो किमी0, चार-चार किमी0 की दूरी पर है और 13 प्रतिशत घरों को जल प्रशोधित करके मिलता है, जिसमें फ्लोराइड, आर्सेनिक, पारा पाया जाता है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में शक्तिनगर क्षेत्र है, वहां पर सुनीता नारायण, सी0एस0आर0 के तहत उन्होंने रिसर्च किया और वहां के हैन्डपंपों में कई ऐसी जगहों को चिन्हित किया, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट लगाई कि हैन्डपम्प के पानी में 84 प्रतिशत पारा पाया जाता है। वहां पर रिहन्द जलाशय है, वहां की मछलियां भी प्रदूषण से प्रभावित हैं, उन मछलियों में भी मिथाइल पारा पाया गया। इससे वहां का वातावरण प्रदूषित रहता है और वहां पर इससे कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। वहां पर फ्लोरिसिस नाम की बीमारी बहुतायत से होती है। वहां के बच्चे इससे प्रभावित हैं, वहां की महिलायें इससे प्रभावित हैं, वहां पर एक आश्रम हैं, उन्होंने 4300 घरों का सर्वेक्षण कराया, उसमें पाया गया कि समय से पूर्व महिलाओं के नाखून सफेद हो रहे हैं, उनकी त्वचा पर सफेद दाग पाया जाता है, साथ ही साथ समय पूर्व उनका गर्भपात हो जाता है, इस तरह की रिपोर्ट दिल्ली की सुनीता नारायण, जिन्होंने सबसे पहले पेप्सी में कीटनाशक का प्रमाण दिया था, उन्होंने इसकी रिपोर्ट दी और हमारे क्षेत्र में सर्वेक्षण कराया। हम सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जितने हैन्डपंपों का पानी पारे से प्रभावित है, उनको चिन्हित किया जाये और उसके लिये अलग से कोई व्यवस्था की जाये ताकि आने वाले समय में 10-20 सालों में लोग इस जहरीले पानी से जो बीमार पड़ते हैं, वह न हो पायें और जो महिलायें शर्म से घर से बाहर नहीं निकलती, उनके शरीर पर सफेद दाने और सफेद दाग हो जाते हैं, चूंकि यह अति लोकमहत्वपूर्ण सवाल है और हमारे मुख्य मंत्री जी पर्यावरण से इंजीनियरिंग किये हुये हैं, मुझे सही जानकारी नहीं है लेकिन इतनी जानकारी है, इसलिये हम इस बात को मुख्य मंत्री जी की जानकारी में देना चाहते हैं । हमारे जनपद में इतने उद्योग हैं, सबसे ज्यादा पावर प्लान्ट जनपद सोनभद्र में हैं और पूरी बिजली दूसरे प्रदेशों को जाती है और हमारा जनपद सोनभद्र अंधेरे में जीता है और वहां के लोग अंधेरे में जीने को विवश हैं। अभी भी हमारे क्षेत्र में एक पॉवर प्लान्ट 1086 मेगावाट का लगाने की परियोजना चल रही है इसमें पांच सौ गांव विस्थापित होंगे हम सरकार से आग्रह करेंगे कि पहले उन विस्थापितों के लिए रहने की व्यवस्था की जाए, उनके घरों की व्यवस्था की जाए, उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था की जाए तथा साथ ही साथ उन्हें पर्यावरण से बचाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्री जगतम्बा सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा प्रस्तुत 2013-2014 के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने यह दूसरा बजट प्रस्तुत किया और इस बजट में जिस तरह के प्रावधान हैं, गांव के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था के लिए, हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। पिछले 11 महीनों में हमारी सरकार की काम की गति यदि धीमी रही है तो वह केवल इसलिए रही है कि इसके पहले के पांच साल जिस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरह से अधिकारियों ने भ्रष्टाचार में लिप्त हो करके काम न करने का एक अपना आचरण बना लिया था, काम न करने की उनकी परिपाटी हो गई थी, सरकारी बजट के 80 प्रतिशत लूट की जो उनकी परिपाटी हो गई थी, उसकी वजह से 11 महीने काम करने में दिक्कतें हुई हैं। वह पहले तो उसी ढर्रे पर चलाना चाहते थे लेकिन जब वह समझ गये कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में लूट नहीं चल पायेगी, तब कहीं जाकर उनके काम करने की प्रवृत्ति अब ठीक हो रही है, वह समझ गये हैं कि हमें ईमानदारी से काम करना होगा। मान्यवर, हमारी सरकार किसानों की सरकार है। मैं चुनार विधान सभा क्षेत्र मिर्जापुर से चुनकर आया हूं, एक बहुत बड़े नेता जी थे और सिंचाई विभाग के मंत्री भी थे लेकिन हमारे चुनार विधान सभा क्षेत्र में कभी नहरें साफ नहीं हुईं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को क्योंकि चालीस सालों में पहली बार हमारे यहां नहरों की सफाई हुई है और इस तरह से सफाई हुई है जैसे कि पहली बार नहर खुद रही हो, इससे गांव का किसान बहुत प्रसन्न है। टेल तक पानी दो दिनों में पहुंच गया इसके लिए मैं अपने सिंचाई मंत्री माननीय शिवपाल सिंह यादव को धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, पहली बार किसानों को न तो खाद की दिक्कत हुई और न ही बीज की दिक्कत हुई, धान की पैदावार बहुत जबर्दस्त हुई है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में लोहिया समग्र ग्राम्य विकास की जो व्यवस्था की है उससे गांवों का समग्र विकास हो रहा है, पांच साल में बहुत जबर्दस्त विकास होगा क्योंकि हर स्तर पर 36 बिन्दुओं के तहत विकास होना है। चूंकि बी0पी0एल0 सूची में तमाम अपात्र लोग भी सम्मिलित हो गये हैं पहली बार हमारी सरकार ने बी0पी0एल0 सूची के अतिरिक्त जिनकी आय 36 हजार रुपए से कम है, ऐसे लोगों को आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने पहली बार स्नातक तक की लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रबन्ध किया है। हमारे मिर्जापुर जनपद में माननीय नेता जी की जब सरकार थी तो उन्होंने एक इंजीनियरिंग कालेज मिर्जापुर को दिया था और वह बनना प्रारम्भ भी हो गया था परन्तु जो पिछली सरकार आई उसने उसका बनना बन्द कर दिया और उसे किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, इंजीनियरिंग कालेज हमारे यहां नहीं बन पाया। माननीय मुख्य मंत्री जी से हमारा अनुरोध रहेगा कि वह हमारे मिर्जापुर को एक इंजीनियरिंग कालेज दें क्योंकि पहले नेता जी ने दिया था। इसी के साथ-साथ माननीय नेता जी ने वर्ष 2007 में मिर्जापुर में गंगा नदी पर भठौली और चुनार में दो पुल दिया था, दोनों पुल बनना शुरू हो गये थे लेकिन पांच साल की पिछली सरकार में पुलों का बनना बन्द था। हमारी सरकार जब से आई है तब से पुलों का निर्माण शुरू हो गया है। अभी इस बजट में इंगित भी किया गया है कि वर्ष 2014 तक वह दोनों पुल बन जायेंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं, उनका आभारी हूं। हमारे यहां जो दोनों पुल विकास के लिए आवश्यक थे वह बन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री जगतम्बा सिंह-

मान्यवर, खत्म कर रहा हूं। एक और हमारी सबसे बड़ी बात हमारी सरकार की रही है कि हम लोग पिछड़े वर्गों से आते हैं, पिछड़े वर्गों के साथ पिछले पांच साल में बहुत अन्याय किया गया है, कहीं स्कॉलरशिप नहीं मिली। पहली बार उम्मीद है कि स्कॉलरशिप ग्राउण्ड लेबिल पर पहुंचेगा। महोदय, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय करते हैं, उनकी नियुक्तियों में अन्याय करते

हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बतायेंगे कि तमाम भर्तियों में अभी जूनियर इन्जीनियर्स का विज्ञापन निकला था, 543 पदों का विज्ञापन हुआ था उसमें पिछड़े वर्ग का उसमें शून्य है जबकि ऐसा सम्भव नहीं है। इसके पहले भी जो पिछली सरकार थी तब भी उच्चाधिकारियों ने पशु-चिकित्सा में मात्र 58 पद बैकवर्ड का निकाला था। मैंने पिछड़ा वर्ग आयोग में एक याचिका दायर किया तो 58 की जगह 328 पद निकले। तो इस तरह से सरकार से मुझे उम्मीद है कि पिछड़े वर्गों के साथ न्याय होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और इस बजट की मैं तारीफ करता हूं।

*श्री राकेश बाबू-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस सरकार को बने एक वर्ष बीत चुका है और दूसरे वर्ष का बजट हमारे सामने है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि बजट में डा0 लोहिया ग्राम समग्र विकास योजना के अंतर्गत सरकार ने विकास का प्राविधान रखा है। लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष हमारी विधान सभा टूण्डला में तीन ब्लाक हैं नारकी ब्लाक, फिरोजाबाद ब्लाक और टूण्डला ब्लाक। परन्तु इनमें से मात्र दो ग्रामों का चयन किया गया था। समाचार-पत्रों और मीडिया में भी इसका प्रचार किया गया था, सलेमपुर नगला खार उलाऊखेड़ा। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इन दोनों ग्रामों में 99 प्रतिशत समाजवादी पार्टी के ही वोटर हैं लेकिन अध्यक्ष जी, एक माह के बाद मीड़िया के माध्यम से इन दो ग्रामों को काट दिया गया। यह हमारे साथ, हमारी विधान सभा के साथ, हमारी जनता के साथ घोर अन्याय है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि अब अगले वर्ष डा0 लोहिया समग्र ग्राम विकास के गांवों का चयन हो तो हमारे तीनों ब्लाकों में से समग्र विकास योजना के अंतर्गत गांवों को चयनित किया जाना चाहिए। इसी तरह से मा0 जनेश्वर मिश्र विकास योजना के तहत जनपद फिरोजाबाद में अन्य विधान सभाओं की तरह हमारी विधान के ग्रामों को चयनित करने से वंचित किया गया है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मा0 जनेश्वर मिश्र विकास योजना के तहत हमारे नारकी, टूण्डला और फिरोजाबाद के गांवों को लिया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पिछले वर्ष हमारी विधान सभा में नव निर्माण में चाहे वह राजीव गांधी ग्राम सड़क योजना हो, चाहे जिला योजना के माध्यम से हो, चाहे नाबार्ड योजना हो, चाहे किसान मण्डी समिति हो एक भी मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आने वाली 2013-2014 की योजना में हमारी भी विधान सभा के मार्गों का चयन करने का काम किया जाए। इसी तरह से मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी विधान सभा क्षेत्र नारकी, टूण्डला, फिरोजाबाद में पेयजल का जलस्तर नीचे चले जाने के कारण अधिकतर हमारे हैण्डपम्प रि-बोर की स्थिति में आ गये हैं लेकिन पिछले वर्ष एक भी हैण्डपम्प किसी भी ब्लाक में रि-बोर नहीं कराया गया है। इसी तरह से नये नल अर्थात नवीन हैण्ड पम्प लगाने का कार्य भी नहीं किया गया है।

अध्यक्ष जी इसी तरह से मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले कार्यकाल में पिछले वर्ष हमारी एक पेयजल योजना थी जो फिरोजाबाद नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आती है काशीराम विहार पेयजल योजना एवं टापा खुर्द पेयजल योजना यह एक साल से कंप्लीट है मैंने इसका क्वैश्चन भी लगाया था क्वैश्चन का जवाब आया है कि योजना हमने बनाकर नगर पालिका परिषद फिरोजाबाद को संचालित करने के लिए स्थानान्तरित कर दी गई है। हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी बैठे हैं इस योजना का आज तक नगर पालिका परिषद द्वारा संचालन नहीं किया गया है जिससे जनता में पेयजल की काफी समस्या है। वहां के लोग काफी दूर से पानी लाने के लिए विवश हैं। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान टूंडला में एक भी राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं है इस ओर ले जाना चाहता हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि टूंडला शहर और आसपास की आबादी को ध्यान में रखते हुए टूंडला शहर में एक महिला राजकीय महाविद्यालय के स्थापना की मांग करता हूं क्योंकि यहां की महिलाओं को 20-30 कि0मी0दूर तक जाना पड़ता है। अध्यक्ष जी इसी तरह से हमारे तीनों ब्लाकों में नार्की टूण्डला फिरोजाबाद ब्लाक में जल स्तर नीचे चले जाने से नलकूप फेल हो गए हैं जिससे किसानों में काफी परेशानी पैदा हो रही है वहां पर सूखाग्रस्त होने के कारण जल स्तर नीचे जाने के कारण सरकार ने नवीन नलकूपों की बोरिंग पर रोक लगा दी है क्योंकि सूखा क्षेत्र हर गांव में नहीं है काफी बम्बा के किनारे, नदी के किनारे के गांव सूखाग्रस्त नहीं हैं लेकिन पूरे ब्लाकों को सूखाग्रस्त घोषित करने के कारण नवीन हैण्डपम्पों की बोरिंग पर रोक लगाने से दिक्कत हो रही है। हमारे काफी किसान ऐसे हैं जो अपना नलकूप लगाना चाहते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो रोक लगाई गई है उन गांवों को चिन्हित करके लगाई जानी चाहिए जहां वास्तव में पानी का संकट है। हमारे क्षेत्र में एक सहगर नदी है एक हर्ना नाला है जिसमें जब बरसात का पानी आता है वह बहता हुआ आगे चला जाता है जिससे जलस्तर बढ़ नहीं पाता है तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सहगर नदी एवं हर्ना नाला पर एक चेक डैम बनाकर जल सहेजने की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। इसी तरह से माननीय अध्यक्ष जी आपका ध्यान अपनी विधान सभा के बरहन रजबहा है उससे नगला सिंगी की तरफ जो बम्बा जाता है इधर नगला बलू की तरफ बम्बा जाता है उसकी आज तक सफाई नहीं की गई तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन रजबहों की भी सफाई कराकर जनता को पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री राकेश बाबू-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनपद फिरोजाबाद के टूडला क्षेत्र में ताज ट्रिपेजियम जोन योजना के अन्तर्गत 24 घण्टे की बिजली देने की व्यवस्था सरकार को आदेशित है और इस 24 घण्टे के हिसाब से किसानों का बिजली का बिल आता है लेकिन काफी समय से इस क्षेत्र के किसानों को 10 या 12 घण्टे बिजली मिल रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां जो ताज ट्रिपेजियम जोन के अन्तर्गत 24 घण्टे बिजली मिलनी चाहिए वह व्यवस्था बहाल की जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री राकेश बाबू-

हमारे यहां कब्रिस्तानों की जो बाउण्ड्री है कब्रिस्तानों की बाउण्ड्री का जो सरकार ने कार्यक्रम चलाया है यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो भूमाफियाओं द्वारा कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जाता है मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन बाउण्ड्री में नार्की ब्लाक के किसी गांव का चयन नहीं किया गया है। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग डरें न सभी को बोलने का मौका मिलेगा। कल और परसों दोनों दिन चर्चा है।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिये एक साथ खड़े होने पर)

सबको बोलने का मौका मिलेगा। टी0राम जी बैठो अभी बुलवाते हैं। आज थोड़ा देर तक चलेगा। हमारी कई महिला सदस्य हैं जो बोलना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी की हैं और हमारी तरफ की भी हैं। इसलिये प्राथमिकता के आधार पर पहले इनको बुलवा लिया जाय। उसके बाद आप लोगों को मौका मिलेगा।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमको बोलने का अवसर दिया, इसलिये मैं आभार प्रकट कर रही हूं। यह बजट जो लम्बा चौड़ा वृहत आकार का है, समस्त लेन देन को पूरा करने के बाद भी 1 करोड़, 226 लाख 53 हजार रुपये घाटे में है। यह घाटा कैसे पूरा किया जायेगा, इसका कोई हिसाब बताया नहीं गया है। यह अंतिम समय में बढ़ी हुई मंहगाई के रूप में जनता के सामने आयेगा। इस बजट में बाल विकास की काफी योजनाएं रखी गई हैं लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि हर 8 मिनट पर एक बच्चा गुम हो जा रहा है। उस बच्चे के मां-बाप तो तड़प कर रह जाते हैं। बच्चा कहां गया ? अंधे, लूले लंगड़े के रूप में है, या ऊपर चला गया कुछ पता नहीं चलता। इसमें सरकार की ओर से ऐसा कोई जाल नहीं बिछाया गया कि खोये बच्चे मिल जायं। पिछले साल साढ़े ग्यारह हजार बच्चे खोये थे जिसमें से केवल ढाई हजार बच्चे वापस मिले थे। इस बजट में विकलांग पेंशन के बारे में कहा गया। श्रवण, दृष्टि और शारीरिक रूप से विकलांग के लिये शिक्षा के लिये एक माध्यमिक स्कूल खोलने की योजना है। मेरा कहना केवल इतना था कि ऐसे बहुत से विकलांग स्कूल आज भी प्रदेश में हैं जो लड़खड़ा कर चल रहे हैं। बनारस में सिद्धगिरी बाग में मानसिक विकलांग का स्कूल है। मानसिक विकलांग को सबसे कठिन होता है पढ़ाना। लेकिन धन के अभाव में वह कब बन्द हो जाय इसका ठिकाना नहीं है। इसी प्रकार से खुशीपुरी गांव में एक विकलांग स्कूल है, उसमें चार हिस्से हैं। बच्चों को शिक्षा देना, व्यावसायिक शिक्षा देना, अंग निरूपण करना, चिकित्सालय की व्यवस्था करना। लेकिन तीन विभाग अभी तक शुरू नहीं हुआ। स्कूल खुले 8 साल हो गये, सरकार ही स्कूल चलाती है लेकिन उसकी पूरी कार्य क्षमता के साथ उसका उपयोग आज भी नहीं हुआ है। नया स्कूल सरकार जरूर खोले लेकिन जो पुराने स्कूल हैं उनको ठीक से चलने का अवसर सरकार दे। इस बजट में महिला कल्याण की बात कही गई है लेकिन सारी महिलाओं का कार्यक्रम ऑगनबाडी के इर्द गिर्द रह गया है। आज महिलाओं की सबसे वृहद् समस्या है उनकी असुरक्षा, वह खेत में, मकान में, कारखाने में, सड़क पर, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। उनकी सुरक्षा की ओर ध्यान दिया जाता। महिलाओं के

विरुद्ध जो दुर्लभतम् अपराध होती है, उसमें कड़ी सजा की व्यवस्था की आवश्यकता थी। केन्द्र सरकार ने एक आर्डिनेंस जारी किया है, उसका भविष्य क्या है, नहीं पता। लेकिन हमारी राज्य सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए था। महिलाओं के लिये माननीय कल्याण सिंह जी के समय में सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इस आरक्षण के अनुरूप महिलाओं को नौकरी मिल रही है कि नहीं कभी इसका लेखा जोखा आज तक नहीं पता चला। कोई एक सरकार आती है तो वह कोई एक वर्ग के बैकलॉग को पूरा करती है। दूसरी सरकार आती है तो वह दूसरे किसी के बैकलॉग को देखती है। महिलाओं की नौकरियों में कितना बैकलॉग आया, अच्छा होता कि इसका एक हिसाब लिया जाता और उसको पूरा किया जाता। महिलाओं के प्रति सही दृष्टिकोण तब होगा जब सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिये जो आरक्षण है उसका पूरा अवसर उन्हें दिया जाय। इस बजट में होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाने में अनियमितता को समाप्त करने की बात की गई है लेकिन होमगार्ड्स की नियुक्ति में ही व्यवस्था का अभाव है उसमें भ्रष्टाचार का पुट है। जितने होमगार्ड्स की सीट है, अगर उतनी ही नियुक्ति की जाती और हर होमगार्ड को 12 महीने नौकरी दी जाती और उनको रोटेशनवाइज नौकरी में अवसर देने की व्यवस्था न होती तो यह भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाता, यह अनियमितता अपने आप खत्म हो जाती और उनके अन्दर जो असन्तोष है वह समाप्त हो जाता। अच्छा होता कि नये होमगार्ड्स की नियुक्ति न की जाती। हर होमगार्ड को 12 महीने नौकरी में डिप्यूट किया जाय। बजट में कहा गया है कि कृषि के उपज में ग्रोथ रेट साढ़े चार परसेन्ट किया जायेगा। आज जो ग्रोथ रेट है वह तो 2 परसेन्ट भी नहीं है, साढ़े चार परसेन्ट के लक्ष्य को कैसे पूरा किया जायेगा। कहा गया है कि खाद उवर्रक, बीज सिंचाई के पानी सबका भण्डार बनाया जायेगा। यह तो हर सरकार कहती है कि मैंने वृहद् भंडार बनाया। भंडार बन जाने से वह किसानों के पास नहीं पहुंच जाएगा। भंडार से जब निकासी होती है तो वह नेपाल के बार्डर पर बंगला देश की सीमा पर पहुंच जाती है। किसानों के हाथ में यह सामान कैसे जाए, यह सोचने की बात है तब तो हमारे किसानों का उत्पादन बढ़ेगा। आज जो हमारा उत्पादकता का रेट है वह भी कम है और उत्पादन का क्षेत्र भी कम है लगातार शहरी सीमा बढ़ती जा रही है और खेत हमारे घटते जा रहे हैं खेतों की सुरक्षा कैसे हो, खेती में हमें घाटा न हो। खेती जब तक उद्योग के रूप में न आ जाए किसानों को वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। खेतों का क्षेत्र घटता जा रहा है, किसान अपने खेत शहर वालों को बेच कर भाग रहा है इसको रोकने की जरूरत है किसान अपने खेत को एक लाभजनक उद्योग के रूप में देखे यह तभी हो सकता है जब उसके ऊपर टैक्स घटे। उसके ऊपर जो ब्याज की रेट सरकार ने लगाई है चार से तीन परसेन्ट करके, अपनी पीठ सरकार ठोक रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहां किसानों को दिया जाने वाला ब्याज रेट जीरो परसेन्ट पर है क्या हमारी सरकार इस पर ध्यान देगी और हमारे किसानों का भी ब्याज रेट शून्य कर देगी। ताकि किसान जो ऋण लेते हैं उसको ही केवल चुकता करने की जिम्मेदारी किसान के ऊपर रहे और उनकी आत्महत्या पर रोक लगे।इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि बजट में यह चिन्ता प्रकट की गई है कि हमारा भू-जल स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है उसका संरक्षण किया जाएगा। राज्य में ऐसी कई पेयजल कम्पनियां हैं जो इतना ज्यादा जल का दोहन कर रही हैं कि उस कम्पनी की जो फैक्ट्रियां लगी हैं उसके चारों ओर की जमीन अनउर्वरक होती जा रही है। सरकार ने उसको ड्राई क्षेत्र घोषित कर दिया है और वहां ट्यूबवेल और हैण्डपम्प

लगाने पर भी रोक लगा रही है। एक तरफ तो पेयजल कम्पनियां जल का दोहन किये जाएं और दूसरी तरफ लोगों को अपने पेयजल के लिए अपना हैण्डपम्प भी न मिले, ट्यूबवेल भी न मिले कितना बड़ा उनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसी पेयजल कम्पनियों पर रोक लगाई जाए और उनको उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर किया जाए। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे हिन्दुस्तान में एक बहुत बड़ी विडम्बना है। हमारे यहां शव जलाने की प्रथा है। बड़ी संख्या में कई जातियां शव जलाती हैं लेकिन शव जलाने की कोई निर्दिष्ट जगह नहीं है।जो भी घाट निश्चित हैं उसमें कहीं भी शव जलाए जाते हैं। होता क्या है कि जैसे-जैसे गंगा जी या नदी का स्तर ऊपर उठने लगता है वैसे-वैसे शव दाह भी ऊपर की ओर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। अन्त में घनी बस्तियों के अन्दर जैसे बनारस में, हरिश्चन्द्र घाट प्रमुख घाट है उस घाट में शव दाह निजी मकानों के बीच में किया जाता है गलियों में शव जलाए जाते हैं। वहां के मछुआरे जमीन देने को तैयार हैं इसलिए घाट के सतह के ऊपर शवदाह के लिए भी चबूतरा बना दिया जाए। जहां उनका शव दाह क्रिया हो, ऐसे करने पर वह निश्चित जगह जलाई जाएगी अन्यथा वह मकानों के बीच में गलियों के बीच में जलाई जाती है इससे आसपास के इलाकों में इतनी दुर्गन्ध जाती है कि घरों में रहना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एक निश्चित जगह बना दी जाए तो अच्छा रहता। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस पर ध्यान दे।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप करें।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

इसी प्रकार से महिलाओं के लिए अनेक प्रकार की बातें कही गई हैं और उनके लिए व्यवसायिक दृष्टि से सुविधा देने की बात कही गई है मेरा नम्र निवेदन है कि इस काम में भी व्यवस्था की जरूरत है महिलायें सामान बना लेती हैं। हस्त कला की बहुत सी शिक्षण संस्थायें हैं जो जगह-जगह संस्था खोलकर महिलाओं को हस्तकला की शिक्षा देती है। लेकिन जब वह माल बना लेती हैं उसको बेचने की व्यवस्था नहीं होती है अगर अधिकारियों का एक दल जापान चला जाता और वहां की हस्तकला की वस्तुओं को बिक्री करने की दृष्टि से व्यवस्था देख लेता तो भारत की जनता का और महिलाओं का बड़ा उपकार होता। वहां की सरकार अपने आदमी भेजकर सारे देशों से पता लगाती है कि इस समय कौन सी चीजें फैशन में हैं। साड़ियों का किस प्रकार की बाजार में मांग है और गांव-गांव में स्थित अपने कारीगरों को निर्देश देती हैं कि इस प्रकार की चीजें बनायें और उत्पादिक माल को सरकार खुद उसको खरीद लेती है और फिर उसको दूसरे देशों में निर्यात करती है इस प्रकार से महिलाओं के द्वारा जो सामान बनाया जाए, और सामान बनाने के बाद उसकी बिक्री की व्यवस्था की जाए तो हम सोचते हैं कि यह महिलाओं के लिये वास्तविक उपकार होगा और महिलायें अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी। सामाजिक कुरीतियों की दबाव में जो महिलाओं की हत्यायें और उन पर अत्याचार हो रहे हैं तो महिलाएं एक बार सोने का अण्डा बन जाती तो उनकी हत्या पर रोक लग जायेगी। मेरा सुझाव है कि महिलाओं के द्वारा बनायी गई हस्तकला की वस्तुओं को बेचने की भी उचित व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रही हूं, इस बजट में बनारस की बड़ी उपेक्षा की गयी है। जो दो पुल बन रहे हैं जो अधूरे पड़े पुल हैं, रिंग रोड की व्यवस्था या किसी दूसरे प्रकार की रोड की व्यवस्था करने का बजट में कोई उल्लेख नहीं है। बनारस सारा शहर जाम से

चिल्लाता रहता है, 7-7 घण्टे, 8-8 घण्टे स्कूली बच्चे बसों में फंसे रहते हैं, इस जाम से बचाने की कोई व्यवस्था बजट में नहीं की गयी है। अध्यक्ष जी, मैंने कुछ मोटी-मोटी बातें कही हैं, मेरा विश्वास है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और उचित कदम उठायेगी, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

सभी सदस्यों से निवेदन है कि जो भी सदस्य बोलना चाहते हैं, आप बैठें, चाहे जितना समय हो जाये, 8 बज सकता है, 9 बज सकता है क्योंकि कल ही इस पर चर्चा है। मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे तो कल बहुत समय नहीं मिलेगा। जो भी सदस्य बोलना चाहते हैं, रहें, जो भी जितनी भी चर्चा करना चाहें, करें, चाहे जितनी भी रात हो जाए, हम बैठेंगे। लेकिन कोरम ही नहीं रहेगा तो क्या होगा ?

*श्री अनूप कुमार गुप्ता-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा बजट उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तुत किया है। मान्यवर, सड़क से ले करके, सिंचाई, ऊर्जा और यहां तक कि बच्चों की पढ़ाई के लिए जो प्राविधान किया गया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे समाज को ध्यान में रखते हुए नई-नई योजनाएं अपने बजट में प्रस्तुत की हैं। इसी के साथ-साथ हमारे जनपद लखीमपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। किसानों के लिए हमारी सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं, चाहे मुफ्त में पानी की सुविधा हो, नहरों का पानी हो, चाहे सरकारी ट्यूबवेल का पानी हो और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बार जो खाद का प्रबन्ध किया है, मान्यवर, जो पिछली सरकार थी, उस समय लोगों को खाद तो नहीं मिलती थी, लेकिन उनको लाठियां जरूर खाने को मिलती थीं। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए जो कार्य किया है, आज गांव में किसान खुश होकर कहता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कम से कम हमें खाद तो मिल रही है, हमारी उपज का समर्थन मूल्य मिल रहा है, चाहे धान का हो, चाहे गेहूं का हो, उसका मूल्य मिल रहा है। मान्यवर, पिछली बार की जो सरकार थी, उनके लोगों द्वारा बार-बार यह कहा जाता है कि हम लोग किसान विरोधी हैं, मान्यवर, आपने देखा है, वह बहुत बड़े किसान के हितैषी थे, पॉच वर्षों में जो बजट उन्होंने पेश किया, पूरा का पूरा बजट केवल पत्थरों के ऊपर प्रस्तुत किया है। ये लोग कानून-व्यवस्था की बात करते हैं, कानून-व्यवस्था के नाम पर इन्होंने केवल यह किया है, ककड़ी के चोर, कटारियों से मारे हैं, मान्यवर, जो लोग तास खेलते थे, उनको पकड़ करके गैंगेस्टर एक्ट लगा देते थे। यहां तक कि राजा भैय्या जैसे हमारे नेता पर लूट का मुकदमा दर्ज करके उन पर गैंगेस्टर एक्ट लगाने का काम किया और स्वयं अपनी पीठ थपथपाते थे कि हम लोगों ने कानून का राज स्थापित कर दिया है। मान्यवर, हमारी सरकार में पूरी तरीके से कानून का राज है। उनके शासन में लखीमपुर के अन्दर क्या हुआ था, वहां पर थाने के अन्दर एक बालिका के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गयी थी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(इस समय 4 बजकर 59 मिनट पर अधिष्ठाता प्रो0 शिवाकान्त ओझा पीठासीन हुए)

इसी तरह से सीतापुर के एक थाने में एक युवक को ले जाकर आत्महत्या दर्शा दिया गया था। यहां की पूरी टीम गयी थी, हमारे नेता लोग भी गये थे। इस प्रकार से यह कानून का राज अलापते थे। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयास से आज हमारे प्रदेश में उद्योगों के लिए बहुत अच्छा माहौल तैयार हो रहा है। बिजली के क्षेत्र में हमारे मुख्य मंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं तो बधायी देना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में 132 के0वी0ए0 के लिए मैंने इनसे अनुरोध किया था, उसको पूरा करके हमारे क्षेत्र पर इन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है। मान्यवर, बहुत सी चीजें हमारे क्षेत्र के लिए रह गयी हैं उसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से मिलकर बात कर लूंगा। मान्यवर, आज हमारे मुख्य मंत्री जी जितना समय रोज यहां रहकर देते हैं पूरे पांच साल बसपा की सरकार में दुर्गा देवी के तो दर्शन किये जा सकते थे लेकिन उस देवी के दर्शन पाने मुश्किल थे। बता दीजिए वह कितनी बार यहां पर आयी होंगी। मान्यवर, आज हमारे मुख्य मंत्री जी जब यहां पर बैठते हैं तो सत्तापक्ष के विधायक भी जाकर उनसे अनुरोध कर लेते हैं, अपने पत्र दे देते हैं। बड़ी खुशी होती है कि विपक्ष के भी माननीय सदस्य जब आते हैं तो उनका भी मान-सम्मान माननीय मुख्य मंत्री जी करते हैं, सबसे मिलने का काम और सबका काम करने का काम करते हैं। मान्यवर, आज सदन चल रहा है। पिछली बार जब हम नये सदस्य होकर आये थे तो हम लोगों को बोलने का मौका बहुत ही कम मिल पाया था क्योंकि सदन ही नहीं चलता था। मान्यवर, जो बजट सत्र हम लोग विभागवार चर्चा करते हैं उस समय में पूरा बजट सत्र मात्र 5 दिन के लिए आहूत किया जाता था और 15-15 मिनट के अंदर पूरा बजट सत्र समाप्त हो जाता था। पिछली बार के बहुत साथी इस बार नहीं आ पाये उनमें से ज्यादातर उधर के ही साथी थे जो नहीं आ पाये, जो इधर बैठा करते थे। अब कम से कम सत्र लंबा चलता है तो जो मा0 सदस्य अपने क्षेत्र की समस्या लाते हैं उन सबको अपनी बात कहने का मौका सदन में मिलता है। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं कुछ सुझाव मा0 नगर विकास मंत्री जी को लिखकर भी दूंगा और कहकर भी दूंगा। कुछ व्यापारियों की समस्याएं जो हमारे पास आती हैं। मान्यवर, नगर के अंदर मकान या दुकान की जो रजिस्ट्री होती है तो उस रजिस्ट्री में दो प्रतिशत विकास शुल्क लिया जाता है। उसके बाद जब दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो उसमें नगर पालिका दो प्रतिशत अलग से लेती है। इससे बहुत से लोगों को तकलीफें हो रही हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रदीप चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं किसानों से संबंधित जिसका जिक्र सरकार की तरफ से बार-बार आया कि एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है। इसके बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि वह सुझाव सरकार इस बजट में जरूर शामिल करे। किसानों को 5 लाख रुपये जो बीमा दिया जाता है वह उस किसान को दिया जाता है जिस किसान के नाम जमीन हो। लेकिन उस किसान को नहीं दिया जाता है जो किसान का बेटा है और उसके साथ बड़ी दुर्घटना घट जाती है और दुर्घटना घटने के बाद उसको मात्र लीपा-पोती या यह कहकर उसको टरका दिया जाता है कि तुम्हारे नाम जमीन नहीं है, इसलिए तुम्हे इसका कोइ लाभ नहीं दिया जायेगा।

मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि किसान के बेटों के लिए भी, जिनके साथ बड़ी दुर्घटना हो जाती है, उसे भी बीमा योजना का लाभ सरकार को देना चाहिए। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि शादी अनुदान का जो पैसा जिलों में दिया जाता है, वह बहुत कम है। ऐसी मंहगाई के दौर में 10 हजार रुपये से काम चलने वाला नहीं है, इसको बढ़ा कर के कम से कम 20 हजार रुपये कर दिया जाय। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ब्लाक डाक्र जोन के रूप में घोषित किये जाते हैं, जबकि कहीं-कहीं देखने में आता है कि उस ब्लाक में एक साइड में वाटर लेविल ऊपर है और एक साइड में नीचे है, लेकिन पूरा ब्लाक डाक्र जोन घोषित होता है इसलिए सारा का सारा ब्लाक उससे प्रभावित होता है, जिसकी वजह से दूसरे लोग जिनके यहां वाटर लेविल ऊपर है और वह यह चाहते हैं कि हमें बिजली का कनेक्शन मिल जाय, हमें सुविधायें मिल जायं, लेकिन डाक्र जोन घोषित होने की वजह से उनको पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है, इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि इसमें पूरे ब्लाक को डाक्रजोन घोषित करने के बजाय न्याय पंचायत/ग्राम पंचायत के हिसाब से उनको घोषित किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा और इसके बाद में मैं यह कहना चाहता हूं कि जनपद सहारनपुर के अन्दर बहुत बड़ी समस्या बाई-पास की है। सरकार को इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है कि जनपद सहारनपुर के अन्दर जितना ट्रैफिक बढ़ रहा है, उससे समय-समय पर जाम लगा रहता है जिससे वहां की जनता को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और पुलिस को जाम खुलवाने के लिए बड़े जबरदस्त तरीके से मसक्कत करनी पड़ती है। अतः सहारनपुर में बाई-पास की नितान्त आवश्यकता है वहां पर बाई-पास बनाकर के इस समस्या से निजात दिलाई जाय। दूसरी बात गंगोह के अन्दर भी बहुत बड़ी समस्या जाम की बनी रहती है, इसलिए गंगोह-सहारनपुर मार्ग को, गंगोह-लखनौती मार्ग से जोड़ते हुए, गंगोह-लखनौती मार्ग से गंगोह-दूधला को और गंगोह-दूधला मार्ग से गंगोह-तीतरो मार्ग को और गंगोह-तीतरो मार्ग से गंगोह-ननौता मार्ग को जोड़ दिया जाय, जिससे बाई-पास की समस्या से निजात मिल जायेगी और हमारे व्यापारियों को, आने-जाने वाले लोगों को, हमारे किसानों को, क्योंकि किसानों को अपना आनाज, गन्ना इत्यादि लाने-ले जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो कस्बे के अन्दर से वह गन्ना नहीं ले जा सकते, इसलिए बाहर बाई-पास से वह अपना सामान लाने-ले जाने का काम कर सकें, यह सुविधा सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए और इस पर बहुत गम्भीरता से विचार कर लिया जाय और इस समस्या से निजात दिलाने का काम कर लिया जाय। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, धन्यवाद।

श्री सन्त प्रसाद-

मान्यवर, आपने वर्ष 2013-2014 के बजट पर संशोधन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि यह प्रदेश गांवों का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, नौजवानों का प्रदेश है, किसान ही इस देश की रीढ़ है। किसानों की ऋण माफी का बजट में प्राविधान किया गया । मा0 अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि केवल भूमि विकास बैंक के किसानों का, जिसमें इस वक्त बहुत ही कम किसान ऋण लेते हैं, हमारा आपसे अनुरोध है, सरकार को हमारा यह सुझाव है कि जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं किसानों द्वारा जो के0सी0सी0 या अन्य लोन लिये गये हैं उन सभी

किसानों को ऋण माफी की योजना से काफी नुकसान हुआ है। उनका ऋण माफ नही हुआ बल्कि दो साल में इतना ब्याज चढ़ गया कि वह और ऋण से ग्रसित हो गये। साथ ही साथ फसलों की खरीद की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं रही। इसके पहले जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय राजनाथ सिंह जी ने यह व्यवस्था बनायी थी कि सभी क्रय केन्द्रों पर चाहे वह रवी की फसल हो, चाहे वह खरीफ की फसल हो, फसलों की खरीद सुनिश्चित होती थी। हमारा इस सरकार से अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय कि जिससे आने वाले समय में किसानों का हित हो। साथ ही साथ सिंचाई की व्यवस्था पर हमारा विशेष अनुरोध है चूंकि हम गोरखपुर जनपद के खजरी विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं, खजरी विधान सभा तीन नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, उत्तर में आमी, मध्य में कुंवानों, दक्षिण साइड में घाघरा, यह बाढ़ प्रभावित इलाका है और उत्तर में जो आमी नदी का जल है वह अत्यन्त ही दूषित है। कारखानों ने वहां का पानी इतना दूषित कर दिया है, जिससे कि उस क्षेत्र का ऊपर से तो पूरा वायुमण्डल प्रभावित है ही। अन्दर जो भूगर्भ का जल है वह दूषित हो रहा है जिससे वहां के निवासियों के पीने के जल का संकट है। हमारा इस सरकार से अनुरोध है, यह सुझाव है कि उस आमी नदी के जल को जो दूषित करने वाली कम्पनियां हैं उन्होंने ऐसे ऐसे प्लाण्ट लगाये हैं जो देखने के लिये हैं। प्लाण्ट तो लगाये गये हैं लेकिन मान्यवर, वे चलाये नहीं जा रहे हैं। हमारा सरकार को यह सुझाव है कि सरकार द्वारा उन्हें और विकसित करके चलाने का प्रयास किया जाये जिससे वहां के किसानों और मजदूरों को उसका लाभ मिल सके। मा0 अधिष्ठाता महोदय, अभी मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना चाहिये। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि आज प्राथमिक विद्यालयों की इतनी दयनीय स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों में कि हमारे खजरी विधान सभा क्षेत्र में जुलाई से सितम्बर तक 200 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे थे, जहां ताला लटका रहा। बार-बार जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी के कहने के बाद भी 15 अक्टूबर के बाद वह विद्यालय खुले। कौन सा ऐसा अभिभावक होगा जो अपने बच्चों के लिये इंतजार करेगा और अक्टूबर में अपने बच्चों का नॉमिनेशन उन विद्यालयों में करायेगा। मान्यवर, यह दुर्दशा है और सरकार बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े पोस्टर छपवाती है सर्व शिक्षा अभियान के। मान्यवर, इस पर मेरा अनुरोध है कि जो शहरी क्षेत्रों के विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें एक विद्यालय में बारह बारह अध्यापक पड़े रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय जो अध्यापक विहीन हैं, अध्यापकों के न रहने के कारण उनमें ताले लटके रहते हैं। ऐसी व्यवस्था हो कि जो शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के अध्यापकों को जो सी0सी0ए0 एलाउंस मिलता है तो ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों को भी ऐसा प्रोत्साहन दिया जाये जिससे वे ग्रामीण क्षेत्र में रह करके पढ़ायें और अध्यापकों की व्यवस्था जुलाई में ही कर दी जाये। साथ ही साथ शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो। अभी डा0 राधामोहन दास अग्रवाल कह रहे थे कि कक्षा 5 में पढ़ने वाले 45 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 2, 3 की किताब भी नहीं पढ़ पाते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस सदन के नेता मा0 राजनाथ सिंह भी रहे हैं और शिक्षा में एक गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास किया था। मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिये जो देश और प्रदेश की रीढ़ हैं उनकी पढ़ाई में गुणात्मक सुधार लाने की व्यवस्था हो और यह तभी सम्भव है जब सरकार कोई ठोस कदम उठायेगी। मा0 अधिष्ठाता महोदय, चूंकि सड़कों के विषय में बहुत सारी बातें आयी हैं जी0जी0सी0 मार्ग जो गोरखपुर की प्रमुख सड़क है, उसे पिछले साल ही उधेड़ कर छोड़

दिया गया है। आज अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो लगता ही नहीं कि वह सड़क है। आज सड़कों की हालत यह है, लग ही नहीं रहा है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। मान्यवर, चूंकि मा0 मंत्री जी हैं नहीं और मा0 ससंदीय कार्य मंत्री जी हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि गोरखपुर जनपद के खजरी विधान सभा में जो सड़कों की हालत है, उसे सुधारने की विशेष योजना बनायी जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री सन्त प्रसाद-

साथ ही साथ मान्यवर, कुवानो नदी पर वनकटा पंचहेता घाट पर पुल की आवश्यकता है।

*श्री छोटे लाल वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया बजट भाषण पर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, समाजवादी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि 16 जातियों को हम अनुसूचित जातियों में सरकार बनने के बाद 36 घण्टे के अन्दर करेंगे। मैं नहीं कह रहा, कल हमारे राष्ट्रीय लोकदल के नेता ने कहा कि अगर आप इन 16 जातियों को आरक्षण दे दें और किसानों के सिंचाई के बिल माफ कर दें तो आपकी बल्ले हो जायेगी। मैं यह बताना चाहता हूं कि ये 16 जातियां इतनी पिछड़ी हुयी हैं और इनके बलबूते पर यह सरकार बनी लेकिन दो चार विधान सभाओं को छोड़ करके बजट भाषण में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। मान्यवर, मैं ये सुझाव दे रहा हूं कि उन 16 जातियों के वोट से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। दो चार विधान सभाओं को छोड़ करके मा0 पूर्व मुख्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 मुलायम सिंह यादव जी के घोषणा-पत्र के आधार पर पूरे प्रदेश की इन 16 जातियों ने समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार की मंशा साफ है, तो जैसे बहन कुमार मायावती जी ने लोकसभा में आरक्षण के मुद्दे पर अनुसूचित जाति-जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण के लिए, राज्यसभा में बिल पास करवा लिया और लोकसभा में करवाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार की मंशा साफ है, और इन 16 जातियों को यह आरक्षण देना चाहते हैं, तो जैसे अभी 16 फरवरी को, इन 16 जातियों के नेताओं को बुलाकर के यहां जो भी प्रस्ताव पास हुआ हो, वह मुझे नहीं मालूम, किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो प्रस्ताव लाकर आप उसे पास करायें, और भारत सरकार का भी बजट चल रहा है, जैसे बहन कुमारी मायावती जी अपने लोगों के लिए जैसे प्रमोशन में आरक्षण का प्रस्ताव पास करा लिया राज्यसभा में, मैं मा0 समाजवादी पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर मंशा साफ है तो उसी प्रकार से करें। यह सरकार केन्द्र की दो पैरों की ऊपर चल रही है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, अगर ये आज नहीं करा पाए तो फिर ये कभी नहीं करा पायेंगे इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार से मा0 राष्ट्रीय नेता हमारे जो समाजवादी पार्टी के हैं,वे इस बिल को पास कराएं जिससे कि लाखों इन 16 जातियों के दबे-कुचलें लोगों को, जिनको कोई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राहत नहीं मिल पाती है, न कहीं यह जिक्र किया गया है जब पूर्व सरकार मुलायम सिंह जी की थी, उस सरकार में इन 16 जातियों को अनुसूचित जातियों में घोषित कर दिया गया था और सारी एस0सी0, एस0टी0 की सुविधाएं उनको दी गयी थी, न ये भी कहीं व्यवस्था की गयी, न कहीं प्रदेश शासन में और न कहीं घोषणा पत्र में किया था, मतलब कोई अलग से इस बात का प्राविधान किया गया है, बहुत सी ऐसी जातियों को उत्पीड़न होता है, उसका भी कोई प्राविधान नहीं किया गया। और न खाद्यान्न में न इनका कोई प्राविधान किया गया और जो खनन और बालू के पट्टे होते थे, वह भी छीन लिये गए, उसमें भी कोई प्राविधान नहीं किया गया। न अलग से कोई आवास देने का प्राविधान किया है, इस बजट में आवास पिछड़ा समुदाय का है, उसमें यह कोई जिक्र नहीं किया गया है कि कितने आवास दिए जाएंगे, केवल यह लिखा हुआ है कि 50 हजार रुपये के हिसाब से आवास दिए जाएंगे यह कहीं जिक्र नहीं है कि उनको इतने आवास दिए जाएंगे। अधिकांश जंगलों के किनारे में, नदियों के किनारे में इन समाजों के लोग रहते हैं, इनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मैं, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी, समाज कल्याण मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप लोग मिलकर के लाए अगर आपकी मंशा साफ है तो उन जातियों को आरक्षण में व्यवस्था दिलाने का आप प्राविधान करें। मैं यह बताना चाहता हूं आपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में, 32 साल पहले लगभग मेरे फतेहाबाद से बाईपास की जमीन इक्वायर की गयी थी। और यह मामला मेरा नियम-51 में लगा हुआ है। वहां के केवल 8 किसानों को मुआवजा दिया गया था। वहां के 59 किसान आज भी 32 साल से मुआवजे से वंचित चले आ रहे हैं, यह मेरा नहीं है यह सरकार के प्रश्न का उत्तर है कि 59 किसानों को मुआवजा नहीं मिला। मान्यवर, 533 रुपये वर्ग मी0 के हिसाब से मुआवजे का प्राविधान किया है, जबकि वहां 1500 से लेकर के 2000 वर्ग फुट के हिसाब से मान्यवर, 20 हजार से लेकर के 10 हजार वर्ग मीटर के हिसाब से किसानों की जमीन बिक रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो 34 साल से इन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है और किसानों की हमारी यह सरकार जो बैठी है, दूसरी तरफ, हम लोगों पर तो आरोप लगते हैं कि यह पत्थर वालों की सरकार है। हम लोग मान रहे हैं कि हमारी बहन जी ने पत्थर लगाए। परन्तु यह तो किसानों की सरकार है, कई बार रह चुकी है, इन किसानों को यह मुआवजा अभी तक नहीं दिया जा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बजट में शामिल करके इन सब किसानों को, जिनकी जमीन बहुत दिन पहले ली गयी, उनको मुआवजा दिया जाए ताकि वह किसान अपनी रोजी-रोजगार का कार्य कर सके, उनकी सारी जमीन चली गयी है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि माननीय अभी हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी के घोषणा पत्र में यह रखा गया है कि हमारे यहां आगरा से लेकर लखनऊ के लिए एक हाईवे बनाया जाए। इस हाई वे में प्राविधान किया जाए किसानों के लिए जमीन का, तो उसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि वह पूरा हाई वे अधिकांश यमुना नदी के किनारे आ रहा है, उसमें भी सारी जमीन अधिकांश आगरा से लेकर और हमारे जहां तक यमुना नदी में जाती है, वह पूरी हमारे अधिकांश समुदाय के लोगों की जमीन जा रही है।

मान्यवर वह जमीन भी ऐसी है जिसमें लोग नदियों के किनारे रहते हैं उसमें लोगों को कम मुआवजा दिया जा रहा है। वह वैसे ही बेरोजगार हैं और कम पैसा मिलने से और साधनविहीन हो

जायेंगें। मेरा कहना है कि मुआवजा उस रेट से न दिया जाय, उस का आंकलन करा लिया जाय, और उनको मुआवजा आज की दर पर मिलना चाहिए। मान्यवर, वह मुआवजा 20,000 रुपये बीघे जमीन के हिसाब से हो सकता है। मान्यवर, वह बेघर हो जायेंगें, और बेरोजगार हो जायेंगें और उनकी जमीन भी नहीं रह जायेगी। मान्यवर, जो हाइवे बनने की बात है वह अच्छी बात है लेकिन किसानों को बेरोजगार न किया जाय। या तो उनको जो नजूल भूमि है, बंजर भूमि है, जो जंगल की भूमि है वह भूमि है उसे अतिरिक्त रूप में दी जाय। जो पैसा मिलता है वह तो खर्च हो जाता है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में भू-गर्भ का जल-स्तर काफी गहरा हो गया है। राजस्थान की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। हमारे यहां आगरा के लिए जो तीन सौ करोड़ रुपये दिए गये हैं वह नगर निगम को दिये गये हैं और शहर के लिए पेय जल के लिए है। देहात के लिए कुछ नहीं है। हमारे यहां नौ विधान सभा क्षेत्र हैं जिसमें बाह क्षेत्र भी है माननीय मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं। उसके अलावा फतेहाबाद, खेरागढ़ क्षेत्र है। हमारे यहां खारा पानी है जिसको पीकर किसान बीमार भी हो रहे हैं उनकी गर्दन टेढ़ी हो रही है। मान्यवर हमारे यहां टी0टी0एस0पी0 योजना लागू हुई थी उसमें टंकियों का निर्माण होना था, ताकि लोगों को पेय जल मिल सके लेकिन वह टंकिया उस क्षेत्र में बन रही हैं जहां प्रभावशाली और दबंग लोग हैं या जिनका कब्जा है। जो गरीब अनुसूचित जाति के लोग हैं वह वंचित हैं तो इसमें मानक तय कराये जायें और उसके अनुरूप कार्य हो। मान्यवर, जो बजट है उसमें हमारे क्षेत्र फतेहाबाद में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार योजना बनाये ताकि किसानों को और गरीबों को लाभ हो सके। मान्यवर, हमारे यहां ओखला से जो आगरा नहर निकलती है, बरसात के समय में तमाम पानी यमुना नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। एक तरफ तो हमारे यहां लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है दूसरे तरफ यह बरसात का पानी व्यर्थ जा रहा है। इसमें कोई पैसा भी नहीं खर्च होगा। आप वहां पर नहरों में उस पानी को रोकने के लिए जलाशय और झीलों को बनवायें, तो उससे यह फायदा होगा कि जो हमारे यहां भू-गर्भ जलस्तर गिरता जा रहा है उसको रोका जा सकेगा। उससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल जायेगा। पशुओं को पानी मिल जायेगा। मान्यवर हमारे यहां यमुना, उत्खन और खारी नदी है। यह तीनों हमारे क्षेत्र में हैं। उत्खन और खारी तो बिल्कुल सूखी हैं। यमुना नदी में दिल्ली के नालों से इतना गन्दा पानी आ जाता है कि उसे पीना तो दूर लोग हाथ धोना भी पसंद नहीं करते इसलिए इस पर ध्यान दिया जाय। मान्यवर हमारे यहां आगरा में एक बैराज बनना था उसमें झगड़ा चल रहा है उस बैराज को हमारे क्षेत्र फतेहाबाद में बना दिया जाय तो उससे लोगों के पेयजल मिलने में सुविधा होगी। जो दिल्ली से गंदा पानी आ रहा है यमुना में उसको प्रदूषण मुक्त बनाने का काम किया जाय। मान्यवर जो मैने बाते कहीं हैं उसको कृपया इस बजट में जुड़वाने का काम करें। धन्यवाद।

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर अभी बहुजन समाज पार्टी के एक सदस्य बोल रहे थे और उन्होंने 16 जातियों का जिक्र किया कि जिन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा और लाभ देने की बात पर सरकार कार्यवाही समाजवादी पार्टी ने चुनाव के पहले अपने घोषणा-पत्र में साफ-साफ लिखा था और मान्यवर, लिखा ही नहीं था बल्कि माननीय नेता जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी आगे सदन में नेता सदन थे, माननीय मुख्य मंत्री जी थे तो उस समय लागू भी किया गया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना

पड़ता है कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी तो इन्होंने रोकने का हर तरह से प्रयास किया और यहॉ तक श्रीमन, कितने अफसोस की बात है कि उनके निजी सचिव की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट भी दाखिल की गयी और जो सुविधाएं माननीय नेता जी ने दिया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था, अपनी सरकार ने दिया था उसको रोकने का काम किया। फिर यह जो चुनाव हुआ अभी एक साल पहले इस चुनाव घोषणा-पत्र में समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में तमाम चीजे लिखीं। किसी पार्टी के लिए, वह चुनाव घोषणा-पत्र किस स्तर तक लेती है उस पर हम नहीं जाना चाहते हमने तो दूसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र देखा ही नहीं, जाने क्या था लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र उतना ही पवित्र है जितना गीता और कुरान, उतना पवित्र है इसलिए सरकार में आने के तुरन्त बाद जो भी घोषणाएं हमारे नेताओं ने चुनाव के पहले किया था जिस तरह से माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है जिसने इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है और जिस तेजी के साथ सारे वायदे पूरे किये जा रहे हैं उससे निश्चित रूप से यकीन दिलाया जा सकता है इस प्रदेश की महान जनता को, यू तो वायदा पूरे करने की अवधि 5 साल की होती है क्योकि जनता हमें 5 साल के लिए चुनती है, सरकार बनाती है लेकिन जिस तरह से, जिस अदम्य साहस और निष्ठा के साथ और जिस संकल्प के साथ माननीय अखिलेश जी की सरकार काम कर रही है सभी क्षेत्रों में दो साल के अन्दर-अन्दर सारे चुनावी घोषणा-पत्र में बाते जो हैं वह पूरी होने की पूरी-पूरी सम्भावना है। मान्यवर, जहां तक दूसरी बात कही है 16 जातियां वह सुधार कर लें 17 जातियां हैं उन 17 जातियों की सूची हमसे ले लेना और हम 17 जातियों के लिए मान्यवर, हमारी ही अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जिसमें माननीय बेरिया साहब, माननीय ब्रह्मा शंकर तिवारी जी, माननीय पारस नाथ जी और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी सदस्य थे और मान्यवर, हमने पूरी तरह से सम्यक अध्ययन किया और पूरी तरह से संविधान में कानून में सारी व्यवस्थाएं देखा फिर जाकर के हम अपना प्रत्यावेदन भेजे उसमें कोई कानूनी लेकुना न रह जाय, बड़ी मेहनत के साथ और यही नहीं श्रीमन, हमने उन जाति के जो नेतागण हैं उनको भी आमंत्रित किया उनके सुझाव को लिया और सुझाव की कद्र किया और पिछले दिनों में जो भारत सरकार की तरफ से वापस आ गया था उस प्रस्ताव की कमीं को, सारी चीजों को देखते हुए उस कागज को भी देखा जो इनके नेता जो नेता सदन भी उन्होंने भेजा था एक पत्र सिम्पली एक पत्र वह तो सीधे वैसे चला आयेगा लेकिन हमारी सरकार ने, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने इसी महिने की 15 तारीख को भारत सरकार को भेज दिया है कि कौन सी जाति शिड्यूल कास्ट में आवे और कौन सी जाति न आवे। श्रीमन्, आप विद्धान है संविधान के अनुच्छेद 341 में स्पष्ट लिखा हुआ है अनुच्छेद के सबक्लास वन और टू में यह सब लिखा हुआ है कि सारी पावर्स डेलीगेटेड हैं, पूरी पावर संविधान में भारत सरकार को और पार्लियामेंट को दी गयी है इसलिये यह शंका करना, हमारी सरकार की नीति पर, हमारी सरकार की नीयत पर, यह पूरी तरह से निर्मूल है, इसमें कोई सत्यता नहीं है और सरकार की तरफ से 15 तारीख को इसे भेजा जा चुका है।

श्री छोटेलाल वर्मा-

आपने कहा कि गौर जाति यह तो आलरेडी हैं, आप उनको क्यों जोड़ रहे हैं। जिनको कहीं नहीं मिला, उनको आप और बैकवर्ड में डाल दोगे। जिनको मिलना है लाभ, वह और उसमें चले जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय छोटेलाल जी, अब आप बैठ जायें ।

श्री छोटेलाल वर्मा-

मैने केवल यह कहा कि अगर आपकी मंशा साफ है और आपकी सरकार इनकी हितैषी है तो जैसे मैनें उदाहरण दिया कि बहन कु0 मायावती ने अनुसूचित जाति के प्रमोशन में आरक्षण का अपना बिल राज्यसभा में पास करा लिया और यह केन्द्र सरकार दो लोगों के सहारे चल रही है, एक समाजवादी पार्टी और दूसरी बहुजन समाज पार्टी ।

श्री अधिष्ठाता-

छोटेलाल जी, आप यह बात पहले कह चुके हैं, अब अपनी बात समाप्त करें । मैनें दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं है, हम लोग एक जुबान के लोग हैं, यह जो बहुजन समाज पार्टी के लोग बैठे हैं, यह दो जुबान के लोग हैं। इनकी जुबान पर कोई एतबार नहीं किया जा सकता। इसलिये पूरी नीयत के साथ भारत सरकार को भेजा है और श्रीमन् इसमें कोई कानूनी कमी नहीं है, संवैधानिक कमी नहीं है, मैनें इसमें अपने एल0आर0 से और कार्मिक विभाग से राय ली है और इन बिरादरियों के जो जानकार लोग हैं, उनसे और तमाम विद्वानों से राय लिया है और मैनें श्रीमन् यह शोध भी कराया, अब उसमें किसी प्रकार का कोई लैकूना नहीं है, कोई कमी नहीं है, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि भारत सरकार को मजबूर होकर इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में लाने के लिये हमारी सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है, उसको हर हाल में उनको मानना पड़ेगा ।

(श्री छोटेलाल वर्मा के पुनः खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय छोटेलाल जी, आप अपनी बात बहुत कह चुके, अब आप बैठिये, अब आपका कुछ लिखा नहीं जायेगा। आप अपनी बात तीन बार कह चुके हैं, आप बार-बार वही बात कहते हैं। अब आप बैठिये।

(बीच में श्री जय प्रकाश, माननीय सदस्य द्वारा बिना माइक आन हुये खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

जब आपकी बारी आयेगी, तब अपनी बात कहियेगा। मैनें दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है। आप सदन को अव्यवस्थित न करें, आप कृपया बैठ जाये। आपकी कोई बात लिखी नहीं जायेगी। मैं दूसरे माननीय सदस्य को पहले ही बुला चुका हूं।

कुंवर भारतेन्द्र-

मान्यवर, आपने मुझे बजट के संशोधन पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं देख रहा हूं, इस सदन में बार-बार सत्ता पक्ष के द्वारा अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। अभी-अभी माननीय मंत्री जी आरक्षण के बारे में कह रहे थे और इन्हें पूरा विश्वास है कि इन्होंने हर

जाति को सम्मिलित कर लिया है जो दलित है । मैं शासन को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक ऐसी जाति जो पिछले 50-55 साल से उत्तर प्रदेश में रह रही है, वह बेचारे गरीब हिन्दू जिन्हें पूर्वी पाकिस्तान या बांगलादेश से निकाल दिया गया था, आज भी गंगा नदी के किनारे चाहे वह बिजनौर हो, चाहे वह मेरठ हो, चाहे वह पीलीभीत हो, चाहे वह बनारस हो, बहुत बड़ी संख्या में वहां पर रह रहे हैं। सबसे दुख की बात यह है कि उस जाति का नाम ही नमो शूद्र है। इस जाति का नाम ''नमो शूद्र'' है, मैं बिजनौर और हस्तिनापुर के बंगालियों की बात बताना चाहता हूं, इन बेचारों की कृषि भूमि में आज भी कम से कम कूल्हे-कूल्हे तक पानी भरा हुआ है और उनका नाम इस सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। बार-बार यहां वाले वहां की गलती बता देते हैं और वहां वाले यहां की और यहां अच्छे भले भाषण माफिया हो गये हैं क्योंकि माननीय अधिष्ठाता जी बार-बार नाम लेकर पुकार रहे हैं तो भी यहां पर सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, यह बजट भाषण की चर्चा थी और विकास का बहुत बड़ा अंश स्थानीय इकाइयों के द्वारा खर्च किया जाता है। जिस तरह से स्थानीय इकाइयों के चुनाव हुए हैं, मैं जिला पंचायत चुनाव की चर्चा करना चाहता हूं। अभी-अभी हमारे आगरा के माननीय मंत्री जी चले गये, बिजनौर के जिला पंचायत का चुनाव जिस तरह से हुआ है, उससे आप सभी अवगत हैं। अखबारों में खबरें आईं, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पार्टी के मंत्री, पार्टी के सांसद खुद बन्दूकें लेकर सदस्यों का अपहरण करने गये। उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हुई। मान्यवर, जिन लोगों के हाथ में हम बिजनौर जैसे छोटे जिले का करीब 50 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का बजट ऐसे लोगों के हाथ में दे देंगे ? जिनके लिए वोट कब्जा करके स्वयं शासन लेकर आ रहा है। इसकी एफ0आई0आर0 दर्ज है महोदय मैं आपको एफ0आई0आर0 की कापी दे दूंगा वह मेरे पास रखी है, तो मान्यवर, हम इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। मान्यवर, बहुत बड़ी संख्या का पैसा खर्च होता है यह बहुत ही दुःखद विषय है और सबसे दुःखद विषय तो यह है कि जिस जिला पंचायत अध्यक्ष को बहुजन समाज पार्टी ने बनाया था उसी महिला को पुनः समाजवादी पार्टी ने बनाया। पहले अविश्वास प्रस्ताव आया और फिर पुनः उसको ही स्थापित कर दिया। मान्यवर, मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि यह वही [x x x] चल रही है केवल अपनी पीठ थपथपा लेने से कोई लाभ नहीं है। पूरे प्रदेश की जनता को बहुत आशाएं हैं एक युवा मुख्यमंत्री पर, एक सुशिक्षित मुख्य मंत्री पर और यह जो सदन में चल रहा है उसके लिए स्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई मैं सुनाना चाह रहा हूं-

सचिव बैद्य गुरु तीनि जौं प्रिय बोलहिं भय आस।
राज धर्म तन तीन कर होय बेगिहीं नास।।

जो हाल इनका (बसपा) हुआ कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार इतने सालों बाद उत्तर प्रदेश में आई थी वह यहां पर आ गई वही इस सरकार के साथ भी होगा क्योंकि न इनमें सच बोल पाने की हिम्मत थी और न यह हिम्मत आप जुटा पा रहे हैं। बहुत ही बिगड़े हुए हालात हैं, परिवर्तन हुआ है तो केवल इतना सा कि पहले नीले झण्डे के नीचे जो [x x x] घूम रहे थे आज वही लोग साइकिल के झण्डे के नीचे घूम रहे हैं। मैं कोई अतिश्योक्ति की बात नहीं कह रहा हूं, आपको उदाहरण देकर कह रहा हूं, बिजनौर की जिला पंचायत अध्यक्षा में वही सब लोग हैं। जिस तरह से सत्ता के दुरुपयोग

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

से को-आपरेटिव बैंक पर कब्जा किया गया था पिछली सरकार में, बिल्कुल उसी तरह से इस सरकार ने पुनः कब्जा कर लिया। यह हमारी मुख्य संस्थाएं जिनके माध्यम से विकास कार्य होते हैं, उन पर उसी प्रकार की [x x x] चढ़ती जा रही है। मान्यवर, बहुत आशा थी, बहुत संस्कारित लोग इस सदन में हैं, पीठ पर माननीय अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय जी हैं, माननीय राजस्व मंत्री जी चले गये हैं, संसदीय कार्यमंत्री जी हैं, इनसे समाजवाद की पहचान बनती है। मगर जो जिलों में हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है, समाजवादियों की पहचान केवल [x x x] को संरक्षण देने की बन रही है। अगर पिछली सरकार में खुद विधायक जाकर बिजनौर में पीटते इंस्पेक्टर को थाना कोतवाली मुख्यालय बिजनौर में पीटते थे तो इस बार यही काम आपके जिला अध्यक्ष कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है, जब तक यह सारी बातें शासन के संज्ञान में न आयें तब तक कोई लाभ नहीं हो सकता है। शासन सत्ता में मुग्ध है और खुला दुरुपयोग हो रहा है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि जनता का विश्वास हम लोकतन्त्र में स्थापित करें, चाहे वह जिला पंचायत के चुनाव हों, चाहे वह ब्लॉक के चुनाव हों। चाहे वह बैंक के चुनाव हों और चाहे वह इस सदन का चुनाव हो। जनता से कोई बात छिपी नहीं है, सब जानते हैं कि कैसे खुली खरीद फरोख्त हो रही है। जिला पंचायत के चुनाव में कैसे खुली खरीद फरोख्त हुई है यह पूरी जनता को मालुम है। जनता का विश्वास इस पूरी प्रक्रिया से टूटता जा रहा है और निश्चित रूप से यह बहुत नुकसानदेह होगा। मान्यवर, बार-बार यह बात चर्चा में आयी है, मैं ज्यादा इस सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं कि मा0 मुलायम सिंह जी के टाइम में, मेरे पिता जी इस सदन के सदस्य रहे हैं, मा0 नारायण दत्त तिवारी जी के समय में, बहुगुणा जी के समय में जितने भी पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं उनके समय में, उन्हें सत्ता के लोग कहते थे कि ज्यादा विश्वास उनका विपक्ष में है, प्रतिपक्ष के विधायकों की बात ज्यादा सुनी जाती है। मुझे याद है मैं यहीं इस सदन में था। मा0 मुलायम सिंह जी आते थे और वहां न जाकर सीधा इधर आते थे और हमारे हाथ से हमारी पर्चियां ले लेते थे। आज वहीं समाजवादी पार्टी बैठी है। किसी विधायक को हैण्डपम्प नहीं मिला, शादी अनुदान के लिए सूची हमें भेजी जाती थी वह सूची हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही है, हमसे राय नहीं मांगी जाती है। सड़कों की योजना के लिए हमसे पूछा जाता था, वह नहीं पूछा जा रहा है। यह सब छोटी-छोटी बातें जरूर हैं, मगर लोकतंत्र से इसका विश्वास, जनता का विश्वास उठता जा रहा है। हैण्डपम्प के लिए मेरे पास शासनादेश यहां पर रखा हुआ है, शासनादेश है कि हैण्डपम्प को मा0 प्रभारी मंत्री के द्वारा जिले में आवंटित किया जाएगा।

श्री अधिष्ठाता-

भारतेन्द्र जी, अब समाप्त करिये।

कुँवर भारतेन्द्र-

जिला बिजनौर में प्रभारी मंत्री जी आये और उन्होंने स0पा0 के दो विधायक जो कि मंत्री हैं, दौ सौ हैण्डपम्प एक को दे दिये, दो सौ हैण्डपम्प एक को दे दिये। आठ विधान सभाओं के जिले में 06 विधान सभा हैण्डपम्पों से वंचित रह गयी हैं, इस तरह से पक्षपात हुआ है। छात्रवृत्ति की बात बार-बार उठी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिजनौर जिले में एक भी अनुसूचित, दलित जाति के छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। एक ओर सरकार कह रही है कि जो अल्पसंख्यक बच्चे जो फेल भी हो जायेंगे उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी मगर दूसरी ओर दलित बच्चों को एक साल से,

जब से आपकी सरकार आयी है तबसे छात्रवृत्ति नहीं मिली है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और विकास के मार्ग में राजनीतिकरण का पक्षपता पूर्ण कार्य है। मान्यवर, बहुत बड़ा कटान होता है, पिछले वर्ष बरसात नहीं हुई थी, बहुत ज्यादा कटान जिला बिजनौर में होता है। मैं चाहूंगा कि रावली से बालावाली तक जो गंगा जी का कटान होता है उसमें स्टड निर्माण करके, यह योजना स्वीकृत होकर गई हुई है, मा0 सिंचाई मंत्री जी इसे निश्चित रूप से बनवाने का कष्ट करेंगें। पिछली दफा आप ही की सरकार ने, पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी ने एक रपटा बनवाया था वह छोटा पड़ गया है, कटान बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे आशा है कि रावली-ब्रह्मपुरी के बीच में जो मालन नदी पर मा0 शिव पाल सिंह जी द्वारा रपटा 10 साल पहले बनवाया गया था इससे लगभग 40 हजार की आबादी मुख्यालय से जुड़ती है, उसे पुनः बनायेंगें। चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों का पेमेण्ट नहीं किया जा रहा है। मैं खुद धरने पर बैठा था। 18 फरवरी को प्रशासन ने चीनी मिलों से यह आश्वासन लिया है कि वह हमें पेमेण्ट दिसम्बर के अन्त तक की कर देंगे जबकि आपका नियम है 15 दिन में पेमेण्ट ब्याज सहित देने का। लेकिन अभी पेमेण्ट जनवरी तक की नहीं हो पायी है। यह मैं आपको पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

भारतेन्द्र जी अब समाप्त करिये।

कुंवर भारतेन्द्र-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण है। जिला अस्पतालों की स्थिति खराब है, ट्रामा सेण्टरों, अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। एम्बुलेंस आपने उपलब्ध जरूर करवाई हैं मगर एम्बुलेंस जिला पार नहीं कर सकती। हमारे जिले में जहां पर मेरठ जाने में तीन जिले पड़ते हैं, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और मेरठ। तीन एम्बुलेंस बदलने में एक्सीडेंट केस के मरीज की मृत्यु हो जाती है इसलिए आज भी गरीब आदमी प्राइवेट एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा है। कृपा करके ऐसे जिले जो मेडिकल कालेजों से दूर हैं, उन्हें एम्बुलेंस उपलब्ध करवाईये। महिला चिकित्सक उपलब्ध करवाईये। मान्यवर, महिला चिकित्सकों की जगह बी0ए0एम0एस0 डाक्टरों से सहायता ली जा रही है जो कि प्रशिक्षित (ट्रेण्ड) नहीं हैं जबकि एम0डी0 गॉयनी और महिला शल्य चिकित्सक की पोस्टिंग होनी चाहिए। पांच की जगह केवल एक महिला शल्य चिकित्सक है। ऐसे हाल में आप जान सकते हैं कि कितने बुरे हाल हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अवधेश प्रसाद-

माननीय सदस्य ने अपने जिले बिजनौर के बारे में बताया है कि अनुसूचित जाति के बच्चों को एक पैसा आज तक नहीं गया है । माननीय सदस्य से मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि अभी लिखकर दे दें 48 घण्टे के अन्दर अगर नहीं गई होगी तो जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही भी करेंगे और इस आदरणीय सदन में भी बताएंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि 15 मार्च तक हर हाल में पहुंच जाय। लेकिन हमें लिखकर अभी दे दें।

श्री शाहिद मंजूर-

माननीय सदस्य ने दो जगह का नाम लिया कि बिजनौर में पानी भराव हो रहा है और बंगाली कालोनी के जो लोग हैं उनको असुविधा हो रही है साथ ही साथ इन्होंने हस्तिनापुर का भी नाम

ले दिया क्योंकि हस्तिनापुर मेरठ में है और मैं मेरठ का रहने वाला हूं मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई जगह है नहीं अगर सदस्य को है तो बतलाएं कि कहां पानी भर रहा है हस्तिनापुर में।

कुंवर भारतेन्द्र-

आप दोनों विषय को मिला रहे हैं। मैंने कहा था कि हस्तिनापुर विधान सभा में भी नमोशूद्र नाम की जाति रहती है जिसे अनुसूचित जाति से वंचित कर दिया गया है। पानी भरान बिजनौर में हो रहा है।

श्री शाहिद मंजूर-

मैं डर गया कि कहीं हस्तिनापुर में तो पानी नहीं भर रहा है।

* श्री मौ0 इरफान-

अधिष्ठाता महोदय, आज बजट के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया मैं बहुत अदब से यह कहना चाहूंगा कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया है जो प्रस्ताव दिया है वह यकीनी तौर पर काबिले तारीफ है 10 प्रतिशत पिछले बजट से इजाफा करना यकीनी तौर पर उसमें विकास को पंख लगेंगे। विकास सबके लिए होता है हमारे दोस्त जितने इस सदन के सदस्य हैं वह चाहें इस पक्ष के हों या उस पक्ष के विकास का लाभ सभी को मिलता है। केवल इस आधार पर तनकीद नहीं करना चाहिए कि हमें तो तनकीद करनी ही है विपक्षी सदस्यों को सोच-समझकर तनकीद करना चाहिए। मैं बहुत अदब से यह भी कहना चाहूंगा कि चूंकि मेरी विधान सभा बिलारी जो नई बनी है जो दो जिलों में पड़ती है उसमें जो मुरादाबाद से संभल के लिए फोर लेन का प्रस्ताव किया गया है उसमें चूंकि मुरादाबाद से बिलारी चंदौसी होकर जो रोड जाता है वह आगरा जाता है और वही रोड संभल होकर आगरा जाता है तो जो बीच का मेरा वाला हिस्सा रह गया जो मुरादाबाद, बिलारी चंदौसी आगरा या मुरादाबाद बिलारी चंदौसी फर्रुखाबाद उसको भी फोर लेन किया जाय। यह मेरी बहुत अदब से गुजारिश है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जो बहुत ही काबिल और काबिले ऐहतराम हैं उन्होंने बिजली को लेकर जो बजट में प्रस्ताव दिए हैं यकीनी तौर पर बहुत ही काबिले तारीफ हैं। लेकिन जो सोलर पावर प्लांट का कहा गया है उसमें मैंने अपनी विधान सभा में हाजीपुर एक गांव है उस हाजीपुर गांव में ग्रिड कनेक्टिंग सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रस्ताव दिया है वहां की गांव सभा से प्रस्ताव पास करा दिया है और तकरीबन 12 हेक्टेएयर जमीन ग्रिड कनेक्टिंग सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रोवाइड करा दी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां लगाने के लिए रामपुर जब तशरीफ ले गए थे तो यह ऐलान भी कर दिया था घोषणा भी कर दी थी लेकिन किन्हीं कारणों से अभी वह काम शुरू नहीं हो पाया है मैं बहुत ऐहतराम से यह कहना चाहूंगा कि उस हाजीपुर गांव के सोलर पावर प्लांट पर शीघ्र से शीघ्र बिजली बनाने का काम शुरू कराया जाय। एक और जरूरी बात अधिष्ठाता जी मैं कहना चाहूंगा। बिलारी नगर पालिका से जो रोड स्टेशन रोड को जाती है वहां पर सिंचाई विभाग का एक डाक बंगला है जो तकरीबन 20 बीघा अराजी में है जो करोड़ों अरबों रुपये की धरोहर है। उसको पूरी तौर से वहां के आस पास के बाशिंदों ने उसकी बाउन्ड्री नष्ट हो जाने के कारण उसके सारे पेड़ों को काट दिया है और उसको अपने निजी उपयोग में ले लिया है। उसकी बाउन्ड्री बनाने का प्रस्ताव यहां पर भी आ चुका है। उस फाइल को निकलवाकर शीघ्रातिशीघ्र कार्य करवाया जाय। 69 लाख रुपये का प्रस्ताव आ चुका है। वह कार्य शीघ्र

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शुरू कराया जाय। एक बात और कहना चाहता हूं जो बिलारी दारनी मार्ग से मुतालिक है वह भी चूंकि दोनों जिलों में होने के कारण, उसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव आधा आधा हिस्सा दो जिलों में, मुरादाबाद वाला पास हो गया और सम्भल वाला रह गया। मुझे यह बताया गया कि सम्भल जिले में गजट में आपका नाम ही नहीं हैं तो मेरे गांव जो तकरीबन 50 गांव हैं, जो सम्भल में पड़ते हैं वह विकास में पीछे इसलिये रह जाते हैं कि अभी हाल में जिला पंचायत की मीटिंग वहां हुई मुझे इत्तेला ही नहीं की गई, मुझे बुलाया ही नहीं गया।मैंने इस सिलसिले में मंत्री जी से शिकायत भी की थी जो सदन में बैठे हैं कि यह तो नाइंसाफी है। अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको खास तौर से दिखवा लें कि सम्भल जिले में जो वहां की योजनाएं हैं, जो वहां की सड़के हैं, जो त्वरित योजना है, जो वहां की जिला पंचायत की योजना है उसमें मुझे नहीं बुलाया गया इसलिये मेरा वह इलाका पीछे रह गया। इसलिये मैं चाहूंगा कि उसमें विकास कार्य कराये जायं और बजट में इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाय। एक बात आखिर में यह कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री योजना के तहत जो सड़कें बनी हैं वह बहुत ज्यादा टूटी हैं, उन पर कोई मरम्मत का कार्य नहीं चल रहा है। बाकी जो हमारे प्रदेश की सड़कें पी0डब्ल्यू0डी0 ने बनाई हैं उन पर मरम्मत का काम चल रहा है, नई बन रही हैं लेकिन प्रधान मंत्री योजना के साथ जो सड़कें बनी थीं वह बहुत खराब हालत में हैं और चूंकि वह हमारी प्रदेश सरकार उसे नहीं करा सकती है इसलिये ऐसी व्यवस्था कराई जाय कि उन सड़कों की तुरन्त मरम्मत हो, उन पर तुरन्त कार्य किया जाय। रही हमारे विपक्षी सदस्यों की बात, विशेष तौर पर जिनका 5 साल का टाइम रहा है, उनके बारे में किस तरह से इनका टाइम रहा है और कैसे इनके हालात रहे हैं इन्होंने तो अपने पुराने 5 साल के टाइम में जो किया वह किसी से छिपा नहीं है। इनके लिये खास तौर पर मेरा शेर, क्योंकि मुझसे फरमाइश की गई है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

माननीय अधिष्ठाता जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सत्ता पक्ष के सदस्य कोरम नहीं पूरा कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कोरम तो पूरी विधान सभा से होता है। कोई सत्ता रूढ़ पक्ष की तरफ से नहीं होता है।

श्री मौ0 इरफान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो शेर मैं कहना चाहूंगा इस पर गौर फरमाइयेगा। जो इन्होंने 5 साल में किया उस पर यह शेर है।

''यह तो गुमां भी न था ऐसा करेंगें वोह
रहगर बने तो कौम का सौदा करेंगें वो।''

धन्यवाद।

*श्री जय प्रकाश निषाद-

माननीय अधिष्ठाता जी, जो मुख्यमंत्री बजट भाषण पर आपने बोलने का मौका दिया इसके लिये आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, अभी तक बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं, जो कहा गया है, जो बजट दिया गया है, उसमें तमाम बातें यह इंगित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करती हैं कि उसमें देख करके एक पक्षीय और उस भाषण में, बजट में जो यह विद्युतीकरण की बात अभी हमारे विद्युत मंत्री जी ने बड़े विस्तार से बताई कि 21 जिलों का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा लेकिन मैं यह साफ तौर पर लेकिन मैं यह साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि तमाम बातें ऐसी हैं जो बताई जाएं। श्रीमन् हमारे क्षेत्र में, हमने प्रश्न भी अपने क्षेत्र का लगाया था, उसमें साफ तौर पर उत्तर आया है कि 76 राजस्व गांव का विद्युतीकरण करा दिया गया, लेकिन हमारे चौरी-चौरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जो शहीदों की धरती है, शहीदों की धरती पर, शहीदों के नाम पर, तमाम ऐसे शहीद स्मारक बनाए गए हैं। स्मारकों के लिए जो बजट में दिया है, वह भी सुचारु रूप से शहीदों के नाम पर कहीं लगाने का काम आज तक नहीं किया जा रहा है।जो बजट दिया गया है बजट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बजट में प्राविधान करना चाहिए। ऐतिहासिक धरती चौरी-चौरा पूरे भारतवर्ष में विख्यात है, कि वहां शहीदों ने 1922 में, दिन शनिवार, दिन चार बजे, अंग्रेजों के शासन काल में, थाने पर धावा बोलकर पूरे देश में संदेश देने का काम किया था।आज उन शहीदों की मूर्तियां टूटी-फूटी बिखरी हुई हैं और आज वह चौरी-चौरा के शहीद स्मारक में यह बयां कर रही है कि जबसे यह शासन आया है, तबसे वहां पर ऐसे जमावड़े, ऐसे तबके के लोग, वहां पर अराजक तत्व के लोग, जाकर के शहीद स्मारक की दुर्व्यवस्था बनाये हुए है। उस दुर्व्यवस्था को सही करने के लिए मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि तमाम शहीदों की, जहां ऐसी धरोहर है, ऐसी स्थली है, ऐसे पुरातत्व के जो भी स्थान हैं उनके लिए तमाम बातें जैसी होनी चाहिए, वैसी उनके रख-रखाव की बजट में व्यवस्था नही बनाई गई। उन शहीदों की विधवाओं के लिए, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी, उनके लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है और बीबियों को, बहनों को, थाने में बैठा दिया जाता है लाख कोशिश के बावजूद उनको तवज्जो नहीं मिलती है। विद्युतीकरण की बात जहां तक आई, विद्युत विभाग में जो इन्होंने कहा है, हमारे क्वेश्चन के उत्तर में, हमने पूछा था, उसके उत्तर में कहा गया कि सरदार नगर ब्लाक में 76 राजस्व गांव आते हैं। सारे गांवों का विद्युतीकरण करा दिया गया है। जबकि मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में विद्युतीकरण के नाम पर अभी तक 20 प्रतिशत गांव का भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है। जबकि मुख्य मंत्री जी के जबाव में आया है कि सारे गांव का विद्युतीकरण करा लिया गया है। अभी छोटेलाल वर्मा जी 17 जातियों के बारे में बात कर रहे थे मैं यह कहना चाहता हूं मा0 मुख्य मंत्री जी, आपने बजट भाषण में उन 17 जातियों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई, जबकि उन्हीं 17 जातियों की बदौलत सरकार आज उत्तर प्रदेश के सदन में, सरकार के रूप में काम कर रही है। आपकी पार्टी को जनमत देने वाली वह 17 जातियां उन जातियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और बजट भाषण में जिसमें निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, धीमर ऐसे लोगों के लिए जो पूर्ववर्ती सरकारों ने व्यवस्थायें बनाई थीं उनके बारे में आपके बजट भाषण में कोई जिक्र नहीं है। मछुआ आवास की जहां तक बात आती है जो मछुआ आवास पहले मिलते थे। उस तरह का मछुआ आवास का प्राविधान आज शून्य कर दिया गया है। मछुआरों के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं कहना चाहता हूं इन मछुआरों की समितियां बनाकर जो पूरे प्रदेश में चलाने का काम किया जाता है उन समितियों के लिए कोई बजट भाषण में, मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी आप कहते हैं पूरे पिछड़े वर्ग के लोगों का पिछड़ेपन आर्थिक, शैक्षिक इनकी माली हालत खराब होने के कारण इनको अनुसूचित जाति का दर्जा हम दिलायेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस सदन में तत्कालीन

मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 मुलायम सिंह यादव जी इस सदन में नहीं हैं मैं उनका सम्मान करता हूं उनके मैनिफैस्टो में इस बात का जिक्र किया गया था। लेकिन जो अपने देश का सदन है, उस सदन में वह मौजूद हैं, कभी भी केन्द्र सरकार के सामने उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया, मा0 सोनिया गांधी से कभी मांग नहीं किया कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया जाए। जब कि प्रदेश सरकार को इस सम्बन्ध में कोई पावर ही नहीं है कि वह इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर ले। यह पावर केन्द्र सरकार के पास है, अगर केन्द्र सरकार चाहे तो इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर सकती है। लेकिन आज तक उनके सामने इसका जिक्र नहीं आया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार केवल इन 17 जातियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मान्यवर, यह 17 जातियों के लोग कमजोर और बुजदिल नहीं हैं, यह सब समझते हैं, आपने उनके लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया, कहीं उनका जिक्र नहीं किया, आने वाले 2014 और 2017 में आपको भलीभांति यह 17 जातियों के लोग दिखाने का काम जरूर करेंगे और वहीं भेजने का काम करेंगे, जहां थे।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री जय प्रकाश निषाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ है, मैंने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर भी नहीं बोला था। मैं बताना चाहता हूं, इन बातों को बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए। हमारी शहीदों की धरती पर दो ओवर ब्रिज बनाये जाने हैं, आए दिन उस पर घटनाएं-दुर्घटनाएं हो जाती हैं और तमाम जाम लग जाता है, आवागमन बाधित होता है। मान्यवर, एक दिन हिन्दुस्तान पेपर के माध्यम से निकला था कि सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट की सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ रुपये देने का प्राविधान किया है। मान्यवर, चौरी-चौरा की शहीदों की धरती पर मैंने दो ओवर ब्रिज बनाने के लिए मैंने बात कही थी लेकिन इस बजट में उसका कोई जिक्र नहीं आया है। मान्यवर, जहां पर शहीदी धरती है, वहां पर एक भी गेस्ट हाउस नहीं है, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बात को कहना चाहता हूं, सरकार के सामने एक सुझाव रखना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र से सटे कुशीनगर एक ऐतिहासिक धरती आती है, महात्मा गौतम बुद्ध की धरती है, मेरे क्षेत्र से होते हुए एक ट्राम वे लाइन चलती है, ट्राम वे लाइन बनी हुई है, लेकिन बहुत दिनों से खराब पड़ी है। इस ट्राम वे लाइन को अधिग्रहीत करके सरकार यदि इन शहीदों की धरती को भगवान बुद्ध की धरती तक जोड़ने का काम करती है तो एक ऐतिहासिक काम होगा।

श्री अधिष्ठाता-

आप समाप्त करें। अब श्री विजय कुमार दुबे जी।

श्री जय प्रकाश निषाद-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

*श्री विजय कुमार दुबे-

माननीय अधिष्ठाता जी, बजट प्रस्ताव पर आपने मुझे भी बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी के इस बजट प्रस्ताव का हम सम्मान तब करते

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। जब इस बजट का लाभ सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की धरती पर मिलते हुए दिखायी देता। वास्तविकता काफी परे है और बीते हुए वर्ष एक इतिहास के रूप में हमारे सामने गवाह हैं कि जब-जब सरकारों की कार्य-प्रणाली में भावभाव की नीति हावी हुई है, तब-तब विकास के रास्ते में न केवल अवरोध पड़ा है, बल्कि जनता ने भी सजा दी है। पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में अगर भेदभाव की नीति को प्रमुखता दी है तो सब कुछ परिणाम देखने के बाद भी आज वर्तमान की सरकार पूर्व की सरकार से भेदभाव की नीति पर दो कदम आगे निकलने को आतुर है। उदाहरण, देश के एक तरफ बसे खड्डा विधान सभा, जहां के बाद नेपाल और बिहार की सीमा प्रारम्भ होती है। उस विधान सभा की परिस्थितियों पर अगर नजर डालें तो काफी कुछ मिलता है। चाहे मुद्दा सड़क निर्माण का हो, चाहे मुद्दा सड़क मरम्मती का, इंडिया मार्का हैण्डपम्प का हो, चाहें लोहिया समग्र ग्राम के चयन का हो सभी में भेदभाव की नीति है। खड्डा विधान सभा क्षेत्र की जनता मुख्यतः गन्ने की खेती पर आश्रित है। वहां की जनता अपनी इज्जत आबरू गन्ने के व्यवसाय से सम्मानपूर्वक रक्षा करती है। गन्ना किसानों का मुख्य आय स्रोत खड्डा और छितौनी मिल पर निर्भर था। छितौनी मिल तो पिछले 30-03-2011 को जमीन के सक्रिल रेट से कम दर पर पूरी मिल के भवन, जमीन, कलपुर्जे को ओंकारा शुगर प्राइवेट लि0 को बेच दिया गया। अब खड्डा मिल बची है। वर्तमान में खड्डा मिल में चाहे घटतौली की शिकायत का मामला हो, चाहे पर्ची गन्ना माफियाओं को बेचने का मामला हो, निजी क्रय केंद्रो के द्वारा किसानों को 200 रुपये प्रति0कु0 के भाव से गन्ना खरीदने को बाध्य किया जा रहा है। मैंने नियम-51 में कल इस मुददे को उठाया भी था। सरकार ने गन्ने मूल्य को बढ़ाया इसके लिए वह बधायी के पात्र हैं, लेकिन उस गन्ने मूल्य का लाभ किसानों को मिल रहा है या बिचौलियों को यह तो प्रदेश सरकार को देखने की बात है। भारी बजट का लाभ यदि सड़क बिजली, शुद्ध पेयजल आदि की सुविधा अगर समान रूप से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को मिले तो निश्चय ही विकास के लक्ष्य का जो मा0 मुख्य मंत्री जी का एजेण्डा है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास करायेंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनायेंगे अवश्य सफल रहता। लेकिन भेदभाव की नीति पर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास कहां और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की मुहिम निश्चय ही पूरा नहीं होगी। मान्यवर, सड़कों का आलम देखें। मान्यवर, उदाहरण के तौर पर बनवारी छपरा से गुलरिया रेगुलेटर की सड़क का हाल बताना चाहूंगा। यह प्रमुख मार्ग दो विकास खण्डों को जोड़ता है। इस प्रमुख मार्ग से लगभग 8 से 10 हजार स्कूली बच्चे बरवा रतनपुर स्कूल जाते हैं। यह बरवा रतनपुर जाने का प्रमुख मार्ग है। इसी पर गन्ना के सीजन में गन्ना लदी ट्रालियों और बालू लदे ट्रकों का भी रास्ता है। इस मार्ग पर हर साल लगभग 5 से 6 बच्चे असमय दुर्घटना के कारण मर जाते हैं। मैंने नाबार्ड के प्रस्ताव के माध्यम इस सड़क को दिया था। लोक निर्माण विभाग में एक दिन पता लगाने पहुंचा तो बताया गया कि सेंक्शन हो चुका है अब धन आवंटन होता है कि नहीं यह तो प्रदेश सरकार के जिम्मे का है। मैंने कहा कि क्यों ? क्या धन आवंटन में दिक्कत है ? बोला कि आप कांग्रेस के हैं तो उम्मीद कम समझियेगा। अब सड़कों के बाद लोहिया समग्र ग्राम के चयन की बात करें तो पिछले वर्ष एक भी गांव खड्डा विधान सभा में नहीं चयनित किया गया। इस साल पूरे जनपद में 41 गांव आये हैं लेकिन इस बार भी खड्डा विधान सभा में एक भी ग्राम सभा लोहिया ग्राम चयनित होते दिखायी नहीं दे रहा है। हमारे जिला प्रभारी मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं। मैंने राज्यपाल अभिभाषण के समय में भी कहा था कि भेदभाव की नीति पर जब भी कोई सरकार चलेगी तो न तो उनका उत्तर प्रदेश के विकास का लक्ष्य पूरा होगा और न तो उत्तर

प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की मुहिम में आप सफल होंगे और इसके अलावा अगर देखें तो इंसेफ्लाइटिस प्रभावित क्षेत्र मुख्यतः कुशीनगर जनपद इस समय है और उस कुशीनगर जनपद में भी खड्डा विधान सभा के अन्तर्गत एक वर्ष में लगभग 50 बच्चों की मौत हुई थी। प्रस्ताव देने के बाद भी इंसेफ्लाइटिस प्रभावित टोलों, मजरों पर शुद्ध पेय जल हेतु इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प की आवश्यकता है। कई बार प्रस्ताव हम लोग दिये, लेकिन अभी तक एक भी इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प उपलब्ध नहीं हो सका। पिछले साल सड़क परियोजना में बजट पास हुआ। जिला योजना की बैठक में मा0 हमारे प्रभारी मंत्री जी ने 40 करोड़ से बढ़ाकर 60 करोड़ कर दिये, लेकिन उस 60 करोड़ में शायद कुशीनगर जनपद की किसी सड़क पर अभी वह धन एक वर्ष बीतने के बाद भी कहीं नजर नहीं आता है। ग्राम सभा चाहे लोहिया चयन का हो, चाहे शुद्ध पेय जल के लिए हो, चाहे सड़कों का आलम हो और इसके अलावा अगर हम विद्युतीकरण की समस्या से अवगत करायें तो हमारी विधान सभा में इस वर्तमान आधुनिक परिवेश में भी कम से कम दर्जनों ऐसे गांव होंगे जहां आज भी 11 हजार की लाइनों पर विद्युत आपूर्ति लकड़ी के जर्जर खम्भों और टूटे हुए तारों के माध्यम से करायी जाती है, जिसकी वजह से प्रतिवर्ष एक दर्जन से अधिक असमय मौतें किसानों को ग्रामीणों को झेलना पड़ता है। बिजली के बिल समय से देते हैं और अगर समय से न दे पायें तो उन्हें जेल की हवा खिला दी जाती है, लेकिन उनको सुविधा के नाम पर लकड़ी के जर्जर पोल और लोहे के तार आज भी मिले हैं। हम अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन से मिले थे, सदन में कई बार आवाज उठाई, लेकिन जहां 200 आर0सी0सी0 पोल लकड़ी के खम्भों के बदले चाहिए, मात्र 80 पोल साल भर में दिया गया है, न तार मिला न कोई स्ट्रूमेण्ट मिला, जिसके चलते यह अधूरा कार्य आज भी अधूरा ही पड़ा हुआ है, तार तक सुलभ नहीं हो पाये। आज के इस बजट प्रस्ताव पर हम विपक्ष के सदस्य यही कहना चाहेंगे कि विकास की नीति अगर भेद-भाव से परे होगी तो आपके बजट का सम्मान है, अन्यथा हमारे सामाजिक जीवन की बुनियाद तो संघर्ष रही है और उसी संघर्ष के दम पर हम यहां तक पहुंचे हैं, कोई वोट बैंक की राजनीति हम लोगों के साथ नहीं और जनता के आशीर्वाद से अगली बार भी संघर्ष के दम पर यहां तक पहुंचेंगे। हां भेद-भाव की नीति पर आप कहां जायेंगे, सामने के बैठे विपक्षीगण आपको परिणाम दे रहे हैं, जय हिन्द ।

श्री अब्दुल मशहूद खां-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मा0 मुख्य मंत्री महोदय द्वारा पेश किये गये बजट की चर्चा मे हिस्सा लेने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मा0 अधिष्ठाता महोदय, एक शेयर बड़ा अच्छा है कि ''हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती''। जिन लोगों की हुकूमत 40 साल से ज्यादा उत्तर प्रदेश में रही हो, यह कैसा खड्डा है जो उनको नहीं दिखा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो बजट मा0 मुख्य मंत्री महोदय द्वारा पेश किया गया है, यह अपने आप में सम्पूर्ण है। सम्पूर्ण इसलिए भी है मान्यवर, क्योंकि इसमें समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि भेद-भाव किया गया। किस मामले में भेद-भाव किया गया, जरा एक प्वाइण्ट बता देते, एक ही प्वाइण्ट बता देते।

श्री विजय कुमार दूबे-

लोहिया ग्राम के चयन को ही देख लें।

श्री अब्दुल मशहूद खां-

जब पहली बार समाजवादी पार्टी के मुखिया मा0 मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो सबसे पहले उनको समाज में खड़ा हुआ जो आखिरी आदमी दिखा, वह था चौकीदार मान्यवर, और चौकीदार को तनख्वाह देने का काम मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने किया। उनका वेतन बढ़ाने का काम भी मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने किया । 40 साल से ज्यादा कांग्रेस ने हुकूमत किया। चार-चार ये जो सामने बैठे हैं। इनकी मुखिया जिनको ये बहन मायावती कहते हैं। जो कहते हैं कि गरीबों की मसीहा हैं। मान्यवर, चार-चार मुख्य मंत्री बनीं उनको समाज का चौकीदार नहीं दिखा और जब मा0 मुलायम सिंह यादव जी का खून, मुलायम सिंह यादव जी का खून, जो बीज उन्होंने बोया था, जब वह पौधा लहलहाया और मा0 अखिलेश यादव जी के रूप में मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठा तो सबसे पहले वह रिक्शावान दिखा। जो आदमियों को खींचता था, वह रिक्शावान दिखा, उसको मोटरचालित रिक्शा देने का काम मा0 अखिलेश यादव जी ने किया। मा0 अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि भेदभाव किया। अरे, एक ही मसला खाली ले लो। अभी विधायक निधि बढ़ाने की बात हुयी थी तो तुम्हारे भी खाते में विधायक निधि का 25 लाख रुपया बढ़कर पहुंचेगा। हमारी पार्टी ने कहीं भेदभाव नहीं किया। हमारी पार्टी ने कभी भेदभाव करने का काम नहीं किया। हमारी पार्टी ने सबको समान रूप से साथ लेकर चलना सीखा है। सबको समान रूप से देखा है। अगर शिक्षकों की अधिवर्षता आयु बढ़ाई तो मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने बढ़ाई, उसको साठ साल से बांसठ साल कर दिया। उसमें सभी जाति, धर्म के लोग थे और सभी दल के मानने वाले लोग थे। कहीं भेदभाव नहीं किया हमारी पार्टी ने। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं। मैं इस सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे मुखिया मा0 मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने समाज के लिये किया और जब उनका लड़का, उनका सपूत मा0 अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा तो विधान सभा के इतिहास में जितने भी बजट पेश हुये हैं उसमें सबसे अच्छो बजट ये पेश हुआ है मान्यवर। मैं इसकी बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूं।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

(इस समय 6 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

5 साल तक बहुजन समाज पार्टी ने लूट करके उत्तर प्रदेश को खोखला कर दिया था। सड़कों को इतना गड्ढायुक्त बना दिया था कि सड़कें गायब हो गयी थीं। गड्ढा ही गड्ढा बचा था और जो उनके चीफ थे वे जीतकर आ गये हैं सदन में। इस कदर लूटा उत्तर प्रदेश को कि सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गयीं। कहीं एक ईट नहीं रखी गयी। अगर कहीं ईंट पत्थर रखा गया तो खाली स्मारक बनाने के नाम पर और जब मा0 अखिलेश यादव जी बैठे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो इतने कम संसाधन में, इतने कम पैसे में और इतने कम समय में जो बजट पेश कर दिया है। वह अपने आप में सराहनीय है मान्यवर। इन्होंने समाज के हर वर्ग के लिये पेश किया। समाज के हर वर्ग के लिये किया और मैं मुसलमान हूं। आज मुझे गर्व होता है कि मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार में मुसलमानों को भी बहुत कुछ दिया। अल्पसंख्यकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 19 प्रतिशत है। लगभग 19 परसेण्ट उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को प्रतिशत है और अपने आपको मुसलमानों का मसीहा कहने वाली मायावती जी जब बजट पेश करती थीं तो इनके बजट में अल्पसंख्यकों के लिये, आप बजट उठाकर देख

लीजिये। रिकार्ड बोलता है, मैं झूठ नहीं बोलता। मान्यवर, 0.68 परसेण्ट था, केवल 0.68 परसेण्ट था। 19 परसेण्ट अल्पसंख्यक जहां उत्तर प्रदेश में निवास करते हों, वहां अगर मुसलमानों को 0.68 परसेण्ट बजट दिया जायेगा तो क्या भला होगा। जब मा0 अखिलेश यादव की सरकार बनी तो उन्होंने उसको लगभग तीन गुना कर दिया। वह 0.68 परसेण्ट को उठा करके 2 परसेण्ट कर दिया। मैं प्रशंसा करता हूं मा0 मुख्य मंत्री जी की। मैं मा0 अखिलेश यादव की सरकार की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने मुसलमानों के बारे में सोचा। अरे जितने भी मुख्य मंत्री बने आजादी के बाद, उन्होंने तो जिन्दा आदमियों का भी ख्याल नहीं रखा और मा0 मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कब्रिस्तानों को बाउण्ड्री वॉल देकर के हमारे वे लोग जो दुनिया से चले गये हैं, उनका भी ख्याल किया, उनकी भी रूह दुआयें देंगी। आप कहते हैं कि उधर चले जाओगे, इधर चले जाओगे। कौन कहां चला जायेगा, यह आने वाला 2014 बतायेगा और 2017 बतायेगा। मान्यवर, भाजपा के लोग खड़े होते हैं बोलने के लिये तो बजट की प्रशंसा करने के बजाय सिफ्र दो तरफ ले जाना चाहते हैं क्योंकि 2014 नजदीक है। कोई पशु तस्करी की बात करता है, कोई पशु वध की बात करता है। अरे, काम की बातें करो सदन में आये हो। उत्तर प्रदेश की भोलीभाली जनता को बहकाने का काम मत करो। कहते हैं कि बजट खर्च नहीं कर पाये। मा0 अध्यक्ष जी, मुझे बोलने दीजिये। मैं बहुत कम बोलता हूं सदन में। मैं बहुत कम बोलता हूँ मुझे एक दो मिनट का मौका और दीजिये। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे एक साथी कह रहे थे कि बजट नहीं खर्च कर पाये। हम अपनी जेब में नहीं ले जाना चाहते थे इसलिये बजट नहीं खर्च कर पाये। ये सच्चाई है, बजट शुरू हो गई, आज भी बारिश का सिलसिला नहीं रुक रहा है। आने वाले एक साल बाद आपको दिखायी पड़ेगा उत्तर प्रदेश का बजट और आपको विकास दिखायी पड़ेगा। और विकास दिखाई पड़ेगा मान्यवर, मा0 मसूद साहब, अब समाप्त करें।

श्री अब्दुल मशहूद खां-

आपकी आज्ञा मान लेते हैं, मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, शुक्रिया।

श्री अध्यक्ष-

टी0 राम जी आप बोल लीजिए, 5 मिनट उसके बाद फिर समाप्त करते हैं।

श्री त्रिभुवन राम-

मा0 अध्यक्ष महोदय, ठीक है जितना आप कहेंगे उतनी देर ही मैं बोलूंगा। मा0 अध्यक्ष महोदय, आज आपने 2013-2014 के बजट पर मुझे बोलने का और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। मान्यवर, मैं 2-3 प्वाइंट पर ही सिफ्र केन्द्रित रहूंगा, पहली बात है डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास की। मान्यवर, इसके पहले पिछली सरकार में डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना लागू की गयी थी और उसमें कोई सीमा नहीं रखी गयी थी, उसमें अगर 50 लाख में कोई गांव संतृप्त होता था, या 5 करोड़ रुपये में होता था या 10 करोड़ में होता था, उसमें कोई एक मजरे की बात नहीं थी, एक मजरा हो, दो मजरा हो, 10 मजरे हो या 20 मजरे हो, चाहे एक किलोमीटर सड़क हो, 2 किलोमीटर हो या 10 किलोमीटर हो सभी में सी0सी0 रोड, पक्की नाली और उसके बाद इंटरलॉकिंग टायल्स् लगायी जाती थीं, और इसको सभी लोग जानते भी हैं, चाहे वह सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के हो, चाहे हमारे रूलिंग पार्टी के ही लोग हो, सब लोग

जानते हैं इस बात को। मान्यवर, यह जो बजट आया है इस बार का 2 लाख 21 हजार 201 करोड़ रुपये का है, निश्चित रूप से सबसे बड़ा बजट है अब तक के इतिहास में, लेकिन इसमें डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम के लिए जो 2012-13 में, मा0 मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण में यह कहा गया था कि 10 हजार गांव लेंगे। 10 हजार गांव में से पहले साल में 2012-13 में 1600 गांव लिए गए थे, मान्यवर, जिसमें 720 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गयी थी, तो औसत आता था लगभग 45 लाख प्रति ग्राम और उसमें एक किलोमीटर, डेढ़ किलोमीटर सड़क भी बन सकती थी। मान्यवर, उसके बाद जो बचे गांव थे, वो 2100 गांव इस साल में हैं, 2100 आगे और फिर 2100 आगे करके 10 हजार गांव हो जाएंगे, पूरे 5 साल में। अब 2100 गांवों के लिए मान्यवर, सी0सी0 रोड, सी0सी0 ड्रेन, आंतरिक गलियों में इंटरलॉकिंग टायल्स् ये लगाने के लिए 287 करोड़ रुपये मात्र की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, अगर एक किलोमीटर में इंटरलाकिंग टाइल लगायी जाए तो भी 30 लाख के करीब खर्चा आ जाता है। सीमेंट, कंक्रीट की रोड अगर बनाते हैं तो भी 40 लाख रुपये आ जाएंगे। 30-35 लाख रुपये जब हम पक्की सड़क बनवाते हैं, तो भी आ जायेगा। इसमें 13 लाख 70 हजार रुपये प्रति गांव के हिसाब से यह बनता है मान्यवर, यह इतनी कम धनराशि है कि इसमें कोई भी गांव संतृप्त करना बड़ा संभव नहीं हो पाएगा। मेरा मान्यवर, आपके माध्यम से शासन से केवल यह निवेदन है कि कम से कम इसे 1000/- करोड़ रुपये कर देना चाहिए, ताकि जो गांव हो, वो संतृप्त हो जाएं। इसमें 36 विकास के कार्यक्रम रखे गए हैं और यह 13 लाख 70 हजार रुपये में कैसे हो पाएंगे यह खुद में एक प्रश्न-चिन्ह लगा हुआ है।

मान्यवर, दूसरी बात है अभी हमारे सदन के लोगों ने जो तमाम बातें कही हैं और एक-दूसरे पर बहुत कीचड़ उछालने का भी प्रयास किया कि हमारी पार्टी ने यह किया, हमारी सरकार ने यह किया, हम उन सब बातों में नहीं जाते हैं, हम केवल यह जानना चाहते हैं कि इतने बड़े बजट में रोजगार सृजन के लिए क्या व्यवस्था हुई। रोजगार सृजन के लिए कोई व्यवस्था इसमें विद्यमान नहीं है, जो सीधे-सीधे गरीब हैं, जो रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं, जो भूमिहीन किसान है, जो खेतिहर मजदूर हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। मान्यवर, अगर मनरेगा को उठाकर देखा जाए तो वर्ष 2010-11 में जो भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि थी 8779 करोड़ रुपये थी और प्रदेश सरकार को जो प्राप्त हुई थी 5267 करोड़ रुपये मिला था, वर्ष 2011-12 में मान्यवर, 8787 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे भारत सरकार से जिसके सापेक्ष 4240 करोड़ रुपये, मतलब पहले साल 60 प्रतिशत मिला था और दूसरे साल 48 परसेन्ट मिला । मान्यवर, 2012-13 में 7003 करोड़ रूपया भारत सरकार ने स्वीकृत किया था, जिसके सापेक्ष मात्र 1170 करोड़ अर्थात् केवल 17 प्रतिशत धनराशि प्राप्त हुई, तो मान्यवर, रोजगार कहां से आएगा उन गरीबों का ध्यान कौन रखेगा। सरकार ने इतना बड़ा बजट बनाया सरकार की तारीफ है, लेकिन रोजगार सृजन की बात इसमें जरूर आनी चाहिए थी। इसमें मेरा एक सुझाव है कि पंचायतीराज तथा ग्राम्य विकास विभाग की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अंतर्गत रोजगार सृजन के लिए, उसमें मजदूरों से काम कराने की एक व्यवस्था सुनिश्चित करवा दी जाए मान्यवर, ताकि कुछ लोगों को रोजगार तो मिल जाए। मेरा यह आपसे निवेदन है आपके माध्यम से शासन से निवेदन है। मान्यवर, दूसरा विद्युत पर बहुत चर्चा हुई, तमाम बातें हुई। यह हुआ कि कोई 25 हजार करोड़ रूपया पिछली सरकार ने छोड़ा, 40 हजार करोड़ छोड़ा, घाटे में है, घाटे में है, सब बातें ठीक हैं। मान्यवर, लेकिन इस प्रदेश को बिजली की जरुरत है इससे सभी लोग सहमत हैं कि विद्युत की परेशानी है हमारे प्रदेश में। 4433 मेगावाट इंस्टाल्ड केपिसिटी है

हमारी, आपने गतवर्ष 8025 करोड़ रु0 की धनराशि रखी थी उत्पादन क्षमता की वृद्धि तथा प्लान्ट्स के आधुनिकीकरण हेतु। इस वर्ष धनराशि 11732 करोड़ रु0 रखी गयी है जो 24.5 प्रतिशत ज्यादा है। मान्यवर, इसमें देख्ना चाहिए कि दो कम्पोनेंट्स हैं हाइड्रो पावर और थर्मल पावर। हाइड्रो पावर में पिपरी में 250 मेगावाट है, माताटीला में 40 मेगावाट है और उत्तराखंड के डाउन स्ट्रीम में जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वह 100 मेगावाट है । इस तरह से बाकी जो बिजली बनती है वह थर्मल पावर से बनती है। थर्मल पावर में ट्रांसमिशन लॉस हो रहा है और डिस्ट्रिब्यूशन लॉस 35 से 40 प्रतिशत तक हो रहा है। इसी तरह से तार में रेजिस्टेंस जिसमें टेक्निकल लॉस होता है वह 15 प्रतिशत तक होना चाहिए। इसी प्रकार मान्यवर 20 से 25 प्रतिशत तक बिजली चोरी और कटिया आदि में चली जाती है। इस तरह से यह जो भारी लास होता है इसकी वजह से बहुत बड़ी परेशानी है। इसको कम कराने का प्रयास किया जाना चाहिए।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे थर्मल पावर के प्लांट्स बहुत पुराने हो गये हैं उनकी प्लांट लोड कैपिसिटी 50 प्रतिशत तक आ गयी है इस तरह से अधिष्ठापित क्षमता से लगभग आधा उत्पादन हो पा रहा है। जबकि जो एनटीपीसी आदि के प्लांट लगे हैं वहां 75 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक का प्रोडक्शन हो रहा है। मान्यवर, बजट में 1522 करोड़ रु0 की धनराशि मशीनों के अपग्रेडेशन और प्लांट लोड फैक्टर को बढ़ाने के लिए रखे गये हैं। मेरा निवेदन है कि जो पुराने प्लान्ट हो गये हैं यदि उनका रिप्लेसमेण्ट करा दिया जाय, तो यह क्षमता जो 50 प्रतिशत के लगभग चल रही है वह बढ़कर 80-85 प्रतिशत तक हो जायेगी और जिससे जो बिजली की आपूर्ति में कमी की शिकायतें हैं उसमें कमी की जा सकती है।

मान्यवर, हाई-टेन्सन लाइन्स बहुत जगह ऐसी जगहों से निकल रही हैं जिसमें नीचे मकान बने हुए हैं और लोग रह रहे हैं और पूरी-पूरी कालोनियां बसी हुई हैं और आए दिन वहां पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस तरफ सरकार ध्यान देने का काम करे।

श्री अध्यक्ष-

मेरे यहां भी यह शिकायतें हैं। आप यह बतायें कि जब लोग उसके नीचे पहले तो मकान बना लेते हैं फिर आके हमसे अनुरोध करते हैं कि हाई-टेन्सन लाइन हटवाई जाए।

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, आपकी बात सही है। मान्यवर वह गरीब लोग हैं, उनके पास जमीन कम हैं तो वह मकान बना लेते हैं। तो उस पर सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए, ताकि कालोनियों के ऊपर से जो हाई टेन्सन लाइन जा रही हैं, उनको हटवाने की व्यवस्था खुद विभाग करे।

श्री अध्यक्ष-

देखिए उसको लोग बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं फिर हटवाने की मांग करते हैं, तो उनको तो मकान बनाना ही नहीं चाहिए।

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में चार-पांच डेथ हो चुकी हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि यह कार्य विभाग करे। मान्यवर, जो ट्रांसफारमर के विषय में बात है वह खराब क्वाल्टी के हैं, सप्लाई बहुत गन्दी होती है और आये दिन जल जाते हैं। यह गांव वाली जो समस्या है यह बहुत बड़ी समस्या है और तीसरी जो समस्या गांव में है वह लोड बढ़ाने की है ट्रांसफार्मर की, जहां पर लोड बढ़ाने की बात आती है

वहॉ भी नियम की बात आ जाती है कि कितने वहॉ पर वैध कनेक्शन हैं उनकी सूचना लेकर के आइये उनके सर्टिफिकेट लेकर के आइये। फिर वह लोड नहीं बढ़ पाता है और असलियत यह भी है कि सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर वहीं फुकते हैं। तो मान्यवर, यह दो तीन समस्याएं थी इसके अलावा हमारे क्षेत्र में एक करोड़ तिरासी लाख की स्वीकृति हुई थी 22 गांव में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कराने की, एक साल से काम बन्द हो गया है मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह कम से कम जो हमारे क्षेत्र के 22 गांव थे उसमें रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन का काम पूरा हो जाय। हमारे यहॉ बिजली 4 से 6 घंटे ही आती है जबकि हमारे बनारस जिले में ही एक दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 18 से 20 घंटे बिजली आती है तो कम से कम बनारस जिले में एक यूनिफार्मिटी हो जाय यह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

मान्यवर, खेलकूद के विषय में फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। खेलकूद में वर्ष 2013-14 में 177 करोड़ के बजट की जो व्यवस्था हुई है उसमें झांसी में एस्ट्रोटफ्र, इटावा में हाकी मैदान में एस्ट्रोटफ्र एवं जिम्नेजियम, आगरा में एस्ट्रोटफ्र, अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और उसके अलावा और कहीं नहीं है। मैं बनारस के बारे में कहना चाहता हूं कि बनारस में हमारा बैडमिन्टन हाल बहुत खराब है और स्टेडियम नहीं है तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं इसके अलावा मान्यवर, बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया भी है कि जो वर्ल्ड ओलम्पिक्स में जाते हैं लड़के गोल्डमेडल ले करके आते हैं उनको एक करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाता है, रजत पदक विजेता को 50 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेता को 25 लाख रुपये दिये जाते हैं। मान्यवर, बहुत से लड़के ऐसे हैं जो जिला स्तर खेलते हैं फिर स्टेट खेलते हैं, नेशनल खेल करके वह वर्ल्ड ओलम्पिक में भाग लेने जाते हैं और ऐसे लड़कों के लिए प्रोत्साहन की कोई बात नहीं है। हमारे क्षेत्र में दो लड़के हैं एक राम सिंह यादव है मैराथन में गया था अभी लंदन में वर्ल्ड ओलम्पिक में और दूसरा, नरसिंह यादव कुश्ती में गया था उनके लिए मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि कम से कम इन लोगों को भी 11-11 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाय और इनका मनोबल बढ़ाया जाय ताकि आगे आने वाले वर्ल्ड ओलम्पिक में वह गोल्ड और सिल्वर जीत कर आयें। मैं यह आपके माध्यम से शासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर इसके अलावा 2-3 छोटी छोटी बाते हैं आप जब कहेंगे तो एक मिनट भी नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मैं तो कह ही रहा हूं।

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कैथी गांव है वहां हमारी गोमती नदी जाकर के गंगा जी में मिलती है उस संगम पर वहॉ पर माकण्डेय महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है उस मंदिर के जीर्णोद्धार और उसके सौन्दर्यीकरण के लिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं दूसरा एक सारनाथ से कटहलगंज होते हुए

बेला से लेकर नियाज तक सड़क है वह सड़क जोड़ती है आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चन्दौली को। मान्यवर, केवल 12 कि0मी0 की सड़क है मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके चौड़ीकरण की व्यवस्था करा दी जाय। तीसरा विकलांग खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था नहीं है विकलांग खिलाड़ियों के लिए इस बजट में व्यवस्था कराई जाय। बस इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

जो माननीय सदस्य आज बोलने वाले हैं, अपना-अपना नाम लिखकर दे दीजिए कल भी चर्चा रहेगी प्राथमिकता के आधार पर जो यहां बैठे हैं, सबको बुलवा देंगे।

* श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

अध्यक्ष जी, आपने मुझे मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी हमारे भाई ने एक बात कही थी और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जैसा भाई ने कहा है कि बजट बहुत बढ़िया बनाया है।

श्री अध्यक्ष-

आप बोल चुके हैं। कितनी बार बोलेंगे। आप दो बार बोले हैं तो कैसे बोलेंगें ।

आप ऐसा है जो लोग हैं उनकी लिस्ट दे दो कि यह लोग बोलने वाले थे, उन लोगों को सुबह बुलवा देंगे। आप लोग सूची दे दीजिए। अब मैं नियम 51 ले रहा हूं

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा बोलने का प्रयास करते रहने पर)

वह जो बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा। आज ऐसा है जो लोग यहां बैठे हैं बोलने के लिये, जो नहीं बोल पा रहे हैं, वह अपनी सूची दे दें, कल प्राथमिकता के आधार पर उन्हीं को बुलवाया जायेगा। कल भी पूरे दिन यह चर्चा रहेगी। कल बड़े नेता नहीं बोलेंगे ।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा बुलवाने का अनुरोध किये जाने पर)

अब आप ही लोग मंत्री हैं, क्या सदन को चलायें ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

नहीं अब कल चलाइयेगा ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप लोग सूची दे दो, कल हम सबको बुलवा देंगे।

(बीच में श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया जी के द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

भदौरिया जी, आप कृपया बैठें ।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा श्री सुरेश बंसल को बुलवाये जाने का अनुरोध करने पर)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

बंसल जी को कल पहले नम्बर पर बुलवायेंगे । अच्छा चलिये बोल लीजिये बंसल जी ।

श्री सुरेश बंसल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे वर्ष 2013-14 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। अध्यक्ष जी, इस बजट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत उपेक्षा की गई है। मेरा जनपद गाजियाबाद जो सबसे ज्यादा रेवन्यू देता है, उसमें जाम की बहुत बड़ी समस्या है और स्वयं मुख्य मंत्री जी ने यह माना है कि गाजियाबाद शहर में जाम की बहुत बड़ी समस्या है और उन्होंने बजट के आठवें पृष्ठ पर यह कहा है कि गाजियाबाद शहर में यातायात के दबाव को देखते हुये हमारी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि गाजियाबाद शहर में नार्दन पेरीफेरल रोड परियोजना लागू की जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, यह योजना पहली है और इस योजना से ही काम नहीं चलेगा । अध्यक्ष जी, आप भी गाजियाबाद जाते हैं, वहां हर समय जाम रहता है। इस जाम का सबसे बड़ा कारण यह है कि विजयनगर और शहर के बीच में रेलवे लाइन है, उस पर ओवरब्रिज नहीं है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि सबसे ज्यादा यह जरूरी है कि कोटधाम फाटक पर ओवरब्रिज बनना चाहिये। यह दो साल से पेंडिग पड़ा है और रेलवे ने सब मंजूरी दे दी है, सिर्फ इसमें धन का आवंटन होना है। अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ जाम की समस्या के लिये यह भी कारण है कि जो मुख्य रास्ते हैं, उसमें गड्ढे हो रहे हैं, उसे कोई भी एजेन्सी नहीं बनाती, इसलिये नहीं बनाती कि पूरा विधान सभा क्षेत्र नगर निगम में आता है और वह कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। जब टूटी सड़कें होंगी तो स्वाभाविक है कि जाम लगेगा। अध्यक्ष जी, इसको ध्यान में रखते हुये, गाजियाबाद में इस समस्या का निदान कराइये।

सरकार ने बजट के पेज-19 पर यह कहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा के लिये शिक्षण हब बनाये जायेंगे । इसमें मेरा यह कहना है कि गाजियाबाद का केलाभट्ठा जो सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें सवा लाख की आबादी है, वहां मात्र एक जूनियर हाईस्कूल है, न उसमें टीचर हैं, न कोई कमरे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप वास्तव में यह चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चों की शिक्षा में सुधार हो और आप हब बनाना चाहते हैं तो कम से कम वहां एक इंटर कालेज बनवा दीजिये। इसके साथ-साथ आपने यह कहा है कि छात्राओं की शिक्षा के लिये डिग्री तक जो छात्रायें पढ़ना चाहती हैं, उनमें सरकारी और सरकारी अनुमोदित स्कूलों में फ्री पढ़ायेंगे । मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज तक कोई सरकारी डिग्री कालेज है ही नहीं। पिछले 20 वर्षों से किसी प्राइवेट व्यक्ति ने डिग्री कालेज बनाया ही नहीं और बनाये हैं तो इंजीनियरिंग कालेज बनाये हैं। कृपया करके जब आप यह चाहते हैं कि बेटियां पढ़ें तो एक डिग्री कालेज का निर्माण करा दीजिये। इसके साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र के विद्युतीकरण की योजना है परन्तु शहरों में भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां बिजली अभी तक नहीं पहुंच पाई है, उनके लिए भी विद्युत की कोई व्यवस्था कीजिए। मेरा यह कहना है कि गाजियाबाद बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियल हब है वहां पर इण्डस्ट्री बन्द हो रही हैं और वह इसलिए बन्द हो रही हैं क्योंकि उन्हें पूरे समय बिजली नहीं मिलती। बहुत सारी इण्डस्ट्री उत्तराखण्ड चली गई हैं, आप इण्डस्ट्री को 24 घण्टे बिजली दीजिए तब इण्डस्ट्री चल पायेंगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या उन क्षेत्रों की है जो

नये बसे हैं लोग बाहर से आकर विजयनगर क्षेत्र में बस गये हैं, वहां न तो सीवर लाइन है और न ही पीने के पानी के लिए हैण्डपम्प हैं, कम से कम पीने के पानी के लिए हैण्डपम्प तो लगवा दीजिए। यदि पीने के पानी के लिए हम हैण्डपम्प भी नहीं लगवा सकेंगे तो फिर हमारा यहां आने से क्या फायदा है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर हम जैसे नये विधायकों के लिए भी कुछ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब जो माननीय सदस्य बोलने से रह गये हैं वह कल बोलेंगे।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष -

आज दिनांक 27-02-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 64 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री केशव प्रसाद मौर्या की जनपद कौशाम्बी के सैनी, कोखराज, कौशाम्बी थाना क्षेत्र के शीतला मां मन्दिर एवं जैन मन्दिर, पालीगांव एवं भैराबाबा मन्दिर से मूर्तियों एवं घंटों की चोरी एवं रामबदन पाल की निर्मम हत्या किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दूसरी सूचना श्री राधेश्याम सिंह की जनपद-कुशीनगर के अन्तर्गत चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का करोड़ों-करोड़ों रुपये बकाया होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

तीसरी सूचना श्री आलम बदी की जनपद-आजमगढ़ सरायमीर नन्दांव मार्ग की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि का अवशेष रिलीज़ कराए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौथी सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा में गोकुल बैराज बनाये जाने के उपरान्त दामोदरपुर आदि गांव जो कि गोकुल बैराज के डूबे क्षेत्र में आते हैं, के किसानों की भूमि का मुआवजा तत्काल दिलाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

पांचवीं सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की तम्बाकू व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम में संशोधन करते हुए एक वस्तु पर एक ही रूप पर समान कर की दर लागू किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

छठीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के छात्रों को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार परीक्षा में अविलम्ब शामिल कराने एवं परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति शासन तथा मनमाने ढंग से बढ़ाये गये शुल्कों की वापसी कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

सातवीं सूचना श्री राकेश बाबू की जनपद फिरोजाबाद में नगर पालिका/परिषद् फिरोजाबाद के अन्तर्गत जल निगम द्वारा बनायी गयी पेयजल योजना टंकी 1-टापाखुर्द 2-काशीराम बिहार पेयजल योजना को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

आठवीं सूचना साध्वी निरंजन ज्योति की जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत टाउन एरिया सुमेरपुर में बनी हुई रिमझिम लोहा फैक्ट्री द्वारा छोड़े जा रहे गन्दे पानी से फैल रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

नवीं सूचना श्रीमती पूजा पाल की जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत ग्राम पीपलगांव उर्फ शाहपुर शिवाला से ट्रिपल आई0टी0 चौराहे एवं लालमन तालाब तक जलभराव की समस्या से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त रोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दसवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद-फैजाबाद के रुदौली क्षेत्रान्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत कराए जा रहे कार्यों में की जा रही धांधली के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

ग्यारहवीं सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया की उत्तर प्रदेश के गलगोटिया विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति से सम्बन्धित प्राविधान की जानकारी न दिए जाने के सम्बन्ध में है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

बारहवीं सूचना श्रीमती विमला सिंह सोलंकी की जनपद-बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर से निकलने वाला गन्दा नाला पक्का कराए जाने व उसकी सफाई कराए जाने के सम्बन्ध में है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

तेरहवीं सूचना श्री राजनारायण बुधौलिया की जनपद-महोबा के किसानों पर जल निगम द्वारा पानी की लूट का मुकदमा कायम कर उत्पीड़न किए जाने के सम्बन्ध में है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

चौदहवीं सूचना श्री राजेश अग्रवाल की जनपद बरेली के राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर बरेली के किला से लीची बाग तक क्षतिग्रस्त व जीर्ण-शीर्ण ऊपरिगामी सेतु के स्थान पर नये ऊपरिगामी सेतु तत्काल बनाये जाने के सम्बन्ध में है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद शामली मुजफ्फरनगर में विभिन्न जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :-

1-श्री गेंदा लाल चौधरी,

2-श्री अमरपाल शर्मा,

3-श्री यासर शाह,

4-ठा0 तेजपाल सिंह,

5-श्री प्रमोद तिवारी,

6-श्री पूरन प्रकश एडवोकेट,

7-श्री राजेश त्रिपाठी,

8-श्री ममतेश शाक्य,

9-श्री अली यूसुफ अली,

10-श्री मदन चौहान,

11-श्री संजय प्रताप जायसवाल,

12-श्री मुकेश श्रीवास्तव,

13-श्री रामलाल अकेला,

14-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

15-श्री मनीष असीजा,

16-श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,

17-श्री संगीत सिंह सोम,

18-श्री विजय बहादुर यादव,

19-श्री रामहेत भारती,

20-श्री अवस्थी बाला प्रसाद,

21-श्री जय प्रकाश निषाद,

22-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द,

23-श्री गोरख पासवान,

24-श्री राधेश्याम जायसवाल,

25-श्री भीम प्रसाद सोनकर,

26-श्री जियाउद्दीन रिजवी,

27-श्री अनूप कुमार गुप्ता,

28-श्री विजय कुमार पासवान,

29-श्री बब्बन सिंह चौहान,

30-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,

31-श्रीमती सीमा,

32-श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा,

33-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

34-श्री प्रदीप चौधरी,

35-श्री संजय कपूर,

36-श्री विजय कुमार दुबे,

37-श्री अजय मिश्र 'टेनी',

38-श्री उमाशंकर सिह,

39-श्री सतीश महाना,

40-श्री उपेन्द्र तिवारी,

41-श्री अनीसुर्रहमान,

42-श्री राजबली जैसल,

43-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,

44-श्री छोटेलाल वर्मा,

45-श्री मुकुट बिहारी वर्मा,

46-श्री रविन्द्र भडाना,

47-श्री अगयश राम सरन वर्मा,

48-डा0 मो0 अयूब तथा

49-श्री अजय कुमार लल्लू।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है इसको वक्तव्य के लिए ले लें।

श्री अध्यक्ष-

ध्यानाकर्षण भी वही होता है, उसमें भी आपके पास जवाब आयेगा।

(मा0 सदस्य श्री प्रदीप चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रदीप चौधरी जी कल आपका 301 भी होगा मैंने सब देख लिया है। अच्छा अब चलिये।

इलाहाबाद स्थित फाफामऊ बाजार की सड़क के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की टी0ए0सी0 से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)-

इलाहाबाद में स्थित फाफामऊ बाजार जनपद का प्रमुख बाजार है। ....

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द सिंह गोप)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य बाल विकास एवं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री वसीम अहमद-

[विगत वित्तीय वर्ष 2010-11 व वर्ष 2011-12 में लोक निर्माण विभाग द्वारा यहां क्रमशः सड़क के सुदृढ़ीकरण (सी0सी0रोड) तथा दोनों ओर नाला व इण्टरलॉकिंग निर्माण हेतु लगभग 78.00 लाख रुपये राज्यांश से स्वीकृत किया गया। यहीं पर बसना नाले पर साइजिंग गली व मातादीन का पूरा के बीच एक पुलिया (रपटा) निर्माण होना था। लगभग 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आधा-अधूरा एवं गुणवत्ताविहीन कार्य कराने से आवागमन की स्थिति और भी खराब हो गई है। जिन दुकानों के सामने नाला बनाया गया है, वहां टूटे-फूटे रास्ते व टूटे नाले से दुकानदारों तथा उपभोक्ताओं को बहुत कष्ट है। जगह-जगह पर जल जमाव होने से लोगों में भारी आक्रोश है। शिकायत, धरना-प्रदर्शन का लोक निर्माण विभाग पर कोई असर नहीं है, जिससे स्थिति विस्फोटक हो रही है।

उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यानाकर्षण करते हुए सरकार से उक्त निर्माणों की गुणवत्ता, भ्रष्टाचार, समयबद्धता आदि की गम्भीरतापूर्वक टी0ए0सी0 से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने तथा सदन में वक्तव्य दिलाने की मांग की गई है।

<u>वक्तव्य</u>

जनपद इलाहाबाद में फाफामऊ बाजार में वित्तीय वर्ष 2009-10 में 3054 सामान्य मरम्मत मद के अन्तर्गत फाफामऊ-सहसों-हनुमानगंज मार्ग के कि0मी0-1 (फाफामऊ) बाजार में सी0सी0 रोड एवं इण्टरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य धनराशि रु0 37.47 लाख स्वीकृत हुआ था। अनुबन्ध के अनुसार कार्य 04/2010 तक पूर्ण होना था। अतिक्रमण आदि के कारण कार्य में व्यवधान होने से कार्य को 01/2011 में लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण किया गया।

जनपद इलाहाबाद में फाफामऊ बाजार में वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्य सड़क निधि मद के अन्तर्गत फाफामऊ-सहसों-हनुमानगंज मार्ग के कि0मी0-1 (फाफामऊ) बाजार में यू टाइप पक्की नाली का कलवर्ट का निर्माण कार्य हेतु धनराशि रु0 35.96 लाख स्वीकृत हुआ था। अनुबन्ध के अनुसार कार्य 03/2011 तक पूर्ण होना था। स्थानीय विवादों एवं अतिक्रमण के कारण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हुआ। कार्य लोक निर्माण विभाग के विशिष्टियों के अनुरूप 12/2012 में पूर्ण करा लिया गया है।

जिलाधिकारी, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 08-08-12 द्वारा 02 सदस्यों की टीम बनाकर जांच की गई, जिसमें उपरोक्त दोनों कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। पुनः श्री अनुग्रह नारायण सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 18-10-12 के क्रम में आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 19-10-2012 द्वारा उपरोक्त दोनों कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु 02 सदस्यीय टीम गठित करके कार्यों की जांच कराई गई। कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई।

जिलाधिकारी, इलाहाबाद एवं मण्डलायुक्त, इलाहाबाद द्वारा स्थानीय स्तर पर कराई गई जांच में विभाग द्वारा कराये गये कार्यों को संतोषजनक पाया गया है, फिर भी मा0 सदस्य की सूचना दिनांक 21-02-2013 का संज्ञान लेते हुए शासन के पत्र दिनांक 22-2-2013 द्वारा उक्त कार्यों की टी0ए0सी0 को जांच के आदेश दे दिये गये हैं। टी0ए0सी0 की जांच आख्या प्राप्त होने पर यदि कराये गये कार्यों में कोई अनियमितता पाई जाती है तो दोषी कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद पीलीभीत की जिला पंचायत में कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

जनपद चन्दौली में वित्तीय वर्ष 2012 में अवमुक्त धनराशि से विकास कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह भी स्थगित है।

जनपद शामली के कतिपय क्षेत्रों में फुंके हुए ट्रांसफार्मर को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि ....

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द सिंह गोप)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य बाल विकास एवं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री वसीम अहमद-

[पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था बहुत ही खराब है मेरे विधान सभा क्षेत्र शामली व पूरे जनपद शामली में किसानों व आम नागरिकों को बिजली सम्बन्धी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजली विभाग द्वारा फुंके हुए ट्रान्सफार्मर नहीं बदले जाते हैं। सरकार द्वारा विद्युत विभाग को ट्रान्सफार्मर फुंकने के उपरान्त लाने व ले-जाने के लिये धन दिया जाता है लाने व ले जाने की जिम्मेदारी विभाग की होती है परन्तु विभाग द्वारा इसकी अनदेखी करते हुए किसानों के ट्रान्सफार्मर फुंकने के उपरान्त घर तक पहुंचाने की बात तो दूर की है वरन् ट्रान्सफार्मर लाने व ले जाने का पैसा किसानों से वसूला जाता है किसानों की लूट की जाती है तथा समय से ट्रांन्सफार्मर नहीं दिया जाता है।

आख्या :-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद शामली में शासन के आदेशों के अनुरूप टाउन एरिया में लगभग 14 घण्टे व ग्रामीण क्षेत्र में 08 घण्टे तथा जनपद मुख्यालय शामली में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जनपद शामली में माह 07/2012 से आज तक 250 के0वी0ए0 एवं 400 के0वी0ए0 क्षमता के 60 फुंके हुए ट्रान्सफार्मर बदले जा चुके हैं एवं 25, 63 व 100 के0वी0ए0 के 490 ट्रान्सफार्मर क्षतिग्रस्त हुए थे जिसमें से 450 ट्रान्सफार्मर बदले जा चुके हैं तथा शेष 40 ट्रान्सफार्मर का बदला जाना प्रक्रियाधीन है, शीघ्र ही बदल दिये जायेंगे।

निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं के फुंके हुए ट्रान्सफार्मर किसानों द्वारा स्वयं भण्डार केन्द्र तक लाने व ले जाने का कार्य किया जाता है जो निगम में प्राविधानित है तथा अन्य श्रेणी के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपभोक्ताओं के फुंके हुए ट्रान्सफार्मर को स्थल से भण्डार केन्द्र तक तथा भण्डार केन्द्र से स्थल तक पहुंचाने हेतु विभाग द्वारा अनुबन्ध किया गया है। कतिपय मामलों में उपभोक्ता अति सक्रियता दिखाते हुए अपने साधन से ट्रान्सफार्मर को लाने व ले जाने का काम अपनी इच्छा से करते है। क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों को बदलने हेतु लाने-ले जाने का कार्य कारपोरेशन/निगम के आदेशों के अनुरूप ही किया जा रहा है।]

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, मेरी सुन लो। यह तो पढ़ा हुआ मान लिया। माननीय अध्यक्ष जी, आज यह वक्तव्य पढ़ करके बड़ा दर्द हुआ, बड़ी दिक्कत महसूस हुई। इसमें माना गया, मैंने उठाया था कि ट्रांसफार्मर दिलाने के लिए सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है विभाग को कि ट्रांसफार्मर लाना और ले जाना। विभाग द्वारा पैसा दिया जाता है इसमें माना है कि हां ऐसा होता है। एक झूठी बात इसमें लिख दी कि किसान अपनी मर्जी से आता है। किसान लुटने के लिए अपनी मर्जी से आयेगा, किसान पैसे देगा, रिश्वत देगा। जबकि प्राविधान यह है कि अगर ट्रांसफार्मर फुंक जाता है तो उसके घर तक पहुंचाने का काम और फुंका हुआ लाने का इंतजाम सरकार का है। सरकार पैसा देती है माननीय अध्यक्ष जी, जिस अधिकारी ने यह लिखकर भेजा है, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। अध्यक्ष जी, कहां कहें हम, आप ही से तो कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा करो, इस वक्तव्य पर एक नोटिस दोगे तो अधिकारी भी तलब होंगे सबसे पूछा जाएगा तो अपने आप सही हो जायेगा।

श्री पंकज कुमार मलिक-

किस नियम में दे दें ?

श्री अध्यक्ष-

नियम 166-167 में।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, ठीक है।

जनपद सीतापुर में चिकित्सकों की तैनाती न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

जनपद मेरठ में जल निगम द्वारा पाइप लाइन डालने हेतु खोदी गई सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी हैं ? नहीं हैं तो आगे बढ़िये।

प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंकों में बैंकिंग लाइसेन्स लेना अनिवार्य किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)-

प्रदेश में त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख ढांचे के अन्तर्गत जिला स्तर पर 50 जिला सहकारी बैंक कार्यरत हैं। दिनॉक 31-03-2012 तक 25 जिला सहकारी बैंकों के पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त था.....

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री शंख लाल मांझी)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य बाल विकास एवं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री वसीम अहमद-

[जबकि शेष 25 जिला सहकारी बैंक लाइसेंस हेतु अर्हता पूर्ण नहीं कर रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 15 मई, 2012 को 25 गैर लाइसेंस प्राप्त बैंकों पर नये निक्षेप लेने पर रोक लगाने के कारण उनका बैंकिंग व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से मु0 191.89 करोड़ की धनराशि 9 जिला सहकारी बैंकों को लाइसेंस की अर्हता पूर्ण करने हेतु उपलब्ध करा दी गई है जिसके फलस्वरूप लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी एवं मऊ में स्थित जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। वर्तमान में प्रदेश में 16 जिला सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न कर पाने के कारण बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सके हैं जिसमें जिला सहकारी बैंक फैजाबाद भी है। अल्पकालीन सहकारी साख व्यवस्था के पुनरुद्धार हेतु वैद्यनाथन कमेटी की संस्तुतियों के क्रम में लागू रिवाइवल पैकेज के अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार से रु0 1545.69 करोड़ तथा राज्यांश के रूप में रु0 265.68 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त होनी थी। राज्य सरकार द्वारा अपना समस्त अंश मु0 265.68 करोड़ रु0 की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जबकि केन्द्र सरकार से केन्द्रांश के रूप में मात्र रु0 623.41 करोड़ प्राप्त हुआ है। केन्द्रांश के रूप में रु0 922.28 करोड़ रु0 की वित्तीय सहायता प्राप्त होना शेष है। इस सन्दर्भ में रिवाइवल पैकेज की संस्तुतियों को लागू करने के सम्बन्ध में हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 में निर्धारित बेंच माक्र की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 नियमावली 1968 एवं उपविधियों में आवश्यक संशोधन किये जा चुके हैं।

2-सभी सहकारी संस्थाओं की प्रबन्ध समिति का निर्वाचन पूर्ण हो चुका है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हैं।

4-प्रदेश सरकार द्वारा वायदाकृत देयताओं की समस्त धनराशि मु0 183.22 करोड़ अवमुक्त की जा चुकी है।

5-सहकारी संस्थाओं की अंशपूंजी में 25 प्रतिशत से अधिक लगी अंशपूंजी की धनराशि को राज्य सरकार ने अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दिया है।

केन्द्रांश की अवेशष धनराशि प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक से बैठकों में एवं पत्रों द्वारा कई बार अनुरोध किया जा चुका है किन्तु उक्त धनराशि अभी तक नहीं मिल पाई है। यदि केन्द्रांश के रूप में अवशेष धनराशि रु0 922.28 करोड़ अवमुक्त हो जाय तो लाइसेंस प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करते हुए लाइसेंस प्राप्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

उक्त धनराशि प्राप्त करने के लिये शासन स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एवं केन्द्र स्तर पर सचिव कृषि, भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठकों में उक्त धनराशि को अवमुक्त करने हेतु कई बार अनुरोध किया जा चुका है एवं केन्द्र सरकार भी राज्य सरकार की इस बात से सहमत है कि राज्य सरकार ने बेंच माक्र की सभी शर्तें पूरी कर ली हैं। परन्तु अभी तक उक्त धनराशि केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त नहीं की गई है जिसके कारण शेष 16 बैंकों को लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं बैंकों में जिला सहकारी बैंक फैजाबाद भी शामिल है। केन्द्रांश की अवशेष धनराशि रु0 922.28 करोड़ प्राप्त होने पर अन्य बैंकों के साथ-साथ जिला सहकारी बैंक फैजाबाद को भी बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।]

(श्री रामचन्द्र यादव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

देखिए, पहले पूरा वक्तव्य पढ़ लीजिए इसमें कोई दिक्कत हो तब मुझसे मिलना।

श्री रामचन्द्र यादव-

मान्यवर, यह सहकारिता आन्दोलन से जुड़ा हुआ और फैजाबाद जिला सहकारी बैंक के वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के लिए सरकार को धन स्वीकृत करना है। इसमें जो आया है, कोई समय-सीमा सुनिश्चित नहीं की गयी है। मान्यवर, इससे दो लाख पैंतीस हजार साधन सहकारी समितियों का, डेढ़ लाख वहां के छोटे काश्तकारों का, 300 कर्मचारियों का मामला है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें मैं आपकी कृपा चाहता हूं कि इसका जो भी वक्तव्य है, इसको समयबद्ध करवा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लेंगे।

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, ठीक है।

जनपद कुशीनगर के पडरौना क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों में विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

बाल विकास एवं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र-पड़रौना में विस्तारित बिजनेस प्लान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में विद्युतीकरण हेतु 33 ग्रामों का चयन हुआ था....

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री शंख लाल मांझी)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य बाल विकास एवं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री वसीम अहमद-

[जिसके लिये शासन से रुपया 2 करोड़ की धनराशि स्वीकृत भी हो चुकी थी परन्तु एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है और अभी तक मात्र सात ग्रामों (जं0 बसहिया बनवीरपुर जंगल चौरिया बनटोलवा, खुड्डा बुजुर्ग, नादह एवं दमवतिया) में ही विद्युतीकरण हुआ है। शेष 26 ग्रामों में कहीं खम्भे गिरे हैं कहीं-कहीं खड़े भी किये गये हैं और किसी-किसी ग्राम में आंशिक खम्भे गिरे हैं, शेष गिरने हैं किन्तु गत एक वर्ष से विद्युतीकरण का कार्य पूर्णतः ठप है। बिना विद्युतीकरण कराये पैसे को हड़प जाने या दुरुपयोग किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यन्त रोष एवं आक्रोश व्याप्त है स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है।

आख्या :-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पडरौना में विस्तारित बिजनेश प्लान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत विद्युतीकरण कार्य कराये जाने हेतु 33 गांवों का चयन किया गया था इसमें से सात ग्रामों का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

वर्तमान में विस्तारित बिजनेश योजना प्रचलन में नहीं है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण जिसे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है, योजना की स्वीकृति उपरान्त विद्युतीकरण का कार्य करा दिया जायेगा।]

श्री अध्यक्ष-

जैसल जी, न तो आपका पड़रौना क्षेत्र है न मौर्या जी का पड़रौना क्षेत्र है, पड़रौना तो मैं भी रहा हूं। ये बहुत बाद में गए, मेरा तो जीवन वहां बीता है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे इसमें मैं सादर अनुरोध यह करूंगा कि 2011-2012 में 33 गांव विद्युतीकरण हेतु विस्तारित बिजनेस योजना के अंतर्गत चयनित किए गये। दो करोड़ रुपया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जितना उस पर कुल लागत आनी चाहिए वह भी स्वीकृत कर दिया गया, धनराशि भी जिले में मौजूद है और जितनी योजना थी, उसमें जितनी लागत थी, उतना पैसा जब मौजूद है तो काम आधा-अधूरा छोड़ दिया गया। केवल 07 गांवों का विद्युतीकरण हो पाया, शेष गांवों में खम्भे कहीं खड़े हैं, कहीं गिरे हैं, कहीं तार लगा हुआ है, कहीं आधा-अधूरा रह गया है। हम केवल इतना अनुरोध करना चाहेंगे कि ये 33 गांवों का चूंकि पैसा ऑलरेडी है तो विद्युतीकरण सुनिश्चित करा दिया जाए।

श्री वसीम अहमद-

जैसा हमारे नेता विपक्ष ने कहा है अगर ऐसा है तो उसको करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है चलिये, आश्वासन हो गया।

श्री वंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, बार-बार उंगली उठाते हो।

जनपद अलीगढ़ के राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी स्थल पर दुकानों के निर्माण में हुई धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ठा0 दलवीर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-18 स्थगित है।

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर में वर्ष 2012-2013 में गन्ना क्रय केन्द्रों पर मनमानी किये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री रोशन लाल वर्मा जी नहीं है, आगे बढ़िये।

आगरा के विधान सभा फतेहाबाद बाईपास के अन्तर्गत निर्माण कार्य में भूमि अधिग्रहीत किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री छोटे लाल वर्मा जी हैं ? नहीं हैं, चलिये, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर में महिला आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को सेवा में वापस लिये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री सुरेश कुमार खन्ना जी नहीं हैं, चलिये, छोड़िये, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।

मेरठ विकास प्राधिकरण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कोलोनाइजर बिल्डरों से मिलकर बड़े पैमाने में घोटाले किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कुंवर भारतेन्द्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

कुंवर भारतेन्द्र जी नहीं हैं, आगे बढ़िये।

जनपद सुल्तानपुर में निर्माणाधीन तहसील जयसिंहपुर की अवशेष धनराशि को अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री अरुण वर्मा जी हैं? अरूण वर्मा जी भी नहीं हैं, चलिये।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र कैण्ट के अन्तर्गत स्थित कतिपय कालोनियों के सीवरों की सफाई एवं जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया जी भी चले गये। अब कोई नहीं है।

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पूर्वाह्न फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 06 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 27 फरवरी, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-11 का उत्तर पीछे पृष्ठ-34-35 पर)

प्रदेश के विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत एम्बुलेंसों का जिलेवार विवरण

क्र0सं0	जनपद	राज्य सरकार के अन्तर्गत एम्बुलेन्स	यू0पी0 एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत एम्बुलेंस	इमरजेन्सी मेडिकल ट्रान्सपोर्ट सेवा (108) के अन्तर्गत एम्बुलेंस
1	आगरा	12	17	19
2	फिरोजाबाद	4	11	11
3	मैनपुरी	5	11	11
4	मथुरा	5	12	12
5	एटा	6	10	10
6	अलीगढ़	5	14	16
7	कासगंज	2	9	9
8	हाथरस	2	9	9
9	बरेली	9	17	19
10	शाहजहांपुर	7	17	17
11	पीलीभीत	5	9	9
12	बदायूं	10	17	17
13	मेरठ	7	14	16
14	गौतमबुद्धनगर	2	6	6
15	बागपत	4	8	8
16	बुलन्दशहर	8	18	18
17	गाजियाबाद	4	6	6
18	हापुड़	2	6	4
19	मुरादाबाद	4	10	12
20	रामपुर	8	8	8
21	अमरोहा	5	8	8
22	बिजनौर	6	13	13
23	सम्भल	2	10	8
24	सहारनपुर	7	13	13
25	मुजफ्फरनगर	8	11	11

क्र0सं0	जनपद	राज्य सरकार के अन्तर्गत एम्बुलेन्स	यू0पी0 एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत एम्बुलेंस	इमरजेन्सी मेडिकल ट्रान्सपोर्ट सेवा (108) के अन्तर्गत एम्बुलेंस
26	शामली	2	7	5
27	फैजाबाद	4	13	15
28	सुल्तानपुर	8	17	16
29	अम्बेडकरनगर	5	11	11
30	अमेठी	3	18	18
31	बाराबंकी	4	17	17
32	कानपुर नगर	10	12	14
33	कानपुर देहात	6	12	12
34	फर्रुखाबाद	5	9	9
35	इटावा	7	10	9
36	कन्नौज	3	10	10
37	औरैया	4	9	9
38	लखनऊ	18	10	13
39	सीतापुर	11	21	21
40	लखीमपुर खीरी	10	17	17
41	हरदोई	5	21	21
42	रायबरेली	6	17	17
43	उन्नाव	5	18	18
44	चित्रकूट	5	7	7
45	महोबा	4	6	6
46	बांदा	5	10	10
47	हमीरपुर	3	9	9
48	झांसी	6	10	12
49	ललितपुर	4	8	8
50	जालौन उरई	6	11	11
51	आजमगढ़	10	24	26
52	मऊ	5	11	10
53	बलिया	9	19	19

क्र0सं0	जनपद	राज्य सरकार के अन्तर्गत एम्बुलेन्स	यू0पी0 एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत एम्बुलेंस	इमरजेन्सी मेडिकल ट्रान्सपोर्ट सेवा (108) के अन्तर्गत एम्बुलेंस
54	इलाहाबाद	16	22	24
55	प्रतापगढ़	10	19	19
56	कौशाम्बी	2	10	10
57	फतेहपुर	8	15	15
58	बस्ती	7	16	15
59	सिद्धार्थनगर	5	16	15
60	संतकबीरनगर	4	11	11
61	बलरामपुर	7	11	11
62	गोण्डा	7	18	18
63	श्रावस्ती	5	7	7
64	बहराइच	7	16	16
65	गोरखपुर	11	21	23
66	कुशीनगर	5	16	16
67	देवरिया	4	18	18
68	महराजगंज	7	14	14
69	मीरजापुर	6	14	14
70	संतरविदासनगर	2	8	8
71	सोनभद्र	3	10	10
72	वाराणसी	7	10	12
73	जौनपुर	12	23	23
74	चन्दौली	4	11	11
75	गाजीपुर	4	18	18
		455	**972**	**988**

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-67 का उत्तर पीछे पृष्ठ-61 पर)

मण्डल	क्रमांक	जनपद	PHC	CHC	Remark
आगरा	1	आगरा	0	0	
	2	फिरोजाबाद	1	0	
	3	मैनपुरी	3	0	
	4	मथुरा	0	0	
अलीगढ़	5	अलीगढ़	0	0	
	6	कासगंज	3	0	
	7	एटा	4	0	
	8	हाथरस	0	0	
इलाहाबाद	9	इलाहाबाद	0	0	
	10	प्रतापगढ़	0	0	
	11	फतेहपुर	11	0	
	12	कौशाम्बी	0	0	
आजमगढ़	13	आजमगढ़	16	0	
	14	बलिया	15	0	15 निर्माणाधीन
	15	मऊ	3	0	
बरेली	16	बरेली	0	0	
	17	पीलीभीत	0	0	
	18	शाहजहांपुर	0	0	
	19	बदायूं	0	0	
देवीपाटन	20	बलरामपुर	4	0	4 निर्माणाधीन
	21	बहराइच	3	0	3 निर्माणाधीन
	22	गोण्डा	0	0	
	23	श्रावस्ती	0	0	
फैजाबाद	24	फैजाबाद	0	0	
	25	अमेठी	4	0	
	26	अम्बेडकरनगर	0	0	
	27	बाराबंकी	0	0	
	28	सुल्तानपुर	1	0	

मण्डल	क्रमांक	जनपद	PHC	CHC	Remark
बस्ती	29	बस्ती	2	0	
	30	सिद्धार्थनगर	2	0	2 निर्माणाधीन
	31	संतकबीरनगर	2	0	2 निर्माणाधीन
गोरखपुर	32	गोरखपुर	0	0	
	33	देवरिया	1	0	
	34	कुशीनगर	0	0	
	35	महराजगंज	0	0	
झांसी	36	झांसी	0	0	
	37	ललितपुर	0	0	
	38	उरई	0	0	
चित्रकूट	39	चित्रकूट	0	0	
	40	महोबा	0	0	
	41	बांदा	0	0	
	42	हमीरपुर	0	0	
कानपुर	43	कानपुर नगर	0	0	
	44	कानपुर देहात	0	0	
	45	फर्रुखाबाद	0	0	
	46	औरैया	0	0	
	47	इटावा	0	0	
	48	कन्नौज	0	0	
लखनऊ	49	लखनऊ	1	0	
	50	रायबरेली	2	0	2 निर्माणाधीन
	51	हरदोई	6	0	5 निर्माणाधीन
	52	उन्नाव	0	0	
	53	सीतापुर	0	0	
	54	खीरी	0	0	
मेरठ	55	मेरठ	0	0	
	56	बुलन्दशहर	2	0	1 निर्माणाधीन
	57	बागपत	0	0	
	58	गौतमबुद्धनगर	4	0	
	59	गाजियाबाद	0	0	
	60	हापुड़	0	0	

मण्डल	क्रमांक	जनपद	PHC	CHC	Remark
सहारनपुर	61	सहारनपुर	0	0	
	62	मुजफ्फरनगर	5	0	5 निर्माणाधीन
	63	शामली	0	0	
मुरादाबाद	64	मुरादाबाद	0	0	
	65	सम्भल	4	0	4 निर्माणाधीन
	66	अमरोहा	0	0	
	67	रामपुर	0	0	
	68	बिजनौर	1	0	1 निर्माणाधीन
वाराणसी	69	वाराणसी	0	0	
	70	गाजीपुर	0	0	
	71	चन्दौली	0	0	
	72	जौनपुर	5	0	7 निर्माणाधीन
मिर्जापुर	73	मिर्जापुर	0	0	
	74	सोनभद्र	0	0	
	75	संतरविदासनगर	0	0	
		कुल योगः	**105**	**0**	**कुल निर्माणाधीन 51**

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-68 का उत्तर पीछे पृष्ठ-62 पर)

प्रदेश के निम्नलिखित चिकित्सालयों में उपलब्ध वेन्टीलेटरों की सूची

1. जिला चिकित्सालय, आगरा,
2. जिला चिकित्सालय, अलीगढ़,
3. जिला चिकित्सालय, बरेली,
4. जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर
5. पी0एल0 शर्मा चिकित्सालय, मेरठ,
6. जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर,
7. जिला चिकित्सालय, सहारनपुर,
8. जिला चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर,
9. जिला चिकित्सालय, फैजाबाद,
10. जिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर,
11. जिला चिकित्सालय, बाराबंकी,
12. यू0एच0एम0 चिकित्सालय कानपुर,
13. जिला चिकित्सालय, इटावा,
14. जिला चिकित्सालय, फर्रुखाबाद,
15. बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ,
16. डा0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय, लखनऊ,
17. डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, लखनऊ,
18. जिला चिकित्सालय, रायबरेली,
19. जिला चिकित्सालय, हमीरपुर,
20. जिला चिकित्सालय, झांसी,
21. जिला चिकित्सालय, जालौन,
22. जिला चिकित्सालय, ललितपुर,
23. जिला चिकित्सालय, मऊ,
24. जिला चिकित्सालय, बांदा,
25. टी0बी0 सप्रू चिकित्सालय, इलाहाबाद,
26. ओपेक जिला चिकित्सालय, कैली, बस्ती,

27. जिला चिकित्सालय, गोरखपुर,
28. जिला चिकित्सालय, देवरिया,
29. जिला चिकित्सालय, कुशीनगर, पडरौना,
30. जिला चिकित्सालय, सोनभद्र,
31. जिला चिकित्सालय, गाजीपुर,
32. जिला चिकित्सालय, वाराणसी,
33. जिला चिकित्सालय, चन्दौली,
34. जिला चिकित्सालय, जौनपुर।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-70 का उत्तर पीछे पृष्ठ-62 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के द्वितीय गुरुवार हेतु निर्धारित श्री कमाल यूसुफ मलिक, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न संख्या-70 के उत्तर का संलग्नक

जनपद-सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र में सरयू नहर परियोजना के विभिन्न खण्डों में निर्माण कार्य कराये जाने विषयक श्री कमाल यूसुफ, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रेषित स्पीड पोस्ट संख्या-आर0यू0 075783496 मुख्य अभियंता (परियोजना) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त हुआ। मा0 विधायक का एक लेटर पैड क-5 संख्या-094157 एवं क-5 संख्या-094180 इस कार्यालय में वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (परियोजना) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-एम0-01/02/परि0 अनु0 दिनांक 28-8-2012 के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जिस पर अद्यतन स्थिति अधोलिखित है :-

क्रमांक/ बिन्दु	लेटर पैड का क्रमांक	आख्या
लेटर पैड क-5 संख्या-094157		
1	बांसी शाखा के चौरा बनगवा हेड से रेहरा तक नाला खुदाई	बांसी शाखा के कि0मी0 0.00 से 2.700 तक नहर के बांये तरफ नाला खुदाई की मांग की गई है। इस स्थल पर कोई ड्रेनेज कट नहीं है। नहर के निर्माण के दौरान ली गई मिट्टी के कारण निकट का भूमि स्तर नीचा है जिससे आंशिक क्षेत्र में जलभराव रहता है। ड्रेन के निर्माण से क्षेत्र की सिंचाई में व्यवधान उत्पन्न होगा। अतः मांग स्थल पर नाले का निर्माण तकनीकी दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है।
2	बांसी शाखा के बनगवा हेड से रेहरा के पुल तक खड़न्जा/पिच का कार्य	नहर पट्टी पर खड़न्जा/पिच कराने के कार्य का परियोजना में प्राविधान नहीं है। इस कार्य हेतु पैक्ट संगठन द्वारा कन्सेप्ट नोट तैयार किया जा रहा है, जिसमें प्रश्नगत नहर की रीच को भी सम्मिलित करने हेतु प्रेषित किया गया है।
3	बांसी शाखा के ग्राम रेहरा में पुल की मांग	ग्राम रेहरा में बांसी शाखा के कि0मी0 1.900 पर पुल स्वीकृत है। निर्माण की कार्यवाही प्रगति में है।
4	बांसी शाखा के ग्राम भतिजवापुर में साइफन का निर्माण	यह स्थल बांसी शाखा के कि0मी0 27.821 से सम्बन्धित है। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा रैम्प पर ह्यूम पाइप कलवर्ट बना लिया गया है जिससे जल निकासी हो रही है। अब प्रश्नगत स्थल पर साइफन निर्माण की आवश्यकता नहीं रह गई है।

क्रमांक/ बिन्दु	लेटर पैड का क्रमांक	आख्या
5	बांसी शाखा के हल्लौर करबले के पुल से सोनहटी पुल तक खड़ंजा/ पिच का निर्माण	बिन्दु-2 के अनुसार
6	कूड़ी डिवाई के टिकरिया ग्राम में नहर की पटरी पर खड़ंजा/पिच का कार्य	बिन्दु-2 के अनुसार
7	कूड़ी डिबाई के ग्राम भग्गोभार पुल से ढेबरुआ ग्राम तक खड़ंजा/पिच का कार्य	बिन्दु-2 के अनुसार
8	कूड़ी डिबाई के परसापुर के कोरई बनिया के पुल तक खड़न्जा/पिच का कार्य	बिन्दु-2 के अनुसार
9	बांसी शाखा के मसिना माइनर के भेलभरिया से छितौनी तक खड़ंजा/ पिच का कार्य	बांसी शाखा में मसिना माइनर के भेलभरिया से छितौनी तक खड़ंजा कार्य हेतु मनरेगा के अन्तर्गत नहर पर 160 मीटर लम्बाई में खड़न्जा कार्य तथा 1.600 कि0मी0 में सविस रोड की मरम्मत की परियोजना लागत रुपये 4.82 लाख की परियोजना समन्वयक जनपद सिद्धार्थनगर को भेजी जा चुकी है।
10	बांसी शाखा के मसिना माइनर पर भैसहिया तक खड़ंजा/पिच का कार्य	उक्त स्थल कूडी डिबाई से सम्बन्धित है। क्रमांक-2 के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
11	बांसी शाखा के मसिना माइनर पर ग्राम सेमरहनी के उत्तर तरफ जल निकासी हेतु साइफन का निर्माण कार्य	ग्राम सेमरहनी में जल निकासी हेतु साइफन की मांग असरहरा माइनर के कि0मी0 0.800 से सम्बन्धित है। इस स्थल पर साइफन का अनुबंध गठित है।
12	बांसी शाखा के टेढ़िया के पुल से नहर की पटरी पर सिसई कला तक खड़ंजा/पिच का कार्य	क्रमांक-2 के अनुसार
लेटर पैड क-5 संख्या-094157		
1	बस्ती शाखा के सरयू नहर परसा माइनर के ग्राम गौहनिया से लटिया ग्राम तक खड़ंजा एवं पिच निर्माण कार्य	नहर पटरी पर खड़ंजा/पिच कराने के कार्य का परियोजना में प्रावधान नहीं है। इस कार्य हेतु पैक्ट संगठन द्वारा कन्सेप्ट नोट तैयार किया जा रहा है, जिसमें प्रश्नगत नहर की रीच को भी सम्मिलित करने हेतु प्रेषित किया गया है।

क्रमांक/ बिन्दु	लेटर पैड का क्रमांक	आख्या
2	बस्ती शाखा के सरयू नहर परसा माइनर के ग्राम बासाचक से गरदहिया तक खड़ंजा एवं पिच निर्माण कार्य	क्रमांक-1 के अनुसार
3	बस्ती शाखा के कि0मी0 112.370 पर जल निकासी हेतु स्वीकृत साइफन कार्य तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ कराया जाय	प्रश्नगत स्थल पर ड्रेनेज साइफन निर्माण हेतु अनुबंध गठित है। इस कार्यालय के ज्ञापांक-5791/ मु0अ0स0प0-2 दिनांक 17-10-2012 द्वारा दिनांक 31-3-2013 तक वांछित समयवृद्धि स्वीकृत की जा चुकी है। ठेकेदार द्वारा अभी कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है।
4	बस्ती शाखा के ग्राम कंचनपुर से वासाचक गांव तक खड़ंजा एवं पिच का कार्य	क्रमांक-1 के अनुसार
5	बस्ती शाखा के परसा माइनर के पटरी पर लटिया गांव तक खड़ंजा/ पिच का कार्य	क्रमांक-1 के अनुसार
6	बाढ़ नियंत्रण खण्ड सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत राप्ती नदी के उत्तरी तट पर शाहपुर से बगहवा गांव के पूरब तरफ तक बंधे पर खडंजा/पिच निर्माण कार्य	मुख्य अभियंता (गण्डक) संगठन के नियंत्रणाधीन सिंचाई निर्माण खण्ड-सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत बांसी डुमरियागंज तटबंध के कि0मी0 35.850 पर ग्राम बगहवा से कि0मी0 39.500 तक ग्राम शाहपुर के मध्य बन्धे पर खड़न्जा/पिच निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कोई परियोजना तैयार नहीं की गई है और न ही उक्त चैनेज पर खड़न्जा/पिच निर्माण कार्य हेतु कोई परियेाजना ही प्रस्तावित है।

पी0एस0यू0पी0-एल0 42 विधान सभा (90)-04-07-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।